रजिस्ट्री संख्या डी-एल-33001/92

REGISTERED NO. DL-33001/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 20, 1992/ज्येष्ठ 30, 1914

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 20, 1992/JYAISTHA 30, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 26 मई, 1992

का.आ. 1565.—भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम (संख्या 57), 1959 के खण्ड 8, उपखण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 1993-94 के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति का गठन करती है :—

1. डा. राजा जे. चेलैया, — अध्यक्ष
   भूतपूर्व सदस्य, योजना आयोग,
   तथा अवकाश प्राप्त प्रोफेसर,
   राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान,
   नई दिल्ली-67

2. डा. जी एस. भल्ला, — सदस्य
   प्रोफेसर अर्थशास्त्र,
   क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र,
   जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय,
   नई दिल्ली-110067

3. डा. एम.एस. वलियाथन, — सदस्य
   निदेशक,
   श्री चित्रा तिरुनाल इन्स्टीट्यूट फोर मेडिकल
   साइंस एण्ड टेक्नोलाजी,
   तिरुवनन्तपुरम-695011

4. प्रो. एस.के चटर्जी, — सदस्य
   प्रोफेसर,
   सांख्यिकी विभाग,
   यूनिवर्सिटी कालेज आफ साइंस,
   कलकत्ता-19

5. प्रो. एस.बी राव, — सदस्य
   भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता
   (भारतीय नागरिक संस्थान के मनोनीत)

6. महानिदेशक, — सदस्य
   केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन,
   सांख्यिकी विभाग, नई दिल्ली

7. वित्तीय सलाहकार, — सदस्य
   सांख्यिकी विभाग,
   नई दिल्ली

8. उप सचिव, सदस्य-सचिव
सांख्यिकी विभाग,
नई दिल्ली।

और उक्त समिति को निम्नलिखित कार्य निर्धारित करती है :—

(1) कार्य के समस्त कार्यक्रम (योजनागत तथा योजनेतर दोनों) की समीक्षा करना तथा संशोधित प्राक्कलन 1992-93 में प्रदान की जाने वाली राशि के संबंध में सिफारिशें करना तथा भारतीय सांख्यिकीय संस्थान को सहायता अनुदान अदा करने के लिए 1993-94 के लिए वित्तीय प्राक्कलनों के संबंध में भी सिफारिशें करना।

(2) (क) 1993-94 के दौरान भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का कार्यक्रम (योजनागत तथा योजनेतर दोनों) दर्शाने वाले विवरण तथा इस प्रकार के कार्य के लिए सामान्य वित्तीय अनुमान तैयार करना और उसे केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार निधि की व्यवस्था करती है।

(ख) कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत रूपरेखा निश्चित करना।

2. समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को 31 मार्च, 1993 से पहले प्रस्तुत करेगी।

3. सांख्यिकी विभाग समिति को जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, सचिवालय सहायता प्रदान करेगा।

[संख्या एम-12011/3/89-समन्वय]

नवल किशोर, उप सचिव

MINISTRY OF PLANNING

(Department of Statistics)

New Delhi, the 26th May, 1992

S.O. 1565.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 8 of the Indian Statistical Institute Act (No. 57) of 1959, the Central Government hereby constitutes a Committee for 1993-94 consisting of :

1. Dr. Raja J. Chelliah, ex-Member, Planning Commission, National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi-67. — Chairman
2. Dr. G. S. Bhalla, Professor of Economics, Centre for Studies in Regional Development, JNU, New Delhi-67. — Member
3. Dr. M. S. Valiathan, Director, Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram-695011. — Member
4. Prof. S. K. Chatterjee, Professor, Department of Statistics, University College of Science, Calcutta-19. — Member
5. Prof. S. B. Rao, Indian Statistical Institute, Calcutta. (Nominee of the ISI). — Member
6. Director General, CSO Department of Statistics, New Delhi. — Member
7. Financial Adviser, Department of Statistics, New Delhi. — Member
8. Deputy Secretary, Department of Statistics, New Delhi. — Member-Secy.

and assigns the following duties to the said Committee, namely :

(1) Review of the agreed programme of work (both Plan and Non-Plan) and make recommendations regarding the amount to be provided in the RE 1992-93, and also make recommendations regarding the financial estimates for 1993-94 for paying grant-in-aid to the ISI.

(2) (a) Preparation and submission to the Central Government of Statement showing programmes of work (both Plan and Non-Plan) agreed to be undertaken by the Indian Statistical Institute, Calcutta, during the year 1993-94 for which the Central Government may provide funds, as well as general financial estimates of such work.

(b) The settlement on broad lines of the programme of work.

2. The Committee shall submit its Report to the Government before 31st March, 1993.

3. The Department of Statistical shall render secretariat assistance to the Committee, the headquarters of which will be at New Delhi.

[No. M-12011/3/89-Coord.]

NAWAL KISHORE, Dy. Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 मई, 1992

का.आ. 1566.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) संशोधन नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 1958 की अनुसूची में, "गृह मंत्रालय" शीर्षक के नीचे क्रम सं. 12 और 13 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और उनसे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

12.	भारत के महा रजिस्ट्रार का कार्यालय	भारत का महा रजिस्ट्रार/ भारत का संयुक्त महा-रजिस्ट्रार/ उप निदेशक।
13	जन गणना कार्य निदेशालय, जनगणना कार्य	जन गणना कार्य निदेशक/संयुक्त जन गणना कार्य निदेशक/ उप जन गणना कार्य निदेशक।

[सं. 23/1/91-पब्लिक]

ए. के. नारायणन, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. 2297, तारीख 3 नवम्बर, 1958 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, पश्चातवर्ती संशोधन भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं., 3406 तारीख 24 अक्तूबर, 1970 द्वारा किया गया और उनका निम्नलिखित द्वारा समय-समय पर संशोधन किया गया है :—

1. का.आ.सं. 1270 तारीख 27-3-1971।
2. का.आ.सं. 1271 तारीख 27-3-1971।

3. का.आ.सं. 1521 तारीख 10-4-1971
4. का.आ.सं. 1668 तारीख 24-4-1971
5. का.आ.सं. 2996 तारीख 11-8-1971
6. का.आ.सं. 3408 तारीख 15-9-1971
7. का.आ.सं. 5079 तारीख 3-11-1971
8. का.आ.सं. 5239 तारीख 23-11-1971
9. का.आ.सं. 5252 तारीख 29-11-1971
10. का.आ.सं. 5594 तारीख 30-12-1971
11. का.आ.सं. 210(अ) तारीख 18-3-1972
12. का.आ.सं. 299(अ) तारीख 18-4-1972
13. का.आ.सं. 327(अ) तारीख 29-4-1972
14. का.आ.सं. 513(अ) तारीख 31-7-1972
15. का.आ.सं. 566(अ) तारीख 30-8-1972
16. का.आ.सं. 716(अ) तारीख 18-11-1972
17. का.आ.सं. 23(अ) तारीख 17-1-1973
18. का.आ.सं. 354(अ) तारीख 25-6-1973
19. का.आ.सं. 2683 तारीख 22-9-1973
20. का.आ.सं. 507(अ) तारीख 19-9-1973
21. का.आ.सं. 519(अ) तारीख 26-9-1973
22. का.आ.सं. 552(अ) तारीख 19-10-1971
23. का.आ.सं. 724(अ) तारीख 1-12-1973
24. का.आ.सं. 263(अ) तारीख 26-4-1974
25. का.आ.सं. 321(अ) तारीख 24-5-1974
26. का.आ.सं. 265(अ) तारीख 18-6-1975
27. का.आ.सं. 140(अ) तारीख 25-2-1975
28. का.आ.सं. 195(अ) तारीख 15-3-1976
29. का.आ.सं. 348(अ) तारीख 14-5-1976
30. का.आ.सं. 480(अ) तारीख 19-7-1976
31. का.आ.सं. 493(अ) तारीख 24-7-1976
32. का.आ.सं. 599(अ) तारीख 6-9-1976
33. का.आ.सं. 698(अ) तारीख 30-10-76
34. का.आ.सं. 19(अ) तारीख 12-1-1977
35. का.आ.सं. 228(अ) तारीख 10-3-1977
36. का.आ.सं. 2255(अ) तारीख 24-3-1977
37. का.आ.सं. 408(अ) तारीख 23-6-1977
38. का.आ.सं. 603(अ) तारीख 2-8-1977
39. का.आ.सं. 649(अ) तारीख 3-9-1977
40. का.आ.सं. 320(अ) तारीख 12-5-1978
41. सा.का.सं. 419(अ) तारीख 30-6-1978
42. का.आ.सं. 2914 तारीख 7-10-1976
43. का.आ.सं. 598(अ) तारीख 19-10-1978
44. का.आ.सं. 576 तारीख 17-2-1974
45. का.आ.सं. 1020 तारीख 24-3-1979
46. का.आ.सं. 338(अ) तारीख 7-6-1979
47. का.आ.सं. 3569 तारीख 26-10-1979
48. का.आ.सं. 852(अ) तारीख 18-12-1979
49. का.आ.सं. 245(अ) तारीख 11-4-1980
50. का.आ.सं. 543(अ) तारीख 7-7-1981
51. का.आ.सं. 768(अ) तारीख 23-10-1981
52. का.आ.सं. 917(अ) तारीख 28-12-81
53. का.आ.सं. 428(अ) तारीख 13-6-1983
54. का.आ.सं. 563(अ) तारीख 8-8-1983
55. का.आ.सं. 639(अ) तारीख 6-9-1983
56. का.आ.सं. 795(अ) तारीख 7-11-1983
57. का.आ.सं. 174(अ) तारीख 31-3-1984
58. का.आ.सं. 1(अ) तारीख 3-1-1984
59. का.आ.सं. 2(अ) तारीख 5-1-1985
60. का.आ.सं. 799(अ) तारीख 30-10-1985
61. का.आ.सं. 46(अ) तारीख 4-2-1986
62. का.आ.सं. 266(अ) तारीख 14-5-1986
63. का.आ.सं. 267(अ) तारीख 13-5-1986
64. का.आ.सं. 738(अ) तारीख 15-10-1986
65. का.आ.सं. 118(अ) तारीख 20-2-1987
66. का.आ.सं. 167(अ) तारीख 10-3-1987
67. का.आ.सं. 934(अ) तारीख 11-4-1987
68. का.आ.सं. 666(अ) तारीख 1-7-1987
69. का.आ.सं. 25(अ) तारीख 8-1-1988
70. का.आ.सं. 746(अ) तारीख 4-8-1988

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 29th May, 1992

S.O. 1566.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and oher Instruments) Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, under the heading "Ministry of Home Affairs", for serial numbers 12 and 13 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substitued, namely :—

"12. Office of the Registrar General, India—Registrar General, India/Joint Registrar General, India/Deputy Director.

13. Directorate of Census Operations—Director of Census Operations/Joint Director of Census Operations/Deputy Director of Census Operations".

[No. 23/1/91-Public]

A. K. NARAYANAN, Jt. Secy.

Note.—Principal rules published vide Notification No. 2297 dated the 3rd November, 1958, Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii), Subsequently amended vide Notification No.3406 dated the 24th October, 1970, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) have been amended from time to time vide :—

1. S.O. No. 1270 dated 27-3-1971
2. S.O. No. 1271 dated 27-3-1971
3. S.O. No. 1521 dated 10-4-1971
4. S.O. No. 1668 dated 24-4-1971
5. S.O. No. 2996 dated 11-8-1971
6. S.O. No. 3408 dated 15-9-1971
7. S.O. No. 5079 dated 3-11-1971
8. S.O. No. 5239 dated 23-11-1971
9. S.O. No. 5252 dated 29-11-1971
10. S.O. No. 5594 dated 30-12-1971
11. S.O. No. 210(E) dated 18-3-1972
12. S.O. No. 299(E) dated 18-3-1972
13. S.O. No. 327(E) dated 29-4-1972
14. S.O. No. 513(E) dated 31-7-1972
15. S.O. No. 568(E) dated 30-8-1972
16. S.O. No. 716(E) dated 18-11-1972
17. S.O. No. 23(E) dated 17-1-1973
18. S.O. No. 354(E) dated 25-6-1973
19. S.O. No. 2683 dated 22-9-1973
20. S.O. No. 507(E) dated 19-9-1973
21. S.O. No. 519(E) dated 26-9-1973
22. S.O. No. 552(E) dated 19-10-1973
23. S.O. No. 724(E) dated 1-12-1973
24. S.O. No. 263(E) dated 26-4-1974
25. S.O. No. 321(E) dated 24-5-1974
26. S.O. No. 265(E) dated 18-6-1975
27. S.O. No. 140(E) dated 25-2-1976
28. S.O. No. 195(E) dated 15-3-1976
29. S.O. No. 348(E) dated 14-5-1976
30. S.O. No. 480(E) dated 19-7-1976
31. S.O. No. 493(E) dated 24-7-1976
32. S.O. No. 599(E) dated 6-9-1976
33. S.O. No. 698(E) dated 30-10-1976
34. S.O. No. 19(E) dated 12-1-1977
35. S.O. No. 228(E) dated 10-3-1977
36. S.O. No. 255(E) dated 24-3-1977
37. S.O. No. 408(E) dated 23-6-1977
38. S.O. No. 603(E) dated 2-8-1977
39. S.O. No. 649(E) dated 3-9-1977
40. S.O. No. 320(E) dated 12-5-1978
41. S.O. No. 419(E) dated 30-6-1978
42. S.O. No. 2914 dated 7-10-1978
43. S.O. No. 598(E) dated 19-10-1978
44. S.O. No. 576 dated 17-2-1979
45. S.O. No. 1020 dated 24-3-1979
46. S.O. No. 338(E) dated 7-6-1979
47. S.O. No. 3569 dated 27-10-1979
48. S.O. No. 852(E) dated 18-12-1979
49. S.O. No. 245(E) dated 11-4-1980
50. S.O. No. 543(E) dated 7-7-1981
51. S.O. No. 768(E) dated 23-10-1981
52. S.O. No. 917(E) dated 28-12-1981
53. S.O. No. 428(E) dated 13-6-1983
54. S.O. No. 563(E) dated 8-8-1983
55. S.O. No. 639(E) dated 5-9-1983
56. S.O. No. 795(E) dated 7-11-1983
57. S.O. No. 174(E) dated 21-3-1984
58. S.O. No. 1(E) dated 3-1-1984
59. S.O. No. 2 dated 5-1-1985
60. S.O. No. 799(E) dated 30-10-1985
61. S.O. No. 46(E) dated 4-2-1986
62. S.O. No. 266(E) dated 14-5-1986
63. S.O. No. 267(E) dated 13-5-1986
64. S.O. No. 738(E) dated 15-10-1986
65. S.O. No. 118(E) dated 20-2-1987
66. S.O. No. 167(E) dated 10-3-1987
67. S.O. No. 934(E) dated 11-4-1987
68. S.O. No. 666(E) dated 1-7-1987
69. S.O. No. 25(E) dated 8-1-1988
70. S.O. No. 746(E) dated 4-8-1988

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 1992

का. आ. 1567 :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/662/89—सी. शु.—8 तारीख 16-11-89 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री लब्दीराज बनराज मेहता, लीबर्टी गार्डन रोड नं. 2, गजानन अपार्टमेंट नं. 2, मालाड (प.), बम्बई 400064 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी का माल लाने, ले जाने अथवा छिपाने या रखने के अलावा इसका धंधा करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/662/89—सी. शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 1992

S.O. 1567.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/662/89-CUS. VIII dated 16th November, 1989 under the said sub-section directing that Shri Labdiraj Vanraj Mehta, Liberty Garden Road No. 2, Gajanan Apartment No. 2, Malad (West), Bombay-400064 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/662/89-Cus. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 1992

का. आ. 1568 :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव, ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/59/90—सी. शु.—8 तारीख 6-3-90 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री मोहम्मद अब्दुल मालेक पुत्र श्री स्व. अब्दुल सारकर, ग्राम—पैकपारा, पो. केडेपारा, थाना तथा जिला—बघेरहाट, बांग्लादेश को निरुद्ध कर लिया जाए और प्रेसीडैन्सी जेल, कलकत्ता में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को लाने, ले जाने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/59/90—सी. शु.-8]

रूपचन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 1992

S.O. 1568.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/59/90-CUS. VIII dated 6th March, 1990 under the said sub-section directing that Shri Md. Abdul Malek, S/o Late Abdul Sarkar, Village Paikpara, P.O. Kadepara, P.S. & District Bagherhat, Bangladesh, be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from engaging in transporting smuggled goods.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, West Bengal, Calcutta within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/59/90-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 1992

का. आ. 1569 :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. 673/487/89—सी. शु.—III तारीख 29-8-89 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री अब्दुल हाई अरबबादशाह, 835, डोपादपटटी बंगाली पुरा, बी. पी. टी., रेलवे, बाधाला, बम्बई—37 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि सामान की तस्करी करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/487/89—सी. शु.-8]

रूपचन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 1992

S.O. 1569.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/487/89-CUS. VIII, dated 29th August, 1989 under the said sub-section that Shri Abdul Hai Arab Badshah, 835, Zopadpatti, Bongalipara, B.P.T., Railway,

Wadala, Bombay-37, be detained and kept in custody in Central Prison, Bombay with a view to preventing him from smuggling goods.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/487/89-Cus. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 1992

का. आ. 1570 :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/255/89—सी. शु.—8, तारीख 18-5-89 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री अयूब अली खान पुत्र श्री सिकन्दर अली खान, खान मोहल्ला, पो.—कुचामान, जिला—नागौर, राजस्थान को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, कलकत्ता में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को लाने, ले जाने अथवा छिपाने के अलावा तस्करी का माल रखने तथा इस धंधे में लिप्त रहने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, जयपुर के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/255/89—सी. शु.-8]

रूपचन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 1992

S.O. 1570.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under order F. No. 673/255/89-CUS. VIII dated 18th May, 1989 under the said sub-section directing that Shri Ayub Ali Khan, S/o Shri Sikandar Ali Khan, Khan Mohalla, P.O. Kuchaman, District Nagour, Rajasthan, be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from engaging in keeping smuggled goods and dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting or concealing smuggled goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Rajasthan, Jaipur within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/255/89-Cus. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 1992

का. आ. 1571.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/218/90 सी. शु.—8 तारीख 12-7-90 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री महिन्दर सिंह, दुकान नं. 1186, कूचा महाजनी, चांदनी चौक दिल्ली को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को लाने ले जाने अथवा छिपाने के अलावा तस्करी का माल रखने तथा धंधा करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 का उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, दिल्ली के समक्ष हाजिर हों।

[फा. सं. 673/182/90—सी. शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 1992

S.O. 1571.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/218/90-CUS. VIII dated 12th July, 1990 under the said sub-section directing that Shri Mahinder Singh, resident of Shop No. 1136, Kucha Mahajani, Chandni Chowk, Delhi, be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from engaging in keeping smuggled goods and dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting or concealing smuggled goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/218/90-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 1992

का.आ 1572.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673 312 90 सी.शु.-8 तारीख 9-10-90 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री के. साथियानारायण पुत्र श्री वी. कृष्णन, 144, करूप्पा काउन्डर स्ट्रीट, कोयम्बटूर, तमिलनाडू को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, कोयम्बटूर में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी का माल छिपाने तथा रखने के अलावा तस्करी के माल को लाने ले जाने तथा इसका धंधा करने में लिप्त रहने से रोका जा सके ।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, मद्रास के समक्ष हाजिर हो ।

[फा. सं. 673/312/90–सी. शु.-8]

रूप चन्द अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 1992

S.O. 1572.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/312/90-CUS. VIII dated 9th October, 1990 under the said sub-section directing that Shri K. Sathiyanarayana, S/o V. Krishnan, No. 144, Karuppa Counder Street, Coimbatore, Tamilnadu, be detained and kept in custody in the Central Prison, Coimbatore with a view to preventing him from engaging in transporting smuggled goods and dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in concealing and keeping smuggled goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Tamil Nadu, Madras, within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/312/90-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 1992

का. आ. 1573.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/416/90 सी. शु०-8 तारीख 21-2-90 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री जिबन साहा ग्राम—नारायण पुर, (कुन्डू कालोनी), पो. तथा थाना बलूरघाट, जिला—दिनाजपुर, प. बंगाल को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, कलकत्ता में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी का माल छिपाने तथा रखने के अलावा तस्करी के माल को लाने ले जाने तथा इसका धंधा करने में लिप्त रहने से रोका जा सके ।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो ।

[फा. सं. 673/416/90—सी. शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 1992

S.O. 1573.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/416/90-CUS. VIII dated 21st February, 1990 under the said sub-section directing that Shri Jibal Saha, Village Narayanpur (Kundu Colony), P.O. & P.S. Balurghat, District West Dinajpur, West Bengal, be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from engaging in transporting smuggled goods and dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in concealing and keeping smuggled goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, West Bengal, Calcutta within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/416/90-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 1992

का. आ. 1574—.भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673 415/90—सी. शु.-8 तारीख 21-12-90

यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री स्वपन कुन्दू पुत्र श्री अमुल्या कुन्दू, नारायण पुर (कुन्दू कालोनी) पो. और थाना—बलूर घाट, जिला—प. दिनाजपुर, प. बंगाल को निरूद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, कलकत्ता में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी का माल छिपाने तथा रखने के अलावा तस्करी के माल को लाने ले जाने तथा इसका धंधा करने में लिप्त रहने के रोका जा सके ।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/415/90—सी. शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 1992

S.O. 1574.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/415/90-CUS. VIII dated 21st December, 1990 under the said sub-section directing that Shri Swapan Kundu, S/o Shri Amulya Kundu, Narayanpur (Kundu Colony), P.O. & P.S. Balurghat, District West Dinajpur, West Bengal be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from engaging in transporting smuggled goods and dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in concealing and keeping smuggled goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, West Bengal, Calcutta within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/415/90-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 1992

का० आ० 1575.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षणऔर तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/283/90—सी. शु.-8 तारीख 14-9-90 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री प्रमोद कुमार पाहवा, सुपुत्र श्री सूरज प्रकाश पाहवा, निवासी एम. यू.-7 प्रीतम पुरा, दिल्ली को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, तिहाड में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को छिपाने तथा रखने के अलावा इसे लाने ले जाने तथा धंधा करने के कार्य में लिप्त रहने से रोका जा सके ।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहो हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धार 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शाक्तयों का अयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, दिल्ली के समक्ष हाजिर हो ।

[फा. सं. 673/283/90—सी. शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 1992

S.O. 1575.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/283/90-CUS. VIII dated 14th September, 1990 under the said sub-section directing that Shri Pramod Kumar Pahwa (Aged 29 yrs.), S/o Shri Suraj Prakash Pahwa, R/o MU-7, Pitampura, Delhi be detained and kept in custody in the Central Prison, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from engaging in transporting smuggled goods otherwise than by engaging in concealing and keeping smuggled goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, New Delhi, within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/283/90-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 1992

का. आ. 1576.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/7/91—सी. शु.-8 तारीख 14-1-91 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री मनमोहन पुत्र श्री प्रेम प्रकाश, 570; सारंग रोड, सोनीपत, हरियाणा को निरूद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ में

अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को छिपाने तथा रखने के अलावा इसे लाने ले जाने में लिप्त रहने से रोका जा सके ।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, दिल्ली के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/7/91—सी. शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 1992

S.O. 1576.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/7/91-CUS. VIII dated 14th January, 1991 under the said sub-section directing that Shri Manmohan, S/o Shri Prem Prakash, H. No. 570, Sarang Road, Sonipat (Haryana) be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from engaging in transporting smuggled goods otherwise than by engaging in concealig and keeping smuggled goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police Delhi within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/7/81-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 1992

का.आ. 1577—:भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/127/89/सी.शु.-8 तारीख 17-3-89 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री मोहम्मद जकारिया शारी 22 अली उमर स्ट्रीट बम्बई-400003 (2) 28 खादिजा स्ट्रीट पो.-भटकल कर्नाटक को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके ।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त बम्बई के समक्ष हाजिर हो ।

[फा. सं. 673/127/89-सी.शु-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 1992

S.O. 1577.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/127/89-CUS. VIII dated 17th March, 1989 under the said sub-section directing that Shri Mohammed Zakaria Sharee 22, Ali Umer Street Bombay-400003 (ii) 28 Khalija Street P.O. Bhatkal, Karnataka, be detained and kept in custody in the Central Prison, with a view to preventing him from Smuggling goods.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay, within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/127/89-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 1992

का.आ. 1578.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/92/90-सी.शु.8 तारीख 18-4-90 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री भरत राय सुपुत्र श्री सूरज राय पता (1) ग्राम गोपालपुर पो.ओ. लालगंज पु० स्टेशन-बलिया, उ०प्र० (2) ग्राम पंचपाड़ा (मौरीग्राम) पो०ओ रधादामी को निरुद्ध कर लिया जाए और प्रेसीडेंसी जेल कलकत्ता में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को लाने ले जाने से रोका जा सके ।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सकें ।

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक पश्चिम बंगाल कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो ।

[फा. सं. 673/92/90-सी.शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 1992

S O 1578.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/92/90-CUS. VIII dated 18th April, 1990 under the said sub-section directing that Shri Bharat Roy, Vill. Gopalpur, P.O. Lalganj, P.S. Balia, District Balia, Uttar Pradesh be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Alipore, Calcutta with a view to preventing him from engaging in transporting smuggled goods.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Calcutta within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/92/90-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2, जून, 1992

का.आ 1579.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से शसक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/514/88-सी.शु. 8, तारीख 12-10-88 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री शंकर गोपाल, ब्लाक 106, दूसरा तल, एच.एस.एल. 426, टोनेल रोड, सिंगापुर-1232 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि सामान की तस्करी करने से रोका जा सके ।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हो ।

[फा.सं. 673/514/88-सी.शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 1992

S.O. 1579.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/514/88-CUS. VIII dated 12th October, 1988 under the said sub-section directing that Shri Shankar Gopal, Block 106, 2nd Floor HSL 426, Townel Road, Singapore-1232 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from smuggling goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No 673/514/88-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का.आ. 1580.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/133/78-सी.शु.-8 तारीख 9-3-88 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री जगजीत सिंह (1) 47, मॉडल टाउन, अमृतसर और (2) ग्राम नौशेरा पनुआ जिला—अमृतसर और (3) ग्राम भोजियन जिला—अमृतसर, पंजाब को निरुद्धकर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी का माल छिपाने अथवा रखने के अलावा तस्करी के माल को लाने, ले जाने तथा इसका धंधा करने तथा माल को तस्करी करने के लिए दुष्प्रेरित करने से रोका जा सके ।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, पंजाब के समक्ष हाजिर हो ।

[फा. सं. 673/133/88-सी.शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 1992

S.O 1580.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974)

issued order F. No. 673/133/88-Cus. VIII dated 9th March, 1988 under the said sub-section directing that Shri Jagjit Singh (i) 47, Model Town, Amritsar, and (ii) Vill. Naushera Panua, District Amritsar, and (iii) Village Bhojian, District Amritsar, Punjab be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from abetting the smuggling of goods, engaging in transporting smuggled goods and dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in concealing and keeping smuggled goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the D.G. of Police, Punjab, within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/133/88-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 1992

का.आ. 1581—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/75/91-सी.शु.-8 तारीख 28-1-91 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री बरनार्ड एन्टोनी फरनांडो पुत्र श्री सुरन्दरम, 136/2, मुन्नाकारा, नोगाम्बो, श्रीलंका को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, मदुरई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि सामान की तस्करी करने से रोका जा सके ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, मद्रास के समक्ष हाजिर हो ।

[फा.सं. 673/75/91-सी. शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 1992

S.O. 1581.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/75/91-Cus. VIII dated 28th January, 1991 under the said sub-section directing that Shri Bernard Antony Fernando, S/o Sundaram, 136/2, Munnakara, Nogambo, Srilanka be detained and kept in custody in the Central Prison, Madurai with a iew to preventing him from smuggling goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the D.G. of Police, Tamil Nadu, Madras within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/75/91-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 1992

का. आ. 1582.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/226/91 सी. शु.-8 तारीख 15-5-91 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री ए. एन्टोनी एलफोन्स पुत्र श्री एन. एस. एन्टोनीमुथु नाडर, 10, लूथरन चर्च स्ट्रीट, काडापेरी, तम्बारम, मद्रास-45 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, मद्रास में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को लाने, ले जाने से रोका जा सके ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, तमिलनाडु, मद्रास के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/226/91-सी. शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 1992

S.O. 1582.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/226/91-Cus. VIII dated 15-5-1991 under the said sub-section direcung that Shri A. Antony Alphonse, S/o N. S. Antonymuthu Nadar, No. 10 Lutheran Church Street, Kadapperi, Tambaram, Madras-45 be detained and kept in custody in the Central Prison, Madras with a view to preventing him from engaging in transporting smuggled goods ;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Government of Tamil Nadu, Madras within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/226/91-CUS.-VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 1992

का. आ. 1583:—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/207/90/सी. शु.-8 तारीख 28-6-1990 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री लाल चन्द वर्मा पुत्र श्री जुगल किशोर वर्मा, 91, मुक्ता राम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता को निरुद्ध कर लिया जाए और प्रेसीडेन्सी जेल, कलकत्ता में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी का माल छिपाने अथवा रखने के अलावा तस्करी के माल को लाने, ले जाने तथा इस धंधे में लिप्त रहने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/207/90-सी. शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 1992

S.O. 1583.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), issued order F. No. 673/207/90-Cus. VIII dated 28-6-1990 under the said sub-section directing that Shri Lal Chand Verma S/o Shri Jugal Kishore Verma, 91, Mukta Ram Babu Street, Calcutta, be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from engaging in transporting smuggled goods and dealing in smuggled otherwise than by engaging in concealing and keeping smuggled goods.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Calcutta within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/207/90-CUS-VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 1992

का. आ. 1584:—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/35/91-सी. शु.-8 तारीख 11-1-1991 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री हरदीप सिंह उर्फ बिल्ला, बाली गैरेज, 58/5, बी, बी. टी. रोड, चिरिया मोड़, कलकत्ता को निरुद्ध कर लिया जाए और प्रेसीडेन्सी जेल, कलकत्ता में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को लाने, ले जाने तथा छिपा कर रखने से रोका जा सके ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/35/91-सी. शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 1992

S.O. 1584.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order under F. No. 673/35/91-Cus. VIII dated 11-1-91 under the said sub-section directing that Shri Hardeep Singh @ Billa, residing at Bali Garrage, 58/5-B, B.T. Road, Chiria More, Calcutta be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from engaging in transporting and concealing smuggled goods ;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, West Bengal, Calcutta within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/35/91-CUS-VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का. आ. 1585:—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/58/90/सी शु.-8 तारीख 6-3-90 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री मोहम्मद कबीर हावलादर पुत्र स्व. श्री ताफिर हावलादर,

ग्राम—बाडुरा, पो.—परचट, थाना और जिला—पिरिचिपुर, बांग्लादेश को निरुद्ध कर लिया जाए और प्रेसीडेंसी जेल, कलकत्ता में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को लाने, ले जाने से रोका जा सके ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/58/90-सी. शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.O. 1585.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/58/90-CUS-VIII dated 6-3-1990 under the said sub-ection directing that Shri Md. Kabir Howlader, S/o Late Tafir Howlader, Vill. Badura, P.O. Perchat, P.S. and Distt. Pirichipur, Bangladesh be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from engaging in transporting smuggled goods ;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, West Bengal Calcutta within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/58/90-CUS-VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का.आ. 1586.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/50/92-सी. शु.-8 तारीख 26-2-92 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री तान थंगा एलियास ताना पुत्र श्री काफनूना, ग्राम—इलेक्ट्रिक वेंग, पो. – रिपब्लिक वेंग, थाना – ऊपरी बाजार, आइजोल को निरुद्ध कर लिया जाए और प्रेसीडेंसी जेल, अलीपुर, कलकत्ता में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को लाने, ले जाने तथा छिपाने एवं रखने जैसी गतिविधियों में लिप्त रहने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस निरीक्षक निदेशक, मिजोरम, आइजोल के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/50/92 – सी. शु.–8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.O. 1586.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/50/92-CUS-VIII dated 26-2-1992 under the said sub-section directing that Shri Tan Thanga alias Tana, S/o Shri Kaphnuna, Vill. Electric Veng, P.O. Republic Veng, Police Station Upper Bazar, Aizwal be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Alipore, Calcutta with a view to preventing him from engaging in transporting and concealing as smuggled goods.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Inspector General of Police, Mizoram, Aizwal within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/50/92-CUS-VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का.आ. 1587.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/158/88/सी.शु.–8 तारीख 3-3-88 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री पुतुल शेख, पो. – डाफरपुर, थाना – रघुनाथगंज, जिला– मुर्शिदाबाद, पश्चिमी बंगाल को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, दमदम में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को, लाने ले जाने तथा छिपाने जैसी गतिविधियों में लिप्त रहने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/158/88—सी. शु.—8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.O. 1507.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F No. 673/158/88-CUS-VIII dated 3-3-1988 under the said sub-section directing that Shri Putul Sheikh, P.O. Dafarpur, P.S. Raghunathganj, District Murshidabad be detained and kept in custody in the Central Prison, Dum Dum, Calcutta with a view to preventing him from engaging in transporting and concealing of smuggled goods;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the D.G. of Police, Calcutta within 7 days of the population of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/158/88-CUS-VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का. आ. 1588.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/56/90—सी. शु.—8 दिनांक 28-2-1990 को यह निदेश जारी किया था कि श्री मनजीत सिंह, सुपुत्र श्री गोकल सिंह, निवासी आर. जेड—110, इंदिरा पार्क उत्तम नगर, नई दिल्ली को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, तिहाड़, में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, दिल्ली के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/56/90—सी. शु.—8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.O. 1588.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/56/90-CUS-VIII dated 28-2-1990 under the said sub-section directing that Shri Manjit Singh S/o Shri Gokal Singh, R/o RZ-110, Indira Park, Uttam Nagar, New Delhi be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi, within 7 days of the publication of this order is the Official Gazette.

[F. No. 673/56/90-CUS-VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का. आ. 1589.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/41/91—सी. शु.—8 तारीख 5-2-91 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री मोहम्मद अख्तर खान, 4-ए, सेंट जार्ज गेट रोड, कलकत्ता—700022 को निरुद्ध कर लिया जाए और प्रेसीडेंसी जेल, कलकत्ता में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को लाने, ले जाने से रोका जा सके ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/41/91—सी. शु.—8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.O. 1589.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 4 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/41/91-CUS-VIII dated 5-2-1991 under the said sub-section directing that Shri Md. Akhtar Khan, A, St. George Gate Road Calcutta-700022, be detained

and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from engaging in transporting smuggled goods.

2 Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Government of Tamil Nadu, Madras within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/41/91-CUS-VIII]
ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का. आ. 1590—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन आदेश फा. सं. 673/90/92—सी. शु. – 8 दिनांक 25-3-92 को यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री मुस्तका अहमद डोसा (1) 53/57, ह्वाइट हाउस, तीसरा/पांचवा तल, नारायण धुरू स्ट्रीट, बम्बई – 3 (2) भाग ई. रहमान नं. 604, छठा तल, राजपूत विला, बम्बई – 11 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हों ।

[फा. सं. 673/90/92 – सी. शु. – 8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.O. 1590.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-ection (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/90/92-CUS-VIII dated 25-3-1992 under the said sub-section directing that Shri Mustafa Ahamed Dossa (i) 53/57, White House, 3rd/5th Floor, Narayan Dhuru Street, Bombay-3, (ii) Bhag. E. Rehmat No. 604, 6th Floor, Rajput Villa, Maharaj Shetty Marg, Agripada, Bombay-11 be detained and kept in custody in the Central Prison, with a view to preventing him from smuggling goods ;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Government of Tamil Nadu, Madras within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/90/92-CUS-VIII]
ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का. आ. 1591.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/91/90—सी. शु. – 8 तारीख 18-4-90 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री रबीउल शेख पुत्र श्री नरीमुद्दीन शेख, ग्राम तथा पो – अहिरों, थाना – सुती, जिला – मुर्शिदाबाद, पश्चिमी बंगाल को निरुद्ध कर लिया जाए और प्रेसीडेंसी जेल, कलकत्ता में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को लाने, ले जाने से रोका जा सके ।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए । यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो ।

[फा. स. 673/91/90 – सी शु – 8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.O. 1591.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/91/90-CUS-VIII dated 18-4-1990 under the said sub-section that Shri Rabiul Seikh, son of Narimuddin Seikh, Vill. and P.O. Ahiron, P.S. Suti, District Murshidabad, West Bengal be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from engaging in transporting smuggled goods ;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Police, West Bengal, within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/91/90-CUS-VIII]
ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का. आ. 1592.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1)

के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त धारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/387/90 – सी. शु. – 8 दिनांक 26-11-90 को यह निदेश जारी किया था कि श्री वी. एम. अब्दुल करीम पुत्र श्री स्वर्गीय मोहम्मद थाहैम, सं. 7-सी, गान्धी नगर, कुम्बाकोनम, (2) नं. 2-57, वैस्ट स्ट्रीट, अथीकाडी, थंजावर जिला को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, मद्रास में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, मद्रास, तमिलनाडु के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/387/90 – सी. शु – 8]

रूपचन्द, अवरसचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.O. 1592.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/387/90-CUS-VIII dated 26-11-1990 under the said sub-section directing that Sri V. M. Abdul Kareem S/o late Mohamed Thaim, No. 7-C, Ghandhi Nagar, Kumbakonam (ii) No. 2-57, West Street, Athikadai Thanjavur, Distt. be detained and kept in custody in the Central Prison Madras with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange ;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Tamil Nadu, Madras within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/387/90-CUS-VIII]
ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का. आ. 1593 —भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से शक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/74/91–सी. शु. – 8 तारीख 28-1-91 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री जे. ए. न्यूटन पुत्र श्री एन्टोनी अप्पु, थेप्पम, वाडापाला, थाडूवावा पो., जिला – पुटलाम, श्रीलंका को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, मदुरई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि सामान की तस्करी करने से रोका जा सके ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु, मद्रास, के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/74/91 – सी. शु. – 8]

रूपचन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.O. 1593.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/74/91-CUS-VIII dated 28-1-1991 under the said sub-section directing that Shri J. A. Newton, S/o Antony Appu, Thappam Vadapala, Thaduvava Post, Putlam District, Srilanka be detained and kept in custody in the Central Prison, Madurai with a view to preventing him from smuggling goods ;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Madras, Tamil Nadu, within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/74/91-CUS-VIII]
ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का. आ. 1594 :– भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त धारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/229/91 – सी. शु. – 8 तारीख 6-6-91 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री एम. एम. आर. पालोल्की, जेरमन नेशनल, पासपोर्ट सं. एच – 5055373 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि सामान की तस्करी करने से रोका जा सके ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, दिल्ली के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/229/91 – सी. शु. – 8]
रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.O. 1594.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/229/91-CUS-VIII dated 6-6-1991 under the said sub-section directing that Shri S. M. R. Pawlowski, German National Holder of Passport No. H-5055378 be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from smuggling goods ;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/229/91-CUS-VIII]
ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का. आ. 1595 :– भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप सशक्त किया गया है, उक्त धारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/322/90 – सी. शु. – 8 दिनांक 26-9-1990 को यह निदेश जारी किया था कि श्री इलियास मोहम्मद खान, प्रो. यूनियन ट्रांसपोर्ट कम्पनी, 5-3-1001, केसरी बिल्डिंग, शंकर बाग, हैदराबाद को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, हैदराबाद में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, हैदराबाद के समक्ष हाजिर हों।

[फा. सं. 673/322/90 – सी. शु. – 8]
रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.O. 1595.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/322/90-CUS-VIII dated 26-9-1990 under the said sub-section directing that Shri Allyas Mohd. Khan, Prop. M/s. Union Transport Co., 5-3-1001, Kesari Bldg., Shankar Bagh, Hyderabad be detained and kept in custody in the Central Prison, Hyderabad with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange ;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Hyderabad within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/322/90-CUS-VIII]
ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का. आ. 1596 :– भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/52/92 – सी. शु. – 8 तारीख 26-2-92 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री जैनिथ कुंगा पुत्र श्री जाफर हामुंगा, रामथर, जिला– आइजोल, मिजोरम को निरुद्ध कर लिया जाए और प्रेसीडेंसी जेल, कलकत्ता में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को लाने, ले जाने तथा छिपाने एवं रखने के कार्य में लिप्त रहने से रोका जा सके ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के

भीतर पुलिस निरीक्षक, मिजोरम, आइजाल के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/52/92 – सी. शु. – 8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.O. 1596.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under order F. No. 673/52/92-CUS-VIII dated 26-2-92 under the said sub-section directing that Shri Zaneith Kunga, S/o Shri Za. Hamunga, Ramthar, District Aizwal, Mizoram be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from engaging in transporting and concealing and keeping smuggled goods;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Inspector General of Police, Mizoram, Aizwal within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/52/92-CUS-VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 जून, 1992

का.आ. 1597.— भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/179/91–सी.शु.–8 तारीख 22-4-91 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्रीमती मरियायी @ सावियथिरी पत्नी श्री एस. पेरूमल, 116 (प्रथम तल), पेरियार नगर, मम्बाला सलाई, त्रिची-5 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, मद्रास में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, मद्रास के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 673/179/91-सी.शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th June, 1992

S.O. 1597.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under order F. No. 673/179/91-CUS. VIII dated 22-4-91 under the said sub-section directing that Smt. Mariyayee @Saviththiri, w/o Shri S. Perumal, No. 116, (First Floor), Periyar Nagar, Mambala Salai, Trichy-5 be detained and kept in custody in the Central Prison, Madras with a view to preventing her from smuggling goods;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing herself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Tamil Nadu, Madras within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/179/91-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 जून, 1992

का.आ. 1598.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन आदेश फा. सं. 673/780-सी.शु.-8 दिनांक 15-12-89 को यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री हाजी रहमान, ग्राम–बीट क्यामारी, करांची, पाकिस्तान को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 673/780/89-सी.शु.-VIII]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th June, 1992

S.O. 1598.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under order F. No. 673/780/89-CUS. VIII dated 15-12-89 under the said sub-section directing that Shri Haji Rahman, Village Beet Kyamari, Karachi, Pakistan be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from smuggling goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/780/89-CUS.VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 जून, 1992

का.आ. 1599.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/64/90/सी.शु.-8 तारीख 2-3-1990 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री दिलीप कुमार सिंह उर्फ दिलीप सिंह सुपुत्र श्री भीगू प्रसाद सिंह, ग्राम—बासदेवपुर, मानसतला, पो. एवं थाना—आरामबाग, जिला—हुगली, पश्चिम बंगाल, को निरुद्ध कर लिया जाए और प्रेसीडेंसी जेल, कलकत्ता में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/64/90—सी.शु.—8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th June, 1992

S.O. 1599.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/64/90-CUS. VIII dated 2-3-90 under the said sub-section directing that Shri Dilip Kumar Singh @Dilip Singh S/o Shri Bhigu Prasad Singh Vill. Basdevpur, Manasatala, P.O.&P.S. Arambagh, Dist. Hooghly, West Bengal be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Alipore, Calcutta with a view to preventing him from engaging in transport smuggled goods ;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, West Bengal, Calcutta within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/64/90-CUS.VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 जून, 1992

का. आ. 1600 :— भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/14/92—सी. शु. — 8 तारीख 9-1-1992 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री हीरा सिंह पुत्र श्री ठाकुर सिंह, ग्राम — अवान लाखा सिंह, थाना — लोपोके, जिला — अमृतसर, पंजाब को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, अमृतसर में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे भविष्य में तस्करी का माल लाने, ले जाने तथा रखने के अलावा तस्करी का माल छिपाने तथा रखने जैसी गतिविधियों में लिप्त रहने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, पंजाब, चण्डीगढ़, के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/14/92 — सी. शु. — 8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th June, 1992

S.O. 1600.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/14/92 CUS. VIII dated 9-1-92 under the said sub-section directing that Shri Hira Singh, son of Thakur Singh, resident of Awan Lakha Singh, Police Station Lapoke, District Amritsar be detained and kept in custody in the Central Jail, Amritsar with a view to preventing him from engaging in concealing smuggled goods and dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting and keeping smuggled goods in future;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the D.G. of Police, Punjab, Chandigarh within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/14/92-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 जून, 1992

का. आ. 1601 :– भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/706/89 – सी. शु. – 8 तारीख 12-12-1989 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री मोहम्मद इकबाल, 2/डी, इस्माइल ओस्टागर लेन, कलकत्ता – 23 को निरुद्ध कर लिया जाए और प्रेसीडेंसी जेल, कलकत्ता में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी का माल रखने अथवा छिपाने में लिप्त रहने के अलावा तस्करी का माल लाने, ले जाने तथा धंधा करने में लिप्त रहने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देता है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/706/89 – सी. शु. – 8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th June, 1992

S.O. 1601.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/706/89-CUS. VIII dated 12-12-1989 under the said sub-section directing that Shri Md. Iqbal, 2/D, Ismail Ostagar Lane, Calcutta-23 be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from engaging in transporting smuggled goods and dealing in smuggled goods otherwise than by engagaing in concealing or keeping smuggled goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Calcutta within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/706/89-CUS.VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 जून, 1992

का.आ. 1602 भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673 13/92–सी.शु.-8 तारीख 9-1-1992 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री जागीर सिंह उर्फ डोढ़ी पुत्र श्री ठाकुर सिंह, ग्राम–अवान लाखा सिंह, थाना—लोपोके, जिला-अमृतसर, पंजाब को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, अमृतसर में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे भविष्य में तस्करी का माल लाने, ले जाने तथा रखने के अलावा तस्करी का माल छिपाने तथा रखने जैसी गतिविधियों में लिप्त रहने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, पंजाब, चण्डीगढ़ के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 673/13/92–सी.शु.-8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th June, 1992

S.O. 1602.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673|13|92-CUS. VIII dated 9-1-1992 under the said sub-section directing that Shri Jagir Singh @ Dodhi, son of Thakur Singh, R/o. Village-Awan Lakha Singh, Police Station Lopoke, District-Amritsar, Punjab be detained and kept in custody in the Central Jail, Amritsar with a view to preventing him from engaging in concealing smuggled goods and dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting and keeping smuggled goods in future;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the D.G. of Police, Punjab Chandigarh within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/13/92-CUS.VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का.आ. 1603 .—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/436/92–सी.शु.-8 तारीख 31-3-92

यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री सुनील कुमार कामरा, जी.एच.-10/66-ए, पश्चिम विहार, नई दिल्ली को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे भविष्य में तस्करी का माल रखने और तस्करी के लिए उत्प्रेरित करने से रोका जा सके ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 673/436/92-सी.शु.-8]

जे.एल. साहनी, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.O. 1603.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/436/91-CUS. VIII dated 31-3-1992 under the said sub-section directing that Shri Sunil Kumar, Kamra, GH-10/66A, Pachim Vihar, New Delhi be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from abetting the smuggling of goods and engaging in keeping smuggled goods in future;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, New Delhi within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/436/91-CUS.VIII]

J. L. SAWHNEY, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का.आ 1604—. भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/79/89—सी.शु.-8 तारीख 27-2-89 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री कान्दम कुलावन मोहम्मद, टी.के. हाउस, पो.—ओलावट्टूर, कोन्डोटी, जिला-मालापुरम, केरल को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, केरल, त्रिवेन्द्रम के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 673/79/89-सी.शु.-8]

जे.एल. साहनी, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.O. 1604.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/79/89-CUS. VIII dated 27-2-1989 under the said sub-section directing that Shri Kandam Kulavan Mohammad, T.K. House, P.O. Olavattoor, Kondotty, Malappuram Distt., Kerala be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from smuggling goods;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Kerala Trivandrum within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/79/89-CUS.VIII]

J. L. SAWHNEY, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का.आ. 1605 .— भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/25/87—सी.शु.-8 तारीख 23-3-87 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री दाऊद हसन शेख इब्राहिम, माक्बा, बिल्डिंग, फ्लैट नं.-5, 94 टेम्कार स्ट्रीट, बम्बई-400 008 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, अकोला में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, महाराष्ट्र, बम्बई के समक्ष हाजिर हो ।

[फा.सं. 673/25/87-सी.शु.-8]

जे.एल. साहनी, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.O. 1605.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Sumggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/25/87-CUS. VIII dated 23-3-1987 under the said sub-section directing that Shri Dawood Hassan Shaikh Ibrahim, Maqba Building flat No. 5, 94 Temkar Street, Bombay-400008, be detained and kept in custody in the Central Prison Akola with a view to preventing him from smuggling goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Maharashtra, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/25/87-CUS.VIII]

J. L. SAWHNEY, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का.आ. 1606 —. भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/693/89—सी.शु.-8 तारीख 7-12-89 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री अब्बास हाजी मामद सिंधी, जानाबाद, मेवाशा रोड, थाना बाक्रा चिन्दी, करांची, पाकिस्तान को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, गुजरात, गांधीनगर के समक्ष हाजिर हो ।

[फा.सं. 673/693/89—सी.शु.-8]

जे.एल. साहनी, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.O. 1606.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/693/89-CUS. VIII dated 7-12-1989 under the said sub-section directing that Shri Abbas Haji Mamad Sindhi, Janabad, Mevesha Road, Thana Bakra Chindi, Karachi, Pakistan, be detained and kept in custody in the Central Prison, with a view to preventing him from smuggling goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Gujarat, Gandhinagar within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/693/89-CUS.VIII]

J. L. SAWHNEY, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का.आ. 1607 —. भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम,, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/302/91—सी.शु.-8 तारीख 3-7-91 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री विजय कुमार करेल उर्फ सोनी, 85/3/1, अध्यानाथ साहा रोड, कलकत्ता-48 को निरुद्ध कर लिया जाए और प्रेसीडेंसी जेल, कलकत्ता की अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को छिपाने, रखने अथवा लाने, ले जाने में लिप्त रहने के अलावा तस्करी का धंधा करने से रोका जा सके ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त

व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 673/302/91—सी.शु.-8]

जे.एल. साहनी, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.O. 1607.—Whereas the Joint Secretary of the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/302/91-CUS. VIII dated 3-7-1991 under the said sub-section directing that Shri Vijay Kumar Karel @ Soni, 85/3/1, Adhyanath Saha Road, Calcutta-48, be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting or keeping or concealing smuggled goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police West Bengal, Calcutta within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/302/91-CUS.VIII]

J. L. SAWHNEY, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का.आ. 1608.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/637/89—सी.शु.-8 तारीख 7-11-89 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री जतिन्दर पाल सिंह पुत्र श्री महाबीर सिंह, ए-34, आशा पार्क, फतेह नगर के पीछे, नई दिल्ली को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ की अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (खंड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 673/637/89—सीशु.-8]

जे.एल. साहनी, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.O. 1608.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/637/89-CUS. VIII dated 7-11-1989 under the said sub-section directing that Shri Jatinder Pal Singh, S/o Shri Mahabir Singh, R/o A-34, Asha Park, behind Fateh Nagar, New Delhi, be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from smuggling goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, New Delhi within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/637/89-CUS.VIII]

J. L. SAWHNEY, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का.आ. 1609 :— भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/71/92—सी.शु.-8 तारीख 25-3-1992 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री अनवर जुमा मलेक (दोदाई) उर्फ अनु सागर, सागर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, शीतला चौक, पोरबन्दर को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, साबरमती में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे भविष्य में तस्करी करने के लिए उत्प्रेरित करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे युक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके।

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7

दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, गुजरात, गांधीनगर के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 673/71/92—सी.शु.-8]

जे.एल. साहनी, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.O. 1609.—Whereas the Joint Secretary of the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Sumggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/71/92-CUS. VIII dated 20-3-1992 under the said sub-section directing that Shri Anwar Juma Mulek (Dodai) @ Anu Sagar, Sagar transport Co., Shitla Chowk, Porbandar, be detained and kept in custody in the Central Prison, Sabarmati, Ahmedabad with a view to preventing him from abetting the smuggling of goods in future;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Gujarat, Gandhinagar within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/71/92-CUS.VIII]

J. L. SAWHNEY, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का. आ. 1610 :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/661/89—सी. शु.-8 तारीख 16-11-89 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री अब्दुला पुत्र श्री मोहम्मद, ई-1-6/6 कोपरा पार्क कालोनी, मालिर, करांची—37, पाकिस्तान को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश की शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, महाराष्ट्र, बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/661/89-सी. शु. -8]

जे. एल. साहनी, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.O. 1610.—Whereas the Joint Secretary of the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Sumggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/661/89-CUS. VIII dated 16-11-1989 under the said sub-section directing that Shri Abdulla S/o Mohammed, E-1-6/6 Kopra Park Colony, Malir, Karachi-37, Pakistan, be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from smuggling goods.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Maharashtra, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/661/89-CUS.VIII]

J. L. SAWHNEY, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का. आ. 1611 :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/607/89—सी. शु.-8 तारीख 24-10-89 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि मिस. एलिजाबेथ, जर्मन पासपोर्ट नं. एफ 6508084, निवासी ग्रैफेलफाईंड, पश्चिमी जर्मनी को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/607/89-सी. शु. -8]

जे. एल. साहनी, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.O. 1611.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and

Prevention of Sumggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/607/89-CUS. VIII dated 24-10-1989 under the said sub-section directing that Ms. Elizabeth, German Passport No. F6508084, R/o Grafelfind, West Germany, be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing her from smuggling goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, New Delhi within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/607/89-CUS. VIII]

J. L. SAWHNEY, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 26 मई, 1992

का. आ. 1612 :—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) में दिनांक 2 जुलाई, 1988 को भारत के राजपत्र के भाग II की खण्ड 3 के उपखण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 8 जून, 1988 की अधिसूचना सं. का. आ. 2010 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले किये गए कार्यों और करने के लिए छोड़े गए कार्यों को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार, एतद्-द्वारा निम्नलिखित सारणी के कालम (1) में उल्लिखित उन अधिकारियों को नियुक्त करती है, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के स्तर के समकक्ष अधिकारी होंगे और उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी होंगे, जो उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उसके अधीन उक्त सारणी के कालम (2) में समनुरूप प्रविष्टियों में उल्लिखित सरकारी स्थानों के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत सम्पदा अधिकारियों को सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करेंगे :—

सारणी

अधिकारी का पद	सरकारी स्थानों की श्रेणियां और अधिकार क्षेत्र की सीमा
1	2
1. सहायक महाप्रबन्धक (भा.) न्यू बैंक ग्राफ इंडिया, प्रधान कार्यालय 1, टाल्सटाय मार्ग, दिल्ली	न्यू बैंक ग्रांफ इंडिया की अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिए गए तथा राष्ट्रीय राजधानी संघशासित क्षेत्र दिल्ली में अवस्थित स्थान।
2. क्षेत्रीय प्रबंधक, न्यू बैंक ग्राफ इंडिया, 71-एफ, मेकर्स टावर, कफ परेड, बम्बई	न्यू बैंक ग्राफ इंडिया की अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिए गए तथा महाराष्ट्र (महानगर शहर बम्बई सहित) गुजरात और गोवा और संघ शासित क्षेत्र दमन और दीव राज्यों में अवस्थित स्थान।
3. सहायक महाप्रबंधक, न्यू बैंक ग्राफ इंडिया, 125, पार्क स्ट्रीट, तीसरा तल, ए. जी. टावर्स, कलकत्ता।	न्यू बैंक ग्राफ इंडिया की अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिए गए अवस्थित स्थान।
4. सहायक महाप्रबंधक, न्यू बैंक ग्राफ इंडिया, एस सी ओ 88-89, सैक्टर-17-सी, चण्डीगढ़	न्यू बैंक ग्राफ इंडिया की अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिए गए और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के राज्यों में अवस्थित स्थान।
5. क्षेत्रीय प्रबंधक, न्यू बैंक ग्रांफ इंडिया, सी-46, सरोजिनी मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर	न्यू बैंक ग्राफ इंडिया की अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी और से पट्टे पर लिए गए, तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में अवस्थित स्थान।
6. क्षेत्रीय प्रबंधक, न्यू बैंक ग्राफ इंडिया, सुदर्शन बिल्डिंग, तीसरा तल, 14 व्हाइट्स रोड, मद्रास	न्यू बैंक ग्राफ इंडिया की अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गए और केरल, कर्नाटक (महानगरीय शहर बंगलौर सहित) तमिलनाडु (महानगरीय शहर मद्रास सहित) और आन्ध्र प्रदेश के राज्यों में अवस्थित स्थान।

[सं. 15/2/92—बी. ओ.—III]

के. के. मंगल, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)

New Delhi, the 26th May, 1992

S.O. 1612.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), and in supersession of the notification of the Department of Economic Affairs (Banking Division) number S.O. 2010 dated the 8th June, 1988, published in the Gazette of India, Part II section 3, sub-section (ii) dated the 2nd July, 1988, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being officers equivalent to the rank of gazetted officers of Government to be estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the estate officers by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table :

TABLE

Designation of the Officer	Categories of Pubic Premises and Local limits of jurisdiction
(1)	(2)
1. Asstt. Gen. Manager, (Services) New Bak of India, Head Office, 1, Tolstoy Marg, NewDelhi.	Premises belonging to or taken on lease by or on behalf of New Bank of India and situated in the Natioaal Capital Territory of Delhi.
2. Regioal Manager, New Bank of India, 71-F, Maker Tower Cuffee Parade, Bombay.	Premises belonging to or taken on lease by or on behalf of New Bank of India andsituated in the Statesof Maharashtra (including Metropolitan City of Bombay), Gujarat and Goa and Union Territory of Daman & Diu.
3. Asstt. Gen .Manager, New Bak of India, 125/1, Park Street, 3rd Floor, A.G. Towrs, Calcutta.	Premises belonging to or taken on lease by or of behalf of New Bank of India ad situated in the States of West Bengal (including Metropolitan City of Calcutta), Assam, Bihar ad Orissa.
4. Asstt. Gen. Manager, New Bank of India, SCO 88-89, Sector 17-C, Chandigarh.	Premises belonging to or taken on lease by or on behalf of New Bank of India and situated in the states of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana and Jammu and Kashmir and the Union Territory of Chandigarh.
5. Regional Manager, New Bank of India, C-46, Sarojini Marg, C-Scheme, Jaipur.	Premises belonging to or taken on lease by or on behalf of New Bank of India and situated in the States of Rajastham, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.
6. Regional Manager, New Bank of India, Sudharsha Building., 3rd Floor, 14, Whites Road, Madras.	Premises belonging to or taken on lease by or on behalf of New Bank of India ad situate in the States of Kerala, Karnataka (including Metropolitan City of Bagalore), Tamil Nadu (including the Metropolitan City of Madras) and Andhra Pradesh.

[No 15/2/92-B.O.III]

K.K. MANGAL, Under Secy.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 27 मई, 1992

का. आ. 1613 :—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा, घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा II की उपधारा (1) के प्रावधान, मप्पायूर, को-आपरेटिव बैंक लि., मप्पायूर, केरल पर इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तरीख से 30 दिसम्बर, 1992 तक की अवधि के लिए लागू नहीं होंगे।

[एफ सं. 10 (2)/91— वित्तास]

तेजिन्दर सिंह लस्चर, संयुक्त निदेशक

(Banking Division)

New Delhi, the 27th May, 1992

S.O. 1613.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Sub-Section (1) of Section 11 of the said Act shall not apply to the Meppayur Co-operative Bank Ltd., Meppayur, Kerala for the period from the date of publication of this notification in the Gazette of India upto 30 December, 1992.

[F. No. 10(2)/91-Dev]

TEJINDER SINGH LASCHAR, Jt Director

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 जून, 1992

का.आ. 1614 :—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1964 के नियम 3 के साथ पठित, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 1903 का 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना सं. का.आ. 1127 तारीख 9 अप्रैल, 199- में रूपान्तर करते हुए श्री वी. एस. वेंकटारमन, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय को डा. जी. सुन्दरम के स्थान पर निर्यात निरीक्षण परिषद का एतद्द्वारा तुरन्त अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[फा. सं. 3/90/85-ई आई एण्ड ई पी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 3rd June, 1992

S.O. 1614.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), read with Rule 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government in modification of Notification S.O. No. 1127 dated 9 April, 1992 hereby appoints Shri V. S. Venkataraman, Additional Secretary, Ministry of Commerce as Chairman of the Export Inspection Council with immediate effect, vice Dr. G. Sundaram.

[F. No. 3/90/85-EI&EP]

KUMARI SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 4 जून 1992

का. आ. 1615—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मैसर्स नेशनल कार्बन कम्पनी (केम्परडाउन वर्क्स) (डिवीजन आफ मैसर्स यूनियन कार्बाईड इंडिया लिमिटेड) 5 रूस्तम जी परसी रोड, कलकत्ता में विनिर्मित शुष्क बैटरियों का निर्यात से पूर्व नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार निरीक्षण करने के लिए मैसर्स नेशनल कार्बन कम्पनी (केम्परडाउन वर्क्स) (डिवीजन आफ यूनियन कार्बाईड इंडिया लिमिटेड) को जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, 1, मिणलटत स्ट्रीट कलकत्ता 700071 में है, जो का. आ. 527 तारीख 18 मार्च, 1989 में अधिसूचित शर्तों के अधीन रहते हुए 18 मार्च, 1992 से तीन और वर्ष की अवधि के लिए अभिकरण के रूप में मान्यता देती है।

अनुसूची

प्रकार	पदनाम	विनिर्देश
1	3	4
915	आर-6	आई एस: 8144 -1976
935	आर-14	आई एस: 203 - 1984
950	आर-20	आई एस: 203 - 1984
950 नीला	आर-20	आई एस : 8144 -1976
935 नीला	आर-14	आई एस : 8144-1976
1035	आर-14	आई एस -2576 -1975
1050	आर-20	आई एस : 2576-1975
नं. 6	आर-20	आई एस : 586 --1976
नटैक्स एन-259	आर-40	86-2 आई ई सी -आर 20ए
नटैक्स एन 5301	आर-14	86-2 आई-ई सी आर 14 एस
नटैक्स एन -519	आर-6	96-2 आई ई सी आर-6 एस
टैस्टरोन यूएम -1 ए	आर -20	86-2 आई ई सी आर-20एस
टैस्टरोन यूएएम-2ए	आर -14	86-2 आई ई सी -आर 14एस
टैस्टरोन यूएम-3ए	आर-6	86-2 आई ई सी आर -6एस
स्टार यू एम -1ए	आर - 20	86-2 आई ई सी-आर-20 एस
स्टार यूएम-2ए	आर-14	86-2 आई ईसी आर-14 एस
स्टार यू. एम-3 ए	आर-6	86-2 आई ई सी -आर 6 एस
कोयडो यू एम-1ए	आर - 20	86-2 आई ई सी आर - 20 एस
कोयडो यू एम -2ए	आर-14	86-2 आई ई सी -आर14 एस
कोयडो यू एम - 3ए	आर- 6	86 - आई ई सी -आर 6 एस
नटैक्स एन - 059	आर - 20	आई एस 203 - 1984
नटैक्स एन 539	आर - 14	आई एस : 203-1984
ओलम्पिक	आर- 20	आई एस 203 - 1984
ओलम्पिक	आर - 14	आई एस : 203 -1904
ओलम्पिक	आर - 20	आई एस : 8144 -1976
ओलम्पिक	आर -14	आई एस : 8144 -1976
ओलम्पिक	आर - 20	आई एस : 2576 - 1975
ओलम्पिक	आर -14	आई एस : 2576 - 1975
ओलम्पिक	आर- 6	आई एस : 8144 - 1976

[फाईल सं. 5/1/89-आई एण्ड ई पी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 4th June, 1992

S.O.1615.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of three years with effect from 18th March, 1992, M/s. National Carbon Company (Comperdown Works)—divison of M/s. Union Carbide India Ltd., having their registered office at 1, Middleton Street, Calcutia-700071 as the Agency for inspection of Dry Batteries, as per schedule appended below manufactured at M/s. National Carbon Company (Comperdown Works)—division of M/s. Union Carbide India Ltd., 5, Rustamjee Parse Road, Calcutta-700002, prior to export, subject to the conditions notified vide S.O. 527 dated 18th March, 1989.

SCHEDULE

Type	Designation	Specification
1	2	3
915	R-6	IS : 8144—1976
935	R-14	IS : 203—1984
950	R-20	IS : 203—1984
950 Blue	R-20	IS : 8144—1976
935 Blue	R-14	IS : 8144—1976
1035	R-14	IS : 2576—1975
1050	R-20	IS : 2576—1975
No-6	R-40	IS : 586—1976
NATEX N-259	R-20	86-2-IEC-R-20 S
NATEX N-5301	R-14	86-2-IEC-R-14 S
NATEX N-519	R-6	86-2-IEC-R-6 S
TESTRON UM-1A	R-20	86-2-IEC-R-20 S

1	2	3
TESTRON UM-2A	R-14	86-2-IEC-R-14 S
TESTRON UM-3A	R-6	86-2-IEC-R-6 S
STAR UM 1A	R-20	86-2-IEC-R-20 S
STAR UM 2A	R-14	86-2-IEC-R-14 S
STAR UM 3A	R-6	86-2-IEC-R-6 S
OYDO UM 1 A	R-20	86-2-IEC-R-20 S
COYDO UM 2A	R-14	86-2-IEC-R-14 S
COYDO UM 3 A	R-6	86-2-IEC-R-6 S
NATEX N-059	R-20	IS : 203 1984
NATEX N-539	R-14	IS : 203 1984
OLYMPIC	R-20	IS : 203 1984
OLYMPIC	R-14	IS : 203 1984
OLYMPIC	R-20	IS : 8144 1976
OLYMPIC	R-14	IS : 8144 1976
OLYMPIC	R-20	IS : 2576 1975
OLYMPIC	R-14	IS : 2576 1975
OLYMPIC	R-6	IS : 8144 1976

[F. No. 5/1/89-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 मई, 1992

का. आ. 1616:—केन्द्रीय सरकार, लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 के खंड 17 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पूर्व इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1567/आ./व./लोहा और इस्पात तारीख 7 अप्रैल, 1971 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त सूचना में —

(1) उपखंड (1) में :

(क) "दो समितियों" शब्दों के स्थान पर "समिति" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "और इस्पात प्राथमिकता समिति" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(2) खंड (2) में :

(क) उपखंड (क) में "कृत्य" शीर्षक के अधीन, पैरा (1) में "रक्षा" शब्द के पश्चात् "रेलमार्ग" शब्द अन्त : स्थापित किए जाएंगे;

(ख) इस्पात प्राथमिकता समिति के गठन और कृत्यों से संबंधित उपखंड (ख) का लोप किया जाएगा।

परन्तु यह कि उपखंड (ख) के ऐसे लोप से उक्त खंड के अधीन पूर्व में की गई कोई कार्रवाई या किए गए कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं. एस सी/1/6/91/डी-III]

ए. के. बसु, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :—मुख्य आदेश दिनांक 7 अप्रैल, 1971 के का. आ. 1567 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया था और बाद में निम्नलिखित का. आ. के अन्तर्गत संशोधन किए गए थे :—

1. सं. का. आ. 104 दिनांक 22-2-1973
2. सं. का. आ. 123 दिनांक 3-3-1975
3. सं. का. आ. 721 दिनांक 20-12-1975
4. सं. का. आ. 744 दिनांक 27-12-1978
5. सं. का. आ. 571 दिनांक 8-10-1979
6. सं. का. आ. 734 दिनांक 9-2-1990
7. सं. का. आ. 1211 दिनांक 4-4-1991
8. सं. का. आ. 44-ई दिनांक 16-1-1992

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 18th May, 1992

S.O. 1616.—In exercise of the powers conferred by cluse 17B of the Iron and Steel (Control) Order, 1956, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Heavy Engineering No. S.O. 1567/ESS/COMM/IRON and STEEL dated the 7th April, 1971, namely:—

In the said notification—

(1) In clause (1) :

(a) for the words "two committees", the words Committee" shall be substituted;

(b) The words 'and the Steel Priority Committee" shall be omitted;

(2) In clause (2) :

(a) in sub clause (a) under the heading "Functions", in paragraph (1), after the word "Defence" the word 'Railways" shall be inserted;

(b) The words "and the Steel Priority Committee" shall tions of the Steel Priority Committee shall be omitted.

Provided that such omission of sub-clause (b) shall not affect any action taken or things done under the said sub-clause previously.

[No. SC|1|6|91-D.III]

A. K. BASU, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal order was notified vide No .S.O. 1567 dated the 7th April, 1971 and subsequently amended vide—

1. No. SO 104 dated 22-02-1973
2. No. SO 123 dated 03-03-1975
3. No. SO 721 dated 20-12-1975
4. No. SO 744 dated 27-12-1978
5. No. SO 571 dated 08-10-1979
6. No. SO 734 dated 09-02-1990
7. No. SO 1211 dated 04-04-1991
8. No. SO 44-E dated 16-1-1992

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) के मामले में

राष्ट्रीय बाल कोष, नई दिल्ली के मामले में

नई दिल्ली, 26 मई, 1992

का. आ. 1617:—राष्ट्रीय बाल कोष, नई दिल्ली के प्रबन्ध बोर्ड द्वारा किए आवेदन पर और उनकी सहमति से पूर्त विन्यास अधिनियम 1890 (1890 का 6) के खण्ड 10 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आदेश देती है कि नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार रु. 28,80,460/ (अठाईस लाख अस्सी हजार चार सौ साठ मात्र) (तीस लाख की छूट कीमत की राशि) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, पंचशील पार्क, नई दिल्ली में सर्टिफिकेट आफ डिपाजिट योजना में 16.6% की ब्याज दर पर 3 महीनों के लिए 25-02-92 को निवेश की गई :

क्रम सं.	राशि	पिछले निवेश की तारीख	भुगतान की तारीख	अभियुक्तियां*
1.	30,00,000/	25-11-91	25-02-92	

*बची हुई राशि सिंडिकेट बैंक, होज खास, नई दिल्ली, में 46 दिनों के लिए फिक्स डिपाजिट योजना में जमा कराई जायेगी।

2. भारत सरकार के तत्कालीन समाज कल्याण विभाग के दिनांक 2 मई, 1979 के समय समय पर यथा संशोधित का. आ. 120 (ई) की अधिसूचना के साथ प्रकाशित राष्ट्रीय बाल कोष, नई दिल्ली के संचालन की योजना के अनुसार प्रयोग किए जाने हेतु उपरोक्त खाता भारतीय पूर्त विन्यास के खजांची के नाम होगा।

[सं. 13-4/92 टी. आर. II]

प्रेम सागर, अवर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Women & Child Development)

In the matter of the Charitable Endowments Act 1890

(6 of 1890)

In the matter of the National Children's Fund, New Delhi

New Delhi, the 26th May, 1992

S.O. 1617.—On the application made by and with the concurrence of the Board of Management of the National Children's Fund, New Delhi, as in exercise of the powers conferred by Section 10(2) of the Charitable Endowments Act 1890 (6 of 1890), the Central Government do hereby order that the sum of Rs. 28,80,460 (Rupees Twentyeight Lakh Eighty Thousand Four Hundred and Sixty only) (discounted value of Rs. 30,00,000) as per particulars given below invested in Certificate of Deposit Scheme for 3 months in Central Bank of India, Panchsheel-Park, New Delhi with effect from 25-2-92 at the rate of interest 16.6 per cent.

Sl. No.	Amount	Date of Previous Investment	Date of Maturity	Remarks
1.	30,00,000	25-11-91	25-2-92	Surplus amount will be deposited in FD for 46 days with Syndicate Bank, Hauz khas, New Delhi

2. The above account shall vest in the treasurer of charitable endowments of India to be held by him for being applied in accordance with the scheme for the administration of the National Children's Fund, New Delhi, published with the Notification of the Government of India in the then Department of Social Welfare No. S.O. 120(E) dated the 2nd March, 1979 as amended from time to time.

[F. No. 13-4/92-TR-II]

PREM SAGAR, Under Secy.

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय)

फरीदाबाद, 21 मई, 1992

का. आ. 1618:—मैं, ओ. पी. बिहारी, कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, सामान्य श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियमावली, 1988 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामान्य श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियमावली, 1988 के नियम 3(8) (डो) के अनुपालन में एतद्द्वारा केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के निम्नलिखित सदस्यों को निर्दिष्ट क्षेत्र में श्रेणी अभिधान चिन्ह वाले किसी भी पैकेज को खोलने तथा उसका निरीक्षण करने अथवा किसी भी श्रेणीकृत उत्पाद का नमूना लेने के लिए प्राधिकृत करता हूं बशर्ते कि सभी नमूनों का घरेलू मंडियों के लिए कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम 1937 (1937 का 1) के अन्तर्गत निर्धारित श्रेणी अभिधानों और श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन नियमावली के अनुसार श्रेणीकृत और चिन्हांकित कृषि एवं अन्य उत्पादों के संदर्भ में भुगतान किया जाएगा।

नाम/पदनाम	निरीक्षण तथा नमूना लेने का कार्य क्षेत्र
1. मिस जया जेतली, 8/105, कौशल्या पार्क, होज खास, नई दिल्ली-110016	केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली
2. श्रीमती सरोजिनी वारदप्पन 48, वैरन रोड, मद्रास-600004	मद्रास म्युनिसिपल कारपोरेशन
3. अध्यक्ष, कर्नाटक उपभोक्ता, सेवा समिति, 32, बेन्सन क्रास, बेन्सन टाउन, बंगलौर - 560046	बंगलौर म्युनिसिपल कारपोरेशन
4. अध्यक्ष, उपभोक्ता ऐक्शन ग्रुप, 44, वेंकटकृष्णा रोड, मान्डावेली, मद्रास-600028	मद्रास म्युनिसिपल कारपोरेशन
5. अध्यक्ष, केरल राज्य उपभोक्ता समन्वय समिति, त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम म्युनिसिपल कारपोरेशन
6. अध्यक्ष, उपभोक्ता ऐक्शन फोरम, 8/1, रैन पार्क प्लेस, कलकत्ता-700082	कलकत्ता म्युनिसिपल कारपोरेशन

7.	अध्यक्ष, भारतीय उपभोक्ता विशा-निर्देश, समिति, पालिका मार्ग कामा अस्पताल के सामने, बम्बई–400001	बम्बई म्यूनिसिपल कारपोरेशन

[सं. टी.–13024/1/91–विस्तार]

ओ.पी. बिहारी, कृषि विपणन सलाहकार

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Directorate of Marketing and Inspection)

Faridabad, the 21st May, 1992

S.O. 1618.—In exercise of the powers conferred on me under the General Grading and Marking Rules, 1988, I, O.P. Behari, Agricultural Marketing Adviser to the Government of India in pursuance of the rule 3(8)(d) of the General Grading and Marking Rules, 1988 hereby, authorise the following members of the Central Consumer Protection Council to open and inspect any package bearing a grade designation mark or take samples of any Agmark graded produce within the area specified, provided that all samples shall be paid for, in respect of agricultural and other produce graded and marked in accordance with the grade designations and the Grading & Marking Rules prescribed under the Agricultural Produce (Grading & Marking) Act, 1937 (I of 1937) for domestic markets :

	Name/Designation	Jurisdiction for inspection and drawing samples
1.	M/s. Jaya Jaitly, 6/105 Kaushalaya Park, Hauz Khas, New Delhi-110016.	Union territory of Delhi.
2.	Smt. Sarojini Vardappan, 48, Warren Road, Madras-600004.	Municipal Corporation of Madras.
3.	President Karnataka Consumer Service Society, 32, Benson Cross, Benson Town, Bangalore-560 046.	Municipal Corporation of Bangalore.
4.	President, Consumer Action Group, 44, Venkatakrishna Road, Mandaveli, Madras-600028.	Municipal Corporation of Madras.
5.	President, Kerala State Consumer Coordination Committee, Ernakulam.	Municipal Corporation of Ernakulam.
6.	President, Consumers' Action Forum, 5/1 Red Cross Place, Calcutta-700062.	Municipal Corporation of Calcutta.
7.	Chairperson, Consumer Guidance Society of India, Hutment J. Mahapalika Marg, Opp, Cama Hospital, Bombay-400001.	Municipal Corporation of Bombay.

[No. T. 13024/1/91-Extn.]

O.P. BEHARI, Agricultural Marketing Adviser

संचार मंत्रालय

(दूर संचार आयोग)

नई दिल्ली, 26 मई, 1992

का. आ. 1619.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976, के नियम 10 (4) के अनुसरण में, संचार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित कार्यालय, जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है।

1. विदेश संचार निगम लि. बंबई का कार्यालय।

[सं. ई-11027/2/88–ओ एल]

एच. सी. शर्मा, उप निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF COMMUNICATION

(Deptt. of Telecommunications)

New Delhi, the 26th May, 1992

S.O 1619.—In pursuance of Rule 10(4) of the Official Language (Use for Official purposes of the Union) Rule, 1976, the Central Govt. hereby notifies following office of the Ministry of Communications where of more than 80% staff have acquired working knowledge of Hindi.

Office of Videsh Sanchar Nigam Ltd. Bombay.

[No. E. 11027/2/88-OL]

H. C. SHARMA, Dy. Director(OL)

पेट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय

(प्राकृतिक गैस विभाग)

नई दिल्ली, 5 जून, 1992

का. आ. 1620.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य जिला—रायगड में मौजे बोरीस, तहसील—अलिबाग मे मौजे—सासाव, तहसील—मुरुड जंजिरा तक नैसर्गिक गैस परिवहन के लिए पाईप लाईन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. 110066 द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार घोषित करती है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए, आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गैस अथारिटी आफ इंडिया लि., प्रभू निवास, दूसरा मजला, अलिबाग, मु. पोस्ट. तहसील—अलिबाग जिला—रायगड को उस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यवसायी के माध्यम ।

परिशिष्ट

राज्य : महाराष्ट्र जिला : रायगढ़ तहसील : अलिबाग

गांव का नाम	सर्वे नंबर	हिस्सा नंबर	गट नंबर	क्षेत्र		
				हेक्टर	आर	सेंटीयर
बरसोली	273	0 भाग	—	—	01	00
	280	14 भाग	—	—	17	80

[सं. ओ-14016/63/90-जी. पी.]
सी. एल. बशाल, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS,

(Department of Petroleum & Natural Gas)

New Delhi, the 5th June, 1992

S.O. 1620.—Whereas it appears to the Central Govt. that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas, From Village-Boris, Tahasil-Alibag, District-Raigad to Village-Salav, Tahasil-Murud Janjira, District-Raigad in the State of Maharashtra pipe line should be laid through the Agency of Gas Authority of India Ltd. 16 Bhikali Cama Place, R. K. Puranm, Ring Road, New Delhi-110 066.

And whereas, it appears to the Central Govt. that for the purpose of laying such pipe lines, it is necessary to acquire the Right of User in the lands described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipe lines (Acquisition of Right of User in the lands), Act, 1962 (50 of 1962) the Central Govt. declares its intention to acquire the Right of User in the lands referred in the schedule :

Provided that any person interested in the said lands having any objection for laying the pipe lines through the said lands may prefer any objection within 21 days from the Date of Notification to the Competent Authority, Thal-Salav Natural Gas pipe line, Prabhu Niwas, 2nd Floor, Alibag At. Post. Tahasil-Alibag, District-Raigad, Maharashtra State.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practationer.

SCHEDULE

State : Maharashtra District : Raigad Tehsil : Alibag

Village	Survey No.	Hissa No.	Block No.	Area		
				Hectare	Are	Cent.
Varsoli	273	O Part	—	—	01	00
	280	14 Part	—	—	17	80

[No. Q. 14016|63|00-GP]
C. L. BASHAL, Director.

नई दिल्ली, 5 जून, 1992

का. आ. 1621.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य, जिला—रायगड में मौजे बोरीस, तहसील—अलिबाग से मौजे सालाव तहसील—मुरुड जंजिरा तक नैसर्गिक गैस परिवहन के लिए पाईप लाईन गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. नई दिल्ली-110066 द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. प्रभू निवास, दूसरा मजला, अलिबाग, मु. पोस्ट. तहसील—अलिबाग, जिला—रायगड को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत ।

परिशिष्ट

राज्य : महाराष्ट्र		जिला : रायगड		तहसील : अलिबाग	
गांव का नाम	सर्वे नंबर	हिस्सा नंबर	गट नंबर	क्षेत्र	
				हेक्टर आर	सेंटीयर
बामणोली	14	1 भाग	—	— 02	40

[सं. आ. 14016/63/90—जी. पी.]

सी. एल. बशाल, निदेशक

New Delhi, the 5th June, 1992

S.O. 1621.—Whereas it appears to the Central Govt. that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas, from Boris Village, Tahsasil-Alibag, District-Raigad to Village-Salav, Tahasil Murud Janjira, District-Raigad in the State of Maharashtra pipe line should be laid through the Agency of Gas Authority of India Ltd. 16 Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, Ring Road, New Delhi-110 066.

And whereas, it appears to the Central Govt. that for the purpose of laying such pipe lines, it is necessary to acquire the Right of User in the lands described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipe lines (Acquisition of Right of User in the lands) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Govt. declares its intention to acquire the Right of User in the lands referred in the schedule :

Provided that any person interested in the said lands having any objection for laying the pipe lines through the said lands may prefer any objection within 21 days from the Date of Notification to the Competent Authority, Thal-Salav Natural Gas pipe line, Prabhu Niwas, 2nd Floor, Alibag At. Post. Tahasil-Alibag. District-Raigad, Maharashtra State

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

State : Maharashtra		District : Raigad		Tahasil : Alibag		
Village	Survey Number	Hissa Number	Block Number	Area		
				Hector	Are	C. Are
Bamnoli	14	1 Part	—	—	02	40

[No. O. 14016/63/90 GP]
C. L. BASHAL, Director

नई दिल्ली, 5 जून, 1992

का. आ. 1622.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य, जिला—रायगड में मौजे बोरीस, तहसील—अलिबाग से मौजे-सालाव तहसील—मुरुड जंजिरा तक नैसर्गिक गैस परिवहन के लिए पाईप लाईन गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. नई दिल्ली-110066 द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्‌पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. प्रभू निवास, दूसरा मजला, अलिबाग पोस्ट, तहसील—अलिबाग, जिला–रायगड को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत स्वरूप में हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत ।

परिशिष्ट

राज्य : महाराष्ट्र जिला : रायगड तहसील : अलिबाग

गांव का नाम	सर्वे नंबर	हिस्सा नंबर	गट नंबर	क्षेत्र		
				हैक्टर	आर	सं. आर
चौल	—	—	2773 भाग / 39	—	24	90
	—	—	2773 / 50 भाग	—	00	90
	—	—	2773 / 58 भाग	—	17	00

[सं. ओ.—14016/63/90—जी. पी.]
सी. एल. बशाल, निदेशक

New Delhi, the 5th June, 1992

S.O. 1622.—Whereas it appears to the Central Govt. that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas, From Boris, Tahasil-Alibag, District-Raigad to Village-Salav, Tahasil-Murud Janjira, District-Raigad in the State of Maharshtra pipe line should be laid through the Agency of Gas Authority of India Ltd. 15 Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, Ring Road, New Delhi-110066.

And whereas, it appears to the Central Govt. that for the purpose of laying such pipe lines, it is necessary to acquire the Right of User in the lands described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Lands) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User in the lands referred in the schedule:

Provided that any person interested in the said lands having any objection for laying the pipe lines through the said lands may prefer any objection within 21 days from the Date of Notification to the Competent Authority, Thal-Salav Natural Gas pipe line, Prabhu Niwas, 2nd Floor, Alibag At. Post. Tahasil-Alibag, District-Raigad, Maharashtra State.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

State : Maharashtra District : Raigad Tahasil : Alibag

Village	Survey Number	Hissa Number	Block Number	Area		
				Hector	Are	C. Are
Choul	—	—	2773 / 39 Part	—	24	90
	—	—	2773 / 50 Part	—	00	90
	—	—	2773 / 58 Part	—	71	00

[No. O-14016/63/90-GP]
C. L. BASHAL, Director

नई दिल्ली, 5 जून, 1992

का. आ. 1623.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य, जिला रायगड में मौजे, बोरीस, तहसील—अलिबाग से मौजे—सालाव तहसील—मुरुड जंजिरा तक नैसर्गिक गैस परिवहन के लिए पाईप लाईन गैस अथारिटी आफ इंडिया लि., नई दिल्ली 110066 द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गैस अथारिटी आफ इंडिया लि., प्रभू निवास, दूसरा मजला, अलिबाग, मु. पोस्ट. तहसील—अलिबाग, जिला—रायगड को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत स्वरूप में हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत ।

परिशिष्ट

राज्य : महाराष्ट्र जिला : रायगड तहसील : अलिबाग

गांव का नाम	सर्वे नंबर	हिस्सा नंबर	गट नंबर	क्षेत्र		
				हेक्टर	आर.	सें. आर.
कावीर	—	—	196-ए भाग	—	04	70

[सं. ओ.-14016/63/90-जी. पी.]
सी. एल. बशाल, निदेशक

New Delhi, the 5th June, 1992

S.O. 1623.—Whereas it appears to the Central Govt. that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas, from Village-Boris, Tahasil-Alibag, District-Raigad to Village-Salav, Tahasil-Murud Janjira, District-Raigad in the State of Maharashtra pipe line should be laid through the Agency of Gas Authority of India Ltd. 16 Bhikaji Cama Place, K. K Puram, Ring Road New Delhi 110 066.

And whereas, it appears to the Central Govt. that for the purpose of laying such pipe lines, it is necessary to acquire the Right of User in the lands described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Lands) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Govt. declares its intention to acquire the Right of User in the lands referred to in the schedule :

Provided that any person interested in the said lands having any objection for laying the pipe lines through the said lands may prefer any objection within 21 days from the date of Notification to the Competent Authority, Thal-Salav Natural Gas pipe line, Prabhu Niwas, 2nd Floor, Alibag At. Post. Tahasil-Alibag, District-Raigad, Maharashtra State.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

State : Maharashtra District : Raigad Tehsil : Alibag

Village	Survey Number	Hissad Number	Block Number	Area		
				Hectare	Are	C. Are
Kavir		—	—	196—A Part	— 04	70

[No. O-14016/63/90-GP]
C. L. BASHAL, Director

नई दिल्ली, 5 जून, 1992

का. आ. 1624.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य, जिला–रायगड में मौजे–बोरीस, तहसील–अलिबाग से मौजे–सालाव तहसील–मुरुड जंजिरा तक नैसर्गिक गैस परिवहन के लिए पाईप लाईन गैस अथारिटी आफ इंडिया लि., नई दिल्ली 110066 द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्‌पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय घोषित किया है ।

बशर्ते की उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गैस अथारिटी आफ इंडिया लि., प्रभु निवास दूसरा मजला, अलिबाग, पोस्ट. तहसील—अलिबाग, जिला—रायगड को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत ।

परिशिष्ट

राज्य : महाराष्ट्र जिला : रायगड तहसील : अलिबाग

गांव का नाम	सर्वे नंबर	हिस्सा नंबर	गट नंबर	क्षेत्र		
				हे.	आर	सें. आर.
बेलकडे	—	—	366 भाग	—	00	85

[नं. ओ.-14016/63/90-जी. पी.]

सी. एल. बशाल, निदेशक

New Delhi, the 5th June, 1992

S.O. 1624.—Whereas it appears to the Central Govt. that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas, from Village Boris, Tahasil Alibag, District-Raigad to Village-Salav, Tahasil-Murud Janjira, District-Raigad in the State of Maharashtra pipe line should be laid through the Agency of Gas Authority of India Ltd. 16 Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, Ring Road New Delhi 110 066.

And whereas, it appears to the Central Govt. that for the purpose of laying such pipe lines, it is necessary to acquire the Right of User in the lands described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Lands) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Govt. hereby declares its intention to acquire the Right of User in the lands referred in the schedule :

Provided that any person interested in the said lands having any objection for laying the pipe lines through the said lands may prefer any objection within 21 days from the Date of Notification to the Competent Authority, Thal-Salav Natural Gas Pipe line, Prabhu Niwas 2nd Floor Alibag At. Post. Tahasil-Alibag, District-Raigad, Maharashtra State.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

State : Maharashtra District : Raigad Tahasil : Alibag

Village	Survey Number	Hissa Number	Block Number	Area		
				Hector	Are	C. Are
Belkade	—	—	366 Part	—	00	85

[No. O-14016/63/90-GP]

C. L. BASHAL, Director

नई दिल्ली, 5 जून, 1992

का. आ. 1625.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय, प्राकृतिक गैस विभाग की अधिसूचना का. आ. 210 दिनांक 1 जनवरी, 1992 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार पाईप लाईन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, 16 भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, रिंग रोड, नई दिल्ली-110066 में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख में निहित होगा ।

[सं. ओ.—14016/63/90—जी. पी.]

सी. एल. बशाल, निदेशक

परिशिष्ट

राज्य : महाराष्ट्र जिला : रायगड तहसील : अलीबाग

गांव का नाम	सर्वे नंबर	हिस्सा नंबर	गट नंबर	क्षेत्र		
				हेक्टर	आर.	सें. आर.
खामाष	67	9 + 15 भाग	—	—	05	20
	67	4 + 6 + 8 + 16 भाग	—	—	03	00
	67	12 + 17 भाग	—	—	04	70
	67	13 भाग	—	—	03	40
	67	14 + 18 + 19 भाग	—	—	12	70
	65	1 + 2 + ए भाग	—	—	09	70
	65	1 + 2 + बी भाग	—	—	00	20
	65	3 भाग	—	—	17	50
	75	1 भाग	—	—	10	40
	76	4-ए भाग	—	—	01	80
	76	3 भाग	—	—	17	40
	78	4 भाग	—	—	05	40
	83	3 भाग	—	—	16	00
	82	0 भाग	—	—	13	80
	92	0 भाग	—	—	05	20

66	1 भाग	—	—	05	20
66	2-ए भाग	—	—	03	60
66	2-बी भाग	—	—	06	30
66	3-ए भाग	—	—	14	50
66	4 भाग	—	—	04	80
1	1 भाग	—	—	06	80
1	2 भाग	—	—	06	40
1	3 भाग	—	—	07	20
1	4 भाग	—	—	04	40
2	2-ए + 2-बी भाग	—	—	20	00

[सं. ओ. 13162 90-जीपी]

सी. एल. वंशल, निदेशक

New Delhi, the 5th June, 1992

S.O. 1625.—Whereas by Notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, S.O. No. 210 dated 1-1-1992 under Section 3 (Sub-Section 1) of the Petroleum and Minerals pipe lines (Acquisition of Right of User in land) Act 1962 (50 of 1962) the Central Govt. declares it's intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that Notification for the purpose of laying Gas pipe line.

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Govt. has, after considering the said report decided to acquire the Right of user in the lands specified in the schedule appended to this Notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Govt. hereby declares that the Right of User in the said lands specified in the schedule appended to the Notification hereby acquired for laying the Gas pipe line.

And, further in exercise of powers conferred by Sub-Section (4) of the Section 6, the Central Govt. directs that the Right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Govt. vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. 16 Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, King Road, New Delhi 110 066 free from encumbrance.

Dated 5-6-1992.

SCHEDULE

State : Maharashtra District : Raigad Tehsil : Alibag

Village	Survey No.	Hissa No.	Area		
			Hector	Are	C.Are
Khanav	67	9+15 Part	—	05	20
	67	4+8+6+16 Part	—	03	00
	67	12+17 Part	—	04	70
	67	13 Part	—	03	40
	67	14+18+19 Part	—	12	70
	65	1+2+ A Part	—	09	70
	65	1+2+B Part	—	00	20
	65	3 Part	—	17	50
	75	1 Part	—	10	40
	76	4-A Part	—	01	80
	76	3 Part	—	17	40
	78	4 Part	—	05	40
	83	0 Part	—	16	00
	82	0 Part	—	13	80
	92	0 Part	—	05	20
	66	1 Part	—	05	20
	66	2-A Part	—	03	60
	66	2-B Part	—	06	30
	66	3-A Part	—	14	50
	66	4 Part	—	04	80
	1	1 Part	—	06	80
	1	2 Part	—	06	40
	1	3 Part	—	07	20
	1	4 Part	—	04	40
	2	2-A+2-B Part	—	20	00

[No. O-14016/63/90-GP]

C. L.

नई दिल्ली, 5 जून, 1992

का. आ. 1626.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय, प्राकृतिक गैस विभाग की अधिसूचना का. आ. 3224, दिनांक 9/11/1990 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाईप लाईन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे इस धारा 6 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 16 भीकाजी कामा प्लेस, रिंग रोड, नई दिल्ली 110066 में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा ।

परिशिष्ट

राज्य : महाराष्ट्र जिला : रायगड़ तहसील : अलीबाग

गांव का नाम	सर्वे नंबर	हिस्सा नंबर	गट नंबर	क्षेत्र		
				हेक्टर	आर.	सें. आर.
तुडाल	1	2 + 3-बी	—	—	06	72

[सं. ओ.-14016/63/90-जी. पी.]
सी. एल. बशाल, निदेशक

New Delhi, the 5th June, 1992

S.O. 1626.—Whereas be Notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, S.O. No. 3224, dated 9-11-1990 under Section 3 (Sub-section 1) of the Petroleum and Minerals pipe lines (Acquisition of Right of User in land) Act 1962 (50 of 1962). The Central Govt. declares its intention to require the Right of user in the lands specified in the schedule appended to that Notification for the purpose of laying Gas pipe line.

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Govt. has, after considering the said report decided to acquire the Right of user in the lands specified in the schedule appended to this Notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Govt. hereby declares that the Right of User in the said lands specified in the schedule appended to the Notification hereby acquired for laying the Gas pipe line.

And further in exercise of powers conferred by sub-section (4) of the Section 6, the Central Govt. directs that the Right of User in the said lands shall instead of vesting in Central Govt. vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. (A Govt. of India Undertaking) GAIL Building, 16 Bhikaji Cama Place R. K. Puram, Ring Road, New Delhi-110 066 free from encumbrance.

SCHEDULE

State : Maharashtra District—Raigad Tahsil - Alibag.

Village	Survey No.	Block No.	Hissa No.	Area		
				H.	Are	C. Are
Tudal	1	—	2+3-B	—	06	72

[No. 14016/63/90-GP]
C. L. BASHAL, Director

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली 9 जून 1992

का.आ. 1627.— यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ए.बी.जी.एल. टी. पोइन्ट से गुजरात गार्डियन लि. तक पैट्रोलियम परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

ए बी जी एल टी पाइन्ट से गुजरात गार्डीयन लि. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तह. : अंकलेश्वर

गांव	ब्लाक नं.	है.	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
उमरवाडा	263	0	20	00
	264/ए	0	22	40
	266	0	20	40
	267/2	0	11	80
	271/1/ए	0	19	20
	269	0	24	80
	373	0	20	80
	374	0	28	80
	387	0	32	00
	390	0	10	60
	389/1/2	0	11	40
	402/1	0	27	80
	403/1/2	0	23	30
	407/1	0	13	60
	405	0	03	06
	406/पी	0	17	60
	408/1	0	06	25
	414/1	0	16	00
	413	0	08	50
	416/पी	0	39	20
	417/1/2	0	45	68
	418	0	19	40
	420	0	39	70
	419/1/2/3	0	00	72
	422/1/2	0	27	58
	423	0	01	22

[सं. O-12016/23/92/ओ.एन.जी.डी. IV]
एम. मार्टिन डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 9th June, 1992

S.O. 1627.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of the petroleum from ABGL-T-Point to Gujarat Guardian Ltd. in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road Vadodara-390 009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from ABGL T. Point to Gujarat Guardian

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Ummarwada	263	0	20	00
	264/A	0	22	40
	266	0	20	40
	267/2	0	11	80
	271/1/A	0	19	20
	269	0	24	80
	373	0	20	80
	374	0	28	80
	387	0	32	00
	390	0	10	60
	389/1/2	0	11	40
	402/1	0	27	80
	403/1/2	0	23	30
	407/1	0	13	60
	405	0	03	06
	406/P	0	17	60
	408/1	0	06	25
	414/1	0	16	00
	413	0	08	50
	416/P	0	39	20
	417/1/2	0	45	68
	418	0	19	40
	420	0	39	70
	419/1/2/3	0	00	72
	422/1/2	0	27	58
	423	0	01	22

(No. O-12016|23|92-ONG.D.-IV)
M. MARTIN, Desk Officer

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 मई, 1992

का. आ. 1628.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, देना बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-5-92 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-12012/77/89-डी-2(ए)]

वी. के. वेणुगोपालन, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 21st May, 1992

S.O. 1628.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1974), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Dena Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 20-5-92.

[No. L-12012/77/89-D.II(A)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, AT BOMBAY

PRESENT :

Shri P. D. APSHANKAR

Presiding Officer

Reference No. CGIT-2/12 of 1989

PARTIES :

Employers in relation to the management of Dena Bank.

AND

Their Workman

APPEARANCES :

For the Employer—Shri R. S. Pai, Advocate.

For the Workmen—Shri N. A. Kulkarni, Advocate.

INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra.

Bombay, dated the 1st May, 1992

AWARD

The Central Government by their order No L-12012/77/89-D 2(A) dated 15-5-1989 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

"Whether the action of the management of Dena Bank in dismissing from service Shri S. R. Shah, is justified ? If not, to what relief is the workman entitled" ?

2. The case of the workman Shri S. R. Shah, as disclosed from the statement of claim Ex. 2 filed by him in person, in short, is thus :

He entered into the service of the Dena Bank in 1973. He was discharging his duties honestly and deligently. However on 11-3-1982 the charge sheet was issued to him by the management of the bank and he was suspended from service. He was then working in the Clearing Department of the Ravivar Peth Branch at Pune. It was alleged against him that he committed misconduct, i.e.

(a) did an act prejudicial to the interest of the bank or gross negligence or negligence involving or likely to involve the Bank in serious loss.

(b) caused willful damage or attempted to cause damage to the property of the Bank or to its customer."

3. The workman further alleged thus :

On 16-12-1982 a customer by name Smt. Savitribai R. Jaju visited the said branch of the bank. The said workman and the customer lady were already well knowing each other. Hence the workman helped that lady in getting renewed the Samruddhi Deposit Receipt (S.D.R.) against maturity of the earlier S.D.R. That lady handed over Rs. 700 to the workman which was to be deposited in her Saving Bank Account No. 2910 and she requested the workman to deposit that amount accordingly in her account on the next day, as the business hours of the bank were then already over. Thereafter the pass book of that lady was returned by the workman on the next day. An entry regarding the deposit of Rs. 700 in the Bank was made in the pass book. However, lateron the complaint was received from that lady Smt. S. R. Jaju that the amount of Rs. 700 of which an entry appeared in the pass book, was not deposited in her Saving Bank Account of the Bank, and as such, the amount in balance at her credit in the bank was less by Rs. 700. It was alleged against the workman that a fraudulent entry of Rs. 700 was made in the pass book of that lady without the amount actually being deposited. It was also alleged against the workman that he issued certain cheques to various parties drawn on his saving bank account of the bank, even though there was no sufficient balance of the amount at his credit in the bank.

4. The workman submitted his explanation to the charge-sheet issued against him. Thereafter, a departmental enquiry was held against the workman. Shri D. M. Vaidya, the Bank officer, was the enquiry officer in the matter. The enquiry officer, after conducting the necessary enquiry, found the workman guilty of the charges levelled against him. The disciplinary authority, on going through the findings of the enquiry officer and the record, confirmed the findings, and imposed the punishment of dismissal against the workman. Against that order, the workman filed the necessary appeal which came to be dismissed by the appellate authority. Thereafter, as the conciliation proceedings held before the Assistant Labour Commissioner (Central) ended in failure, the Central Government made the reference, as above.

5. The workman further alleged thus :—

The action on the part of the workman in helping the customer cannot be termed as a misconduct in terms of the provisions of the Bipartite Settlement. There was absolutely no evidence on record to hold the workman guilty of the charges levelled against him. As such the findings of the enquiry officer are perverse. The complaint letter by the said lady was written by some person in the Bank and it was in Marathi, and that lady Smt. Jaju could not read and write Marathi. As such it was not a complaint-letter in fact by her. Further, lateron that lady withdrew that complaint on 13-3-1982 stating therein that there was some misunderstanding on her part and therefore she requested for the withdrawal of that complaint, even though the enquiry proceedings were conducted against him. The allegation of the bank management that the entry regarding the amount of Rs. 700 in the pass book of that lady was made by the workman, was unproved in the enquiry proceedings. Further, no hand writing expert was examined to prove that the hand writing of the entry in the pass book of that lady regarding the deposit of Rs. 700 was

of the workman. The findings of the enquiry officer have been recorded without any evidence on record. As such the punishment passed upon him on such perverse findings is also bad-in-law. The allegation of the bank management that the workman was in the habit of issuing the cheques without the sufficient balance of the amount in his account, was also false, and that cannot be said to constitute as a misconduct. Further, in the present case no financial loss has been caused to the Bank. The punishment of dismissal from service is highly disproportionate to the alleged charges levelled against him. The workman, therefore, lastly prayed that the action of the Bank management in dismissing him from service be held as unjust and improper, and that bank be directed to reinstate him in service with full back wages and the continuity of service.

6. The Bank Management by their Written Statement (Ex. 3) contested the said claim of the workman, and in substance contended thus :—

The said workman was working as the Cashier-cum-Clerk in the Bank since 1973. However, it is not true that he was discharging his duties honestly and deligently. The explanation submitted by the workman to the charge-sheet was not found satisfactory, and hence the necessary domestic enquiry was conducted against him. The Bank Management stated in their Written Statement that the workman himself admitted in his statement of claim that he had received the amount of Rs. 700 from the said lady Mrs. Jaju. The said lady had handed over Rs. 700 to that workman for crediting it in her account in the bank. Firstly that lady had made an oral complaint with the Branch Manager about the less amount of Rs. 700 in her account. She was, thereupon, directed to report about it to the Regional Manager, and hence she lodged the complaint in writing with the Regional Manager on 9-3-1982. That complaint, eventhough written in Marathi, was read out to her in the language understood by her, and only thereafter she put her signature therebelow. Eventhough that lady lateron withdraew her complaint, that did not in any way nullify the act of criminal breach of Trust committed by the workman. In fact the workman had committed misappropriation in respect of that amount of Rs. 700 handed over to him by the said lady. The entry regarding Rs. 700 in the pass-book of that lady was made by the workman himself. It is not true that the findings of the enquiry officer are perverse. It is true that the Bank did not suffer any financial loss. However the amount given by the customer to the workman for being deposited into this bank was not actually deposited by the workman in the bank, but he had misappropriated it. As such he committed the offences of criminal breach of trust and misappropriation in respect of that amount. The Bank Management lastly prayed that the action taken by them be held as just, legal and proper, and the prayer of the workman be rejected.

7. The issues framed at Ex. 5 are :—

(1) Whether the findings of the Inquiry Officer are perverse ?

(2) Whether the order of the Bank Management in dismissing the workman S. R. Shah from service is just, valid and legal ?

(3) If not, to what relief he is entitled ?

(4) What Award ?

8. My findings on the said issues are :—

(1) No.

(2) Yes.

(3) Issue does not survive.

(4) As per below ;

REASONS

ISSUE NO. 1.

9. The workman Shri S. R. Shah filed his affidavit (Ex 6) support of his case and he was cross-examined on behalf of the Bank Management. No oral evidence was led on behalf of the Bank Management. The admitted facts are thus. An amount of Rs. 700 was handed over by the lady Smt. Jaju to the workman on 16-12-1981, that the said amount was not deposited by the workman in the bank, and that lateron the workman returned the amount of Rs. 700 to that lady. The necessary domestic enquiry was held against the workman. The fairness of the enquiry has not at all been challenged by the workman in his pleadings, or during the course of the evidence before this Tribunal. It is seen from the enquiry proceedings that sufficient opportunity was given to the workman to defend himself, that the witnesses examined on behalf of the bank were cross-examined by the defence representative of the workman, and the workman also led the evidence on his behalf before the enquiry officer. As such the Enquiry held against him was held properly and as per the rules of natural justice.

10. However, the main contenion of the workman is that the findings of the enquiry officer are perverse and as such, the punishment of dismissal imposed upon him is not just and legal. I find the findings of the enquiry officer are just and proper, based upon the evidence on record and are not perverse. The question regarding the perversity of the findings or otherwise of the enquiry officer was considered by the Supreme Court in the case 1962 II LLJ 772, wherein it was held by the Supreme Court, that when the finding is supported by the legal evidence on record and when the finding is such that on the basis of the material on record, a reasonable man could have arrived at that conclusion that finding is just and proper and not perverse. Again in the case of Banaras Electric Light & Power company limited Vs. Labour Court reported in (1972 II LLJ-328) the Supreme Court held that a finding can be considered as perverse only when there is no evidence at all to support the conclusions of the enquiry officer and no reasonable man would come to the conclusion on the basis of the evidence on record, or is entirely opposed to the whole body of evidence adduced before it. Taking into consideration the said guideline laid down by the Supreme Court, I find that the findings of the enquiry officer are not at all perverse, but are quite just and proper, based on the evidence led before him.

11. As can seen from the enquiry proceedings (Ex. 12), five witnesses were examined on behalf of the bank management during the enquiry held against the workman. All those five witnesses were cross-examined on behalf of the workman. The first witness was the Branch Manager Shri P. R. Vaidya who in his evidence before the enquiry officer in substance stated thus :—

"On 25-2-1982, the lady Mrs. Savitribai Jaju had visited the branch to withdraw the amount of Rs. 400 from her Saving Bank Account. It was then noticed that the amount of Rs. 700 was not actually deposited in her account in the bank, and as such, her balance in the bank was less than Rs. 700. Thereafter the Branch Manager contacted the workman Shri S. R. Shah on telephone, and the workman admitted that the said lady had handed over Rs. 700 to him in the afternoon of 16-12-1981, and that the entry regarding Rs. 700 in the Pass Book of that lady was made by him. As such the workman had admitted before the Branch manager that the said lady had handed over Rs. 700 to him, and that he had made the credit entry in her pass book showing that the amount of Rs. 700 was deposited in her account in the bank. However the amount was not deposited by the workman in the bank." Therefore on the basis of the evidence of the Branch Manager as above, the finding of the enquiry officer holding the workman guilty of the charge in question cannot at all be said to be unjust, improper or perverse. It is

true that no handwriting expert was examined during the enquiry proceedings. However, the fact remains that the said lady had handed over Rs. 700 to the workman and that the workman had not deposited that amount in her account in the bank. The handwriting regarding the entry of Rs. 700 in the pass book of that lady was compared by the enquiry officer with the other admitted hand writing of the workman, and then he concluded that the handwriting regarding that entry of Rs. 700 was in the handwriting of the workman. I find that there is nothing illegal in this act of the Enquiry Officer.

12. The second witness for the Bank Management before the enquiry officer was Shri B. G. Kulkarni, the Cashier. He stated in his evidence that on 16-12-1981 the said lady had been to the branch of the bank for the renewal of S.D.R. and had contacted the workman in that respect. As such the presence of that lady Mrs. Jaju in the bank on the said day is proved by the evidence of this witness.

13. The third witness was Shri V. L. Madan, the clerk, who was then dealing with the F.D.R. Section in the Bank. He also deposed about the presence of that lady in the bank in connection with the renewal of the S.D.R. on that day, and further stated that, that lady had contacted him and the said workman in that respect.

14. The fourth witness was Mrs. M. S. pundalik, who was then working in the saving Bank Department. She stated that on 25-2-1982 the said lady Mrs. Jaju had come to the bank for withdrawing the amount of Rs. 400, that it was then found that there was no corresponding entry of Rs. 700 in the ledger book of the bank eventhough the credit entry of Rs. 700 appeared in her pass book, and hence that lady Mrs. Pundalik asked Mrs. Jaju to approach the Branch Manager in that respect.

15. The last and fifth and the important witness before the enquiry officer was the said lady Mrs. Jaju. This lady in substance stated before the enquiry officer thus :

16. 'On 25-2-1982 she had gone to the Ravivar Peth Branch for the withdrawal of Rs. 400 from the Bank. She had already handed over the amount of Rs. 700 to the said workman for being deposited in her account in the bank, in December, 1981, and that thereafter she lodged the necessary complaint against the workman with the bank management. That complaint was written by somebody in the bank on the information supplied by her.'

17. That complaint letter filed by the said lady dated 9-3-1982 is at Ex. 10. In that complaint the said lady stated thus :

"She had visited to the Ravivar Peth Branch on 16-12-1981 for getting the S.D.R. renewed and had contacted the said workman Shri S. R. Shah, a person already wellknown to her. Thereafter she handed over the amount of Rs. 700 to the workman for being deposited in her account in the bank. On the next day the workman sent her pass book at her residence, and she found that there was a credit entry of Rs. 700 in her pass book. Some weeks thereafter, i.e. in March, 1982 she again went to the bank for the withdrawal of amount of Rs. 400. She then found that even though the credit entry was made in her pass book, the amount of Rs. 700 was not actually deposited by the workman in her account in the bank, and she was asked to inquire about it. Thereafter she contacted the workman Shri Shah and he told her that through mistake he had deposited that amount in the account of some other person, and that he would settle the matter on the next day. However he did not deposit that amount in her account in the bank nor did he return the amount to her even though he promised to return it again and again. As such the bank employee has misbehaved regarding the bank transaction. By that complaint application the said lady requested the bank management to help her in getting that amount from the workman Shri Shah.

18. After the evidence of five witnesses for the Bank Management was over, the said workman examined himself before the enquiry officer. In substance he stated in his evidence before the enquiry officer thus :

"On 16-12-1981 the said lady Mrs. Jaju had come to that branch in connection with renewal of the S.D.R., and that he helped her in that matter. That lady handed over Rs. 700 to him." However he denied that, that amount was paid by that lady to him for being deposited in her account in the bank. Even then the fact remains that the said lady had handed over Rs. 700 to the workman in the evening of 16-12-1981, that that amount was not actually deposited in the bank account by the workman, and that later on the said lady had filed the necessary complaint on 9-3-1982 (Ex. 10) against the workman in the matter. It is true that the said lady withdrew that complaint on 13-3-1982 by her letter dated 13-3-1982. In that withdrawal letter she stated that through mistake she had lodged the complaint and hence that complaint be filed. Even then the fact remains that the said lady had handed over the amount of Rs. 700 to the workman, and the amount was not deposited by him in the bank account.

19. On the basis of the evidence on record, as above, the enquiry officer came to the conclusion that the workman had committed the misconduct as alleged against him. In view of the nature of the evidence, as above, before the enquiry officer and the complaint and the other documents before him, it cannot at all be said that the findings recorded by him are unjust, improper and illegal. The said workman had committed misappropriation in respect of the bank customer's amount of Rs. 700. Before arriving at the necessary conclusion, I find from the enquiry report, that he had carefully gone through the examination-in-chief and the cross-examination of the different witnesses, the documents produced before him, the arguments advanced by both the parties before him, and then he came to the necessary conclusion which are in favour of the bank management and against the workman. He had correctly believed the evidence of the witnesses examined on behalf of the bank management. Even in the cross-examination of the workman before this Tribunal he admitted that, he had admitted in the enquiry proceedings that the lady S. S. Jaju had handed over Rs. 700 to him, and that he did not deposit that amount in her account. Therefore, for all the above-said reasons I find that the findings of the enquiry officer are just and proper, and are not at all perverse.

Issue No. 1 is therefore found in the negative.

20. According to the workman, the order of dismissal from service is highly disproportionate to the charges levelled against him. However it is seen from the enquiry proceedings that in the past the memos were issued to him by the bank management, as his service record was not good. The question regarding the justifiability and the propriety of the dismissal order of the workman for the misconduct of theft of Rs. 150 was considered by the Calcutta High Court in the case reported in 1987 LIC 77. It is observed in that case that the employee concerned showed that he was dishonest and his suitability and reliability to continue in service might be affected for that reason and would have a bearing on his contract of service and as such the said offence was a good ground for dismissing the workman from the service. In the case reported in 1C1R page 121, it was held by the High Court, Gujarat, that the order of dismissal in the matters of fraud like duping the poor citizens is the most proper punishment. In the present case, the workman in question had received the amount of Rs. 700 from the said lady Mrs. Jaju, but did not actually deposit it in her account in the bank but misappropriated it, even though he returned that amount to her subsequently. This act on the part of the said workman clearly amounts to the misconduct as contemplated under para 19.5 of the Bipartite settlement, as he did an act prejudicial to the interest of the bank and also caused willful damage to the property of the bank's customer. Therefore, I find that the action of the bank management in dismissing the said workman

from service is quiet just, legal and proper and as such he is entitled to no relief.

21. Point No. 2 is therefore found in the affirmative.

22. In the result, the following Award is passed :

AWARD

The action of the management of Dena Bank in dismissing from service Shri S. R. Shah is just, legal, and proper.

The parties to bear their own costs of this reference.

Sd/-

P. D. APSHANKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 21 मई, 1992

का. आ. 1629.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-5-92 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-12012/316/91-आई आरबी-II]

वी. के. वेणुगोपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st May, 1992

S.O. 1629.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Indian Overseas Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 20-5-92.

[No. L-12012/316/91-IR (B.II)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMILNADU, MADRAS

Wednesday, the 29th day of April, 1992

PRESENT :

Thiru M. Gopalaswamy, B.Sc., B.L., Industrial Tribunal

Industrial Dispute No. 17 of 1992

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the management of Indian Overseas Bank, Madras)

BETWEEN

Thiru P. Shankarapandian, Mavadi Street, Cheranmahadevi, Tirunelveli District, Pin Code-627 424.

AND

The Chief Officer (IRD), Indian Overseas Bank, 752, Annasalai, Madras-600002.

REFERENCE :

Order No. L-12012/316/91-IR(B.II), dated NIL of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on this day for final disposal in the presence of Thiruvalargal G. Narasimhalu, R. Sridharan and V. R. Kamalanathan, Advocates appearing for the management upon perusing the reference and other connected papers on record and the workman is reported to be dead, this Tribunal passed the following :

AWARD

This dispute between the workman and the management of Indian Overseas Bank, Madras-2 arises out of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in its Order No. L-12012/316/91-IR(B.II), dated Nil of the Ministry of Labour, for adjudication of the following issue :

"Whether the action of the management of Bank of Tamil Nandu (now Indian Overseas Bank) in terminating the services of Shri P. Shankarapandian is justified? If not, to what relief is the workman entitled to ?"

2. Summons were issued to the parties. The management was represented by counsel. The summons were returned from the Petitioner-workman to this Tribunal with an endorsement "Addressee deceased."

3. Today, when the dispute was called, no representation was made on behalf of the deceased workman.

4. Hence this Industrial Dispute is dismissed as the Petitioner-workman is dead.

Dated, this 29th day of April, 1992.

N. GOPALASWAMY, Industrial Tribunal

नई दिल्ली, 21 मई, 1992

का. आ. 1630.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, बैंक आफ बड़ौदा के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-5-92 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-12012/275/86-डी-2(ए)]

वी. के. वेणुगोपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st May, 1992

S.O. 1630.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on the 20-5-92.

[No. L-12012/275/86-D.II(A)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, AT BOMBAY

PRESENT :

Shri P. D. Apshankar, Presiding Officer.

Reference No. CGIT. 2/46 of 1986

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bank of Baroda.

AND

Their workman.

APPEARANCES :

For the Employer—Mr. R. B. Pitale, Representative.

For the Workman—Mr. A P. Kulkarni, Advocate.

INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra

Bombay dated the 6th May, 1992

AWARD PART-II

1. The Central Government by their order No. L-12012/275/85-D.II(A) dated 7-10-1986 have referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

"Whether the action of the management of Bank of Baroda in relation to its Central Office, Bombay, in retiring Shri Kallappa Kotian on 31-12-1984, is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The facts of the present case in short are thus :

The workman Shri Kallappa Kotian had entered into the service of the Bank of Baroda as a peon on 1-5-1945. His birth date as initially recorded in the Bank's record is 20-3-1924. The age of retirement for the class IV employees of the Bank is 60 years. As such he was retired from the bank service on 31-12-1984. However about two months prior to his retirement, i.e., on 14-11-1984 he sent an application to the Bank management stating that he learnt that he was to be retired from the bank's service by the end of that year, but that his correct date of birth is 5-8-1926 as recorded with the Bombay main office, and as such he could not be retired from service on 31-12-1984, but that his correct date of retirement would be 31-12-1986. Thereafter the bank give him an opportunity to produce the necessary evidence regarding his alleged correct date of birth. However, as the workman could not produce the necessary satisfactory evidence regarding his correct date of birth as 5-8-1926, the bank made him to retire from the service on 31-12-1984. Hence the present Industrial Dispute arose between the parties. Accrording to the bank management, the correct date of birth of the workman is 20-3-1924 as recorded in the bank's record on his entering into the bank's service. According to the workman, his correct date of birth is 5-8-1926.

3. The necessary Issues framed at Ex. 4 are :

(1) Whether the workman Shri Kallappa Kotian proves that his correct date of birth is 5-8-1926?

(2) Whether the date of birth of the said workman as appearing in the record of the Bank's Bombay Main Office is also 5-8-1926?

(3) Whether the termination of the services of the said workman on 31-12-1984 by the Bank of Baroda amounted to his retrenchment, and if so, whether it is in violation of the provisions contained in Section 25F of the Industrial Disputes Act ?

(4) Whether the Bank of Baroda Employees' Trade Union Congress of which the said wrokman is a member, is not competent to espouse the cause of the said workman?

(5) Whether no industrial dispute existed or exists in the present case?

(6) Whether the date of birth given by the said workman when he joined the service of Bank was 20-3-1924?

(7) Whether the action of the management of the Bank of Baroda in relation to its Central Office, Bombay in retiring Shri Kallappa Kotian on 31-12-1984 is justified?

(8) If not, to what relief is the workmen entitled?

(9) What Award?

4. The issue Nos. 4 and 5 were tried as preliminary issues, and by the Award Part I passed on 2-6-1989, it was found that the union in question was competent to espouse the cause on behalf of the workman, and that the industrial dispute existed between the parties.

5. My findings on the rest of the issues are :

(1) No

(2) Yes, but it is not correct.

(3) No.

(6) Yes.

(7) Yes.

(8) Issues does not survive.

(9) Award as per below.

REASONS

6. After the Award part-I was passed the workman examined himself in support of his case at Ex. 6, and he was cross-examined on behalf of the Bank Management. Shri R. V. Dalvi, the Chief Manager, (Staff Administration), of the bank filed his affidavit (Ex. 7) in support of the case of the bank and he was cross examined on behalf of the workman.

7. There are the documents on the record showing the date of birth of the workman as 20-3-1924, and there are the documents showing the date of birth of the workman as 5-8-1926. On carefully going through the different documents I find that the documents showing the date of birth of the workman is 20-3-1924 are reliable documents, and the documents showing the birth date as 5-8-1926, as now alleged by the workman cannot be safely relied upon. The documents showing the date of the birth of the workman as 20-3-1924 on the strength of which the workman was retired from the bank service are thus :

The workman admittedly entered into the service of the bank on 1-5-1945. Thereafter he became the member of the Provident Fund of the bank, and for that purpose he filled in the necessary declaration form on 20-9-1945 (Ex. 15). This is an original document. The birth date mentioned by the workman therein is 20-3-1924. This declaration form has been signed by the workman and has been attested by the witness. This declaration form for becoming a member of provident fund was filled in by the workman only within four months after joining the services with the bank about 40 years before his retirement. Thus, as per this declaration form the birth date of the workman is 20-3-1924. The workman stated in his evidence that the alleged signature below that declaration form is not his, and he did not put his signature thereon. Now, as per Section 90 of the Indian Evidence Act, where a document purporting to be thirty years old, produced from any custody which the court in the particular case considers proper, the court may presume that the signature and every other part on that document, which purports to be in the handwriting of any particular person, is in that person's handwriting, and, in the case of a document executed or attested, that it was duly executed or attested by the persons by whom it purports to be executed or attested. Therefore, as the said declaration form dated 20-9-1945 (Ex. 15) is a document more than 30 years old, the presumption will be that the signature below that form is of the workman Shri Kallappa Kotian However the workman denied that signature as his. Therefore, it was for the workman to produce the evidence of the handwriting expert showing that the alleged signature on that form was not his. However he did not produce any such evidence. Under Section 114 (e)(f) of the Indian Evidence Act, the court may presume that the "judicial and official acts have been regularly performed, and the common course of business has been followed in the particular case". Therefore, it will be presumed in the present case that, when the said workman entered into the service of the bank in May, 1945, the Bank Management obtained the necessary declaration form regarding the Provident Fund from the employee concerned only, i.e. from Kallappa Kotian, and not from any other person As such I find that the said declaration form dated 20-9-1945 filled in only four months after entering into the service was filled in by the workman himself about 40 years before his retirement from service, and that the birth date mentioned therein as 20-3-1924 was, and is, his correct date of birth. On the basis of this birth date and the document, the workman was retired from the Bank's Services on 31-12-1984.

8. Ex. 19 is the original 'Employee Record of Service' of the workman Shri Kallappa Kotian. Even in this document, the birth date of the workman mentioned is 20-3-1924. The entries in this document have been made since 1945, i.e. since 40 years before the date of his retirement, and as such, it is a very old and reliable document wherein the date of birth of the workman shown is 20-3-1924. The presumption under section 114(e)(f) will arise as regards this document also that the official acts have been regularly performed, and that the common course of business has been followed in the particular case, i.e. the entries made in that service record were made correctly and they are the correct entries. Ex. 20 is a copy of the birth year register, i.e. the copy of the document showing the year of birth of the employee as 1924. As per this document also, the birth date of the workman is 20-3-1924. I find that the above said three documents are the genuine and reliable documents showing the date of birth of the workman as 20-3-1924 as the correct date of birth.

8 (A). On the contrary, the workman is relying upon the following documents showing his date of birth as 5-8-1926. Ex. 5 is an original horoscope in Kannad language. This horoscope states that a son was born to Smt. Baidy, wife of Kittapa Kotian, on 5-8-1926, and that the son was named as Kallappa. Therefore, according to the workman, his correct date of birth is 5-8-1926, and not 20-3-1924. However, the said horoscope has not been signed by anybody, and also the date on which it was prepared has also not been mentioned therein. The person who prepared that horoscope has not been examined as a witness in the present case. It is also not known who supplied the information regarding the birth date mentioned in the horoscope to the person who prepared it. While the present reference was made by the Central Government in 1986, the workman produced that horoscope before this Tribunal for the first time in August 1989, i.e., three years after the reference. Further if, according to the workman, his correct date of birth was 5-8-1926, he could have produced that horoscope long before his retirement before the Bank Management. However it seems that he did not produce it at any time before the Bank Management till the date of his retirement. As such, the birth date mentioned therein as 5-8-1926 cannot be safely relied upon.

9. The workman is relying upon the Bank of Baroda Staff Register, the copy whereof is at Ex. 12. The birth date of the workman mentioned therein is 5-8-1926. However, it is not known on what basis that birth date as 5-8-1926 was mentioned therein, when the birth date as initially mentioned by the workman while entering into the Bank services was 20-3-1924. Further the entries in this Staff Register have been made since 1980, and as such, this is not a very old document, as the workman was made to retire by the end of the year 1984. Ex. 26 is a xerox copy of the document showing the information of different workmen in a computerised form. As per this computerised statement, the birth date of the workman shown therein is 5-8-1926. However, this is an unsigned document, and is also not bearing any date on which it was prepared. As such the entries made therein cannot at all be relied upon. It is not known who made the entries therein, and when, and on what basis. Ex. 14 is a copy of the forwarding letter by the Bank dated 17-9-1982. By this letter the workmen's application for getting the necessary loan was forwarded by the bank to the authority concerned. The birth date of the workman mentioned in this forwarding letter dated 17-9-1982 is also 5-8-1926. However, as regards this document also, it is not known on the strength of what document the birth date of the workman was mentioned therein as 5-8-1926. It is true that this is Bank's document. However, as there is no evidence on record showing the basis for mentioning the date of birth as 5-8-1926, the entry in that respect cannot be safely relied upon. As noted above, the birth date mentioned in the Provident Fund's application dated 20-9-1945 (Ex. 15) of the workman is 20-3-1924. As such the workman should have led further evidence before this Tribunal that subsequently he had made an application to the bank for the correction of his birth date to 5-8-1926, and that he had produced before the bank management the particular and necessary evidence showing his date of birth as 5-8-1926. No such evidence has been produced by the workman before this Tribunal showing that the bank management subsequently changed his date of birth from 20-3-1924 to 5-8-1926 on the basis of particular documentary evidence produced by him. Therefore, the subsequent documents of the bank of the year 1982 and onwards showing the date of the birth of the workman as 5-8-1926 cannot be safely relied upon.

10. Ex. 11 is the 'Certificate of birth' dated 28-1-1985 issued by the Chief Registrar of births and deaths of the Government of Karnataka. The birth date mentioned in this certificate of birth of the workman is also 5-8-1926. This certificate states that the information mentioned in that certificate was obtained from the original record of birth which was in the Register for the year 1985. However, there is no evidence on record showing as to who supplied the necessary information regarding the date of birth as 5-8-1926 to the office of the Chief Registrar of Births and Deaths. While the workman was retired from the bank services in 1984, the certificate of birth was obtained from him in January 1985, i.e. after his retirement. In case his correct date of birth was 5-8-1926, he could have obtained that certificate much earlier, and could have produced it before the bank management. However he did not produce it at any time before the Bank Management. Therefore the said certificate of birth (Ex. 11) based upon the information recorded in the Register in 1985 only, i.e. after the retirement of the workman, cannot at all be safely accepted.

11. In the result, I find that the correct date of birth as recorded in the Provident Fund's application and in the employees record of service long bank as in 1945 is the correct date of birth, and it is 20-3-1924, and not 5-8-1926 as alleged by the workman. Only a few years before the date of his retirement. Therefore, the workman was rightly made to retire from service as on 31-12-1984. The different issues as mentioned above are therefore found accordingly. My attention was drawn on behalf of the bank management to the case reported in II LLN page 685 of the High Court of Judicature at Madras between Mukkottumudi Estate. Mudis V|s. Chadayappan and another. It was held in that case that the "entries in a birth register would not constitute evidence by themselves, and they should be corroborated by evidence of person who knew the facts in order to identify the person mentioned in the certificate as the person concerned. Unless communication is made out between the certificate and the person concerned, the certificate will be of no evidential value". In the recent case of 1986 of the Madhya Pradesh High Court—Indore Bench between the Steel Authority of India Limited V|s. Industrial Court and others, it was observed thus :

> "It is difficult to agree with the submissions made by the learned counsel for the respondent that an employee who enters into the contract of service can at any point of time or even at the fag and of his service submit such an application that his date of birth recorded in the service book, which bears his signature, was wrongly recorded. It is also somewhat unnatural that an employee would not know his correct date of birth and would after a lapse of several years would all of a sudden come to know what is his correct date of bith and that the one recorded when he entered into service was wrongly recorded."

The observations made in the abovesaid case apply to the present case also.

12. The workman was made to retire from service. On his attaining the age of retirement. As such, he was not retrenched from the Bank's service. The different issues framed above are found as mentioned above.

13. In the result, I find that the action of the bank management in retiring the said workman as on 31-12-1984 is quite just, legal and proper. The following Award is therefore passed :

AWARD PART-II

The action of the management of Bank of Baroda in relation to its Central Office, Bombay in retiring Shri Kallappa Kotian on 31-12-1984 is just, proper and legal.

The parties to bear their own costs of this reference.

P. D. APSHANKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली 21 मई, 1992

का. आ. 1631.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, बैंक आफ महाराष्ट्र के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-5-92 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल—12011/24/89-डी-2 (ए)]

वी. के. वेणुगोपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st May, 1992

S.O. 1631.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank of Maharashtra and their workmen, which was received by the Central Government on 8-5-1992.

[No. L-12011/24/89-D.II A)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, AT BOMBAY

PRESENT :

Shri P. D. Apshankar, Presiding Officer.

Reference No. CGIT. 2/41 of 1989

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bank of Maharashtra,

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employer—Mr. R. M. Samudra—Management Representative.

For the Workmen—Mr. Vinayak Karmarkar, General Secretary, Bank of Maharashtra Karamchari Sangh.

INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 13th April, 1992

AWARD

1. The Central Government by their Order No. L-12011/24/89-D.II (A) dated 22-9-1989 have referred the following Industrial Dispute to this Hon'ble Court for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

"Whether the action of the management of Bank of Maharashtra in relation to its Bajirao Road branch and Deputy Manager's Office, Pune, in not assigning Special Assistants Post to Shri V. K. Shaligram and Shri Vilas Kulkarni, Bajirao Road branch and Deputy General Manager's Office respectively, as per the settlement signed between All India Bank of Maharashtra Employees Federation and the employer on 24-3-1983, is justified ? If not, to what relief the workmen are entitled ?"

2. The case of the Bank of Maharashtra Karamchari Sangh as disclosed from the statement of claim (Ex. W/2) filed by its General Secretary, in short, is thus :

"The service conditions of the workmen are governed by various Awards and Bipartite settlements. The post of the Special Assistant is an allowance-carrying post. The settlement dated 24-8-1983 was entered into between the Bank of Maharashtra Employees' Federation and the Bank management Clause No. 7 of that settlement stated that, "The post of Special Assistant shall be filled in accordance with the aggregate marks obtained by the eligible candidate under the head of service and qualifications".

The allotment of marks shall be as under :

(a) One mark for each completed year of service.

(b) Two marks for the Educational qualification of graduation.

In case the two workmen get the same number of marks, then the workman who had joined the services earlier shall be selected for the post of the Special Assistant.

3. The Clause No. 15 of that settlement provides for the Groupwise Seniority. It stated thus :

"The groupwise seniority list of candidates who have put in minimum of 5 years service, as well as who have secured minimum 7 marks, as on 31st December of the year, shall be circulated amongst the staff members every years."

4. Clause 18 of that settlement stated that ;

"The vacancies of Special Assistant arising out of promotion|retirement|death|termination|resignation etc. shall be filled in as per groupwise seniority."

5. As provided in clause 15 of the said settlement, the Bank prepared and circulated seniority lists as on 31st December 1983 and 31st December 1984. However, the bank did not thereafter prepare and did not circulate the seniority lists of 31st December, 1985 and on 31st December, 1986, revising the list by taking into consideration the service and qualifications attained by the employees during those two years. In view of the provisions contained in clause 15 of the said settlement, the bank should have prepared and should have circulated the seniority lists as on 31-12-1985 and 31-12-1986, after taking into consideration the qualifications earned by the workmen. The vacancies created during the years 1986 and 1987 because of the promotion|retirement|death|termination|resignation etc. were filled in by the bank by allotting those posts to the employees appearing senior as per seniority list prepared on 31-12-1984 only. As such the bank management has committed a breach of the provisions contained in clauses 15 and 18 of the said settlement.

6. The two workmen in question viz. Shri V. K. Shaligram and Vilas Kulkarni, working as clerks, passed their degree examination and became graduates in June, 1986. As such, as per the clause 7 of the said settlement, both of them became entitled to get two marks for their graduation, in addition to their marks for completed years of their service as on 31-12-1986. However, no seniority list as on 31-12-1986 was prepared by the bank, and as such, the said qualifications of the two workmen were not taken into consideration by the bank. In case the Bank had prepared the seniority list as on 31-12-1986, the said workman Shri V. K. Shaligram and Shri Vilas Kulkarni, after having got the necessary more marks, would have appeared at the top in the seniority list. In the year 1987 three vacancies of the posts of special assistants arose, but they were wrongly allotted to some other employees, viz. Shri A. S. Dandekar, S. K. Kshire, and S. P. Paranjape, who were junior to the said two workmen in question, viz. Shri V. K. Shaligram and Shri Vilas Kulkarni. The workman in question Shri V. K. Shaligram had entered into the service of the bank in 1968, and the other workman Shri Vilas Kulkarni had entered into service in September, 1969, while the other three workmen, viz. Shri A. S. Dandekar, S. K. Kshire and S. P. Paranjape joined the service in the bank in October, 1969. As such, the said two workmen Shri V. K. Shaligram and Vilas Kulkarni are senior in services to the other three workmen. Even then the posts of Special Assistant were allotted, wrongly to those three workmen to which, in fact and in law, the said two workmen Shri Shaligram and Vilas Kulkarni were entitled. The posts of special assistants were offered to those 3 other workmen in January, June, and

August, 1987. The allowance for the post of special assistant was Rs. 456 per month till October, 1987, and thereafter it was increased to Rs. 524 per month. The two workmen in question, viz. Shri V. K. Shaligram and Shri Vilas Kulkarni were offered the posts of special assistant with effect from 1-5-1988, as per the latest settlement dated 4-5-1988. As such the two workmen in question have suffered the monetary loss as they were not allotted the posts of special assistants at the time they were allotted to those other three workmen. As such, the action of the Bank Management in question is unjust and illegal, and in breach of the settlement dated 24-8-1983. The Union, therefore, lastly prayed that this Tribunal should hold the action of the bank management in question as unjust and illegal, and should direct the management to pay the allowance of the posts of special assistant to the two workmen in question viz. V. K. Shaligram and Vilas Kulkarni with effect from the dates they were allotted to the said other three workmen ,and the two workmen in question should be deemed to be holding the said posts from the dates those posts were allotted to those three other workmen.

7. The Deputy General Manager (Personnel) of the Bank of Maharashtra, Pune by his Written Statement in (Ex-M. 3 opposed the said claim of the union and in substance contended thus :

The two workmen in question are not the members of the said Union, nor have they authorised that union to espouse their cause on their behalf. As such, the present union is not competent to espouse the cause in question. The two workmen in question have been allotted the posts of special assistants with effect from 1-5-1988, i.e. during the conciliation of proceedings before the Assistant labour Commissiontr (Central) Poona. After the said settlement dated 24-8-1983 was entered into, a fresh settlement dated 17-9-1984 was entered into between the Bank and the Federation of the workmen. That settlement dated 17-9-1984 provided that the post of special assistant shall be filled in on the basis of the suitability determined by the process of interview. Therefore the said two settlements dated 24-8-1983 and 17-9-1984 existed when the posts of special assistant were to be allotted to the workmen during certain period. Thereafter, after holding discussions with the union, a further agreement dated 4-5-1988 was entered into between the bank management and the union. It was recorded in the agreement dated 4-5-1988 that the earlier settlement dated 24-8-1983 had expired on 24-8-1986 i.e. after a period of 3 years The present union in question was not a party to the settlement dated 24-8-1983 or to the settlement dated 17-9-1984. As the agreement dated 24-8-1983 had expired on 24-8-1983 or to the settlement dated 17-9-1984. not be prepared on the basis of the agreement dated 24-8-1983. It is not true than the posts of the special assistants were offered to the workmen junior to the workmen in question. Those posts in 1987 were allotted on the basis of the seniority list as on 31-12 1984. As the agreement dated 24-8-1983 had expired on 23-8-1986 the alleged seniority of two workmen in question on the basis of having passed the degree examination, was not available with them, when they were allotted the posts of special assistants. The two workmen in question were allotted the posts of special assistants as per their entitlement as per the provisions of the agreement dated 4-5-1988. The said two workmen in question were not entitled to those posts fro mthe date they were alloted to the other three workmen. The bank management, therefore, lastly prayed that this Tribunal should uphold the action the Branch Manager in question as just, propet, and legal, and should reject the prayer of the union

8. The Issues framed at Ex. 4 are :

(1) Whether the Bank of Maharashtra Karamchari Sangh is duly authorised to espouse the cause in question on behalf of the two workmen Shri V. K. Shaligram and Vilas Kulkarni.

(2) Whether in view of the agreement dated 4-5-1988, the settlement dated 24-8-1983 ceased to be operative from 24-8-1986 ?

(3) Whether the Bank management has violated the provisions of clauses 15 and 18 of the settlement dated 24-8-1983 ?

(4) Whether the posts of Special Assistants were wrongly allotted by the Bank to Shri A. S Dandekar, S. K. Kshire and S. P. Paranjpe in 1987, who were juniors to Shri V. K. Shaligram and Vilas Kulkarni ?

(5) Whether the Bank should have allotted those posts to Shri V. K. Shaligram and Vilas Kulkarni on the dates they were allotted to the said three employees ?

(6) Whether the said two employees are entitled to the allowance of Special Assistants' posts from the the dates they were allotted to the said three employees ?

(7) Whether the action of the management of Bank of Maharashtra in relation to its Bajirao Road branch and Dy. General Manager's Office Pune in not assigning special assistants' posts to Shri V. K. Shaligram and Shri Vilas Kulkarni, Bajirao Road Branch and Deputy General Manager's Office respectively as per the settlement signed between All India Bank of Maharashtra Employees Federation and the employer on 24-8-1983 is justified ?

(8) If not, what relief the workmen are entitled to ?
(9) What Award ?

9. My findings in the said Issues are :
(1) Yes.
(2) No.
(3) Yes.
(4) Yes.
(5) Yes.
(6) Yes.
(7) No.
(8) As per Award below ;
(9) As per Award below ;

REASONS

ISSUE No. 1

1. No oral evidence was led on behalf of either of the parties. Both the parties relied upon the different documents produced before this Tribunal. According to the Bank Management, the Bank of Maharashtra Karamchari Sangh, the union in question, is not duly authorised to espouse the cause in question on behalf of the two workmen Shri V. K. Shaligram and Shri Vilas Kulkarni. According to the Bank Management, these two workmen have now already been assigned the posts of Special Assistants with effect from 1-5-1988, that they accepted these posts un-conditionally, and there is no dispute in the matter, and as such the present union cannot espouse the cause on their behalf in the matter. However, I find that the present union is quite competent to raise the Industrial Dispute in question. Admittedly the union in question is a registered trade union, registered under the Trade Unions Act. 1926. Further, according to that Union, the two workmen in question are the members of the union. As per Section 2(k) of the Industrial Disputes Act, an 'industrial dispute' means a dispute or difference between the employers and the workmen connected with the employment or non-employment or the terms of employment or with the conditions of labour of any person. Therefore, eventhough the abovesaid two workmen in question might not be the parties to the present proceeding, still the union in question can raise the industrial dispute, concerning any person, i.e. concerning the present two workmen also, in connection with the terms of their employment or with the conditions of Labour. Even though the said two workmen did not protests against the assignment of the posts of special assistants assigned to them at a later date, the union is quite competent and is entitled to point out the mistake committed by the Bank Management, with a view to see that no such mistake would take place in future, and no injustice would be done to any other em-

ployees in future. The two workmen in question accepted the said posts unconditionally and without protest as they were interested in getting those posts of Special Allowance, and otherwise they would not have got those posts immediately. Hence they did not protest against the action of the Bank Management in question. According to the present union, it had espoused the cause in question before the Assistant Labour Commissioner during the conciliation proceedings, and at that time the Bank Management had not raised any objection regarding its competance or authority to espouse the cause in question. Taking into consideration all these aspects of the matter I find that the present Union is quite competent to espouse the cause in question on behalf of the said workmen.

Issues No. 1 is therefore found in the affirmative.

ISSUES No. 2

11. According to the Bank Management, in view of the agreement dated 4-5-1988, the earlier settlement dated 24-8-1983 ceased to be operative from 24-8-1986. I find that this contention of the Bank Management is not correct, and that the earlier settlement of 1983 did not cease to be operative with effect from 24-8-1986, but continued till the execution of the new agreement dated 4-5-1988. Claure 19 of the agreement dated 24-8-1983 (Ex. W/8) stated that this agreement shall be in operation for a period of 3 years from the date it is signed by the parties and shall continue to be binding on the parties upto the expiry of the period aforesaid and until the expiry of two months from the date on which a notice in writing of an intention to terminate the settlement is given by one of the parties to the other party or parties of that settlement. Therefore as per the contents of clause 19 of the agreement of 1983 (Ex. W/8), it did not automatically become in operative after the expiry of the period of 3 years, i.e. on 23-8-1983, but it continued for the further period. There is no documentary evidence on record to show that the notice was given by either of the parties after the expiry of the period of 3 years, i.e. in August , 1986 or thereafter, of the intention to terminate that settlement. Therefore that agreement dated 24-8-1983 continued after 24-8-986 till the fresh agreement was executed on 4-5-1988 (Ex. 10). The opening portion of that settlement dated 4-5-1988 states that the Special Assistant agreement dated 24-8-1983 expired on 23-8-1986. However that statement is not valid and legal, and as such, it cannot be accepted in law. Para 20 of the settlement of 4-5-1988 states that this agreement dated 4-5 1988 supersedes the earlier two agreements dated 24-8-1983 and 14-6-1984. Therefore, it is quite clear from this para 20 that the earlier agreements dated 24-8-1983 did not become inoperative on 24-8-1986, but continued upto the execution of the new settlement dated 4-5-1988. Therefore the agreement dated 24-8-1983 (Ex 8) was operative and was in force when the said posts of Special Assistants were offered to the other three workmen in 1987 and when the two workmen in question were deprived of those posts.

Issue No. 2 is, therefore, found in the negative.

ISSUE NO. 3.

12. According to the union, the bank management has violated the provisions of clauses 15 and 18 of the agreement dated 24-8-1983. The clause 15 of that agreement states that the groupwise seniority list of candidates who have put in minimum service of 5 years and have secured minimum 7 marks as on 31st of December of the year shall be circulated amongst the staff members every year. Therefore, the groupwise seniority list of the necessary eligible candidates is to be circulated every year as on 31st December of the year. In the present case, the Bank Management has circulated those groupwise seniority lists as on 31-12-1983 and on 31-12-1984. However, the Bank Management did not prepare and did not circulate the groupwise seniority list as on 31-12-1985 and on 31-12-1986, and it was thereafter circulated on 31-12-1987. Clause 18 of the said agreement dated 24-8-1983 states that the vacancies of Special Assistants arising out of promotion/retirement/death etc. shall be filled in as per the groupwise seniority. Therefore, as no groupwise seniority lists as on 13-12-1985 and on 31-12-1986 were prepared and circulated, admittedly the vacancies of Special Asistant, including those in respect of the other three junior employees, were filled in on the basis of the seniority list prepared on 31-12-1984. Therefore the Bank Management has committed a breach of the provisions contained in clauses 15 and 18 of the agreement dated 24-8-1983.

Issue No. 3 is therefore, found in the affirmative.

ISSUE NO. 4.

13. According to the union, the posts of Special Assistants were wrongly allotted by the bank to Shri A. S. Dandekar, Shri S. K. Kshire, and Shri S. P. Paranjape in 1983, who were junior to the two workmen in question, viz. Shri V. K. Shaligram and Shri Vilas Kulkarni. I find that it was so. According to the union, the two workmen in question viz. Shri Shaligram and Shri Vilas Kulkarni passed the degree examination and became graduates in June, 1985, Clause 7 of the agreement dated 24-8-1983 (Ex. W/8) states that the post of Special Assistant shall be filled in in accordance with the aggregate marks obtained by the eligible candidates under the head of service and qualifications. The allotment of marks shall be as under :

(a) On mark for each completed year of service.

(b) Two marks for the Educational qualification of graduation.

In case the two candidates secure equal number of marks, the candidate who had joined the bank services earlier shall be selected for the post of the Special Assistant. According to the union, the two workmen in question viz. Shri V. K. Shaligram and Shri Vilas Kulkarni passed the degree examination in June, 1986. As such, they were entitled to two marks more, in addition to their other marks. However the groupwise seniority list was not prepared as on 31-12-1986, and as such, the fact that the two workmen got the additional marks was not taken into consideration, when the other three workmen were allotted the posts of Special Assistants in 1987, as those 3 other employees were assigned those posts on the basis of the seniority list as on 31-12-1984 only. Further, while the workman Shri V. K. Shaligram had joined the Bank's service in 1968, and the other workman Shri V. Kulkarni had entered into service in Setember, 1969, and other three employees had joined the service in October, 1969. As such the two workmen in question viz. Shri Shaligram and Shri Vilas Kulkarni were and are admittedly senior in service to the other three employees mentioned above. As noted above, the two workmen in question had passed their degree examination in June, 1986, and as such had got 2 marks more, and as those 2 workmen were senior in service to the other three workmen, the two workmen in question were certainly entiled to the posts of their Special Assistants, when they were allotted to the other three workmen in 1987. Therefore, the posts of Special Assistants were wrongly allotted by the Bank to Shri A. S. Dandekar, S. K. Kshire and Shri S. P. Paranjae in 1987, who were juniors to the two workmen in question, viz. Shri V. K. Shaligram and Shri Vilas Kulkarni.

Issue No. 4 is therefore found in the affirmative.

ISSUE NO. 5.

14. Therefore for the above said reasons, the two workmen in question should have been allotted the said posts when they were allotted to the other three employees mentioned above, as the two workmen in question were entitled to those posts then.

Issue No. 5 is therefore found in the affirmative.

ISSUE No. 6.

15 As such, the two workmen in question are entiled to the allowance of the posts of Special Assistant from the dates those posts were allotted to the said three employees.

Issue No. 6 is found in the affirmative.

ISSUE No. 7.

16. Therefore, for the reasons mentioned above, the action of the Bank Management in not assigning the posts of Special Assistant to Shri Shaligram and to Shri V. Kulkarni, as per the settlement dated 24-8-1983, is not just and proper.

Issue No. 7 is therefore found in the negative.

ISSUE NO. 8.

17. The two workmen in question are therefore entiled to the posts of Special Assistant from the dates they were offered to the other three workmen, who were junior to them then, and are entitled to the allowance of those posts from those dates

Issue No. 8 is found accordingly.

18. The following Award is therefore passed.

AWARD

The action of the Bank Management of Bank of Maharashtra in relation to its Bajirao Road branch and Deputy Managers Office, Pune, in not assigning Special Assistants post to Shri V. K. Shaligram and Shri Vilas Kulkarni, Bajirao Road branch and Deputy General Manager's office respectively, as per the settlement signed between All India Bank of Maharashtra Employees Federation and the employer on 24-9-1983, is not just and proper.

The Bank Management is hereby directed to pay the allowance of the post of Special Assistant to the said two workmen due from the dates they were assigned to the other three employees, and the two workmen in question shall be deemed to have been allotted the said posts from the dates they were allotted to the other two employees

The parties to bear their own costs of this Reference.

Sd/-

P. D. APSHANKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 मई, 1992

का. आ. 1632.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-5-92 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल—12012/321/89—डी-2 (ए)]

वी. के. वेणुगोपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th May, 1992

S.O. 1632.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Indian Overseas Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 26-5-92.

[No. L-12012/321/89-D.II(A)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 24/90

केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या : एल-12012/321/89—डी2(ए) दि. 21-3-90

राजकुमार द्वारा रीजनल सैक्रेटरी एन. सी. बोर्ड 9/565 राजेन्द्रपुरा, अजमेर ।

बनाम

जोनल मैनेजर, इंडियन ओवरसीज बैंक, रचना बिल्डिंग, 2 राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली ।

उपस्थिति

माननीय न्यायाधीश श्री जगत सिंह, आर. एच. जे. एस.

श्रमिक पक्ष की ओर से : श्री जे. एल. शाह ।

नियोजक पक्ष की ओर से : कोई हाजिर नहीं ।

दिनांक अवार्ड : 12-3-92

अवार्ड

केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित विवाद इस न्यायालय को वास्ते अधिनिर्णय हेतु अपनी अधिसूचना संख्या : एल. 12012/321/89—डी-2(ए) दि. 21-3-90 के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा -10(1)(घ) के अंतर्गत प्रेषित किया है—

"Whether the action of the management of Indian Overseas Bank in terminating the services of Shri Raj Kumar S/o Sh. Hukam Chand, Temporary Messanger, Ajmer Branch of the Bank is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. प्रार्थी राजकुमार, जिसे तत्पश्चात श्रमिक सम्बोधित किया है, ने जरिए क्लेम प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 1 ने संदेश वाहकों के रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु नियोजन कार्यालय से नाम मांगे थे, अन्य व्यक्तियों के साथ श्रमिक का नाम भी भेजा गया था जो अनुसूचित जाति का है और नियोजक ने साक्षात्कार के उपरांत श्रमिक को भी अपने पत्र दिनांक 30-5-85 द्वारा चयनित व्यक्ति के पैनल में रखा । तथा दिनांक 1-6-85 से 450 रु. प्रतिमाह मूल वतन एवं नियमानुसार देय महंगाई भत्ते व मकान किराए भत्ते पर नियुक्ति की गई । श्रमिक के साथ सर्व श्री सुनील व रमेश को भी अस्थाई संदेश वाहक नियुक्त किया गया था । श्रमिक कहता है हालांकि वह भी सर्व श्री सुनील व रमेश की तरह चयनित था परन्तु उसके साथ भेदभाव किया गया और उपरोक्त दो व्यक्तियों को तो लगातार नियोजन में रखा गया जबकि श्रमिक की सेवायें कई बार बिना युक्तियुक्त कारण के सेवायें समाप्त कर दी । यह भी कहा है कि तत्पश्चात सर्व श्री सुनील व रमेश को तो बैंक सेवा में स्थाई कर दिया और श्रमिक की फरवरी 88 में अनधिकृत तरीके से सेवा समाप्त कर दी ।

3. श्रमिक कहता है उसे दिनांक 1-6-85 से जनवरी 88 तक नियोजन में रखा गया था तथा फरवरी 88 में उसकी सेवायें गलत तरीके से दुर्भावनापूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई । सेवा समाप्ति से पूर्व उसे न तो नोटिस दिया न ही नोटिस अवधि की एवज में वेतन का भुगतान किया और इस प्रकार धारा 25 एफ, जी, एच एवं 25 एन के प्रावधानों के उल्लंघन किये है । इसलिए सेवा मुक्ति अपास्त करते हुए उसे वेतन सेवा में लिया जाए ।

4. अप्रार्थी सं. 2 ने जरिए प्रतिउत्तर प्रकट किया कि राजकुमार की सेवायें अजमेर शाखा में जून 85 के उपरांत से अस्थाई रूप में अनेक तारीखों को ली गई थी परन्तु कभी भी 90 दिवस लगातार उसकी सेवा नहीं ली गई और इस प्रकार उससे सेवा मुक्ति के पूर्व किसी 12 माह में 240 दिवस लगातार सेवा नहीं की है और धारा 25एफ के लाभ का अधिकारी नहीं है । सेवा शर्तों के अनुसार श्रमिक अस्थाई

था इसलिए बिना कारण बताए उसकी सेवा समाप्त की जा सकती थी अस्थाई संदेश वाहकों का पैनल बनाने का उद्देश्य यह था कि स्थाई श्रमिकों के अवकाश पर जाने के कारण उनकी जगह अस्थाई व्यक्ति की आवश्यकता थी । श्रमिक को जून 85 से जनवरी 88 तक की अवधि में उक्त पैनल में रखा गया था परन्तु उक्त अवधि में भी जब कभी स्थाई संदेश वाहक अवकाश पर था तभी उसकी सेवायें ली गई थी। यह भी कहा है कि श्रमिक का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक नहीं था जब कभी उसकी सेवाओं की आवश्यकता हुई वह उपलब्ध नहीं हुआ तथा सेवारत होते हुए भी श्रमिम अनेकों बार कार्यालय अवधि समाप्त होने के पूर्व ही शाखा छोड़कर चला जाता था जिसके लिए भी न तो कभी अपने उच्च अधिकारी को सूचित किया और न ही उनकी अनुमति ली और इसी कारण से जनवरी 88 के उपरांत से उसकी सेवायें नहीं ली गई ।

5. दिनांक 30-5-91 को विपक्षी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ तत्पश्चात भी 3-8-91 और 17-9-91 को भी विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ फलस्वरूप श्रमिक ने एक पक्षीय साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर सत्यापित कराया । आज दिन तक भी नियोजक की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया इसलिए मैंने पत्रावली का निरीक्षण किया और श्रमिक प्रतिनिधि को विस्तारपूर्वक सुना ।

6. अपने क्लेम को साबित करते हुए श्रमिक राजकुमार ने अपने शपथ पत्र में भी दर्ज किया है कि उसकी नियुक्ति साक्षात्कार के उपरांत की गई थी तथा उसका नाम भी नियोजन कार्यालय से भेजा गया था और उसने एविज. डब्ल्यू-2 द्वारा 1-6-85 से ज्यूटी ज्वाइन कर ली थी और कार्य करने लग गया था उसका मूल वेतन 459 रु. प्रतिमाह था जिस पर महंगाई भत्ता व अन्य सुविधायें भी दी गई श्रमिक कहता है कि हालांकि उसका कार्य स्थाई प्रकृति का था लेकिन फिर भी नियोजक बीच बीच में जबरन ब्रेक दे देते थे और पुनः वापिस उसी कार्य पर रख लेते थे । उसे कभी कोई पत्र या चेतावनी नहीं दी गई और अनुसूचित जाति होने के नाते उसके साथ भेदभाव किया गया तथा उसे स्थाई नहीं किया गया जबकि उसके दो साथी सर्वश्री सुनील व रमेश को स्थाई कर दिया गया । श्रमिक यह भी कहता है कि फरवरी 88 के बाद मौखिक आदेश द्वारा उसे सेवा मुक्त कर दिया गया । श्रमिक के अनुसार उसने जून 85 से फरवरी 88 तक लगातार विपक्षी बैंक में कार्य किया था और 12 माह में साप्ताहिक अवकाश, त्यौहारों व राष्ट्रीय अवकाशों को मिलाकर 240 दिवस से अधिक सेवा की है। उपस्थिति पंजिका में भी उसकी हाजरी होती थी । श्रमिक कहता है उसने डब्ल्यू-4 नोटिस वकील के मार्फत नियोजक को भेजा था जिसका भी उत्तर नहीं दिया गया । उक्त साक्ष्य के विपरीत नियोजक की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है और इकतरफा कार्यवाही हो रही है । श्रमिक के मौखिक कथनों की पुष्टि नोटिस डब्ल्यू-4 से होती है जिसमें उसने दिए गए प्रत्येक माह वेतन का भी उल्लेख किया है इसलिए अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित है कि सेवा समाप्ति से पूर्व 12 माह में श्रमिक ने 240 दिवस सेवा पूरी कर ली थी । यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 1-6-85 से फरवरी 88 तक श्रमिक ने सेवा की है । चाहे श्रमिक को बीच में ब्रेक दे दिया गया हो परन्तु B. R. oil mills Bharatpur v/s B. R. Oil Majdoor Komar S.B. civil writ patition No. 889/81—निर्णय दिनांक 10-11-81 न्यायदृष्टान्त के अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा-25बी के अनुसार श्रमिक के द्वारा किया गया कार्य एक वर्ष लगातार सेवा की परिभाषा में आता है और इसलिए भी वह धारा 25एफ के प्रावधानों के लाभ का अधिकारी होता है ।

7. क्लेम में श्रमिक ने यह भी कहा है कि सर्व श्री सुनील व रमेश उससे कनिष्ट थे जिन्हें सेवा मुक्त नहीं किया गया । अपने शपथ पत्र में भी राजकुमार कहता है कि उससे कनिष्ठ सर्वश्री सुनील व रमेश को सेवा मुक्त नहीं किया गया है इस प्रकार नियोजक द्वारा धारा 25जी के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया है । अतः निर्विवाद रूप से नियोजक द्वारा श्रमिक को एक माह का नोटिस नहीं दिया न ही उसकी एवज में एक माह का वेतन दिया गया यहां तक कि छंटनी का मुआवजा भी नहीं दिया गया इसलिए नियोजक द्वारा की गई सेवा मुक्ति धारा 25एफ के प्रावधानों के विपरीत होने से स्वतः ही अवैध एवं शून्य हो जाती है । और श्रमिक सेवा में ही लगातार माना जाएगा। तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्नप्रकार से किया जाता है —

श्रमिक राजकुमार अस्थाई संदेश वाहक अजमेर शाखा की सेवा मुक्ति उचित एवं वैध नहीं है और इसे उक्त पद पर नियोजित मानते हुए पिछला बकाया वेतन व अन्य सभी लाभ दिलाए जाते है । इसकी सेवा की निरन्तरता कायम रहेगी ।

अगर नियोजक उक्त राशि अंदर तीन माह में अदा नहीं करेगा तो 12 प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष उक्त राशि पर नियोजक श्रमिक को अदा करेगा। उक्त आशय का अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को अंतर्गत धारा 17(1) अधिनियम प्रकाशनार्थ भेजा जाए ।

जगत सिंह, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 26-5-1992

का.आ. 1633:— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूनाईटिड कर्मिशयल बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-5-92 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्यां एल-12012/27/89-डी-2 (ए)]
बी. के. वेणुगोपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th May, 1992

S.O. 1633.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of United Commercial Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 26-5-92.

[No. L-12012/27/89-D.II(A)]
V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर ।

केस न. सी.आई.टी. 81/1989

रैफरैंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल. 12012/27/89-डी-2 (ए) दिनांक 8-8-89

श्री राम प्रकाश प्रजापति पुत्र श्री रघुनाथ प्रजापित ग्राम पोस्ट गोटन, जिला नागौर, राजस्थान ।

प्रार्थी

बनाम

क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूनाईटेड कार्मिशयल बैंक लि.ए. 30 (बी) शास्त्री नगर, जयपुर ।

अप्रार्थी

उपस्थिति

माननीय न्यायाधीश श्री जगतसिंह आर.एच.जे.एस.
प्रार्थी की ओर से : श्री जे.एल. शाह
अप्रार्थी की ओर से : श्री मानसिंह गुप्ता
दिनांक अवार्ड : 30-3-1992

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपनी उपरोक्त अधिसूचना द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 (1) (घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया हैं ।

"Whether the action of the management of UCO Bank in terminating the services of Shri R. P. Prajapat and not considering him for further employment while recruiting fresh hands under Section 25H of the ID Act is justified ?"

2. श्री राम प्रकाश प्रजापित, जिसे तत्पश्चात् श्रमिक संबोधित किया है, ने जरिये क्लेम प्रकट किया कि उसकी प्रथम नियुक्ति 6-6-86 को विपक्षी बैंक की गोटन शाखा में पीओन के पद पर 8/- रुपये प्रति दिन की दर से की गई थी । उसकी ड्यूटी प्रातः 9.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक होती थी । शनिवार को सुबह 9 30 से दोपहर 2 बजे तक होती थी । उसका कार्य संतोषप्रद था इसलिए 10-9-86 से उसका वेतन बढ़ाकर 10/- रुपये और 1-1-87 से 12/- रुपये प्रतिदिन कर दिया गया । श्रमिक कहता है उसने 6-6-86 से 18-3-88 तक लगातार बैंक की गोटन शाखा में कार्य किया है तथा उक्त अवधि के वेतन का भुगतान भी उसे वाउचर द्वारा किया जा चुका है । उपरोक्त अवधि में रविवार साप्ताहिकी अवकाश या दिन, राष्ट्रीय अवकाश व त्यौहारों का उसे वेतन नहीं दिया गया है और न ही हाजरी लगाई गई है । श्रमिक कहता है 19-3-88 को उसे मौखिक आदेश से सेवा मुक्त कर दिया । सेवा मुक्ति से पूर्व समाप्त हुए एक कलैण्डर वर्ष में उसने 240 दिवस से अधिक सेवा पूरी कर ली थी फिर भी उसे न तो एक माह का नोटिस या नोटिस के एवज में एक माह का वेतन दिया यहा तक कि छंटनी का भत्ता भी नहीं दिया गया इस प्रकार धारा 25-एफ के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना हुई है फलस्वरूप सेवा मुक्ति स्वतः ही अवैध, प्रभावहीन व शून्य हो गई है। श्रमिक यह भी कहता कि सेवा मुक्त करने के बाद नई नियुक्तियां भी पीओन के पद पर की गई हैं जिसकी सूचना उसे नहीं दी गई इसलिए धारा 25-एच की भी अवहेलना हुई है । इसलिए सेवा मुक्ति को अवैध एवं अनुचित घोषित करते हुए उसे सवेतन सेवा में लिया जावे ।

3. अप्रार्थी बैंक ने जरिये प्रत्युत्तर श्रमिक के कथनों को अस्वीकार किया है और कहा है कि बैंक की शाखाओं में जहां नियमित कार्य नहीं होता है और जहां केवल घंटे आधा घंटे या डेढ़ घंटे बैंक में विविध कार्य करने के लिए कार्य होता है वहां शुद्ध रूप से लगभग आवश्यकतानुसार घंटे-डेढ़ घंटे के लिए अंशकालीन आकस्मिक आधार पर ही श्रमिक राम प्रकाश को विविध कार्य करने के लिए लगाया गया था । उसकी हाजिरी रजिस्टर में अपस्थिति नही होती थी, उसके वेतन का भुगतान भी मेजेरी अकाउन्टस से नहीं होता था बल्कि वाउचर पर हाजिरी होती थी और विविध खाते से ही उसे वेतन का भुगतान किया जाता था इसलिए प्रार्थी श्रमिक की परिभाषा में नहीं आता है उसको केवल अंशकालीन रूप में जब कभी आकस्मिक कार्य की आवश्यकता होती थी लगा दिया जाता था । पूर्ण समय उससे कभी भी कार्य नहीं लिया गया इसलिए सेवा मुक्ति अवैध नहीं है । नियोजक के अनुसार 6-6-86 से 18-3-88 तक श्रमिक ने लगातार कार्य नहीं किया । जून 1986 से मई 1987 तक 295 दिन या 18-3-87 से मार्च 88 तक 264 दिन भी कार्य नहीं किया । श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश, अथवा राष्ट्रीय अवकाश या त्योहारों का लाभ देय नहीं है । इसलिए उसने एक वर्ष में 240 दिवस भी कार्य नहीं किया है तथा धारा 25-एफ के के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । सेवा मुक्ति के उपरांत भी अन्य किसी व्यक्ति को पीओन के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है इसलिए धारा 25-एच की भी अवहेलना नहीं की गई है ।

4. अपने कथनों के समर्थन में श्रमिक ओम प्रकाश प्रजापित ने स्वयं का शपथ पत्र पेश कर सत्यापित कराया जिससे नियोजक प्रतिनिधि ने जिरह की । इसके विपरीत नियोजक की तरफ से श्री गोपी चन्द ने शपथ पत्र पेश किया जिससे श्रमिक प्रतिनिधि ने जिरह की । तत्पश्चात मैंने पक्षावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों की विस्तारपूर्वक सुना

5. क्लेम के प्रत्युत्तर में तो नियोजक का कथन है कि आंशिक रुप से कार्य होने पर ही घंटे-डेढ़ घंटे के लिए श्रमिक को नियोजित किया जाता था । परंतु नियोजक साक्षी श्री गोपी चंद का कहना है कि उसने कभी गोदन शाखा में कार्य नहीं किया उसे तो रिकार्ड से ही जानकारी है । पेमेंट वाउचर पर चार घंटे काम करने का उल्लेख हो तो उसे पता नहीं । साक्षी कहता है उसे यह भी पता नहीं कि कितने बजे से कितने बजे तक उससे काम करवाया था । तत्कालीन शाखा प्रबन्धक श्री गुप्ता थे, जिनका स्थानान्तरण हो गया है । नियोजक के साक्षी श्री गोपीचंद के अपुष्ट कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि क्लेम के प्रत्युत्तर में तो घंटे-डेढ़ घंटे ही काम लेने का उल्लेख है जबकि इस साक्षी ने अपने शपथ पत्र में 3-4 घंटे ही प्रति दिवस कार्य लेने का उल्लेख किया है । साक्षी यह स्वीकार करता है कि वह गोदन शाखा में कभी नियोजित नहीं रहता है उसे तो केवल रिकार्ड से ही जानकारी है परंतु पेमेंट वाउचर पर 3-4 घंटे प्रति दिवस कार्य लेने का उल्लेख नहीं है न ही पैमेंट वाउचर अभिलेख पर पेश किये गये हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि इस साक्षी ने अंशकालीन काम लेने का उल्लेख अपने शपथ पत्र में मिथ्या किया है । अगर वास्तव में अंशकालीन काम ही किया गया होता तो श्रमिक के पैमेंट वाउचर पर इसका उल्लेख होता अथवा उसे इस विषय का लिखित आदेश भी दिया गया होता जब श्रमिक ने क्लेम के अनुसार शपथ पत्र में भी यह दर्ज कर दिया था कि वह प्रातः 9.30 से सायं 5.30 बजे तक कार्य करता था तो नियोजक से यह अपेक्षा थी कि वे उक्त साक्ष्य में विपरीत अंशकालीन कार्य लेने बाबत प्रालेखिक अथवा विश्वसनीय मौखिक साक्ष्य पेश करता श्रमिक से भी प्रति परीक्षा में ऐसे सुझावात्मक प्रश्न नहीं किये गये हैं कि उससे 3-4 घंटे ही प्रत्येक दिवस कार्य लिया गया हो । न तो क्लेम के प्रत्युत्तर में और न ही नियोजक साक्षी गोपी चंद ने अपने शपथ पत्र में यह दर्ज किया है कि कितने बजे से कितने बजे तक श्रमिक से अंशकालीन कार्य लिया जाता था तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि श्रमिक अंशकालीन कर्मचारी था तो भी यशवन्त सिंह यादव बनाम राजस्थान राज्य 1989 (ii) एल.एल.एन. 1011 पर उपलब्ध न्यायापीठ के अनुसार पार्ट टाईम एम्पलाई भी अधिनियम की धारा 2 (एस) के अन्तर्गत कर्मकार की परिभाषा में आता है । इस विषय में उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टान्त ए.आई.आर. 1967 (एस.सी.) 884 तथा गोविन्द भाई बनाम एन.के. वेसाई 1988 लैब.आई.सी. 505 के न्याय दृष्टान्तों का भी उल्लेख किया जा सकता है । इस प्रकार प्रत्येक दृष्टिकोण से परखने पर नियोजक की प्राथमिक आपत्ति निराधार मानते हुए अपास्त की जाती है ।

6. जहां तक धारा 25-एफ के प्रावधानों का प्रश्न है क्लेम के अनुसार ही अपने शपथ पत्र में भी राम प्रकाश कहता है कि उसने 6-6-86 से 8-3-88 तक बैंक की गोदन शाखा में लगातार कार्य किया है । श्रमिक के अनुसार जून 1986 से मई 1987 तक 251 दिवस कार्य किया तथा जनवरी 1987 से दिसम्बर 1987 तक 248 दिन कार्य किया है । जनवरी 1988 में 28 दिवस, फरवरी में 23 दिन, मार्च 1988 1988 में 15 दिन कार्य किया है । उपरोक्त तथ्यों बाबत श्रमिक से विस्तारपूर्वक प्रति परीक्षा नहीं की गई है और न ही नियोजक साक्षी गोपीचंद ने अपने शपथ पत्र में उक्त तथ्यों का प्रतिवाद किया है बल्कि प्रति परीक्षा करने पर नियोजक साक्षी भी कहता है कि प्रदर्श एम-1 के मुताबकि ही उसने काम किया है । तत्पश्चात नियोजक साक्षी ने यह कहा है कि जून 1986 से मई 1987 तक 251 दिन होते होंगे । 1-1-88 से 8-2-88 के बीच 31 दिन काम करना स्वीकार किया है । यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श एम-1 नियोजक द्वारा ही प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार ही श्रमिक ने 6-5-86 से 31-12-87 तक 405 दिवस काम किया है । इसके बाद 1 जनवरी से 8 फरवरी 1988 तक काम करना नियोजक साक्षी स्वीकार करता है । इसलिए उपरोक्त प्रालेखिक एवं मौखिक साक्ष्य से यह साबित है कि सेवा मुक्ति को समाप्त हुए एक कलैण्डर वर्ष में श्रमिक ने 240 दिवस से अधिक की सेवा पूरी कर ली थी । निर्विवाद रुप से सेवा समाप्ति के समय धारा 25-एफ के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है इसलिए सेवा मुक्ति स्वतः ही अनुचित अवैध व शून्य हो गई है ।

7. क्लेम में श्रमिक ने यह दर्ज नहीं किया कि सेवा मुक्ति के उपरांत किसी व्यक्ति को कितने दिन के लिए नियोजित किया गया अपने शपथ पत्र में भी श्रमिक ने उक्त तथ्यों का समावेश नहीं किया गया है । नियोजक साक्षी गोपी चंद इस विषय में प्रति परीक्षा करने पर कहता है उसको हटाने के बाद इस वाला काल रैंगुलर व्यक्तियों ने किया था । इन परिस्थितियों में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित नहीं है कि सेवा मुक्ति के उपरांत दैनिक वेतन पर किसी व्यक्ति को पीओन के पद पर लगाया गया हो और धारा 25-एच की अवहेलना साबित नहीं है ।

8. तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार दिया जाता है :

श्रमिक राम प्रकाश प्रजापति को 18-3-88 से सेवा मुक्ति अनुचित एवं अवैध है और इसे दैनिक वेतन भोगी पीओन के पद पर नियोजित घोषित किया जाता है तथा उक्त पद का वेतन व अन्य सभी लाभ दिलाये जाते हैं । 100/– रुपये खर्चा मुदकमा भी दिलाया जाता है । अगर नियोजक उक्त राशि अंदर तीन माह अदा नहीं करेगा तो 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना पड़ेगा । "

9. अवार्ड की प्रति प्रकाशनार्थ भारत सरकार को अन्तर्गत धारा 17 (1) अधिनियम के पठाई जावे ।

श्री जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 26 मई, 1992

का. आ. 1634.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण,

जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/50/91-आई आर (बी-2)]
वी. के. वेणुगोपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th May, 1992

S.O 1634.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 22-5-92.

[No. L-12012/50/91-IR(B.II)]
V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 37/1991

रैफरैन्स : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल 12012/50/91 आई. आर. बी. 2/दिनांक 276-91

श्री जे. पी. आसोपा, कैशियर मार्फत महासचिव राजस्थान बैंक एम्पलाईज यूनियन, जोधपुर।

—प्रार्थी

बनाम

सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, जयपुर।

उपस्थित —अप्रार्थी

माननीय न्यायाधीश श्री जगत सिंह जी, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नहीं
अप्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नहीं
दिनांक अवार्ड : 5-12-91

अवार्ड

फरीकेन की ओर से कोई एहाजिर नहीं है। प्रार्थी यूनियन की ओर से आज क्लेम पेश करने हेतु यह प्रकरण निर्धारित था किन्तु ना ही कोई क्लेम पेश हुआ और नाही यूनियन की ओर से कोई उपस्थित आया। अतः प्रकरण में अदम पैरवी में डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को वास्ते प्रकाशन अन्तर्गत धारा 17(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 भेजा जावे।

जगत सिंह, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.आ. 1635.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि. की धनबाद कोलिअरी के प्रबन्धतंत्र के संबंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 2) धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/352/86-डी-3(ए)]
वी.के. वेणुगोपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1635.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, (No. 2), Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhatdih Colliery of M/s. B.C.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 21-5-92.

[No. L-20012/352/86-D.III(A)]
V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. Ram, Presiding Officer.

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

Reference No. 225 of 1987

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bhatdih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen—Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

On behalf of the employers—Shri R. S. Murthy, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 18th May, 1992

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(352)/86-D.III(A), dated, the 14th August, 1987.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bhatdih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Llimted, in denying regularisation as Trammer to Shri Ratan Napit and stopping him from work as Trammer with effect from 27-8-1985 is justified? If not, to what relief the workman is entitled and from what date?"

2. In this case both the parties appeared and filed their respective W.S. documents etc. Subsequently at the stage of oral evidence both the parties appeared before me and filed a Joint Compromise Petition. I heard both the parties on the said petition of compromise and do find that the terms contained therin are fair, proper and beneficial to both of them. Accordingly I accept the same and pass an Award in terms thereof which forms part of the Award as Annexure.

B. RAM, Presiding Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 225/87

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Bhatdih Colliery of Bharat Coking Coal Ltd.

AND

Their workmen

JOINT COMPROMISE PETITION OF THE EMPLOYERS AND WORKMEN

The above mentioned Employers and workmen most respectfully beg to submit jointly as follows :—

(1) That the Employers and the workmen have jointly negotiated the Dispute covered by the above Reference with a view to arriving at a mutually acceptable and amicable overall settlement.

(2) That as a result of such joint and mutual negotiations, the Employers and the workmen have jointly arrived at an agreement on the following terms :—

(a) It is agreed that Sri Ratan Napit, the workman concerned will be taken back in the employment of the Management as a Trammer without payment of any back wages but with continuity of service within 15 days from the date of acceptance of this Joint Compromise Petition by this Hon'ble Tribunal.

(b) It is agreed that the Management shall pay an amount of Rs. 20,000 (Rupees Tyenty thousands) only to the workman concerned to metigate his hardship on account of his continued unemployment for a period of 5 years or so.

(c) It is agreed that this is an overall settlement in full and final settlement of all the claims of the Sponsoring Union and the workman concerned arising out of the above Reference.

(3) That the Emplyoyers and the workmen consider and hereby declare that the above terms of settlemen are fair, just and reasonable to both the parties.

In view of the above, the Employers and the workmen jointly pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this Joint Compromise Petition and give an Award in terms thereof and dispose off the above Reference.

And for this, the Employers and the workmen shall ever remain grateful.

Sd/-
(B. Mohanty)
Secretary,
Bihar Colliery Kamgar Union.
for and on behalf of workman.

Sd/-
General Manager,
Mohuda Area,
Bharat Coking Coal Ltd.,
for and on behalf of Employers.
(Ral. S. Murthy),
Advocate,
for Employers.

नई दिल्ली, 28 मई, 1992

का.आ. 1636.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-17012/15/86-डी-4(ए)]
वी. के. वेणुगोपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th May, 1992

S.O. 1636.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Management of Life Insurance Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on 26-5-92.

[No. L-17012/15/86-D.IV(A)]
V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर
केस नं. सी आई.टी. 51/1987

रिफरेन्स : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल. 17012/15/86—डी 14 (ए) दिनांक 5-5-87

श्री त्रिलोक चन्द अग्रवाल पुत्र श्री गोपी किशन अग्रवाल नया बाजार, अजमेर।

—प्रार्थी

बनाम

खण्ड प्रबन्धक, खण्ड कार्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम, जीवन प्रकाश रामाडे मार्ग पो. बाक्स नं. 2 अजमेर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री जगत सिंह जी, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री बी. एल. समदरिया
अप्रार्थी की ओर से : श्री एम. डी. अग्रवाल
दिनांक अवार्ड : 10 मार्च, 1992

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (1) (घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है :

"क्या भारतीय जीवन बीमा निगम अजमेर की श्री टी. सी. अग्रवाल को 20-2-84 से सेवा से बरखास्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है। यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है।"

2. श्री टी. सी. अग्रवाल, जिसे तत्पश्चात् श्रमिक संबोधित किया है, ने क्लेम प्रकट किया कि उनकी नियुक्ति अप्रार्थी जीवनबीमा निगम, जिसे तत्पश्चात् निगम

संबोधित किया है, द्वारा चपरासी के पद पर 8-8-75 को 6 माह की परिवीक्षा पर की गई थी। उक्त पद पर उसे 12-2-76 को स्थाई भी कर दिया गया। श्रमिक कहता है उसे 31-3-83 और 17-5-83 की तारीखों के दो आरोप पत्र विपक्षी निगम द्वारा 18-7-83 को दिये गये थे जिनका उत्तर भी 22-7-83 को दे दिया था और बिना अवकाश स्वीकृत कराये एवं बिना अनुमति अनुपस्थित रहने बाबत क्षमा याचना भी कर ली थी और यह भी निवेदन कर दिया था कि उसने 18-7-83 को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के बाद उपस्थिति दे दी है तथा बीमारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र भी वह शीघ्र ही पेश कर देगा परंतु फिर भी जांच अधिकारी श्री आर. के. शर्मा ने 31-3-83 के दिनांक वाले आरोप पत्र पर जांच प्रारंभ रखी और 1-8-83 को जांच रिपोर्ट भी नियोजक को पेश कर दी। श्रमिक कहता है उसने जांच के दौरान जांच अधिकारी को भी स्पष्ट बता दिया था कि अवकाश स्वीकृति का प्रार्थना पत्र समय पर पत्नी की बीमारी में व्यस्त रहने के कारण पेश नहीं कर सका परन्तु फिर भी जांच अधिकारी ने उक्त स्पष्टीकरण पर अपना निष्कर्ष नहीं निकाला और उक्त रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनिक अधिकारी ने 20-2-84 के आदेश द्वारा सेवा मुक्ति का दण्ड दे दिया। उक्त आदेश में भी कोई कारण दर्ज नहीं किया। 20-2-84 के उक्त आदेश के विरुद्ध श्रमिक ने आंचलिक प्रबंधक नई दिल्ली को अपील भी प्रस्तुत की थी जिसमें भी पत्नी की बीमारी में व्यस्त रहने के कारण समय पर अवकाश का प्रार्थना पत्र नहीं पेश कर सकने का कारण दर्ज किया था परंतु फिर भी उक्त अधिकारी ने भी 22-5-85 को अपील सरसरी तौर पर रद्द कर दी। श्रमिक कहता है उसने निगम के चेयरमैन को भी एक मैमोरियल सितम्बर, 1985 में 20-2-84 और 22-5-85 के आदेशों, के विरुद्ध किया था जो भी सरसरी तौर पर ही 17-1-86 को खारिज कर दिया गया और मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर गौर नहीं किया गया।

3. इस न्यायालय के समय भी श्रमिक का कथन यह है कि 20-2-84 का आदेश अनुचित, अवैध और शून्य है क्योंकि न तो जांच अधिकारी ने और ना ही अनुशासनिक तथा अपील अधिकारी ने ही श्रमिक द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर किया है कि अपनी पत्नी की बीमारी में वह व्यस्त था इसलिए समय पर अवकाश स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सका। श्रमिक यह भी कहता है कि हालांकि उसे 31-3-83 तथा 17-5-83 के दो आरोप पत्र जारी किये गये थे परंतु जांच केवल 31-3-83 के ही आरोप पत्र पर की गई है जिस पर ही जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर 20-2-84 को सेवा मुक्ति का आदेश दिया गया है इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि 17-5-83 का आरोप पत्र नियोजक द्वारा समाप्त कर दिया गया है जो भी श्रमिक द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों के आधार पर ही किया गया है। श्रमिक कहता है आवश्यक समय में वह स्वयं हार्टफाईड तथा कोलाईटस जैसी दर्दनाक बीमारियों में ग्रस्त था जैसा कि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों व प्रार्थना पत्रों से भी प्रकट होगा। श्रमिक यह भी कहता है कि हालांकि उसने नियोजक को स्पष्ट कर दिया था कि स्वयं व पत्नी की बीमारी में व्यस्त रहने के कारण वह समय पर अवकाश स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सका और जिस गलती के लिए उसने नियोजक से क्षमा याचना भी कर ली थी परंतु फिर भी उक्त तथ्यों व परिस्थितियों पर नियोजक द्वारा विचार नहीं किया गया और सेवा मुक्ति जैसा कठोर दण्ड दे दिया गया। श्रमिक का कहना है कि उसके अलावा उसके परिवार में अन्य कोई व्यक्ति जीविकोपार्जन करने वाला नहीं है और उसके परिवार में पत्नी के दो अवयस्क पुत्रियां क्रमश 9 व 6 वर्ष की तथा उसकी विधवा माता भी है जो सब उसी पर निर्भर करती है। श्रमिक ने कहा है कि उसकी जन्म दिनांक दिनांक 15-2-53 है और वह अधिक आयु होने से नव-नियोजक के लायक भी नहीं रहा है इसलिए भी सेवा मुक्ति का दण्ड देना अनुचित है। उपरोक्त समस्त कारणों से श्रमिक की प्रार्थना है कि सेवा मुक्ति आदेश अपास्त किया जावे और उसे सवेतन नियोजन में रहने का आदेश पारित किया जावे।

4. अप्रार्थी नियोजक बजाय प्रत्युक्त श्रमिक के कथनों को अस्वीकार करते हुए कहा है कि श्रमिक के पिता श्री गोपी किशन अग्रवाल बीमा निगम की अजमेर शाखा में अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे जिनकी मृत्यु 20-6-75 को सेवा के दौरान हो गई थी इसीलिए उसी के एवज में श्रमिक की नियुक्ति 12-8-75 को की गई थी। श्रमिक ने अपने सभी प्रकार के अवकाशों का उपभोग कर लिया था और वह 1977 के उपरांत अधिकतर बिना वेतन अवकाश पर भी रहा है जैसाकि एनैक्सचर-1 से प्रकट है। नियोजक के अनुसार श्रमिक के अवकाश लेखे संतोषजनक नहीं हैं क्योंकि 133-1/2 दिनों का असाधारण अवकाश बिना वेतन के 15 अक्तूबर 1978 तक स्वीकृत कर लिया था परंतु फिर भी वह बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित रहा है। 19-10-78 को भी श्रमिक को एक आरोप पत्र एनैक्सचर—1 दिया गया था जो उसे 25-10-78 को प्राप्त हो गया था जिसका उसने कोई उत्तर नहीं दिया। 11-11-78 को भी आरोपों का उत्तर देने के लिए श्रमिक को पुनः पत्र डाला गया और अंततोगत्वा 22-11-78 को श्रमिक ने एनैक्सचर-2 उत्तर दिया जिसमें भी उसने भविष्य में सतर्क रहने का आश्वासन दिया और उक्त परिस्थितियों में ही श्रमिक के विरुद्ध नर्मी का रुख अपनाते हुए 28-11-78 को एनैक्सचर-3 द्वारा उसे सैन्सर का ही दण्ड दिया गया और उसने दिवस की अनाधिकृत अनुपस्थिति को "डायस नोन" मान लिया गया। नियोजक का कहना है कि तत्पश्चात् भी श्रमिक 12-12-78

से अनुपस्थित हो गया और 24-1-79 को उसे एनैक्सचर-4 आरोप पत्र उसके घर के पते पर भेजा गया जो श्रमिक के घर पर नहीं मिलने से वापस आ गया फलस्वरूप नोटिस बोर्ड पर उक्त आरोप पत्र लगाया गया तत्पश्चात् भी श्रमिक द्वारा क्षमा याचना का जवाब दिनांक 23-2-79 एनैक्सचर-5 प्राप्त होने पर उसे 7-4-79 को कारण बताओ नोटिस दिया गया जिसका उत्तर भी 19-4-79 को प्राप्त होने पर कि भविष्य में नियमों को पालना करेगा, उसके विरुद्ध सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही की गई थी तथा उसे एक स्टैप नीचे पदावनति का ही एनैक्सचर-8 दिनांक 15-5-79 द्वारा दण्ड दिया गया था और उसकी 12-12-78 से 10-2-79 की 61 दिवस की अनुपस्थिति भी डायसनोन मान ली थी। नियोजक कहता है कि तत्पश्चात् भी 25-4-79 से श्रमिक बिना अनुमति के अनुपस्थिति हो गया और उसे 22-5-79 को एनैक्सचर-4 आरोप पत्र दिया गया जो उसे 28-5-79 को मिल गया परंतु श्रमिक ने कोई उत्तर नहीं दिया इस पर 3-7-79 को एनैक्सचर-10 कारण बताओ नोटिस दिया गया जिस पर 18-7-79 को एनैक्सचर-11 उत्तर श्रमिक ने दिया और उसकी गरीबी व दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए नर्मी का रुख अपनाया गया तथा उसे उसके पद से एक और स्टेज नीचे कर दिया गया तथा 25-7-79 से 28-9-79 तक 65 दिवस की अनाधिकृत अनुपस्थिति को डायसनोन मान लिया गया। नियोजक कहता है तत्पश्चात् भी श्रमिक 25-2-79 को बिना पूर्वानुमति के गैर हाजिर हो गया बाबत भी उसे एनैक्सचर-13 आरोप पत्र 31-10-79 को जारी किया गया। 21-11-79 को एनैक्सचर-14 श्रमिक का जवाब आया जिस बाबत 3-12-79 को एनैक्सचर-15 कारण बताओ नोटिस जारी किया गया उसका भी जवाब एनैक्सचर-16, 19-12-79 प्राप्त हुआ और हमेशा की तरह श्रमिक ने सहानुभूतिपूर्वक रुख अपनाने की योजना को फलस्वरूप श्रमिक को दो स्टैप नीचे की बजाय एक स्टैप नीचे ही पदावनत किया गया और 25-9-79 से 30-11-79 तक 40 दिवस की उसकी अनाधिकृत अनुपस्थिति को भी डायसनोन मान लिया गया। तत्पश्चात् भी 14-7-85 से 1-3-80 तक 19 दिवस के लिए श्रमिक बिना अनुमति के अनुपस्थित हो गया और उसकी छुट्टी की अर्जी 4-8-80 को प्राप्त हुई उसका भी भी स्पष्टीकरण मांगा गया। उक्त स्पष्टीकरण पर अभी विचार करना ही था कि 6-8-80 से 28-8-80 तक 23 दिवस के लिए श्रमिक पुनः अनुपस्थित हो गया इसका जवाब 6-9-80 को मांगा गया और 8-9-80 को श्रमिक ने जवाब दिया कि भविष्य में कभी भी इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगा फलस्वरूप एक वर्ष के लिए एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड अनैक्सचर-18 द्वारा दिया गया। नियोजक का कहना है कि तत्पश्चात् भी श्रमिक 4-2-81 से 28-8-81 तक 3-3-81 से 1-4-81, 16-4-81 से 24-4-81, 27-4-81 और तत्पश्चात् भी अनुपस्थिति हो गया फलस्वरूप 27-5-81 को एनैक्सचर-21 आरोप पत्र दिया गया जिसका जवाब 16-9-81 को एनैक्सचर-23 द्वारा दिया और दुराचरण स्वीकार करते हुए भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने का आश्वासन दिया फलस्वरूप 2 वार्षिक वेतन वृद्धियों रोकने का दण्ड 4-1-82 को एनैक्सचर-25 द्वारा दिया गया। नियोजक कहता है इस पर भी श्रमिक ने अपने आपको नहीं सुधारा और पुनः बिना अनुमति व अवकाश स्वीकृत कराए 26-10-82 से 1-1-83 तथा 21-1-83, 24-1-83 से 28-1-83, 2-3-83 से 4-3-83 और 17-3-83 को भी अनुपस्थित हो गया। कुल 108 दिवस गैर हाजिर हो गया जिस बाबत 31-3-83 को अनैक्सचर-27 आरोप पत्र दिया गया जिसका 15 दिवस तक श्रमिक ने उत्तर नहीं दिया फलस्वरूप आर. के. शर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी के समक्ष भी अनेकों अवसर देने पर भी श्रमिक उपस्थित नहीं हुआ और जान-बूझकर जांच अधिकारी द्वारा भेजे हुए पत्रों को प्राप्त नहीं किया। अंततोगत्वा 1-8-83 को जांच अधिकारी के समक्ष श्रमिक उपस्थित हुआ और 31-3-83 की दिनांक के आरोप पत्र को स्वीकार किया। फलस्वरूप जांच अधिकारी ने 1-8-83 को एनैक्सचर-32 जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर 25-1-84 को एनैक्सचर-33 कारण बताओ नोटिस श्रमिक को जारी किया गया कि क्यों नहीं उसे प्रस्तावित दण्ड दिया जावे जिसका भी श्रमिक ने कोई उत्तर नहीं दिया फलस्वरूप 20-2-84 एनैक्सचर-34 से सेवा मुक्ति का दण्ड दिया गया है जो तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में सही है।

5. नियोजक का कहना है कि 17-5-83 का जो आरोप पत्र श्रमिकों दिया गया था उसमें भी 1-4-83 से श्रमिक अनेकों दिवस अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति था और 15-4-83 के बाद से लगातार गैर हाजिर था। 18-7-83 को जब श्रमिक उपस्थित हुआ तो उसे जवाब पेश किया तथा 20-2-83 के आदेश द्वारा श्रमिक को सेवा मुक्त कर दिया था इसलिये भी 17-5-83 का आरोप पत्र समाप्त कर दिया गया। नियोजक का कहना था कि जांच अधिकारी के समक्ष श्रमिक ने 31-3-83 के दुराचरणों को स्वीकार कर लिया था जिसका उल्लेख जांच रिपोर्ट में भी है और जांच अधिकारी ने दुराचरण साबित पाये थे दण्ड देने से पूर्व कारण बताओ नोटिस भी श्रमिक को जारी किया गया था परन्तु श्रमिक द्वारा प्रस्तुत किये गये यह कारण कि पत्नी की बीमारी में व्यस्त रहने के कारण वह छुट्टी के प्रार्थना पत्र नहीं दे सका, संतोषजनक नहीं पाये गये और इसलिए स्टाफ रेगुलेन्स 1970 के रेगुलेशन 30(1) के अन्तर्गत श्रमिक ने गंभीर दुराचरण किया है और जिस कारण 20-2-84 को सेवामुक्ति दण्ड दिया गया। उक्त दण्डादेश के विरुद्ध आंचलिक मैनेजर द्वारा श्रमिक की अपील भी सकारण नियमानुसार खारिज की गई है। नियोजक भी उसे उक्त दुराचरणों के लिए अनेकों दण्ड दिये गये

थे परन्तु श्रमिक ने अपनी आदतें नहीं सुधारीं फलस्वरूप सेवा मुक्ति जैसा कठोर दण्ड देना पड़ा इसलिए यह श्रमिक किसी अनुतोष का अधिकारी नहीं है।

6. विचारण के दौरान श्री टी.सी. अग्रवाल का देहान्त हो गया और 5-7-89 को उसकी विधवा पत्नी श्रीमति शशि अग्रवाल ने अर्जी पेश की कि उसके पति का देहावसान 14-5-89 को टी. बी. की बीमारी के कारण जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में हो गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोस्टेट प्रतिलिपियां रजिस्ट्रार नगर परिषद अजमेर तथा चिकित्सा प्रभारी अधिकारी अजमेर के साथ प्रस्तुत की हैं। दिनांक 27-9-89 को तत्कालीन योग्य अधिकारी ने मृतक की पत्नी श्रीमति शशि अग्रवाल उसकी अवयस्क पुत्रियां मंजुलता आयु 10 वर्ष, व संगीता आयु 7 वर्ष तथा उसकी माता श्रीमति कमला देवी आयु 65 वर्ष को भी बतौर वारिसान मृतक रिकार्ड पर लिया। दिनांक 21-1-92 को श्रमिक के योग्य प्रतिनिधि श्री समदरिया ने घरेलू जांच की फेयरनेस पर कोई आपत्ति नहीं की और औद्योगिक विवाद 1947 की धारा 11—ए बाबत ही बहस करने की इच्छा प्रकट की। उक्त विषय का उल्लेख 21-1-92 की आदेशिका में पाया जाता है।

7. मैंने पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना।

8. चूंकि नियोजक द्वारा कराई गई घरेलू जांच की फेयरनैस पर कोई आपत्ति नहीं की गई है और इसे फेयर व प्रोपर मान लिया गया है इसलिए जांच में ली गई साक्ष्य के विश्लेषण से ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि श्रमिक पर लगाये गये आरोप साबित हैं अथवा नहीं और उक्त दुराचरण के लिये दिया गया दण्ड अनुचित एवं अत्याधिक तो नहीं है। श्री समदरिया ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की है। श्रमिक पर 31-3-83 की तारीख का जो आरोप लगाया गया था उसके अनुसार प्रथम आरोप 26-10-82 से 1-1-83 तक 68 दिवस, 21-1-83 को 1 दिवस 24-2-33 से 28-2-83, 35½ दिवस, 2-3-83 से 4-3-83 तक 3 दिवस और 17-3-83 को एक दिवस कुल 108½ दिवस तक यह श्रमिक अनाधिकृत रूप से बिना अवकाश का प्रार्थना पत्र दिये अनुपस्थित रहा है। आरोप सं. 2 के अनुसार श्रमिक अवकाश का उपभोग करने के उपरान्त अवकाश मंजूर कराने का प्रार्थना पत्र पेश करने का आदी रहा है और नियोजक के अनुसार 26-10-82 से 30-11-82 तक 36 दिवस के अवकाश का अपभोग करने के उपरान्त उसने 17-1-83 को अर्जी दी। इसी प्रकार 1-12-82 से 31-12-82 तक 31 दिवस का अवकाश उपभोग करने के उपरान्त 17-1-83 को अर्जी पेश की, 24-1-83 से 28-1-83 तक 5 दिवस का अवकाश उपभोग करने के उपरान्त 28-1-83 को अर्जी दी। 29-1-83 से 2-2-83 तक 5 दिवस का अवकाश उपभोग करने के पश्चात् 3-2-83 को अर्जी दी। 28-2-83 को आधे दिवस का अवकाश उपभोग करने की अर्जी 12-3-83 को दी। 2-3-83 से 3-3-83 2 दिवस के अवकाश उपभोग के उपरान्त अर्जी 4-3-33 को दी। 4-3-33 के अवकाश की अर्जी 12-3-83 को दी और 17-3-83 के अवकाश की अर्जी 21-3-83 को दी। श्रमिक पर तीसरा आरोप यह था कि वह 1-1-83 को तथा 21-1-83 को भी अनुपस्थित रहा था, 3-2-83 से 27-2-83 तक भी अनुपस्थित रहा था और उक्त दिवसों बाबत उसने अवकाश की अर्जियां दी ही नहीं। श्रमिक पर चौथा आरोप यह था कि उसने अपने अवकाश बाबत जो प्रार्थना पत्र दिये थे उसमें स्वयं का पता दर्ज नहीं किया था। इस प्रकार नियोजक के अनुसार उक्त चारों आरोपों द्वारा श्रमिक ने स्टाफ रेगूलेशन्स 1969 के रेगूलेशन 30(1) के अन्तर्गत गंभीर दुराचरण किया था जिसका दण्ड रेगूलेशन 39(1)(ए) लगायत(जी) में दर्ज है। उपरोक्त आरोपों से यह प्रकट हुआ कि आरोप सं. 1 में 26-10-82 से 17-3-83 तक की अवधि का उल्लेख है जिस बाबत दुराचरण यह बताया गया है कि अवकाश उपभोग करने से पूर्व अवकाश का प्रार्थना पत्र नहीं दिया और न ही अनुमति ली जबकि इसी अवधि बाबत आरोप सं. 2 में यह उल्लेख है कि श्रमिक अवकाश उपभोग करने के उपरान्त अवकाश स्वीकृति करने हेतु अर्जी देने का आदी है, अभिप्राय यह है कि आरोप सं. 1 व 2 में उल्लिखित अवधियां भिन्न भिन्न नहीं हैं। इसी प्रकार आरोप सं. 3 में भी 1-1-83 से 27-2-83 की अवधि अन्तर्विलित है जिस बाबत दुराचरण यह है कि 27 दिवस की अवधि के लिये तो अवकाश स्वीकृत करने का प्रार्थना पत्र दिया ही नहीं। अर्थात् कुल अवधि 108½ दिवस की है जो 26-10-82 से 17-3-83 तक की है जिसमें 27 दिवस के लिये तो श्रमिक ने अवकाश उपभोग करने के उपरान्त भी स्वीकृति के लिये प्रार्थना पत्र नहीं दिया और शेष 81½ दिवस की अवधि के लिये अवकाश उपभोग के उपरान्त प्रार्थना पत्र दिये हैं। जांच अधिकारी के समक्ष श्रमिक ने दिनांक 22-7-83 को अपने पत्र प्रदर्श 5 प्रस्तुत किया था और अपनी अनुपस्थिति स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की थी तथा यह भी दर्ज किया था कि उक्त अवधि में वह बहुत तेज ज्वर से पीड़ित था जो तत्पश्चात् टाईफाइड हो गया। जांच रिपोर्ट 1-8-83 की है जिसके अनुसार भी यह प्रकट होता है कि श्रमिक जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ था और 31-3-83 के आरोप पत्र का श्रमिक ने कोई लिखित उत्तर नहीं दिया था। जांच अधिकारी द्वारा उक्त आरोप सुनाने व समझने के पश्चात् श्रमिक ने सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था। जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि श्रमिक ने प्रदर्श पी-4 लगायत पी-12 छुट्टियों के प्रार्थना पत्र नियोजक को प्रस्तुत किये थे। इनमें से किसी पर भी स्वयं का घर का पता अंकित नहीं था तथा सभी प्रार्थना पत्र अवकाश उपभोग करने के उपरान्त ही पेश किये गये थे। उक्त प्रार्थना पत्र भी

81½ दिवस बाबत ही थे अर्थात् 27 दिवस बाबत अवकाश उपभोग के उपरान्त भी अवकाश स्वीकृति के प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये गये जिसका संबंध आरोप सं. 3 से है। उक्त तथ्यों को जांच अधिकारी के समक्ष भी श्रमिक ने स्वीकार किया था। श्रमिक का एक मात्र कथन यह था कि वह अपनी पत्नी की बिमारी में व्यस्त रहने के कारण समय पर अवकाश के प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सका था। अवसर देने पर भी जांच के दौरान श्रमिक ने प्रति रक्षा में साक्ष्य पेश नहीं की। फलस्वरूप जांच अधिकारी ने श्रमिक पर लगाये गये सभी आरोप साबित पाये।

9. मेरी राय में भी जांच अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष श्रमिक की स्वीकारोक्ति पर ही आधारित था और किसी प्रकार की साक्ष्य प्रबन्धक की ओर से पेश नहीं की गई थी। मेरे समक्ष भी बहस के दौरान श्री समदरिया योग्य प्रतिनिधि प्रार्थी का यह तर्क नहीं था कि जांच प्रधिकारी का निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है और श्रमिक की स्वीकारोक्ति पर ही आधारित है इसलिये हस्तक्षेप योग्य हो। अभिप्रयय यह है कि जब जांच अधिकारी के समक्ष ही दुराचरणों को श्रमिक ने अपनी स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था तो प्रबन्धक पक्ष द्वारा साक्षी पेश करना आवश्यक था। श्रमिक ने भी अवकाश उपभोग करने के उपरान्त ही प्रदर्श 4 से प्रदर्श 12 प्रार्थना पत्र 81½ दिवस के लिये प्रस्तुत की थी इसलिए ऐसी किसी प्रतिरक्षा को भी पेश नहीं कर सकता था जिससे कोई विपरीत निष्कर्ष निकलता हो। अतः उपरोक्त समस्त कारणों से श्रमिक की स्वीकारोक्ति से तथा प्रदर्श पी-4 से प्रदर्श 12 उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों से मेरी राय में भी जांच अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर ही आधारित है जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

10. श्री समदरिया योग्य प्रतिनिधि प्रार्थी का तर्क यह था कि श्रमिक ने 12-8-75 को सेवा में प्रवेश किया था और 12-2-84 को उसे सेवा मुक्त किया गया है अर्थात् उसने करीब 9 वर्ष तक नियोजक की सेवा की थी और 14-5-89 को उसका देहावसान भी हो चुका है तथा वह एक मात्र परिवार का जीविकापार्जन करने वाला सदस्य था, उसकी विधवा पत्नी, वृद्ध माता और उसकी दो अवयस्क पुत्रियां ही उसके परिवार में हैं तथा श्रमिक ने अवकाश उपभोग करने के उपरान्त 81½ दिवस का अवकाश स्वीकृत कराने बाबत प्रदर्श-4 लगायत प्रदर्श-12 प्रार्थना पत्र भी पेश कर दिये थे। 27 दिवस के अवकाश स्वीकृति हेतु ही प्रार्थना पत्र नहीं दिये थे इसलिए उक्त दुराचरण एवं श्रमिक के परिवार की उक्त परिस्थितियों को देखते हुए सेवा मुक्ति जैसा कठोर दण्ड देना अत्याधिक व अनुचित होने से अपास्त करने योग्य है। इसके विपरीत श्री एम.डी. अग्रवाल, योग्य प्रतिनिधि नियोजक का तर्क यह था कि 31-3-83 का जो आरोप पत्र दिया गया था उसके पूर्व भी श्रमिक ने अनेकों बार बिना अवकाश स्वीकृत कराये एवं बिना अनुमति लिये अवकाशों का उपभोग किया था और जिस बाबत नियोजक ने श्रमिक को भिन्न-भिन्न दण्ड भी दिये थे परन्तु फिर भी श्रमिक ने अपनी आदतों को नहीं सुधारा। अपने कथनों के समर्थन में श्री अग्रवाल ने अनेक अवसरों का उल्लेख किया है जिसके अनुसार यह श्रमिक 13-9-78 से 24-10-78 तक अनुपस्थित था जिस बाबत आरोप पत्र जारी किया गया और श्रमिक का जवाब आने पर 1-12-78 के आदेश द्वारा उसे सेन्सर का दण्ड दिया गया। तत्पश्चात् 12-12-78 से 10-2-79 तक यह श्रमिक अनुपस्थित रहा जिस बाबत आरोप पत्र दिया गया और जवाब आने पर श्रमिक को 15-5-79 के आदेश द्वारा एक स्टैप नीचे पदावनत कर दिया गया। तत्पश्चात् यह श्रमिक 25-4-79 से 28-4-79 तक अनुपस्थित रहा जिस बाबत आरोप पत्र जारी किया गया और कारण बताओ नोटिस देने के उपरान्त 25-7-79 के आदेश द्वारा श्रमिक को एक स्टैप और नीचे पदावनत कर दिया गया। इसके बाद श्रमिक 25-2-79 से 3-11-79 तक गैर हाजिर हो गया जिस बाबत 5-1-80 को एक स्टैप नीचे पदावनति का दण्ड दिया गया। 14-7-80 से 1-8-80 और 6-8-80 से 28-8-80 तक भी गैर हाजिर हो गया जिस बाबत आरोप पत्र देकर और उसका जवाब लेकर उसे 9-10-80 के आदेश द्वारा 1 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड दिया गया। इस पर भी श्रमिक ने स्वयं को नहीं सुधारा और 4-2-81 तथा 3-3-81 से 1-4-81 तक 16-4-81, 24-4-81 और 27-4-81 को फिर गैर हाजिर हो गया। जिस बाबत भी आरोप पत्र जारी किया गया और जवाब आने पर श्रमिक को 4-1-82 के आदेश द्वारा 2 वार्षिक वेतन वृद्धियां स्थाई प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया गया। नियोजक का कहना है कि उपरोक्त सभी अवधि को डायसनोन मान लिया गया फिर भी श्रमिक 26-10-82 से अनुपस्थित हो गया जिस बाबत 31-3-82 को आरोप पत्र दिया गया था। श्री समदरिया योग्य प्रतिनिधि का तर्क यह था कि 31-3-83 के पूर्व के किसी भी दण्ड का प्रयोग यह दण्ड देते समय नहीं किया जा सकता क्योंकि जांच अधिकारी की रिपोर्ट 1-8-83 में पूर्व में दिये गये उक्त किसी भी दुराचरण का एवं दण्ड का उल्लेख तक नहीं है और न ही पूर्व में दिये गये उक्त दण्ड अथवा दुराचरण से संबंधित कोई पत्र आदि जांच के दौरान जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। यहां तक कि 31-3-83 के आरोप पत्र में भी यह उल्लेख नहीं है कि इसके पूर्व में भी श्रमिक ने ऐसा ही दुराचरण किया था जिस बाबत उसे पूर्व में भी दण्डित किया गया था और फिर भी उसने स्वयं को नहीं सुधारा। 20-2-84 को जो सेवा मुक्ति का दण्ड दिया गया था उसमें भी पूर्व के दुराचरणों तथा उस पर दिये गये दण्ड का उल्लेख तक नहीं था इसलिए भी पूर्व के दुराचरणों का प्रयोग यह न्यायालय नहीं कर सकता। श्री अग्रवाल, योग्य प्रतिनिधि

नियोजक ने यह तो स्वीकार किया कि 31-3-83 के आरोप पत्र में पूर्व के दुराचरणों का उल्लेख नहीं है और न ही जांच अधिकारी की रिपोर्ट 1-8-83 में पूर्व के दुराचरण का उल्लेख है यहां तक कि 20-2-84 के आदेश में भी पूर्व के दुराचरणों का उल्लेख नहीं है। इन परिस्थितियों में मेरी राय में पूर्व के जो दुराचरण थे वे मटीरियल ऑन रिकार्ड नहीं माना जा सकता क्योंकि जांच अधिकारी के समय पूर्व के दुराचरणों के कोई आदेश आरोप पत्र अथवा कारण बताओ नोटिस की प्रतियां पेश नहीं की गई थीं और न ही उनका उल्लेख जांच अधिकारी की रिपोर्ट में पाया जाता है इसलिए 1991 ITTI एल.एल. जे. 430 पर उपलब्ध आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टान्त के अनुसार पूर्व के दुराचरणों को मटीरियल ऑन रिकार्ड नहीं माना जा सकता और न ही उनका प्रयोग अब इस न्यायालय में नियोजक कर सकता है।

11. मेरे समक्ष यहां प्रश्न रहता है कि क्या 31-3-83 को लगाये गये चारों आरोपों बाबत श्रमिक को दिये गये दण्ड दुराचरण के अनुपात में है या अत्याधिक और अनुचित हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में ही स्पष्ट किया है कि 108½ दिवस की अनुपस्थिति श्रमिक की थी जिसमें से 89½ दिवस के अवकाश स्वीकृति के प्रार्थना पत्र अवकाश उपभोग के उपरान्त श्रमिक ने पेश कर दिये थे जो प्रदर्श-4 लगायत 12 हैं और 27 दिवस के प्रार्थना-पत्र श्रमिक द्वारा पेश नहीं किये गये। श्रमिक का कथन यह था कि वह स्वयं तीव्र ज्वर से पीड़ित था जो तत्पश्चात् टायफाईड और फिर टी.बी. में परिवर्तित हो गया और उसकी पत्नी भी गंभीर रूप से बीमार थी जिसमें व्यस्त रहने के कारण प्रार्थना पत्र समय पर पेश नहीं कर सका। श्रमिक के कथनों में सत्यता का आभास होता है क्योंकि अन्ततः टी.बी. की बीमारी से ही श्रमिक की मृत्यु भी हो गई है। दुराचरण के अनुपात में ही दण्ड देने का सिद्धांत है और मक्खी को मारने के लिये रोड रोलर की आवश्यकता नहीं है। विपक्षी बीमा निगम का प्रार्थी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था जिसकी नियुक्ति भी उसके पिता जो नियोजक के यहां अधीक्षक थे, की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने से उसके परिवार के प्रति सहानुभूतिपूर्वक रुख दिखाते हुए की गई थी और जो तपेदिक जैसे रोग से पीड़ित था तथा जिसने भी 81½ दिवस के तो अवकाश स्वीकृति के प्रार्थना पत्र पेश कर दिये थे तथा जिसके पीछे वृद्ध माता, विधवा पत्नी व दो अवयस्क पुत्रियां शेष रहती है, उसे सेवा मुक्ति जैसा कठोर दण्ड देना मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में अनुचित एवं अत्याधिक है। 1987 लैब. आई.सी. 685 के न्याय दृष्टान्त में निम्न मत व्यक्त किया है :

"Dismissl from service means deprivation of bread. When an authority is conferred with the power to inflict one of several punishments, the authority must give a serious thought to the question of choice of penalty. The choice cannot be arbitrary but must depend on the nature of misconduct established in a given case. Just as a Road Roller cannot be brought to crush a fly so also the extreme penalty of dismissal cannot be inflicted which is not equally grave. The consequences of dismissal or removal from service are severe, sometimes the entire family is ruined because another job or work may not be easy to find and therefore, it is all the more necessary that the punishment of removal or dismissal should be invoked sparingly and in cases which can be described as gross, such as receiving or defalcation of public funds, behaviour which is morally reprehensible gross abuse or misuse of authority etc..."

ए.आई.आर. 1985 (एस.सी.) 772 के न्याय दृष्टान्त में भी माननीय उच्चतम न्यायालय का मत था कि :

"Right to impose penalty carries with it the duty to act justly. The power has to be exercised fairly, justly and reasonably."

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० बनाम मोहम्मद उस्मान 1981 (2) एल.एल.जे. 386 के न्याय दृष्टान्त में उच्चतम न्यायालय का मत था कि :

"Section 11 of the ID Act confers on Labour Court the powers to evaluate the severity of misconduct and to assess whether punishment imposed by the employer is commensurate with the gravity of misconduct. If the Labour Court after evaluating the gravity of misconduct held that the punishment of termination is disproportionately heavy and exercised its discretion, this Court, in the absence of any important legal provisions could not undertake to re-examine the question of adequacy or inadequacy of material for interference by Labour Court."

तत्पश्चात् जसवन्तसिंह बनाम पैप्सू रोडवेज़ 1984 लैब आई.सी. 7 के न्याय दृष्टान्त में उच्चतम न्यायालय ने, 1986 लैब.आई.सी. 938 के न्याय दृष्टान्त में गुजरात उच्च न्यायालय ने, 1988 (72) एफ.जे.आर. 22 के न्याय दृष्टान्त में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने, 1991 (2) एल.एल.जे. 405 के न्याय दृष्टान्त में मद्रास उच्च न्यायालय ने, 1991 लैब. आई.सी. 1555 के न्याय दृष्टान्त में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी यही व्यवस्था दी है कि धारा 11-ए के अन्तर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण मामले के तथ्यों और विशेष परिस्थितियों में नियोजक द्वारा दिये गये सेवा मुक्ति के दण्ड में हस्तक्षेप कर सकता है और सकारण उसकी जगह उचित दण्ड दे सकता है।

12. मामले के तथ्यों और परिस्थिति के संदर्भ में और उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार मेरी राय में श्रमिक टी.सी. अग्रवाल को दिया गया सेवा मुक्ति का दण्ड अनुचित एवं अत्याधिक होने से अपास्त किया जाता है और उसकी जगह 4 वार्षिक वेतन वृद्धियां संचई प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया जाता है। चूंकि श्रमिक की मृत्यु 14-5-89 को हो चुकी है इसलिए उसे पदस्थापित तो नहीं किया जा सकता बल्कि उसके असहाय परिवार को उसके

पद का वेतन ही दिलाया जा सकता है। अतः उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :

"श्री टी.सी. अग्रवाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 20-2-84 से की गई सेवा मुक्ति उचित एवं वैध नहीं है तथा सेवा मुक्ति की जगह उसकी 4 वार्षिक वेतन वृद्धियां स्थाई प्रभाव से रोके जाने का ही दण्ड दिया जाता है। उक्त वेतन वृद्धियां वर्ष 1984, 1985, 1986 एवं 1987 की ही रोकी जायेंगी। श्रमिक का देहावसान 14-5-89 को हो चुका है इसलिए उसकी विधवा पत्नी, वृद्ध माता एवं दो अवयस्क पुत्रियों को ही 20-2-84 से 13-5-89 तक का वेतन ही दिलाया जाता है जो भी दण्डस्वरूप लगाई गई उपरोक्त धारा वेतन वृद्धियां काटने के उपरोक्त ही दिया जायेगा। नियोजक से यह भी आशा की जाती है कि मांडल एम्पलायर के नाते श्रमिक की जगह उसकी विधवा पत्नी अथवा अन्य किसी निकटतम सदस्य को सेवा देने की सहृदयता करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वर्दाश्त करेंगे।"

3. उक्त आशय का अवार्ड पारित किया जाता है केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17(1) अधिनियम, भेजा जाये।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 29 मई, 1992

का.आ.1637.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मै. इंडस्ट्रियल फ्यूल कम्पनी के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं. 1) धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 25-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-20012(277)/89-आई.आर! (कोल-1)]
वी० के वेणुगोपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th May, 1992

S.O. 1637.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 1), Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Industrial Fuel Company and their workmen, which was received by the Central Government on 25-5-1992.

[No. L-20012(277)/89-IR(COAL-I)]
V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 19 of 1990

PARTIES :

Employers in relation to the management of M/s. Industrial Fuel Co.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers : Shri B. Lall, Advocate, and Shri U. S. Sinha, Advocate.

For the Workmen : Shri J. P. Singh, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dated, the 18th May, 1992

AWARD

By Order No. L-20012/277/89-IR.(Coal-I), dated, the 12th February, 1990, the Central Government in the Ministry of Labour, has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2-A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of M/s. Industrial Fuel Co., Katras Road, Dhanbad in dismissing Shri Yogendra Kumar Rajak vide dismissal Order No. IFC/346/88, dated 21-9-88 is justified ? If not, what relief the workman is entitled to ?"

2. The case of the management of M/s. Industrial Fuel Company, as disclosed in the written statement submitted by it, details apart, is as follows :

M/s. Industrial Fuel Co. manufactures Hard Coke by coal obtained from M/s. B.C.C. Ltd. as per allocation Yogendra Kumar Rajak was entrusted by the management of Industrial Fuel Co. to do essential works. He was authorised to visit the different collieries of M/s. B.C.C. Ltd. in order to arrange speedy loading and transportation of coal to the Hard Coke Bhatta of the company situated at Bhuli, Dhanbad persuant to the Delivery Orders issued by M/s. B.C.C. Ltd. in the name of the company. Sri Rajak used to take money to meet the miscellaneous expenses for arranging speedy delivery of coal at the plant of the company from the different collieries of M/s. B.C.C. Ltd. He was being given money by the management in its confidential capacity as the work entrusted to him was very essential and in the case of non-delivery of coal in proper time, there is every likelihood of the working of the plant of the company being seriously affected. It was found that although Sri Rajak had taken Rs. 15,826 on different dates from the Cashier of the company to meet the miscellaneous expenses for arranging speedy delivery of M/s. B.C.C. Ltd., coal was not delivered at the plant and the money in question was not also accounted for by him. When he was asked to account for the money entrusted to him and state the reason, if any, for non-delivery of coal at the plant, he outrageously misbehaved with Sri N. K. Karn, Works Manager and threatened him with dire consequences. Since the matter was serious he was immediately suspended by letter dated 18-6-88. A regular chargesheet was issued to him in terms of the certified Standing Orders of the company. He was assigned on charges for (i) absence from duty without permission or information to the management, (ii) fraud and mis-appropriation of money amounting to Rs 15,826, (iii) causing financial loss to the company, (iv) riotous or disorderly behaviour or any acts subversive of discipline, (v) unlawful assembly and resorting to rowdism and (vi) threatening, abusing Sri N. K. Karn in the chamber of Mr. Karn's office at Rajendra Market under Clauses 15(5), (2), (3), (8), (29) and (18) of the certified Standing Orders of the Company. The concerned workman submitted his reply to the chargesheet denying the allegations. The management found the reply of the concerned workman unsatisfactory, decided to hold domestic enquiry and in the process appointed Sri D. K. Verma, as Enquiry Officer as there was no competent person acquainted with the procedure of hold-

ing domestic enquiry in the establishment of the management, fixed the date of enquiry and intimated the concerned workman accordingly. The concerned workman was duly informed to attend the enquiry to be held on 5-8-88. Although the concerned workman received the letter, he did not attend the enquiry. The Enquiry Officer sent another letter by Registered Post with A.D. which was duly received by the concerned workman. In terms of that letter the domestic enquiry was to be held on 17-8-88. Although he received the letter, he did not attend the enquiry. The Enquiry Officer gave him another opportunity to participate in the enquiry to defend himself. The Enquiry Officer also sent to him all relevant papers as demanded by him, by his Registered letter dated 27-8-88. He received letter of the Enquiry Officer and in terms of the letter of the Enquiry Officer the date of hearing of the domestic enquiry was fixed on 15-9-88. But the concerned workman did not attend the enquiry, and in the circumstances the Enquiry Officer held the enquiry ex parte and found him guilty of all the charges levelled against him. The disciplinary authority carefully considered the enquiry proceeding, the report of the Enquiry Officer and concurred with the finding of the Enquiry Officer. Considering all the aspect of the case, the Disciplinary Authority was constrained to pass an order of dismissal of the concerned workman from service for the proven charge of misconduct. The employers of the concerned workman are businessmen and they are concerned with smooth running of their business in proper manner. They cannot afford to retain an employee like the concerned workman who indulged in misappropriation of money entrusted to him for business purpose and flagrantly resorted to bullying tactics and indulged in abusing and manhandling the superior officer of the company. The concerned workman manifested intemperate behaviour and mentality in his letter addressed to the Asstt. Labour Commissioner (C), Dhanbad, where he falsely alleged that N. K. Karn was associated with the Maha gangs and hoodlums. He also made wild and slanderous allegations against the Company in his petition filed before the Deputy Commissioner, Dhanbad. Anyway, the management has asserted that it has rightly dismissed the concerned workman from service and that he is not entitled to get any relief in the present dispute.

3. The concerned workman has raised the dispute under Section 2-A of the Industrial Disputes Act. His case, as made out in the written statement, is as follows :

He was employed by the company on 15-5-76 as Asstt. Clerk and Loading Supervisor and was posted at Hard Coke Bhatta at Bhuli belonging to the company. The Company used to obtain deilvery orders from the Head Quarters of M/s. B.C.C. Ltd. for obtaining coal from the coal mines for preparation of Hard Coke called Industrial and domestic fuel. The work assigned to him was to collect such devilvery orders from the office of the company and to visit the collieries for obtaining coal. The company used to advance money to him on voucher for engagement of labour and for defraying some miscellaneous expenses and the charge for hire of truck for transportation of coal used to be paid by the office of the management on delivery of such coal in Hard Coke Plant. It was the duty of the Manager of the Plant to pay M/s. B.C.C. Ltd. the price of the coal by pay order/draft on Bank. He rendered satisfactory service to the company by hard work and honest service. He rendered account of advance made to him on vouchers. Such cordial relationship between the employers and him continued till 1985 when he was verbally informed by the Manager of the Hard Coke Plant, Sri N. K. Karn that the company had started depositing his provident fund contribution with the management's contribution in his provident fund account. He also informed him that no deposits of his provident fund deduction from his pay made earlier, i.e., from 1977 was deposited by the management. He was, however, informed that the deduction from his pay between 1977 and 1984 would be refunded to him in due course. He made protest of such state of affairs to Shri Manoj Chaturvedi, Manager of the Company, who felt annoyed with him. The company paid him consolidated pay of Rs. 500 from 1976 and from 1983 his pay was enhanced to Rs. 800. Since 1985 his pay was further raised to Rs. 975. He was paid his salary at consolidated rate and similar payments were made to other members of staff. He alongwith other members of the staff approached the management for giving them dearness allowance and other benefits. The management considered him to be the ring leader and decided to teach him a lesson. On 18-6-88 at about 2.30 P.M. three unknown persons came to his house on Tracker, entered into his room and blurted out that he had to refund the advance money taken from the company. He informed them that he had already accounted for the money received by him on voucher and nothing was due from him. But these persons wanted to use force but were prevented from doing so by the members of his family. He managed to escape and reached Dhansar Police Station. Police came there and arrested the culprits from the spot. Close on the heels of the occurrence the management of the company issued a chargesheet dated 22-6-88 against him making wild allegations. The charges on five counts were levelled against him. He replied to the chargesheet alleging that it was baseless and motivated. He also stated that since the charges were based on documents which form the subject matter of domestic enuiry, no comment was called for at that stage The management, ignoring his explanation passed an order for holding domestic enuiry and appointed Shri D. K. Verma, Advocate, Dhanbad, as Enquiry Officer. The domestic enquiry was held exparte by the Enquiry Officer as he could not participate in the domestic enquiry for want of notice which was not served on him. The Enquiry Officer submitted his report holding him guilty of the charges levelled against him. The management thereafter dismissed him from service by order dated 21-9-88. He made a demand for reinstatement, but since there was no response from his employer to his demand, he raised an industrial dispute before the Asstt. Labour Commissioner (Central), Dhanbad. The management appeared in conciliation proceeding and showed adamant attitude with regard to his demand for reinstatement or settlement of the dispute by Arbitration. The enquiry Officer was particularly changed by the management because he happened to be an Advocate pracising in Labour Courts at Dhanbad and happened to be a junior of an eminent lawyer, Shri Baban Tall. Shri Verma was appointed Enquiry Officer in order to plug all loopolles in domestic enquiry. Anyway, the report of the Enquiry Officer is perverse and the conclusion reached by him is not based on facts or evidence. In the circumstances, he has prayed that the action of the management in dismissing him from service is unjustified and he is entitled to back wages and other emoluments as admissible to him.

4. In rejoinder to the written statement of the concerned workman, the management has asserted that the concerned workman was not appointed by the management on and from 15-5-76 as Asstt. Clerk and Loading Supervisor. He was appointed much later on 1-11-85. Anyway, the length of service of the concerned workman is not the relevant point of dispute in the present case. The allegation of the concerned workman on the point of deposit of provident fund contribution is motivated and nothing but a figment of wild imagination. The management did not know anything about the occurrence allegedly happened in his house. Shri D. K. Verma, Advocate, was appointed Enquiry Officer when the reply of the concerned workman to the chargesheet was not found satisfactory. Shri D. K. Verma was appointed with the sole purpose of conducting the domestic enquiry in accordance with the principles of natural justice.

5. In rejoinder to the written statement of the management, the concerned workman has denied that he was given anything in his confidential capacity for the purpose of lifting of coal from Coal Company. He was given some money on voucher to meet miscellaneous expenses and he was to account for the money given to him in the Accounts Office of his employer. He will prove by photostat copies of documents through which he received money from his employer and also accounts given by him in respect of such money in the employer's Account Office. He could receive money from the employer only through voucher and not otherwise. The employers are bound to produce documents on the basis of which money was entrusted to him on different dates by the office of his employer. He has denied to have received Rs. 15,826 on different dates from the Cashier of the company to meet miscellaneous expenses for delivery of coal. He has also denied that he was asked for the money entrusted to him and that he misbehaved with Works Manager, N. K. Karn and threatened him with dire consequences. The domestic enquiry was conducted experts which is highly prejudicial to his defence and on this ground alone the domestic enquiry was not fair and proper. He has submitted that except Charge No. 2 of the chargesheet,

the other charges cannot be said to warrant a case of dismissal and he could be given lighter punishment in respect of other charges, if proved. The reference by the management to his alleged intemperate behaviour and mentality in the letter addressed to the Asstt. Labour Commissioner (Central) and slanderous allegation against the company as made in his petition submitted before the Deputy Commissioner, Dhanbad do not constitute any part of disciplinary proceeding and as such do not require any comment.

6. At the instance of the management, the propriety and fairness of domestic enquiry was considered as preliminary issue. The management examined Sri D. K. Verma, Enquiry Officer as MW-1 and laid in evidence a sheaf of documents which have been marked Exts. W-1 to W-4.

On the other hand, the concerned workman did not examine himself but laid in evidence some items of documents which have been marked Exts. W-1 to W-4.

Shri J. P. Singh, learned Advocate appearing for the concerned workman conceded that the domestic enquiry was held fairly and properly. Upon consideration of materials on record also it was held that the domestic enquiry was held fairly and properly. Accordingly, the preliminary issue was disposed of by holding that the domestic enquiry was held fairly and properly. Thereafter the case was heard on merits.

7. The present industrial dispute has been raised by the concerned workman under Sec. 2-A of the Industrial Disputes Act, 1947 over his dismissal from service by the management upon being found guilty in a domestic enquiry held for enquiring into various acts of misconduct allegedly committed by him under the various provisions of Certified Standing Orders of the establishment of the management. Before coming to the nub of the real controversy in the present dispute, I shall deal with some points not directly germene to the main issue.

8. According to the concerned workman, he got into employment of the company on 15-5-76 as Asstt. Clerk and Loading Supervisor and was posted at Hard Coke Bhatta at Bhuli belonging to the company. In rejoinder to the written statement of the concerned workman, the management has asserted that he was not appointed by the management on and from 15-5-76 as Asstt. Clerk and Loading Supervisor; he was appointed much later on 1-11-85. The management has produced no evidence in support of the fact that the concerned workman was appointed on 1-11-85. On the other hand, the concerned workman has produced document from the company certifying that he had been working in the company as Asstt. Clerk and Loading Supervisor since 15-5-76. This document was issued on 25-2-81 (Ext. W-1). He has produced another letter of authorisation to the Finance Manager, Bharat Coking Coal Ltd., Area No. VII, Bhagaband dated 4-10-87 authorising him to receive upto date bill against the D.O on behalf of the Company. (Ext. W-2). These two documents firmly establish the fact that the concerned workman was appointed by the company on 15-5-75 as Asstt. Clerk and Loading Supervisor. There is no dispute that since his appointment he was posted to Hard Coke Bhatta at Bhuli belonging to the company.

According to the concerned workman, he rendered satisfactory service to the company by hard work and honest service and he rendered account of advance made to him on vouchers and such cordial relationship between the employers and him continued till 1985 when there arose some fissure consequent upon he was being informed by the Manager, Hard Coke Plant that the company started depositing his provident fund contribution with the management's contribution in his provident fund account and that provident fund amount deduction from his salary earlier i.e. 1977 was not deposited by the management and he protested over the matter. The management has disputed the correctness of these statements of facts in its rejoinder and asserted that the protest allegedly made by him is nothing but motivated and a figment of wild imagination. The parties arrayed have not adduced any meaningful evidence on this aspect of the matter, but the certificate issued by the management dated 25-2-81 in favour of the concerned workman discloses that the management found his conduct very satisfactory. But this certificate does not necessarily means that the conduct of the concerned workman was satisfactory till 1985 when a fissure arose as a result of his having protested to the management for non-deposit of provident fund amount deducted from his salary from 1977. Anyway, these issues are not heard of real controversy in the present dispute.

9. Undeniably, M/s. Industrial Fuel Company manufactures hard coke by coal obtained from M/S. B.C.C. Ltd. as per allocation. The company used to obtain delivery order from M/S. B.C.C. Ltd. for obtaining coal from the coal mines for preparation of hard coke called industrial and domestic fuel. The concerned workman was authorised by the management to collect the delivery order from the office of M/S. B.C.C. Ltd., to visit the collieries for obtaining coal and to arrange for speedy loading and transportation of coal to the Hard Coke Bhatta of the company at Bhuli and the company used to advance money to him to meet the miscellaneous expenses for arrangement speedy delivery of coal at the plant of the company from different collieries of M/S. B.C.C.L. The management has asserted that he was being given money in his confidential capacity as the work entrusted to him was very essential and in the case of non-delivery of coal in proper time, there was every likelihood of the working of the plant of the company being seriously affected. The concerned workman has denied that he was given money in his confidential capacity, but admitted that he was given money for the purpose of lifting of coal from the coal company. But he has not disputed the fact that in case of non-delivery of coal in proper time, there was every likelihood of the working of the company being seriously affected. All that he has asserted is that he was advanced money by the management on vouchers.

10. It appears that in June, 1988 N. K. Karn was the Works Manager of the company. On 18-6-88 Sri Karn made a complaint in writing to Sri Ramesh Kumar Chawda, Patner of the company, against the concerned workman alleging various acts of misconduct committed by him (concerned workman). This complaint was marked Ext.M-6 in the domestic enquiry. Shri Chawda forwarded the complaint to Sri M. Chaturvedi, Manager (Administration) with a direction to initiate disciplinary action against the concerned workman as per Certified Standing Orders of the company. It is on record that Sri Chaturvedi considering the gravity of the charges put the concerned workman under suspension with immediate effect i.e. from 18-6-88 and informed him that a chargesheet would be served on him later. On 22-6-88 Sri Chaturvedi arraigned the concerned workman on charges on six counts for commission of various acts of misconducts as per Certified Standing Orders of the company. The chargesheet is re-produced hereinbelow (Ext. M-1) :

> "This chargesheet has reference to our letter No.IFC/204/88 dated 18-6-1988 whereby you have been put under suspension. The following charges of misconducts have been made against you.
>
> Charge No. 1 : You absented yourself from duty from 8-6-1988 to 13-6-1988 without permission from or information to the management. You were asked by the Works Manager, Mr. N. K. Karan, to submit an explanation to the satisfaction of the management for your absence from duty. But you audaciously refused to submit any explanation and told him that you had no care at all for the Standing Orders of the Company. You further told him that you could absent yourself from duty according to your sweet will.
>
> Charge No. 2 : You were authorised by the management for lifting and transporting of coal from the collieries of BCCL. You took money amounting to Rs. 15,826, from company's cashier on different dates saying that it was required by you for speedily lifting of coal from the collieries of BCCL for our plant at Bhuli. You are aware that you had taken Rs. 5,000 on 9-5-1988, Rs 6,828 on 25-5-1988 and Rs. 4,000 on 2-6-1988 which comes to a total of Rs. 15,826. While taking money you had assured that you would submit a statement of expenses of the amount taken by you. But in spite of repeated advices to you by Mr. N. K. Karan you did not submit any account of the money. Your behaviours

and roundabout replies to the queries put to you by Mr. N. K. Karan have inevitably led us to believe that you had fraudulently taken money as stated above and misappropriated it.

Charge No. 3 : As assured by you, the management had been expected to receive coal in time at the plant because all legal procedures had been completed for procurement of coal from BCCL's collieries. But coal was not received in time which ultimately resulted in financial loss to the company to the tune of nearly Rs. 2,00,000. The Plant operation was seriously hit by the acute shortage of coal. You used to give vague replies to the queries of the Works Manager, Mr. N. K. Karan, which he put to you on several occasions regarding any real cause of delay in procurement of coal. On making contact with the appropriate persons of BCCL and our transporter the fact emerged that you had not been in touch with them and you kept the management in the dark. In this way you wilfully caused financial damage to the company as stated above.

Charge No. 4 . When Mr. N. K. Karan advised you on 15-6-1988 at about 11-30 A.M. in the plant's office in the presence of Mr. Kamal Banerjee and Mr. Madhusudan Singh to submit full account of the money taken by you, you flared up and abused him in contemptibly offensive languages. You told him that you were not bound to furnish any account. You haughtily moved about in his office creating harsh grating sound by you shoes. While leaving his office you threatened him that any further attempt on his part to question you in the matter of money would result in serious misfortune for him as you had full support of "Dadas" of Dhanbad bazar.

Charge No. 5 : On 17th June, 1982 at about 11.45 A.M. you accompanied by ferocious looking 7 unknown persons rushed into the chamber of Mr. N. K. Karan located in Rajendra market and threatened to teach him a lesson for asking you to furnish account of money taken by you. Gesticulating at Mr. Karan you told your cohorts, "Achi Tarah Se is Adami Ko Tumlog Pahachain lo. Ise Main Zinda Nahin Chhorunga Kisi Bhi Kimat Par. Az Tumlog Pahachan lo Fir Khabhi Dekha Jayega". Saying thus you violently thumped his desk and came out of his chamber followed by those 7 outsiders. Thus you resorted to rowdism forming an unlawful assembly in his chamber.

Charge No. 6 : On 18th June, 1988 also when you came to the office of the company in Rajendra Market Mr. Karan asked you in his chamber at about 11 A.M. to furnish a statement of account of the money allegedly expanded by you on coal transporting. But you again got furious and abused him in filthy language. While flouting his most reasonable and lawful advice you created a riotous scene in his chamber which attracted the attention of other staff working in the office. As it has been alleged against you, you raised your right hand with the obvious intention to slap him but he frusted your move by holding your hand. You tried to grapple with him but he saved himself by swiftly moving away from his position and leaving his chamber. Still you kept on abusing him which was heard not only by other personnel of the company but some customers also who had come to the office in connection with business with the company. You left the office shouting that you would finish off Mr. Karan very soon. You uttered these words in Hindi. "Mistar Karan Mein Tumhara Jald Hi Kam Tamam Kar Dunga. Tumko Mujko Aur Rupya Dena Hoga. Aur Yeh Bhai Sunlo Ki Maine Jo Advance Rupya Liya Hai Use Bhi Nahin Dunga. Apane Salary se Nahin Katwaunga."

Please note that charge Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 constitute beyond all reasonable doubts serious misconducts on your part under sub-sections 5, 2, 3, 8, 29 and 18 of section 15 of the certified Standing Orders of the company. Accordingly we hereby charge you that you have committed serious misconducts as stated above.

You are, therefore, hereby called upon to submit your explanation in writing to the full satisfaction of the management within 3 days from the date of receipt of this chargesheet as to why appropriate disciplinary action should not be taken against you by the management of the company for your aforesaid misconducts. Please note that if your explanation is not received by us as directed above it will be safely presumed that you have no explanation to offer in your defence and as such you have accepted the charges of misconducts alleged against you. In that position the management shall be at liberty to dispose of this matter according to its discretion and you shall have no lawful grievance to complain against the company."

11. It appears that the charge-sheet conforms to the complaint made by Shri N. K. Karan, Works Manager to Mr. Chaturvedi. It is required that the charge shall contain such particulars as to the time and place of the alleged offence and the things in respect of which it was committed as are reasonably sufficient to give the person proceeded against notice of the matter with which he is charged. But where the nature of the case is such that the particulars mentioned above do not given the person proceeded against sufficient notice of the matter with which he is charged, the charge shall also contain such particulars of the manner in which the alleged offence was committed as will be sufficient for the purpose. In the present case the charge-sheet discloses the time and place of the alleged offence, the things in respect of which it was committed and the manner in which the concerned workman committed the various acts of misconduct have borne out in the charge-sheet.

The concerned workman was served with a charge sheet and pat came his reply/explanation to the charge-sheet dated 27th June, 1988 which is re-produced hereinbelow (Ext. M-2):

"While acknowledging receipt of the letters under reference received by Regd. Post, I lay the following facts for your kind consideration and judicious orders please.

The charges as levelled against me are baseless, without grounds and are in no way connected to my nature and character. I have served the company for years together without any complaint of any sort, from any corner, I have neither mis-behaved with the Works Manager Sri Karan at any stage nor I have misappropriated any money of the company during my working.

A fact finding enquiry will yield the correct picture in the matter as the charges so levelled are based on substantial evidences and records.

Incidentally I will like to mention herein that I was man-handled by three un-known persons who came to my residence on 18th June, 1988 afternoon and at the instant moment I became very much perplexed, frightened and in course of self defence I informed the Police and subsequently they were arrested while running away by Dhansar Police official and they stated many things and also said that I should resign from the job, so that the Works Manager Sri Karan can employ 4 persons of his choice. I would further like to mention that the letter placing me under suspension is dated 18th June, 1988 (Saturday) whereas the same has been Regd. on 21st June, 1988 (Tuesday). It is very strange that when the suspension letter was signed on 18th June, 1988 then why the same was not despatched on 20th June, 1988 (Monday) and this makes me a bit confused and I feel that the suspension letter was prepared on 21st June, 1988 (Tuesday) on being apprised of the facts that the un-known persons who man-handled me on 18-6-1988 have been arrested and to

prepare a shield to safe guard Sri Karan, the baseless charges have been levelled against me.

I would further request your kindself to kindly issue letters to me in HINDI considering that I am a HARIJAN.

You are also requested to allow me to resume my duties with immediate effect and oblige."

12. In his reply/explanation to the charge-sheet submitted by the concerned workman to the management he denied the charges as levelled against him as they were baseless. without any ground and in no way connected with his nature and character and that he had neither mis-behaved with the Works Manager, Shri Karan at any stage nor had he mis appropriated any money of the company. Thereafter, he narrated the incident allegedly happened in his residence on 18th June, 1988 afternoon, when three un-known persons burged into his room, man-handled him and he informed the matter to the police. It is evident from his reply/explanation that he did not disclose any positive statements of facts with regard to the charges brought against him.

13. I will now proceed on to scan the charges, evidence laid by the management to prove the same and whether there is sufficient evidence on record to hold if charges have been proved or not. But before doing so, I consider worthwhile that 18th June, 1988 was an important date in so far as the present proceeding is concerned. On that date, as per attendance register the concerned workman was present in his duty. As per the charge-sheet on that date at about 11 A.M. the concerned workman abused Shri N. K. Karan in his chamber in the office of the company at Rajendra Market and attempted to assault him. On that date Shri Karan made a written complaint against the concerned workman to Shri Ramesh Kumar Chawda and at about 2 P.M. on that date Shri Chawda directed the Manager (Administration) to initiate immediate disciplinary proceeding against the concerned workman as per Certified Standing Orders of the company. As per the information provided by the concerned workman to the Officer Incharge, Dhansar Police Station on that date at about 3.30 P.M. some 5/6 persons who allegedly barged into his room, man-handled him and asked him to return Rs. 10,000 which he had taken from the company. On that date also the concerned workman was put under suspension.

14. The first count of charge relates to absence of the concerned workman from duty from 8th June, 1988 to 13th June, 1988 without permission from or information to the management. The Enquiry Officer, relying on the evidence laid by the management, came to the conclusion that the concerned workman absented himself from duty from 8th June, 1988 to 13th June, 1988. He did not, however, record any definite finding as to whether the concerned workman was guilty of the charge comprehended under Clause 15(5) of the Certified Standing Orders of the Company. Clause 15(5) envisages that absence without sanction of leave on the part of any workman is a misconduct. I consider this provision to be a suffocating one as it does not provide for any contingency or exigency. Absence from duty without information to or permission from the management is not a misconduct under the Certified Standing Orders. The evidence on record including Attendance Register (Exts. M-17 and M-17/1) indicates that the concerned workman was absent from duty from 8th June, 1988 to 13th June, 1988 without making any application for leave. There is no evidence on record that there existed contingency or exigency on the part of the concerned workman to remain absent from duty without permission from or intimation to the management or without sanction of any leave. Even so, I agree with Shri J. P. Singh, learned Advocate for the concerned workman that this misconduct was not of such grave in nature as to warrant dismissal of the concerned workman from service, if considered isolatedly. But this misconduct, taking into account of other acts of misconducts, may lead to dismissal from service.

The second count of charge is that the concerned workman had taken a sum of Rs. 15,828 in total—Rs. 5000 on 9th May, 1988 Rs. 6,828 on 25th May, 1988 and Rs. 4000 on 2nd June, 1988, but did not render any account. It was alleged that he had taken money fraudulently and mis-appropriated the same and thereby committed fraud or dishonesty in connection with company's business or property comprehended under Clause 15(2) of the Certified Standing Orders of the company. In his rejoinder to the written statement of the management. the concerned workman has simply denied the charge, and stated that he was given some money on vouchers to meet miscellaneous expenses and he was to submit account for the money given to him in Accounts Office of the employers.

Shri J. P. Singh, learned Advocate for the concerned workman has contended that the concerned workman used to receive advance on vouchers for defraying miscellaneous expenses and that he has accounted for the money advanced to him. He has drawn my attention to the voucher dated 26th May, 1988 for Rs. 2098, voucher dated 28th May, 1988 for Rs. 2358 and voucher dated 30th May, 1988 for Rs. 2372.50 aggregating to Rs. 6,828.50 marked Exts. M-10. M-10/1 and M-10/2 in the domestic enquiry proceeding. The particulars of the vouchers read as : 'Cash paid to Y. Rajak towards loading and supervision expenses incurred at following collieries against D.O. dated 14/5 as slip dated 26/5, 27/5 and 28/5,. On 25th May, 1988 Shri Rajak submitted a statement of account marked Ext. M-8 in the domestic enquiry for Rs. 6,828.50. Shri J. P. Singh has submitted that the concerned workman incurred the expenses as represented in Ext. M-8 and the management reimbursed him by voucher marked Ext. M-10 series. He has further submitted that the referred to some other collieries, such as, East Bhggatdly made exhibit in domestic enquiry. In other words, the contention of the concerned is that he defrayed the expenses and was reimbursed by the management. On the other hand, the contention of the management is that Ext. M-8 represents an estimated amount of expenses which was paid to the concerned workman by vouchers on different dates. The D.Os. marked Exts. M-7 series are referable to collieries named North Tisra, Joyrampur, Jeenagora, Maheshpur and Damagoria quantities being 43MT, 43MT, 21MT, 65MT and 43MT respectively. But in Ext. M-8 the concerned workman has referred to some other collieries, such as, East Bhggatdly Area, G.O.C.P. Area, Ghannodih Area by referring the same D.O. date. When there existed no D.O. for delivery of coal from these collieries, there was no scope for referring these collieries in his purported expenses as reflected in Ext. M-8. This being so, he could not have incurred this expenses as mentioned in Ext. M-8. The Enquiry Officer has also stated that it was an estimated amount of expenses. The other evidence on record also is indicative of this position. Hence, it is evidenced that the concerned workman submitted as estimated account of expense by Ext. M-8 for Rs. 6,828.50 which he was paid by three different vouchers on three different dates as mentioned in Ext. M-10 series. There is no evidence to indicate that he rendered any account of this expense.

Sri Manohar Lal Rathore has stated that apart from this some of Rs. 6,828.50 he gave the concerned workman Rs. 5,000/- and Rs. 4,000/- on 9-5-88 and 2-6-88 respectively under the advice of Shri Karan and Shri Manoj Chaturvedi. Shri N. K. Karan has stated that the concerned workman took Rs. 5,000/- on 9-5-88 an Rs. 4,000/- on 2-6-88 for lifting of coal from the collieries. The management produced a slip written by Shri Rathore confirming that on the advice of Shri Karan and Shri Chaturvedi he gave a sum of Rs. 5,000 to the concerned on 9th May, 1988 and Rs. 4,000 on 2nd June, 1988 (Ext. M-13).

With regard to the advance of money the concerned workman has taken different stances in different forum. His first stance is that he was advanced Rs. 6,828.50 from the company and rendered accounts therefor. I have already concluded that there is no evidence on record to indicate that he rendered accounts for this amount. Before the Asstt. Labour Commissioner he had stated in writing that he had taken Rs. 9.000 only from the company and submitted accounts on 25-5-88 giving full details for Rs. 6,828.50 and the remaining amount was returned/handed over to Shri N. K. Karan, Manager. There is no evidence on record to indicate that he returned the balance amount to Shri N. K. Karan. Shri Karan was not the Cashier of the company. He was Works Manager. In this context if is improbable to believe that the concerned workman handed over balance amount to Shri N. K. Karan. Then again, in his written information to the police on 16-6-88 (Ext. W-4) he has stated nearly 5/6 days ago Shri Narendra Kumar Karan, who is Manager of the Company had given him Rs. 10,000 to do the company's

work concerning collieries and he returned the above amount on 15-6-88 at 11 A.M. because the work was not accomplished. He has not disclosed to whom he returned the money. Thus, upon consideration of evidence on record and keeping in view the inconsistent stand of the concerned workman with respect of advance of money to him by the management, I come to the conclusion that the company advanced to him a sum of Rs. 15,828 on different dates for defraying expenses in connection with lifting of coal from different collieries, but the concerned workman did not render any account nor did he pay back the amount to the company. In the circumstances, I hold that he committed an act of misconduct of dishonesty in connection with company's property or business.

The third count of charge underlines the fact that since the concerned workman could not procure coal from the collieries of M/s. B.C.C. Ltd. in spite of his assurance, the company suffered financial loss to the tune of nearly Rs. 2,00,000 because the plant operation was seriously hit by acute shortage of coal. This being the position, the concerned workman was arraigned on a charge for causing wilful damage or loss of company's goods or property to the tune of nearly Rs. 2,00,000 under Clause 15(3) of the Standing Orders of the Company.

Shri J. P. Singh, learned Advocate for the concerned workman has contended that the management has failed to produce the Stock Book to show the stock position of the coal or to show if the coal had arrived or not. Indeed, the stock book of coal, if produced, could have thrown light on the stock position of the coal of the company. Sri N. K. Karan is the sole witness for the management to prove this count of charge. He has stated in the domestic enquiry that he waited for the whole day on 3-6-88 at the plant for arrival of coal, but coal was not brought till the evening and non-arrival of coal resulted in loss of about Rs. 2,00,000 to the company. He has not explained how non-arrival of the coal affected the opeation of plant and in the process the company suffered loss of Rs. 2,00,000. The Enquiry Officer held the concerned workman guilty of misconduct on this count of charge. But he has not spelt out any reason for coming to the conclusion. I have no hesitation to hold that the Enquiry Officer was not justified in holding the concerned workman guilty of misconduct on this count of charge.

15. Now I will consider three other counts of charges, namely, Charge Nos. 4, 5 and 6 levelled against the concerned workman.

Charge No. 4 underlines the fact that when advised by Shri N. K. Karan on 15-6-88 at about 11.30 A.M. in the plant office in presence of Sri Kamal Banerjee and Sri Madhusudan Singh to submit full account of the money taken by him, the concerned workman flared up and abused Shri Karan in contemptuous offensive language and haughtily moved about in the office creating harsh grating sounds by shoes and while leaving the office he threatened Shri Karan. For this act of misconduct the concerned workman was arraigned charge of misconduct for riotous or disorderly behaviour.

Shri N. K. Karan has stated in his statement in the domestic enquiry that he was having discussion on 15-6-88 at about 11.30 A.M. at the plant office with S|Shri Kamal Banerjee and Mahusudan Singh, employees of the company, when the concerned workman appeared He has further stated that on being advised submit accounts of expenses of the money he had taken from the company, the concerned workman flared up, behaved disorderly and banged on the floor by shoes. Kamal Kant Banerjee and Madhusudan Singh have corroborated the fact stated by Shri Karan. There is no evidence on record to militate against this fact. Hence, I have to conclude that the charge of misconduct of disorderly behaviour brought against the concerned workman has been satisfactorily proved.

Charge No. 5 discloses that on 17-6-88 at 11.45 A.M. the concerned workman accompanied by ferocious looking seven unknown persons rushed into the chamber of Sri N. K. Karan located in Rajendra market and threatened to teach him a lesson for asking him (concerned workman) to furnish account of money. Gesticulating at Sri Karan he told his cohorts : "Achi Tarah Se is Adami Ko Tumlog Pehachan lo, Ise Main Zinda Nahin Chhorunga Kisi Bhi Kimat Par, Ab Tumlog Pahachan lo Fir Khabhi Dekha Jayega." and saying thus he violently thumped his desk and came out of the chamber of Sri Karan followed by those seven outsiders. Upon these facts charge of misconduct for forming unlawful assembly and resorting to rowdism has been brought against the concerned workman. Sri N. K. Karan has stated that on 16-6-88 when he was working in the company's office situated at Rajendra Market, the concerned workman barged into his chamber accompanied by ferocious looking seven outsiders. The concerned workman asked them to recognise Shri Karan carefully and declared that he would not allow Sri Karan to remain alive and while saying so he violently thumped his desk and went out of the chamber followed by those seven persons. He has stated that such behaviour on the part of the concerned workman greatly perplexed him and as such he felt danger to his life. Maniruddin Ansari was posted as Guard in the company's office situated in Rajendra Market. He has explained that on 17-6-88 at about 12 Noon the concerned workman marked his attendance in the Attendance Register, went into the chamber of Sri Karan accompanied by 6/7 persons and the concerned workman began threatening Sri Karan that he would teach him (Sri Karan) a lesson. Sri Karan has not disclosed in his statement about the time of occurrence. According to Sri Ansari the occurence took place at about 12 noon while the charge-sheet speficies it to have happened about 11.30 A.M. Sri Ansari seems to be a "peeping" witness. It appears from the Attendance Register that the cocerned workman attended his office on 17-6-88. There is no evidence on record to indicate that he left the office on the sly, brought 6/7 unknown persons and formed an unlawful assembly in the chamber of Sri Karan. Besides, Sri Karan has not disclosed in his evidence as to the time when alleged occurrence took place. Hence, cannot persuade myself to believe that the management has been able to prove this count of charge satisfactorily.

The last charge against the concerned workman is for commission of misconduct of threatening, abusing and attempt to assault any superior in the plant premises. The charge-sheet discloses that on 18-6-88 the concened workman came to the office of the company in Rajendra Market and on being asked by Sri N. K. Karan in his chamber at about 11 A.M. to furnish statement of account, he became furious, abused him in filthy language, created riotous scene and attempted to assault Sri Karan. This incident was witnessed by other workmen of the office of the company and customers who had come to the office in connection with the business of the company. Shri N. K. Karan is a superior officer of the concerned workman. Shri Karan has stated that on 18-6-88 he asked the concerned workman about his intention to bring outsiders to the office yesterday and wanted to know what was troubling him in submitting account of money which he had taken from the company. According to Sri Karan, the concerned workman exploded with anger, threatened him and raised his hand to hit him (Sri Karan). He rushed out of the chamber but the concerned workman kept on raining invectives on him (Sri Karan) even though he had left the chamber. Maniruddin Ansari has supported Sri N. K. Karan by stating that the concerned workman abused and threatened Sri Karan in his Chamber. S. P. Srivastav is an outsider. He has stated that on 18-6-88 while he was sitting in the chamber of Sri Karan and talking to him, the concerned workman came there and on being asked by Sri Karan to submit account the concerned workman began to abuse Sri Karan and raised his hand to hit him. According to him, Sri Karan swiftly jumped out of his chair and moved away in a corner, but the concerned workman lunged at him and witness was asked to keep quiet by the concerned workman by frown. Indra Shekhar Karn, Stenographer of the company, has supported these two witnesses. Jhagru Ram associated with coal business with the Industrial Fuel Company, has also supported the statement of Sri N. K. Karan.

Upon consideration of evidence, I hold that the charge of misconduct of threatening, abusing or attempt to assault any superior officer inside the plant premises against the concerned workman has been proved satisfactorily.

16. Thus, the charges of fraud of dishonesty in connection with company's business or property, disorderly behaviour and threatening abusing and attempt to assault Sri N. K. Karan, superior officer, inside the plant premises, have been proved

satisfactorily. These acts of misconducts are indeed of grave nature and in the circumstances, the management was justified in dismissing the concerned workman from service for these acts of misconducts.

17. Before I conclude I direct the management to pay the concerned workman his provident fund dues with full interest and other benefits and a sum of Rs. 5,000 in consideration of his past satisfactory service.

18. Accordingly, the following award is rendered—

the action of the management of M/s. Industrial Fuel Company, Katras Road Dhanbad in dismissing Shri Yogendra Kumar Rajak vide dismissal order No. IFO/346/88 dated 21-9-1988 is jusified. The management is directed to pay him his provident fund dues with full interest and other benefits and also to pay him Rs. 5,000 in consideration of his past satisfactory service.

In the circumstances of the case, I award no cost.

This is my award.

S. K. MITRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 29 मई, 1992

का.आ. 1638.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मै. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं. लि. की चासनाला कोलियरी के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 2) धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-20012/80/86-डी-3(ए)]
वी. के. वेणुगोपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th May, 1992

S.O. 1638.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Chasnaha Colly. of M/s. Indian iron of Steel Co. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 27-5-92.

[No. L-20012/80/86. D-III(A)]
V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. Ram, Presiding Officer.

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

REFERENCE NO. 217 OF 1986

PARTIES :

Employers in relation to the management of Chasnalla Colliery of Messrs Indian Iron and Steel Company Ltd. and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

On behalf of the employers : Shri R. S. Murthy, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dated, Dhanbad, the 21st May, 1992

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/80/86-D.III(A), dated, the 1st July, 1986.

SCHEDULE

"Whether the demand of Bihar Colliery Kamgar Union that the management of Chasnalla Colliery of M/s. Indian Iron and Steel Company Limited should give their workmen, whose names are given below, one additional increment each from 1-1-1983 is justified. If so, to what relief are these workmen entitled ?"

1. Shri L. N. Mahato.
2. ,, R. Barhi.
3. ,, A. K. Dasgupta.
4. ,, Beblal Singh.
5. ,, Jhalu Sao.
6. ,, M. D. Hassim.
7. ,, C. R. Chakraborty.
8. ,, Shri S. P. Kar
9. ,, S. N. Chakraborty.
10. ,, S. K. Biswas.
11. ,, B. D. Singh.
12. ,, R. N. Singh.
13. ,, D. N. Mukherjee.

2. There are in all 13 concerned workmen as referred to in the schedule who claimed one additional increment each from 1-1-83. It was stated on their behalf that they are permanent workmen of Chasnalla colliery. Shri B. D. Singh, Shri R. N. Singh and D. N. Mukherjee are Overman while the rests are Mining Sirdars. It was stated that the provision of NCWA-II and III was implemented by the management and according to the provision of NCWA-III all the concerned workmen are entitled for one spacial increment for putting 10 years of service in the same job. It was also pointed out that other workemen have already been sanctioned special increment according to the said provision.

3. The concerned workmen represented their case before the management several times for their increment as per NCWA-III but without any effect.

4. It was stated that the Mining Sirdars are entitled for Technical Grade-C and Overmen for Grade-B from the date of their appointment in their respective posts. But the management simply to victimise them have placed the Mining Sirdars and the Overmen in the said grade since from the year 1975 only. The management refused to settle the issue amicably so the concerned workmen had to raise the industrial dispute before the ALC(C), Dhanbad and that also ended in failure giving rise to the present reference.

5. The management refused the claim of additional increment as stated by the concerned workmen. It was stated that the notes of the conclusion drawn by the JBCCI after the finalisation of NCWA-III dated 11.11.83 made certain provision with regards to stagnation increment to the employees in the coal industry. In the W.S. necessary provision have already been reproduced.

6. It was further pointed out that the promotion policy committee however could not reach at any unanimous conclusion in regard to the service link promotion scheme as envisaged in the above extract. Therefore it was decided that the employees who have ramained in the same pay scale category/grade for 10 years or more for want of promotional avenue as on 1.1.83 would be given one increment in the revised pay scale under NCWA-III with effect from 1.1.83.

7. As regards gradation of the Mining Sirdar and Overman it was stated that NCWA-I came into force from 1.1.75 according to which the head overman or the Senior Overman or Overman incharge were placed in Technical and Supervisory Grade-A while Overman were placed in Grade-B

Similarly Mining Sirdar Class I were placed in Grade-C and so there was nothing wrong if the management placed them in the aforesaid Grade from the year 1975. There was up gradation of the pay scale of subordinate Mining staff in the year 1975 and so they cannot be said to be in the same grade or scale for the last 10 years as on 1.1.83 and therefore they are not entitled to the abeve benefit granted by NCWA. For these reasons it was stated that the concerned workmen have got no claim and the award be passed accordingly.

8. The workmen claim one additional increment as on 1.1.83 on the ground that they have already completed 10 years of service in the same pay scale of the grade. In the W.S.I find no mention anywhere as to when these concerned workmen had actually joined their services. Naturally there is no point as to from when the period of 10 years will be counted. According to them they completed 10 years of service as on 1.1.83 so naturally they are expected to have join their service on or before 1.1.73. They have claimed one additional increment according to the provision contained in NCWA-III. Sub-para 2.3 of NCWA-III provides that the promotional policy committee should complete its work as expeditiously as possible but not later than three months and its unanimous recommendation will be implemented from 1.1.1983 in so far as they relate to those employees who for want of promotional avenues continue to remain in the same category/grade throughout their service carreer for 10 years or more as on 1.1.83. At this stage the learned counsel for the managment submitted that NCWA-I was implemented on 1.1.75 whereby the wage structure of all the employees irrespactive of their position were changed giving so many benefits to the workmen and so naturally the concerned workmen pay structure had undergone change in the years 1975. Therefore they cannot be said to be in the same pay as contended by the learned counsel for the workmen. A period of 10 years will not be covered in between 1.1.75 and 1.1.83 and therefore the concerned workmen are not entitled for any additional increment.

9. As regards the gradation of the Mining Staff it was pointed out that in Chapter VI to the NCWA-I there were some necessary provision whereby the head overmen or Senior Overman or Overman incharge were placed in Technical and Supervisory Grade-A while the overman were placed in Grade-B. Similarly as per sub clause 6.2 the mining Sirdar Class I and Class II were placed in revised grade-C. It was submitted by the learned counsel for the management that according to the provision the concerned workmen were placed in the grade only after the implementation of NCWA-I and so there was no question of any victimisation of the concerned workmen by the management. I have gone through the ralevant provision of NCWA-I and NCWA-III and in view of the specific provision and also as per discussions made above I find no merit in the demand of the concerned workmen and they are not entitled to any additional increment as on 1.1.83 as canvassed by the learned counsel for the workmen.

In the result, I hold that the demand of Bihar Colliery Kamgar Union that the management of Chasnalla Colliery of M/s. Indian Iron and Steel Company Limited should give their workmen, whose names are given below, one additional increment each from 1.1.1983 is not justified consequently the concerned workmen are entitled to no relief.

B. RAM, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 29 मई, 1992

का.आ. 1639.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मै. बी.सी.सी.एल. की जीलगोरा कोलियरी के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं. 1), धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-20012/57/88-आई.आर. (कोल-1)]

वी.के. वेणुगोपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th May, 1992

S.O. 1639.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 1). Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the manaemgent of Jealgora Colliery of M/s. B.C.C.Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on 25-5-92.

[No. L-20012(57)/88-IR(Coal-I)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I AT DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 51 of 1990

PARTIES:

Employersin relation to the management of Jealgora Colliery of M/s. B.C.C. Ltd.

AND

Their Workmen

PRESENT:

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the Employers—Shri R. S Murthy, Advocate.

For the Workmen—Shri D. Mukherjee, Secretary Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dated, the 19th May, 1992

AWARD

By Order No. L-20012(57)/88-I.R. (Coal-I), dated, the 27th February, 1990, the Central Govt. in the Ministry has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2-A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to his Tribunal :

"Whether the action of the management of Jealgora Colliery of M/s. B.C.C.L in denying employment to Shri Nitish and 119 other workmen (given in Annexure) is justified? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?"

ANNEXURE

Jealgora Colliery

1. Nitish
2. Harilal
3. Satia
4. Sukhnandan
5. Dasrath
6. Ramswarup
7. Dyaram
8. Monilal
9. Jugal Kishore
10. Thakuri
11. Kailash
12. Ambika
13. Naijan
14. Hamam
15. Moyeen
16. Jamaluddin
17. Basudeo
18. Lashman
19. Barku

20. Nagina
21. Chandrashwar
22. Ajim
23. Ganga Prasad
24. Moti Chand
25. Khurshid
26. Halimuddin
27. Niazuddin
28. Ramdhant
29. Ramwatar
30. Kapildeo
31. Sahadao
32. Naddique
33. Md. Ahmed
34. Baijnath
35. Nazir.
36. Sahadat
37. Chandika
38. Jayram
39. Sri Bhagwan
40. Sri Ram
41. Ramlashmun
42. Mayaram
43. Meghan
44. Durga
45. Jaut
46. Jabahir
47. Sarju Thakur
48. Chandradip
49. Ramanand
50. Prayg
51. Pramanand
52. Bimal
53. Kishoreram
54. Narayan
55. Rajnath
56. Musuf
57. Jangli
58. Ramanand
59. Sukuru
60. Harikishun
61. Saguni
62. Gangadhar
63. Dinanath
64. Ganeshi
65. Kaloo
66. Dhuneshwar
67. Saddique
68. Bhuneshwar
69. Kalicharan
70. Rama Prasad
71. Laldip
72. Jagdish
73. Nageshwar
74. Jhari
75. Mahamad
76. Chaturi
77. Siawenath
78. Kartik
79. Mitu Prasad
80. Baleshwar
81. Sarjoo
82. Ramdhani
83. Dipchand
84. Ramlal
85. Nirmal
86. Jagarnath
87. Rainath
88. Budhadeo
89. Puran
90 Md. Yunia
91. Chattu
92. Ramratan
93. Rajaram
94. Mangal
95. Gopali
96. Rupan
97. Alok Saw
98. Bhim
99. Ali Hussain
100. Martuja
101. Muktar
102. Gobind
103. Sakaldeo
104. Irfan
105. Biswanath
160. Rafiik
107. Mazid
108. Jagdish
109. Nageshwar
110. Atul
111. Janardhan

2. The case of the management of Jealgora Colliery of M/S. B.C.C. Ltd, Dhanbad, as disclosed in the written statement-cum-rejoinder, details apart, is as follows :

The Central Government as the appropriate Government had no power or authority to revise its earlier decision refusing to refer the dispute for adjudication. Besides, the dispute is also over-stale and the appropriate Government was quite justified in rejecting the reference of the industrial dispute for adjudication earlier on the ground of its being stale. That apart, the issue referred to the Tribunal is not an industrial dispute within the meaning of Sec.2(k) of the Industrial Disputes Act. There exists a three tier set up for examination and consideration of the demand of the principal unions. The sponsoring union being one of such principal trade unions. It had never had taken up the issue covered by the present reference at any time with the management at any level. Suddenly the union sprang a surprise by sending a letter dt. 23-2-87 to the Asstt. Labour Commissioner (C), Dhanbad, in connection with the present matter. A.L.C.(C), Dhanbad, by letter dated 24-3-87 sent a copy of the letter of the union calling upon the management to attend a meeting in his office on 4-4-87. It is for the first time that the management heard of the matter towards the end of March, 1987. Although the union had stated that it had attached to its letter a list of persons concerned embodying information relating to the number of days of attendannce put in by the persons concerned and their token numbers, but no such information was included in the said letter. It is well known that in Jharia Coalfields some of the interested persons have been making efforts to induct impersonators into the employment of the management of M/s. B.C.C Ltd. on some ground or other and the management has reason to believe that the present case is one such cases, otherwise, there is no ostensible reason as to why the so called persons have kept quiet for nearly 20 years and suddenly they have woken up like Rip Van Winkle of Kumbhakarna. The concerned persons are all fake persons and impersonators; they have no right to claim employment in M/s. B.C.C. Ltd. A deliberate attempt is being made to induct these fake persons into the employment of the management because it is well known that no employer keeps records of persons employed by him for 10, 15 or 20 years. As per the provisions of the Coal Mines Provident Fund Scheme. as amended upto 1970, the workers putting in attendance of 48 days in a coal mine in the underground section and 64 days on the surface are entitled to become members of the C.M.P.F. The C.M.P.F: authorities are extremely strict in enforcing this provision. If there is any grain of truth in the case of the workmen, they would have been members of the C.M.P.F. Scheme. but there is no evidence whatsoever to that effect. That the union has never at any stage and even before this Tribunal disclosed the parentage, address, age of the persons concerned will go to fortify the stand of the management that the present claim is a fake claim and a deliberate attempt is being made to induct fake persons and impersonaters into the employment of the management. When the union raised the dispute before the A.L.C.(C) Dhanbad by letter dated 23-2-87 it had stated that the persons concerned were stopped from duty in the year 1974-75. But now the union has come forward with an entirely different story. The persons were never the members of the sponsoring union and it has no locus standi to take up their case and to raise the present dispute The persons concerned are not entitled to employment under the management. The management is not also required to keep into employment each and every person whose case is taken up by any trade union by misrepresentation and after a generation gap. In the circumstances, the management has submitted that the Tribunal be pleased to hold that the management is not required to employ any of the persons concerned and the stand of the management not to provide employment to them is justified.

3. The case of the concerned workmen, as appearing in the written statement on behalf of the sponsoring union, Bihar Colliery Kamgar Union briefly stated is as follows :

The concerned 111 workmen had been working in Jealgora colliery and against the permanent vacancy continuously since long prior to the date of take over of the colliery. Some of the concerned workmen were stopped from duty by the management without assigning any reason from June/July/August/September, 1972 and some were stopped in the year 1973. The concerned workmen vehemently protested against the illegal and arbitrary stoppage of work by the management. They represented before the management challenging the illegal and arbitrary stoppage of work with a demand for reinstatement in service with full back wages. At that time the management assured them that their grievance will be looked into and informed them that the matter had been referred to the Headquarters for decision. The management of M/s B.C.C.Ltd., however, appreciating the legal position, allowed many other workmen of different collieries to resume their duties on the strength of their putting 75 days attendance during the calendar year 1973—76. The concerned workman represented to the management that they should be atleast allowed to resume duty in pursuance of the aforesaid decision of the management. Their further submission was that they had put 240 days attendance in each calendar year. Even so they are ready to accept the offer of employment as has been done in connection with de-listed workmen who had put in only 75 days attendance in a calendar year. They further submitted to the management that a note sheet dated 2-7-72 was initiated by the then Group Officer Shri S. S. Sharma and Personnel Officer, Sri S. K. Banerjee, Jealgora colliery for their reinstatement/deployment. By the said notesheet/letter the aforesaid officers represented to the Head Quarters to approve deployment of 132 workmen. The list of 132 workmen was subsequently increased by adding 11 more workmen to make it 143. This was done as per letter dated 17-8-79 of Sri R. K. Trivedi, the then Welfare Officer of Jealgora colliery. Such addition of 11 more workmen was done as per the advice of Group Officer and Personnel Officer and the same was communicated by their letter dated 5-7-72 and 26-6-73. The Manager of the colliery also addressed a letter dated 14-7-73 to the then Group Officer, Jealgora Colliery for employment of the concerned workmen alongwith some other workmen. Out of the aforesaid list of 143 workmen, the management has taken into employment 16 workmen after entering into a conciliation settlement with the United Coal Workers Union under the leadership of Sri S. K. Rai on 26-4-78. The concerned workmen had brought the matter to the notice of the management, but the local management preferred to discriminate the workmen on the ground of Trade Union Affiliation. The Agent of the colliery recommended for employment of the concerned workmen by letter addressed to Sri B. K. Singh, Dy. Personnel Manager (HQ). Besides the aforesaid letter and some other letters, the local management had issued several other letters and initiated notesheet addressed to the Head Quarter for employment of the concerned workmen, but the Head Quarter never approved of the notesheet or the letter of the maangement for deployment of the concerned workmen in order to victimise them for their affiliation to B.C.K. Union. The same issue was also discussed with the management on several occasions and lastly on 14-5-85. As per the aforesaid discussion, a record note of discussion was also prepared and thereby the management agreed to take action in the matter. But the management had never communicated to the union the action taken by it in the matter as per the note-sheet. After exhausting all avenues, the concerned workmen raised a dispute before the A.L.C(C), Dhanbad, but the same ended in failure due to adament attitude of the management. The Government of India, Ministry of Labour, at first rejected the dispute for reference on some flimsy ground. The union challenged the decision of the Government before the Hon'ble High Court, Patna, Ranchi Bench. The Hon'ble Court was pleased to issue a show-cause notice to the Government of India for not referring the dispute after admitting writ petition. The union also represented to the Ministry of Labour stating therein the whole facts and the decision of the High Court in the matter. The Ministry of Labour Govt. of India, appreciating the legal position, referred the dispute for adjudication to this Tribunal. The action of the management of Jealgora Colliery in denying employment to the concerned workmen is unjustified and illegal. The action of the management in not providing employment to them with retrospective is illegal, arbitratry and against the principles of natural justice.

4. In rejoinder to the written statement of the sponsoring union, the management has stated that the persons for whom the employment is claimed are not the persons bearing those names and they never worked under the management. Since they were never employed by the management, the question of the management stopping any of these persons from duty does not arise. It transpired that some documents have been manipulated and fabricated to support untenable case. The union manipulated and fabricated some of the documents. The persons concerned also manipulated and fabricated some documents. Finally the management has stated that the claim of the workman is not justified and that the appropriate Government was not right in referring the dispute for adjudication.

5. In rejoinder to the written staetment of the management, the union has asserted that the appropriate Governmetnt has absolute power to refer the dispute for adjudication which was rejected earlier. The decision cited by the management on the point of demand of the Union being overstale has got no relevancy in so far as the present dispute is concerned. The management had issued circular in different years and lastly also in 1980 wherein and whereby they agreed to take back into employment of all the workmen who had put 75 days attendance during calendar years 1973—76. The concerned workmen represented before the management several times for their deployment as per the aforesaid circular, but without any effect. The present industrial dispute is an industrial dispute within the meaning of Sec. 2(k) of the Industrial Disputes Act. The present dispute was taken up with the management several time and the management assured the sponsoring union to settle the issue favourably. The union has denied that the concerned workmen are fake persons or impersonators. It has been alleged that the higher management has been doing nefarious things to induct persons in M/s. BCCL It has been submitted that all the concerned workmen are real workmen and they have got right for reinstatement in service of M/s. B.C.C.L The union has denied that it has made deliberate attempt to induct fake persons into employment of the management.

6. The management, in order to sustain its action has adduced no oral evidence, but laid in evidence some documents which have been marked Exts. M-1 to M-3.

On the other hand, the sponsoring union has examined two of the concerned workmen, namely W.W.1 Alok Saw and W.W. 2 Dipchand and laid in evidence some documents which have been marked Exts. W-1 to W-4.

7. Undeniably, Jealgora colliery is a coking coal mine and it was nationalised with effect from 1-5-1972 and prior to nationalisation the colliery was owned by East India Coal Co. Ltd., Jealgora

8. The case of the spensoring union is that the concerned 111 workmen had been working in Jealgora Colliery continuously from before the date of take over of the colliery and that some of them were stopped from duty by the management without assigning any reason from June/July/August/September, 1972 and some in the year 1973. The union has further asserted that the concerned workman had put in more than 240 days attendance in each calendar year and consequent upon their representation on being stopped from work, Sri S. S. Sharma, the then Group Officer and Sri S. K. Banerjee, the then Personnel Officer of Jealgora colliery, by letter dated 2-7-72 informed the Head Quarters to approve deployment of 132 workmen including the concerned workmen and later this list of 132 workmen were increased by adding 11 more workmen to make it 143. The Manager of the colliery also by letter dated 14-7-72 addressed to the then Group Officer, Jealgora colliery providing information about employment of the concerned workmen alongwith other workmen and that out of the list of 143 workman, the mangement took into employment 16 workmen after entering into a conciliation settlement on 26-4-78 with the United Coal Workers Union. The Agent of the colliery also recommended employment of the concerned workmen by his letter addressed to Sri B. K. Singh, Dy. Personnel Manager, Head Quarters The union has been pusuing the case since long and held several discussions, lastly on 14-8-85 with the management. It has been asserted that after exhausting all

avenue and industrial dispute was raised before the ALC(C) Dhanbad, but the same ended in failure and the Ministry of Labour at first rejected the dispute for reference on some firmly ground. The decision of the Governmentt was challenged by the union before Hon'ble High Court, Patna, Ranchi Bench and the Hon'ble Court was pleased to issue show-cause notice to the Government of India for not referring the dispute for adjudication and thereafter the union made further representation to the Ministry when the appropriate Government was pleased to make the present reference for adjudication.

The case of the management is that the dispute is overstale as the union kept quiet for nearly 20 years and suddenly woke up like Rip Van Winkle after a lapse of so many years. The management has asserted that the concerned workmen are fake persons and the union is trying to get them into impersonators and the documents referred to in the pleadings impersonators and the docments referred to in the pleadings of the union are products of manipulation and fabrication.

9. The management, as I have pointed out earlier, has not adduced any oral evidence in support of its action in denying employment to the concerned workmen. It has submitted three items of documents to combat the claim of the union, one of which is the letter of the Personnel Officer of Bhowra Area dated 18-6-87 addressed to the A.L.C.(C), Dhanbad, in reply to the claim of the union (Ext. M-1). The second item of document is a letter of Welfare Officer of Jealgora colliery to the Colliery Manager, Jealgora Colliery dated 17-8-73 (Ext. M-2) on the subject details of including 143 numbers of Casual Labour sent to C.I.R.P. in the month of June, 1973." From this letter it appears that Sri S. S. Sharma, the then Group Officer of the colliery approved of the list of 143 casual hazri workers and that the list was signed by the Group Officer and the Personnel Officer of the colliery and the workmen listed were offered the job upto September, 1972 and thereafter they were not engaged due to lack of job. In the month of May|June, 1972 due to trouble with the trammers of 7 Pit near about 30 workmen were engaged from the list of 143 casual pool. The third item of document is a letter addressed by the Manager, Jealgora Colliery to the Sub-Area Manager, Jealgora Sub Area dated 14-7-1978 (Ext. M-3). In this letter the position as emerging in Ext. M-2 has been confirmed. In addition it has been stated that in the month of May|June, 1975 about 30 persons from these casual workers were engaged as per his order due to trouble with the trammers of 7 Pit Jealgora colliery and those casual workers have been engaged from time to time on requirement from the Pit Incharge. The Manager informed the Sub Area Manager that they were preparing a list of workmen with particulars, such as, father's name, address etc. Thus, from the evidence laid by the management it appears that the claim of the union regarding employment of the concerned workmen by the management is not at all fake. It appears from the evidence laid by the management that they were engaged as casual workmen.

10. The union has examined two of the concerned workmen, namely, WW-1 Alok Saw and WW-2 Dipchand whose names appear at serial Nos. 97 and 83 respectively in the annexure to the schedule of reference.

WW-1 Alok Saw has stated that they were working in Jealgora colliery from 1970, as General Mazdoors and the management had stopped them from work from 1973-74. Some of their co-workers got employment in Jealgora colliery after the management had arrived at a settlement with Sri S. K. Rai and all of them put in attendance for more than 240 days and this fact will be borne out from the attendance register and bonus registers, if produced by the management. He has further stated that Gupta Saheb was the Agent of Jealgora Colliery who signed the Labour Bonus Record Attendence of the Jealgora colliery marked Ext. W-3. As a matter of fact Ext. W-3 is an enclosure of Ext. W-4. This witness has further stated that when they got into employment of the colliery it belonged to East India Coal Co. Ltd. and Gupta Saheb was the higher officer of the colliery. He has further stated that they used to get bonus from the employer on the basis of 'Chutka', which were taken back by the management. He has asserted that Labour Bonus Record Attendance does not reflect their exact attendance which may be available from the Bonus Register and that they used to get Rs. 25|- to 30/- as wages per week. It has not been suggested to this witness that he is a fake person or that he has impersonated any real workman. WW-2 Dipchand has corroborated the testimony of Alok Saw in material details. Dipchand has stated that by an agreement with the union led by Sri S. K. Rai the management has taken some 16 workmen who were working with them as General Mazdoors. It was suggested by the management to WW-1 Alok Saw that the case of 16 workmen is not similar to the present case. The witness has, of course, denied this suggestion. The agreement with the United Coal Workers Union has been produced by the sponsoring union and marked Ext. W-2 in the present case. There is nothing in this agreement (Ext. W-2) to indicate that the case of the workmen covered by the said agreement|settlement was dissimilar to the present case. In terms of the settlement|agreement the management agreed to employ 16 workmen as per Annexure 'A' as casual wagon loaders. This agreement/settlement was reached way back on 26-4-1978.

Labour Bonus Record Attendance. Jealgora colliery includes the names of as many as 116 workmen with reference to their attendance in the years 1973, 1974, 1975 and 1976. The names of most of the concerned workmen are included in this list of 116 workmen.

I would like to re-produce hereinbelow the letter (Ext. W-4) of the Agent of Jealgora Colliery addressed to Shri B. K. Singh, Dy. Personnel Manager (H. Q.) Karmik Bhawan on the subject 'details regarding 116 De-listed Casual workman of Jealgora colliery' as it provides some details regarding the concerned workmen in Jealgora colliery :—

"Please refer to your visit to this Colliery about two months back in connection with the case of 116 casual workers of Jealgora colliery. We have gone through the various records available at Colliery and our comments are as follows :—

1. After abolition of Contract System in March, 1972, Sri S. S. Sharma, the then Group Officer of Jealgora Colliery Group No. XIX and Sri S. K. Banerjee, Personnel Officer of Group, sent an approved list of 132 casual Hazree Mazdoors to Jealgora colliery vide letter No. 063828 dated 2-7-1972. A copy of the same is enclosed herewith.

2. On further scrutiny of the records, it revealed from the letter No. Nil dated 17-8-1973 of Sri R. K. Dwivedi, the then Welfare Officer of Jealgora Colliery addressed to his Manager that the said list of 132 persons was revised to 143 after addition of 11 heads as per advices received from the then Group Officer and Personnel Officer vide their letter No. 074918 dated 5th July, 1972 and letter No. 064527 dated 26-6-1973. It is also very clearly indicated that the said 143 casual workmen were offered jobs upto Sept. 1972 and again about 30 persons in the month of May-June 1973 (copy of list and letter enclosed). These facts have been corroborated by the then Manager, vide his letter No. KJ|1043|73 dated 14-7-73 addressed to the then Group Officer, Jealgora Sub-Area that the said 143 casual Mazdoors as per approved list, were provided with work in June|July|August|September, 1972.

3. Out of this approved list of 143 persons, 16 persons were given regular employment under an agreement with United Coal Workers Union and posted in different collieries of this Area.

4. The attendances of the various heads as per the approved list have been collected from the various records, now available at the Colliery. The various records includes Bonus Register, Attendance Register, Pay Sheets and other available documents of the Colliery. The attendance of all the persons do not appear in any one record. Some are available in Bonus Register, some in Paysheets and some in other Registers and records.

5. It may please be noted that due to shifting of records from Sub-Area Office and Area Office & there after due to closure of the Mine on two occasions, proper preservation of records could not be done.

During these processes lot of records appear to have been misplaced.

6. The attendances of some of these casual Mazdoors have appeared in P|R wagon loading as well as in T|R jobs. This has been probably done as per the letter No. PA-I|2(12)|73|45025-26 dt. 29-8-73 from Chief Industrial Relations and Personnel, Vihar Bldg.

7 The attendances of the heads under approved list in Nov. 1973 have also been revealed by the letter No. KJ|31|74 dated 9-1-74 to the General Manager, Area No. V, by the then Manager, Sri A. P. Gupta.

8. Attendances in case of some of the casual workmen are not available at all. It may be because of the fact that vide letter AJ|P.O.|225 dated 5-12-75, 35 casual mazdoors were transferred to Bhowra (South) Colliery as per order of General Manager, Bhowra Area vide letter No. GM-PER|MP|XI|75| 23003-40 dated 21-11-75 so their attendances thereafter may therefore be available at Bhowra South Colliery only.

9. On the basis of the records available in the colliery as per above mentioned reference the claim of the union now persuing the case, cannot be totally and wholly ignored. The names appearing in the approved list can be given preference over the fresh persons.

The details of the attendances are given in the enclosed Annexure."

The letter highlights the fact that the attendance of the workmen have been collected from various records, such as, Bonus Register, Attendance Register, Paysheets and other available documents and that the attendance of all the persons do not appear in any one record; some are available in Bonus Register and some in paysheets and some in other register or records. The Agent has reported that due to shifting of records from sub-area office and Area office and thereafter due to closure of the mine on two occasions proper preservation of record could not be done. During these processes lot of records appear to have been misplaced. Hence, Labour Bonus Record Attendance (Ext. W-3) which is part of Ext. W-4 is not a complete and comprehensive document regarding the attendance of the concerned workman in Jealgora Colliery. The evidence on record establishes the fact that the concerned workmen had been working as General Mazdoor; some of them, 16 in number were taken back in employment as casual wagon loader way back on 26-4-78. But these concerned workmen have been kept under tenter-hooks for years on end. It has been firmly established by hard evidence that the concerned workmen had worked in the colliery as General Mazdoor for atleast three years or more. It is the duty of the management to give them employment to them as General Mazdoors.

11. Shri R. S. Murthy, learned Advocate for the management, has submitted that the demand of the union is overstale as it appears that since 1973 the union was sleeping over the matter and woke up suddenly in 1987.

Shri D. Mukherjee, authorised representative of the union, has countered this argument by stating that the union was having discussion with the management over the issue for years on end. The submission of Shri Mukherjee is fortified by the fact as appearing in evidence by Ext. M-2 dated 17-8-73, Ext. M-3 dated 14-7-77, the settlement with the United Coal Workers Union on 26-4-78 and the letter of the agent of the colliery though undated, but can be placed sometime of 1976 (Ext. W-4). In this letter the Agent has stated that on the basis of record available in the colliery, the claim of the union now pursuing the case cannot be totally ignored and the names appearing in the approved list can be given preference over the fresh persons. It appears that in 1984 the union was having discussion with the management over the employment of the concerned workmen and this discussion was lastly held on 14-8-85. The union raised the dispute before the ALC (C), Dhanbad, but the appropirate Government refused to refer the dispute for adjudication. It is a well known fact that the conciliation settlement is a time consuming affair. The union, being dis-satisfied with the order of the appropriate Government in rejecting the dispute for adjudication, moved the matter before Hon'ble High Court, Patna, Ranchi Bench and again submitted representation to the appropriate Government and thereafter the present reference was made by the appropriate Government on 27-2-90. This being the position I consider that the demand of the union is not overstale at all as contended by Shri Murthy.

12. Shri R. S. Murthy has submitted that the question of identification of the concerned workmen will be a thorny matter.

Shri D. Mukherjee has submitted that the union preferred their claim before the ALC(C), Dhanbad with photographs of the concerned workman and their particulars. This has also been testified by WW-2 Dipchand. Anyway, the problem of identification may be sorted out by the management in consultation with the union.

13. I am alive to the fact that M|s. B.C.C. Ltd is in the red. Hence, it would not be prudent and justified to saddle the management with the obligation of reinstatement of the concerned workmen from the date they were stopped from duty. Taking a pragmatic view of the matter, I direct the management to give employment to the concerned workmen as General Mazdoors within four months from the date of publication of the award.

14. Accordingly, the following Award is rendered—

The action of the management of Jealgora Colliery of M/S B.C.C. Ltd. in denying employment to Shri Nitish and 110 other workmen (given in Annexure) is not justified. The management is directed to give them employment as General Mazdoors within four months from the date of publication of the award

In the circumstances of the case, I award no cost.

This is my award.

S. K.| MITRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 जून 1992

का.आ. 1640.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैं. भारत कोकिंग कोल लि., का सुदामडीह क्षेत्र के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं. 2), धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय परकार को 25-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल—20012/173/87)]
वी०के० वेणुगोपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th June, 1992

S.O. 1640.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 2), Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Sudamdih Area of M|s. B.C.C. Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on 25-5-92.

[No. L-20012(173)/87]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. Ram,

Presiding Officer.

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947.

Reference No. 314 of 1987

PARTIES :

Employers in relation to the management of Sudamdih Area of M|s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen.—Shri P. B. Choudhury, authorised representative.

On behalf of the employers.—Shri R. S. Murthy, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dated, Dhanbad, the 18th May, 1992

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(173)/87, dated, the 21st December, 1987.

THE SCHEDULE

"Whether the demand of Dhanbad Colliery Karamchari Sangh, Sudamdih Project, Dhanbad that Shri Ajit Kumar Supkaar and Shri Khuduram Supakaar, (Electric Fitter Grade-VI) be promoted as Asstt. Foreman Grade C is justified ? If yes to what relief are the workmen entitled ?"

2. In this case both the parties appeared and filed their respective W. S. documents etc. Thereafter the case proceeded along its course. Subsequently at the stage of oral evidence both the parties appeared before me and filed a Joint Compromise petition under their signature. I heard both the parties on the said petition of compromise and do find that the terms contained therein are fair, proper and beneficial to both of them. Accordingly I accept the said petition of compromise and pass an Award in terms thereof which forms part of the Award as annexure.

B. RAM, Presiding Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, DHANBAD

Reference No. 314|87

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Sudamdih Area of Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Sudamdih, Distt. Dhanbad.

AND

Their workmen

JOINT COMPROMISE PETITION OF THE EMPLOYERS AND THE WORKMEN

The above mentioned Employers and the workmen| Sponsoring Union most respectfully beg to submit jointly as follows :—

(1) That the representative of the Employers and the representatives of the workmen/Sponsoring Union have jointly negotiated the above matter referred to this Hon'ble Tribunal with a view to arriving at a mutually acceptable and amicable settlement.

(2) That as a result of such mutual negotiations, the parties have agreed to settle the matter covered by the above reference on the following terms and conditions :—

(a) It is agreed that S|Sri Ajit Kumar Supakar and Khudiram Supakar, Electrical Fitters Gr. VI will be deemed to have been promoted to the posts of Technical and Supervisory Gr. 'C' as Asstt. Foremen (Electrical) w.e.f. 1-7-89 provided they produce the High Tension Certificate under the Indian Electricity Act and the Rules framed thereunder and thereafter they will be given all the benefits of the promotion. (The workmen have already been placed in such Technical and Supervisory Gr. 'C' as they have completed 10 years service in terms of para 2.11 of NCWA IV.)

(b) It is agreed that if the 2 workmen concerned fail to obtain the High Tension Certificates under the Indian Electricity Act and the Rules framed thereunder within a period of 2 months from the date of this Joint Compromise Petition being accepted by this Hon'ble Tribunal, the matter will be treated as closed.

(c) It is agreed that this is an over-all settlement in full and final settlement of all the claims of the workmen concerned and the Sponsoring Union arising out of the above reference

(3) That the Employers and the workmen|Sponsoring Union consider and hereby declare that the above terms and conditions are fair, just and reasonable to both the parties.

In view of the above, the Employers and the workmen| Sponsoring Union most respectively pray jointly that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this Joint Compromise Petition and dispose of the above reference accordingly by giving an Award in terms thereof.

Sd/- Illegible
Secretary,
Dhanbad Colliery Karmachari Sangh,
Sudamdih Project, B.C.C.L.,
for and on behalf of workmen.

Sd|- Illegible
General Manager,
Sudamdih Area, B.C.C.L.,
for and on behalf of Employers.

Dated : 29-4-92

Dy. Chief Personnel Manager,
Sudamdih Area, B.C.C.L.,
for and on behalf of Employers.

नई दिल्ली, 21 मई, 1992

का.आ. 1641.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, कोलम के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/206/89-आई आर (बी-III)]

सुभाष चन्द्र शर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st May, 1992

S.O. 1641.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Kollam as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Travancore and their workmen, which was received by the Central Government on 21-5-92.

[No. L-12012/206/89-IR (B-III)]

S. C. SHARMA, Desk Officer

ANNEURE

IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, KOLLAM

(Dated this the 13th day of May, 1992)

PRESENT :

Sri. C. N. SASIDHARAN,
Industrial Tribunal

IN

Industrial Dispute No. 157/89

BETWEEN

The Managing Director, State Bank of Travancore Head Office, Poojapura, Trivandrum-695 001.

(By Sri. R. Lakshmana Iyer, Advocate, Trivandrum)

AND

The General Secretary, State Bank of Travancore Staff Union, Central Office, P. B. No. 5601, Trivandrum-695039.

AWARD

The Government of India as per Order No. L-12012/206/89/IR/B.III dated 30-11-1989 have referred this Industrial Tribunal for adjudicating the following issue :

"Whether the action of the State Bank of Travancore in withdrawing special allowance for a period of one year under clause IX-3(i)(a) of III Bipartite settlement from the workman Shri S. Suresh Kumar, while he was functioning as Head Cashier (tem.) in the Changanacherry Branch was legal and justified ? If not, to what relief the workman is entitled to and from which date ?"

2. The Union espousing the cause of the workman Sri. S. Suresh Kumar has filed a detailed statement which is briefly as under : Sri. Suresh Kumar while working as temporary Head cashier at Changanacherry Branch of the management Bank was placed under suspension and was punished with withdrawal of his special allowance for a period of one year. The punishment is victimisation Sri. Suresh Kumar was working as Teller at Changanacherry Branch and he was next only to the Head Cashier in seniority. The Head Cashier died on 15-5-1988. The management refused to give the worker temporary charge of Head Cashier though he was senior most. The management agreed to give him temporary charge at the instance of the union and denial of justice started from that point. This was much to the displeasure of the branch officials also. The duties of Head cashier are mainly supervising the working of the cash department at branches like Changanacherry. There is an Assistant Head Cashier to assist him in this work. There are separate cashiers for accepting receipts and making payments. There is a currency chest at the branch. There will be a withdrawal from the currency chest in the morning to meet urgent payments. He was served with a charge memo on 9-9-1988 levelling charges of disobedience to the orders of the manager and failure to render better service to the customer which is prejudicial to the interest of the Bank. Though he was given seven days time for giving explanation to the charge sheet, he was placed under suspension before that. It is second stage of clear victimisation. The management ordered an enquiry and in the enquiry he was found guilty of the charge. The entire process of enquiry has been proved to be a farce. The office submitted the report without investigating the correctness of the complaint. The report is contrary to the facts and well motivated. The enquiry officer based his findings to a great extent on the deposition of this investigating officer. The findings of the enquiry officer was perverse. The clear evidences of the motive of victimisation were not at all considered by the enquiry officer. The disciplinary authority also did not consider the various points submitted to him. A copy of the enquiry officer was not given to the workman. He was served with a copy only after a written request. He was given only three days time to submit his explanation As held by the disciplinary authority nobody instructed the workman to effect payment because it was not at all his duty. The punishment of withdrawal of special allowance is nothing but victimisation. The appellate authority reduced the punishbent to the extent of withdrawal of special allowance for a period of one year. The management proceeded with a motive to punish the worker without considering the arguments submitted by him. The worker was made a scape goat for various irregularities short comings and ills in the functioning of the branch. It cannot be believed that the manager or accountant instructed the workman to withdraw Rs. 2 lakhs from the chest immediately after withdrawing Rs. 19.53 lakhs in the morning. Such alleged instruction is either lawful or proper. According to the union the punishment imposed is wholly illegal and in operative and the prayer is to revoke the punishment.

3. The management opposes the case pleaded by the union. The case of the management is briefly as under : Sri. Suresh Kumar is not a workman as defined in the Industrial Disputes Act 1947 (the Act for short). He was doing supervising work of the cash department and his monthly wage was more than Rs. 1,600. This Tribunal has no jurisdiction to adjudicate this reference. The workman was punished after finding him guilty of definite charges on the basis of a domestic enquiry. He was given reasonable opportunity to prove his case in the enquiry. He has not raised any objection against the enquiry proceedings. The enquiry officer found him guilty of the charges and he was given opportunity to show cause before awarding the punishment. The enquiry is not vitiated by any procedure irregularities. There is absolutely no reason to interfere with the punishment in question. There is absolutely no material to substantiate the allegation of victimisation. As per the to substantiate the allegation of staff circular dated 2-2-1983 victimisation. As per the Teller should not be disturbed for making posting of Head Cashier. However, on the basis of the representation of the worker his request for posting as cashier was allowed. There was no displeasure of the branch officials as alleged. The workman was charge sheeted on th basis of a complaint from a customer and a preliminary enquiry was conducted by a senior officer of the Bank. He was placed under suspension since a prima facie case was established against him. The suspension was only after conducing a preliminary enquiry. There was no question of any prejudice or victimisation. The enquiry officer has found the workman guilty of the charges on the basis of evidence let in before him. The findings of the enquiry officer are no perverse. The enquiry was conducted in an impartial manner. It was proved in the enquiry that the delay in making the payment to customer would have been avoided if Sri. Suresh Kumar had withdrawn necessary funds from the chest as instructed by the accountant and branch manager. Copy of the enquiry report was furnished to the workman. The management denies all other allegations made against it. The further case of the management is that the punishment is proper and the workman is not entitled to any relief.

4. No oral evidence has been adduced on both sides. Exts. W1 to W7 on the side of the union and Exts. M1 to M3 on the side of the management have been marked on mutual consent.

5. The management has raised a preliminary objection that Sri. Suresh Kumar is not a workman to as defined in the Act and this Tribunal has no jurisdiction to adjudicate upon the reference. The union contneded that Head Cashier is a workman under the Act, and his duties and responsibilities are not supervisory. In support of this contention the union has brought to the notice of this Tribunal the decision of the Supreme Court in All India Reserve Bank Employees Association Vs. Reserve Bank of India. (65 II LLJ it was held that ordinary checking is not supervision within 175) wherein the meaning of Section 2(s) of the Act. The question whether Sri. Suresh Kumar is a workman under the

Act depends on the nature of work rendered by him. In para 4 of the claim statement of the union it is clearly stated that the duties of Head Cashier at Changanacherry branch are mainly supervising the working of cash department and that there is an Assistant Head Cashier to assist him in this work. The above statement of the union clearly establish that the workman was discharging supervising duties. It is not disputed that he was drawing salary more than Rs. 1,600 PM. Even according to the union Sri. Suresh Kumar was doing supervising duties and therefore the above decision relied on by the union has no application here. In this sate of affairs Sri Suresh Kumar cannot be stated to be a workman as defined under the Act. That being the case this Tribunal has no jurisdiction to adjudicate this reference. The preliminary objection raised by the management is therefore sustainable.

6. I shall now pass on to the merits. The prayer of the union is to set aside the punishment imposed on the workman. The punishment imposed is withdrawal of special allowance for a period of one year. Such a punishment is not covered by Sec. 11-A of the Act. The punishment was imposed on the basis of a domestic enquiry conducted regarding the charges levelled against the workman as per charge memo dated 9-9-1988. The enquiry proceedings have been marked as Ext. M1 to M3 as consented to by the union representative without examining the enquiry officer or any other witness on the side of the management. The burden is therefore on the union to establish that the enquiry findings are liable to be quashed as contended by the union. It is evident from Ext. M1 to M3 that the workman participated in the enquiry throughout without raising any objection at any stage regarding the procedure adopted in the enquiry or the person who conducted the enquiry. It is not disputed that he was afforded sufficient opportunity to prove his case.

7. The main point of attack against the enquiry is that the findings of the enquiry officer are perverse. On a perusal of Ext. M1 to M3 proceedings it is clear that the enquiry officer considered the entire evidence before him and came to the conclusion that the workman disobeyed the repeated orders of the manager and accountant to take cash from the currency chest. On behalf of the union it was contended that the enquiry officer has not considered the material points to prove that the workman is not guilty of the charges. In support of the argument that the findings of the enquiry officer are perverse it was pointed out that the workman was not instructed to withdraw the amount from the currency chest either by the accountant or by the branch manager. According to the union there was no necessity to instruct the workman to withdraw amount of Rs. 2 lakhs from the currency chest as there was a withdrawal of Rs. 19.53 lakhs from the currency chest in the morning of that day itself. The accountant as PW9 has stated before the enquiry officer that Rs. 19.53 lakhs withdrawn were not completely recounted and therefore could not be issued to the customers. The enquiry officer analysed the evidence of all witnesses separately and came to the conclusion that the workman was repeatedly instructed by the accountant and branch manager to withdraw Rs. 2 lakhs from the currency chest and disobeyed the lawful orders. It was also proved that he refused to credit Rs. 2 lakhs in sundry deposit account as instructed by the manager. The findings of the enquiry officer are fully supported by evidence. It was not established in the enquiry that the management witnesses are enemical towards the workman to depose against him. The union has produced and marked Exts. W1 to W7 documents. These documents are only copies of letters of union to the management, appeal petition filed by the workman, the order on such petition etc. It is not explained that none of these documents can prove that the enquiry is vitiated or the findings are perverse. It may be recalled that the union has not adduced any evidence to establish their case before this Tribunal. There are no justifiable reason to conclude that the findings of the enquiry officer are in any way perverse.

8. The next argument on behalf of the union is that the punishment imposed is an act of victimisation. It is alleged that the workman was given temporary charge of the Head Cashier in the Changanacherry branch of the Bank at the instance of the union only and that was much to the displeasure of the Branch officials. The further case of the union is that the branch manager was biased and that also contributed to the victimisation. It is noteworthy that not a single question was asked to the manager while he was examined as PW3 before the enquiry officer, with regard to the alleged displeasure or bias. So the present contention of victimisation and bias can only be considered as an after thought. The Branch Manager had explained before the enquiry officer the reason for not giving the workman the charge of Head Cashier immediately after the death of the permanent cashier of Changanacherry Branch. He had further stated that the workman was given charge of the Head Cashier when he made written request to the management. In such circumstances question of bias and victimisation does not arise. Further, union has not adduced any evidence before this Tribunal in support of the allegation of victimisation. The allegation of victimisation is not specially established and therefore this contention is also to be rejected.

9. The union has yet another contention that though copies of settlements and Awards aplicable to the workman were not produced here, this Tribunal may presume the existence of those facts by exercising the powers conferred under section 114 of the Indian Evidence Act, 1872. At the outset I may state that the Indian Evidence Act as such is not applicable in adjudication proceedings. Further, this Tribunal is not made aware of any of the settlement or Awards and therefore the union cannot build up a case under any of the provisions of the evidence Act.

10. From the decision made above it is clear that the workman was charge-sheeted on specific charges and those charges were established in a properly conducted domestic enquiry. The management inflicted the punishment in question after taking a lenient view in the matter. Before inflicting the punishment the workman was afforded sufficient opportunity to give explanation and he was served with copy of the enquiry report. The punishment imposed by the management cannot in any way said to be illegal or excessive. There are absolutely no reasons to interfere with the punishment.

11. In the result, an award is passed upholding the punishment of withdrawing special allowance for a period of one year from the workman Sri. S. Suresh Kumar and that the workman is not entitled to any relief.

C. N. SASIDHARAN, Industrial Tribunal

APPENDIX

Document marked on the side of the Workmen

Ext. W1—Photocopy of letter addressed to the Managing Director of the management Bank from the Union dated 12-9-1988.

Ext. W2.—Photocopy of letter addressed to the Managing Director of the management Bank from the union dated 17-10-1988.

Ext. W3.—Preliminary order dated 28-1-1989 of the disciplinary authority of the management Bank.

Ext. W4.—Memo issued to the workman from the Regional Manager of the management Bank dated 10-2-1989.

Ext. W5.—Reply of the workman to the Disciplinary authority dated 16-2-1989.

Ext. W6.—Appeal Memorandum submitted to the Appellate authority by the workman dated 16-3-1989.

Ext. W7.—Order of the Appellate Authority dated 15-4-1989.

Document marked on the side of the Management :

Ext. M1.—File containing, findings of the enquiry officer, order of the appellate authority, correspondings between the workman and the management Bank etc.

Ext. M2.—series (2 Nos.) Enquiry registers containing enquiry proceedings and deposition of witness.

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का.आ. 1642:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, कोटा (राजस्थान) के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल–12012/222/90-आई आर (बी-3)]
सुभाष चन्द शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1642.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Kota (Rajasthan) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Hadoti-kshetriya Gramin Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 25-5-92.

[No. L-12012/222/90-IR(B-3)]
S. C. SHARMA, Desk Officer

अनुबन्ध

न्यायाधीश/औद्योगिक न्यायाधिकरण, कोटा (राजस्थान)

निर्देश प्रकरण क्रमांक : औ० न्या० (केन्द्रीय)–3/1991

दिनांक स्थापित : 7/2/91

प्रसंग : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के आदेश संख्या एल–12012/222/90-आई. आर (बी-3) दिनांक 29/1/91

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

मध्य

महासचिव, हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एम्पलाईज एसोसियेशन, छ–12, साबरमती कालोनी, कोटा।

—प्रार्थी युनियन

एवं

अध्यक्ष, हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 9-ए. बी., झालावाड़ रोड, कोटा।

—प्रतिपक्षी नियोजक

उपस्थित

श्री जगदीश नारायण शर्मा

आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी यूनियन की ओर से प्रतिनिधि :— श्री पुरुषोत्तम दाधीच
एवं
श्री भंवरलाल
(श्रमिक स्वयं)

प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से प्रतिनिधि :—श्री एस. सी. गुप्ता

अधिनिर्णय दिनांक : 23 अप्रैल, 1992

अधिनिर्णय

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा निम्न निर्देश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1)(घ) एवं उपधारा (2–क) के अन्तर्गत इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सम्प्रेषित किया गया है :—

"Whether the action of the Hadoti Kshetriya Gramin Bank, Kota is terminating the services of Shri Bhawarlal, Carpenter, Part Time worker at their Bhilwari Branch w.e.f. 24-6-90 is justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled to ?"

2. निर्देश न्यायाधिकरण में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये तदुपरान्त दोनों पक्षों की ओर से अपनी-अपनी उपस्थिति न्यायाधिकरण में दी गयी। प्रार्थी युनियन की ओर से श्रमिक भंवरलाल के सम्बन्ध में क्लेम स्टेटमेन्ट प्रस्तुत किया गया।

3. आज यह पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिपक्षी नियोजक नियत थी, परन्तु श्रमिक स्वयं भंवरलाल मय प्रतिनिधि श्री पुरुषोत्तम दाधीच ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र पेश कर प्रकट किया कि वह वर्तमान में प्रतिपक्षी नियोजक के यहां नियोजन में है और अब इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा विवाद रहित अधिनिर्णय पारित किये जाने का निवेदन करता है। प्रतिपक्षी नियोजक प्रतिनिधि श्री एस. सी. गुप्ता ने भी उपस्थित होकर इसमें कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। अतः श्रमिक के स्वयं के उक्त कथन के आधार पर इस प्रकरण में "विवाद रहित अधिनिर्णय" पारित किया जाता है।

इस अधिनिर्णय को भारत सरकार, श्रम मंत्रालय को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भिजवाया जाये।

जगदीश नारायण शर्मा, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 21 मई 1992

का. आ. 1643.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नागेश्वर सत्ग्राम युनिट ऑफ बेनाली (आर) कोलियरी ऑफ ईस्टर्न कोलफील्डस लि. के प्रबन्धतंत्र के सबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20/5/92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल–22012/221/91-आई आर (सी–II)]
राजा लाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st May, 1992

S.O. 1643.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Nageshwar Satgram Unit of Benolee (R) Colliery of Eastern Coalfields Ltd. of their workmen, which was received by the Central Government on the 20-5-92.

[No. L-22012/221/91-IR(C-II)]
RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, ASANSOL
Reference No. 6/92

PRESENT :

Shri N. K. Saha, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Nageshwar Satgram Unit of Benalee (R) Colliery of M/s. E.C. Ltd.,

AND

Their Workman.

APPEARANCES :

For the Employers—Sri P. K. Das, Advocate.
For the Workman—Sri Sanjiv Banerjee, Representative of Union.

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal.

Dated, the 6th May, 1992

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry's Order No. L-22012/221/91-IR (C.II) dated the 9th January, 1992.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Nageshwar Satgram Unit of Benalee (R) Colliery, M/s. E.C.L., P.O. Benalee, Dist. Burdwan in fixing the basic wages of Shri Devraj Dussadh, Security Guard at Rs. 612 of the scale of Rs. 580-16-804 w.e.f. 1-1-83 and in not granting annual increments for the years 1984, 1985 and 1986 of the said time scale was justified ? If not, to what relief the workman is entitled to ?"

2. Today (16-5-92) Sri Sanjib Banejree the Representative of the union submits that he has no instruction to proceed with this case. The concerned workman is also not present.

3. In view of the above submission by the union, I have no other alternative but to pass a no dispute award and accordingly a no dispute award is passed in this case.

N. K. SAHA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 21 मई, 1992

का. आ. 1644.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार रत्तीवाली कालियारी ऑफ मैसर्स ई सी एल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20/5/92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/124/90-आई आर (सी- II)]

राजा लाल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st May, 1992

S.O. 1644.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Ratibati Colliery of M/s. E. C. Ltd. of their workmen, which was received by the Central Governmnet on the 20-5-1992.

[No. L-22012/124/90-IR(C-II)]
RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, ASANSOL
Reference No. 12/92

PRESENT :

Shri N. K. Saha, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Ratibati Colliery of M/s. E. C. Ltd.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Sri P. K. Das, Advocate.
For the Workmen—Sri Sanjib Banerjee, Representative of the union.

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal.

Dated the 6th May, 1992

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry's Order No. L-22012/124/90-IR(C-II) dated 17-2-1992.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Ratibati Colliery of M/s. E.C. Ltd., in denying payment of wages of Shri Rai and 9 others (as per details enclosed in the Annexure) is legal and justified ? If not, to what relief the concerned workmen are entitled to ?"

2. Today (6-5-92) Sri Sanjib Banerjee the Representative of the union submits that he has no instruction to proceed with the case. The concerned workmen are also not present.

3. In view of the above submission by the Union, I have no other alternative but to pass a no dispute award and accordingly a no dispute award is passed in this case.

N. K. SAHA, Presiding Officer

ANNEXURE

Sl. No.	Name	Designation	From	To	Present place of posting.
1.	R.N. Rai	Welder	1-3-84	15-6-84	Kumarkhela OCP
2.	Abdul Rahman	D.S. Operator	1-3-84	1-6-84	-do-
3.	Rablu Bouri	Ap. Helper	1-3-84	6-6-84	-do-
4.	Suriama Nunia	Ap. Fitter	1-3-84	6-6-84	-do-
5.	Utpal Chatterjee	-do-	1-3-84	6-6-84	-do-
6.	Subhas Singh	-do-	1-3-84	6-6-84	-do-
7.	Chandan Chatterjee	-do-	1-3-84	6-6-84	-do-
8.	Narain Mukherjee	-do-	1-3-84	6-6-84	-do-
9.	Shyamal Ghosh	-do-	1-3-84	6-6-84	do-
10.	Pabitra	-do-	1-3-84	6-6-84	-do-

Sl/-Illegible
Vice President

नई दिल्ली, 21 मई, 1992

का. आ. 1645.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सिदुली (आर) कोलियरी ऑफ मैसर्स ई०सी० लि० के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14/5/92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/264/89-आई आर (सी-II)]

राजा लाल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st May, 1992

S.O. 1645.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Siduli (R) Colliery of M/s. E. C. Ltd. of their workmen, which was received by the Central Government on the 14-5-1992.

[No. L-22012/264/89-IR (C-II)]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, ASANSOL

Reference No. 7/90

PRESENT :

Shri N. K. Saha, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Siduli (R) Colliery of M/s. E. C. Ltd.

AND

Their Workman.

APPEARANCES :

For the Employers—Sri P. K. Das, Advocate.

For the Workman—Sri B. Kumar, Joint Secretary of the Union.

INDUSTRY : Coal STATE : West Bengal.

Dated, the 29th April, 1992

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by Clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry's Order No. L-22012(264)/89-IR (C. II) dated the 8th February, 1990.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Siduli (R) Colliery of M/s. E.C. Ltd., in denying to refer Sri S. R. Banerjee, Senior Overman, to the Apex Medical Board is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. The case of the union brief is that Sri S. R. Banerjee was a Senior Overman in the C. I. Jambad Unit of Bahula (R) Colliery and commenced his work in the year 1962. He was an underground employee. Due to his long service in the underground he became a victim of some acute occupational diseases arising out of environment. He received treatment in the Regional Hospital, Chora and Central Hospital, Kalla. Due to continuous suffering from such incurable diseases he was compelled to remain out of employment w.e.f. 22-10-87 sustaining clear loss of employment. The workman due to such long continuous suffering and inability to perform any job effectively, applied to the employer to refer him to Area Disablement Medical Board to assess his disability and to give him the relief of Clause 9.4.3 of N.C.W.A.-III. On his prayer he was referred to the Area Disablement Board which was held on 18-8-88 and the Board declared him fit for duty and advised to continue treatment. The workman could not continue working due to his suffering and physical condition and remained idle from 25-10-87 till the last date of his attaining the age of superannuation. In the meantime he applied again and again to refer his case to the Apex Medical Board But the management did not pay any heed to his prayer in spite of the opinion of the Sr. Specialist/Physician of the Cenral Hospital, Kalla who declared him unfit for any job below ground by a certificate dated 8-9-88. In the meantime the workman superannuated while he was sitting idle It is entirely an unfair labour practice.

The workman raised dispute through union. The attempts of conciliation failed. The matter was sent the Ministry of Labour, Government of India and ultimately the Ministry of Labour has referred the dispute to this Tribunal for adjudication.

3. The management has filed written objection contending inter-alia that the workman was an underground employee. But it is denied that he was ever a victim of some acute occupational diseases arising out of environment and working conditions. Such allegations are false and baseless. There was no loss of employment due to such ailment. On the prayer of the workman he was directed to appear before a Medical Board on 16-10-87. He was advised by the Board to report to Sanctoria Central Hospital for detailed investigation/treatment for obtaining expert opinion of the Physicians about his alleged disablement. The concerned workman was found fit for duty by the Board on the said date. On 13-6-88 he again appeared before a Board and he was advised for specialist opinion. The workman again appeared before the Board on 18-8-88 and he was found fit for duty by the Board and was advised to continue treatment. There was no merit in the prayer of the workman for referring him to Apex Medical Board. So the workman cannot get any relief in this case.

4. Admittedly Sri S. R. Banerjee the concerned workman was an underground worker of Siduli Colliery of C. I. Jambad Unit at Kenda Area under Eastern Coalfields Ltd. He has come with the story that he became unfit to perform work from 25-10-87 due to occupational diseases arising out of environment and conditions of service. This has been denied by the management. But it is admitted that on the prayer of the concerned workman he was referred to Medical Board at different point of time for examination and those Boards declared him fit but advised to continue treatment and take opinion of specialists.

In support of the case the union has filed a good number of documents marked Exts. W-1 to W-21 in this case. From the documents filed by the union I find that the workman was suffering for a considerable time from before the date of his superannuation. The nature of ailment is not clear from the documents as some medical terms have been used. But it has been contended by the union that this workman was declared unfit by the Senior Specialist of Kalla Hospital. It may be mentioned that there is a Central Government Hospital at Kalla near Asansol. In this connection we are to refer Ext. W-20 which speaks a volume in favour of the workman. The relevant note on the back side of the said document Ext. W-20 reads as follows :

"Sri Santi Rath Banerjee, Sr. Overman C.I. Jambad Colliery attended the Area Disablement Board on 10-8-88 last and the opinion of the Board was "FIT FOR DUTY".

On 8-9-88 Sri Banerjee was examined by Sr. Specialist (Medicine) of Kalla Hospital and his opinion is

"Old hypertension with effort intolerance H/O chest pain and is unfit for any employment below-ground."

The Screening Committee could not allow him to appear again the disablement board held in this area on 6-10-88 as he had only 5 months to retire.

He is not working since 25-10-87.

In view of the comments given by Sr. Specialist Kalla Hospital and his approaching superannuation, he may be sent to apex Medical Board for review and opinion."

P. M. Kenda Area

Sd./- Illegible,
15-11-88
Area M.O.
Kenda."

From this document we find that the specialist opined that this workman was unfit for any employment below ground On the basis of the said report the Area Medical Officer advised to refer his case to Apex Medical Board for review and opinion. I find that the management ignored this note given by the Area Medical Officer. Further I find that the opinion of the specialist was also ignored. So considering all the documents filed before me and the facts and circumstances, I find that the management was not justified in denying to refer Sri Banerjee, the concerned workman to the Apex Medical Board.

4. In the result, I find that it is a fit case where it was the duty of the management to refer the workman to Apex Medical Board to determine his disablement. So I direct that the management shall refer this workman Sri S. R. Banerjee to Apex Medical Board within three months from the date of publication of this award The apex Medical Board shall examine the concerned workman and consider his present condition of health and shall also consider all the document of treatment which may be filed by the workman and the management before the Board :

(a) If the Medical Board, after considering the present condition of health of the workman and other papers, finds that he was not a permanently disabled person before his superannuation then the workman shall not get any relief in this case.

(b) If the Medical Board finds after such examination that the workman was a permanently disabled person and was unfit to perform his duty belowground. then the workman shall be given all the benefits of Clause 9.4.3 of N.C.W.A.-III.

This is my award.

N. K. SAHA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का. आ. 1646.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (n) के उपखण्ड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3134 दिनांक 6 दिसम्बर, 1991 द्वारा लौह अयस्क खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 8 दिसम्बर, 1991 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित मे उक्त कालावधि को छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (n) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 8 जून, 1992 से छह मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/12/85-डी-1(ए)]

एस. एस. पराशर, अवर सचिव

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 1646.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of cluase (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 3133 dated the 6th December, 1991 the iron ore mining industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period six months, from the 8th December, 1991;

And, whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for further period of six months from the 8th June, 1992.

[No. S-11017/12/85-D.I(A)]

S. S. PRASHER, Under Secy

नई दिल्ली, 26 मई, 1992

का. आ. 1647.—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि पाइराइटस खनन उद्योग को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 20 के अंतर्गत आता है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (n) के उपखण्ड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/1/80-डी-1 (ए)]

एस. एन. पराशर, अवर सचिव

New Delhi, the 26th May, 1992

S.O. 1647.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the Pyrites Mining Industry, which are covered by entry 20 in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months.

[No. S-11017/1/80-D.I(A)]

S. S. PRASHER, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 मई, 1992

का. आ. 1648.—बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम 1978 के नियम 3 के उप नियम (2) के साथ पठित बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 62) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए, आन्ध्र प्रदेश के लिए एतद्द्वारा सलाहकार समिति का पुनर्गठन करती है अर्थात् :—

1. श्रम मंत्री, आन्ध्र प्रदेश सरकार	अध्यक्ष
2. कल्याण आयुक्त, हैदराबाद	उपाध्यक्ष (पदेन)
3. संयुक्त आयुक्त, श्रम-II श्रमायुक्त कार्यालय, हैदराबाद	सदस्य (पदेन)
4. श्री ए. विठ्ठल रेड्डी, विधायक रामायण पेट, जिला मेडक	सदस्य विधान सभा
5. श्री पी. गंगा रेड्डी, मद्रास चक्कर बीड़ी फैक्ट्री वारंगल	नियोक्ताओं के प्रतिनिधि
6. श्री बशेर बाई, निजामाबाद बीड़ी मैन्युफैक्चरर्स तथा टोबैको मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, निजामाबाद	
7. श्री बासवाराजु सराया, अध्यक्ष, तेलंगाना बीड़ी कर्मकार यूनियन मकान नं 14-1-189 मंडी बाजार वारंगल	कर्मचारियों के प्रतिनिधि
8. श्री ए. एस. पोसेट्टी, अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश बीड़ी कर्मकार फेडरेशन कोटापल्ली निजामाबाद	
9. श्रीमती के लक्ष्मी बाई महासचिव, बीड़ी मजदूर यूनियन निजामाबाद	महिला प्रतिनिधि
10. कल्याण प्रशासक, हैदराबाद	सचिव

2. केन्द्र सरकार उक्त नियमावली के नियम 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त सलाहकार समिति का मुख्यालय एतद्द्वारा हैदराबाद में निर्धारित करती है ।

[संख्या यू-19012/3/88 डब्ल्यू-II (सी)]
वी. वी. नागर, अवर सचिव

New Delhi, the 26th May, 1992

S.O. 1648.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976, (62 of 1976), read with sub-rule (2) of rule 3 of the Beedi Workers, Welfare Fund Rules, 1978, the Central Government hereby reconstitutes an Advisory Committee for the State of Andhra Pradesh consisting of the following members, namely :

1. Minister for Labour, Government of Andhra Pradesh	Chairman
2. Welfare Commissioner, Hyderabad.	Vice-Chairman (Ex-Officio)
3. Joint Commissioner, Labour-II, Office of the Commissioner of Labour, Hyderabad.	Member (Ex-Officio)
4. Shri A. Vittal Reddy M.L.A., Ramayampet, Medak District.	Member of Legislative Assembly.
5. Shri P. Ganga Reddy; Madras Chakkar Beedi Factory, Warangal	Employer's Representative
6. Shri Bacher Bai, Nizamabad Beedi Manufacturers and Tobacco Merchants Association, Nizamabad.	
7. Shri Basavaraju Saraiah, President, Telangana Beedi Workers Union H.No. 14-1-189, Mandi Bazar, Warangal.	Employees Representative.
8. Shri A.S. Posetty, President, A.P. Beedi Employee Federation Kotpally, Nizamabad.	
9. Smt. K. Laxmi Bai, General Secretary, Beedi Mazdoor Union, Nizamabad.	Woman Representation
10. Welfare Administrator, Hyderabad.	Secretary

2. The Central Government in exercise of the powers conferred by rule 16 of the said rules, hereby fixes Hyderabad as the Headquarters of the said Advisory Committee.

[No. U-19012/3/88-W.II(C)]
V. D. NAGAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 मई, 1992

का.आ. 1649.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार आल इंडिया रेडियो, सूरतगढ़ के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-5-92 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-42012/182/86-डी 2(बी) (पीटी)]
बी.एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th May, 1992

S.O. 1649.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of All India Radio, Suratgarh and their workmen, which was received by the Central Government on 25-5-92.

[No. L-42012/182/86-D.II(B)(Pt.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी आई.टी. 87/87

रैफरेंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-42012/182/86-डी II (बी) दिनांक 20-10-87

श्री खेता राम पुत्र श्री रामचन्द्र शर्मा, मार्फत जनरल सैक्रेट्री बीकानेर डिवीजन ट्रेड यूनियन कौंसिल, खजान्ची बिल्डिंग, बीकानेर ।

—प्रार्थी

बनाम

प्रोग्राम एक्जिक्यूटिव एवं स्टेशन इंजीनियर, आकाशवाणी सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनसिंह जी. आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री भारत भूषण आर्य

अप्रार्थी की ओर से :

दिनांक अवार्ड : 25 मार्च, 1992

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपनी उपरोक्त अधिसूचना द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10(1)(घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है :—

"Whether the action of the management of Station Engineer, All India Radio Suratgarh in terminating Shri Kheta Ram from service with effect from 24-06-84 is legal and justified ? If not, to what relief the workman is entitled..

2. बीकानेर डिवीजन ट्रेड यूनियन काउंसिल, बीकानेर, जिसे तत्पश्चात् प्रार्थी संघ संबोधित किया है, ने जरिये क्लेम प्रकट किया कि श्रमिक खेताराम की प्रथम नियुक्ति 3-8-83 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव एवं स्टेशन इंजीनियर, आकाशवाणी सूरतगढ़ द्वारा की गई थी जिस पद पर श्रमिक ने 24-6-84 तक निरंतर बिना किसी व्यवधान के कार्य किया था और वह स्थाई कर्मचारी था। 24-6-84 को जबानी आदेश से उसे सेवा मुक्त कर दिया। सेवा मुक्ति को समाप्त हुए एक कलण्डर वर्ष में श्रमिक ने 240 दिवस से अधिक सेवा पूरी कर ली थी फिर भी न तो उसे सेवा मुक्ति का कोई कारण बताया और न ही सेवा मुक्ति से पूर्व कोई नोटिस दिया यहां तक कि नोटिस के एवज में वेतन तथा छंटनी मुआवजा भी नहीं दिया गया है। इसलिए नियोजक द्वारा धारा 25-एफ के प्रावधानों की अवहेलना की गई। प्रार्थी संघ का यह भी कहना है कि श्रमिक की सेवा मुक्ति के समय उससे कनिष्ट व्यक्ति कार्य कर रहे थे और वरिष्ठता सूची भी नहीं बनाई गई थी इसलिए धारा 25-जी की भी अवहेलना की गई है तथा सेवा मुक्ति के उपरांत भी नियोजक ने सर्वश्री साहिबराम, भगवान राम व बोधचंद को नियुक्त किया था और इस श्रमिक को सूचना तक नहीं दी गई इसलिए धारा 25-एच की भी अवहेलना की गई है। प्रार्थी संघ के अनुसार सेवा मुक्ति आदेश अनुचित एवं अवैध होने से स्वतः ही शून्य हो गया है इसलिए श्रमिक को सेवा में मानते हुए उसे उसके पद का वेतन व अन्य सभी लाभ भी दिलाये जायें।

3. अप्रार्थी ने जरिये प्रत्युत्तर क्लेम के कथनों को अस्वीकार किया है और कहा है श्रमिक खेताराम को 23-8-83 को या अन्य किसी तिथि को किसी पद पर नियुक्त नहीं किया था उसे कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। नियोजक के अनुसार विभाग में यदाकदा ऐसा विशेष कार्य सीजनल या आकस्मिक आ जाता है जिसको सम्पन्न कराने हेतु नियमित कर्मचारियों के अलावा मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है इसके लिए इस विभाग में कुछ समय के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है इसके लिए इस विभाग के बजट में बजट हैड "आफिस एक्सपेंसेज" के मद से ऐसे कंटीनजेन्ट खर्चे कर दिये जाते हैं और कुछ समय के लिए ज्यादातर अस्थाई आकस्मिक दैनिक मजदूरी पर कुछ व्यक्ति आवश्यकतानुसार रख लिये जाते हैं और उनकी मजदूरी का चुकारा विभाग के सैलेरी हैड से न देकर कंटिनजैन्सी फण्ड से ही दिया जाता है और जब ऐसे अस्थाई आकस्मिक एवं सीजनल कार्य समाप्त हो जाते हैं तो स्वतः ही ऐसे मजदूरों की सेवायें बंद कर दी जाती हैं। न तो लगाने का और न ही हटाने का कोई आदेश पारित किया जाता है। अगस्त 1983 में राजकीय भवन के लॉन में घास व खरपतवार बढ़ गया था और बारिश के कारण एक बार सफाई करने के बाद वर्षा होने से लॉन में घास व खरपतवार बढ़ जाती है, इसकी निराई, गुड़ाई व सफाई हेतु श्री खेताराम व अन्य 2 व्यक्तियों को 8 रुपये रोजाना मजदूरी पर लगाया गया था, जिनकी मजदूरी हर 15 दिन बाद कंटिन्जेन्सी फंड से चुका दी जाती थी। एक बार एक स्पेसिफिक, आकस्मिक एवं सीजनल काम खत्म होने पर कोई पुनः कोई कैजुअल काम आ जाता है तो स्वाभाविक तौर पर जो मजदूर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और जो कर्मचारियों से सम्पर्क रखते हैं और जिन्होंने पहले ठीक काम को अंजाम दिया है उन्हें पुनः लगा लिया जाता है। सितम्बर 1983 के बाद खेताराम के साथ लगे सर्वश्री रतनसिंह व जगदीश को भी हटा दिया गया। अक्टूबर, नवंबर व दिसम्बर 1983 में सूरतगढ़ बीकानेर रोड पर ट्रांसमीटर सेंटर की शुरुआत हुई उसके लिए श्री खेताराम के अलावा सर्वश्री हनुमान, नरपतलाल व माहूबराम को अक्टूबर, 1983 में उक्त काम पर लगाया था और नवंबर 1983 में खेताराम के अलावा सर्वश्री जगदीश, गुलामअली व विनोद को भी लगाया गया था। जनवरी, फरवरी, मार्च, 1984 में लॉन की सफाई, निराई व गुड़ाई करने हेतु तथा बीकानेर रोड पर स्थित ट्रांसमीटर सेन्टर की सफाई हेतु मजदूरों की आवश्यकता पड़ी तो खेताराम व अन्य सर्वश्री हनुमान, जगदीश व विनोद को लगाया गया। अप्रैल व मई 1984 में गर्मी का मौसम होने के कारण कार्यालय में पानी की प्याऊ, कर्मचारियों और अधिकारियों को पानी पिलाने हेतु और कूलर आदि में पानी डालने हेतु अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ी तो खेता राम व अन्य व्यक्तियों को लगाया गया। नियोजक के अनुसार उपरोक्त सभी मजदूरों को उक्त सभी अवधि के लिए कंटिनजैंसी फंड से ही मजदूरी चुकाई गई थी विभाग के रिकार्ड के अनुसार 21-5-84 से 6-6-84 के बीच की अवधि की मजदूरी खेताराम को देना पाई जाती है। 6-6-84 के बाद मजदूरी देने का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। नियोजक यह भी कहता है कि कंटिन्जैंसी फण्ड पर रखे गये ऐसे अस्थाई आकस्मिक मजदूरों की वरिष्ठता सूची जारी करने की न तो कोई प्रथा है और न ही कोई प्रावधान। इसलिए यह श्रमिक कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। नियोजक ने यह भी कहा है कि प्रार्थी संघ का आकाशवाणी सूरतगढ़ से कोई वास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थी संघ आकाशवाणी सूरतगढ़ के तथाकथित कर्मचारी की तरफ से यह विवाद नहीं उठा सकता। नियोजक के अनुसार उनका संस्थान आल इंडिया रेडियो भारत संघ का एक विभाग है जिसके कर्मचारी संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों से शासित होते हैं। इसलिए प्रार्थी खेताराम कर्मकार की परिभाषा में नहीं आता है। यह भी कहा है कि आकाशवाणी सूरतगढ़ में नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों का नियोजक या तो भारत संघ है या भारत सरकार या डायरेक्टर आल इंडिया रेडियो सूरतगढ़ जिन्हें पक्षकार बनाये बिना वाद चलने योग्य नहीं है। नियोजक के अनुसार भारत सरकार के आदेश ओ एम.नं. 14(4)ई कोर्ड/77 दिनांक 27-5-77 द्वारा वित्त मंत्रालय ने दैनिक वेतन भोगी स्थाई या अस्थाई कर्मचारी नियुक्त करने पर पूर्ण रोक लगा रखी है इसलिए खेताराम की कथित नियुक्ति भी अवैध है। उसकी नियुक्ति न तो रोजगार कार्यालय की सिफारिश पर हुई है और न ही खेताराम कोई योग्यता रखता है इसलिए भी श्रमिक कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता।

4. अपने कथनों के समर्थन में श्रमिक खेताराम ने स्वयं का शपथपत्र दिनांक 26-5-89 को प्रस्तुत कर सत्यापित कराया। उसी रोज श्याम प्यारेलाल संघ के महामंत्री का भी शपथ पत्र पेश कर सत्यापित करा लिया गया था। उस रोज अप्रार्थी नियोजक की तरफ से कोई उपस्थित नहीं था इसलिए उपरोक्त दोनों साथियों से जिरह हेतु 2-5-89 बीकानेर कैम्प में रखी गई जहां पर कोई पक्षकार उस तिथि को उपस्थित नहीं हुआ। 28-7-89 को दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधि उपस्थित थे परन्तु उस रोज प्रार्थी अथवा उसके गवाह उपस्थित नहीं था इसलिए जिरह नहीं हो सका। तत्पश्चात् अनेकों पेशियां दी गई परन्तु प्रार्थी अथवा उसके साथी

जिरह हेतु उपस्थित नहीं हुए । अंततोगत्वा दिनांक 5-3-91 को संघ के प्रतिनिधि ने प्रकट किया कि वे अपना गवाह पेश नहीं करना चाहते। अभिप्राय यह है कि श्रमिक खेताराम तथा उसका साथी राम प्यारेलाल प्रति परीक्षा हेतु उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके शपथ पत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता ।

5. नियोजक की तरफ से भी दिनांक 6-4-91 को श्री मानक चंद सोनगरा का शपथ पत्र पेश किया गया था और दिनांक 19-7-91 को श्री दिनेश चंद शर्मा का शपथ पत्र पेश हुआ था उस रोज प्रार्थी संघ की तरफ से कोई उपस्थित नहीं था इसलिए गवाहों से जिरह का हक बंद कर दिया गया। तत्पश्चात् प्रार्थी संघ के प्रतिनिधि उपस्थित आए थे परन्तु उन्होंने नियोजक के साथियों से जिरह करने की प्रार्थना नहीं की । अभिप्राय यह कि न तो श्रमिक अथवा उसके साक्षी से जिरह हुई है और न ही नियोजक के साथियों से जिरह हुई। प्रालेखिक साक्ष्य में प्रार्थी संघ की तरफ से डब्ल्यू–1 लगायत डब्ल्यू–2 फोटो प्रतियां पेश हुई हैं । जबकि नियोजक की तरफ से एम–1 लगायत एम-16 मस्टरोल की फोटो प्रतियां पेश हुई है । तत्पश्चात् मैंने पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना।

6. क्लेम के प्रत्युत्तर में नियोजक ने कुछ प्राथमिक आपत्तियां प्रस्तुत की हैं जिन्हें साबित करने का भार सबूत भी नियोजक पर ही था परन्तु नियोजक के किसी भी साक्षी ने यह नहीं कहा कि अप्रार्थी संस्थान का कोई भी कर्मचारी प्रार्थी संघ का सदस्य नहीं हो अथवा प्रार्थी संघ को इस श्रमिक का विवाद उठाने का अधिकार नहीं हो । किसी भी साक्षी ने यह भी नहीं कहा कि अप्रार्थी संस्थान का नियोजक भारत संघ, भारत सरकार अथवा स्टेशन डायरेक्टर आफ आल इंडिया रेडियो सूरतगढ़ हो । इनमें से किसी भी साक्षी ने यह भी नहीं कहा कि श्रमिक खेताराम कर्मकार की परिभाषा में नहीं आता होगा वह संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों से शासन है इसलिए साक्ष्य के अभाव में नियोजक द्वारा उठाई गई उपरोक्त आपत्तियां आधारहीन मानते हुए खारिज की जाती हैं ।

7. नियोजक साक्षी श्री दिनेश चंद शर्मा ने ही अपने शपथ पत्र में कहा है कि अप्रार्थी संस्थान उद्योग नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य व्यापारिक फायदा उठाना नहीं है । मेरी राय में जहां कोई संस्थान घाटे में ही जा रहा हो वह औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(जे) के अन्तर्गत परिभाषित उद्योग की परिभाषा से नहीं बच सकता । बैंगलोर वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा 1978 (2) एस.सी.सी. 2131 के न्याय दृष्टान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय का मत यह था कि जहां पर किसी संस्थान में सिस्टमैटिक एक्टीविटी होती हो तथा नियोजक एवम नियोजिति के सहयोग से उत्पादन अथवा वा की जा रही हो चाहे उस संस्थान में हानि ही होती हो वह उद्योग की परिभाषा में आ जायेगा । बाम्बे उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने इंडियन नेवी सेलरस होम के न्याय दृष्टान्त 1986 लैब आई.सी. 1118 में भी केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठान को उद्योग माना था । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1985 लैब आई.सी. 198 के न्याय दृष्टान्त इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पैट्रोलियम को भी उद्योग करार दिया है जो भी केन्द्रीय सरकार का ही प्रतिष्ठान था । अतः उपरोक्त समस्त कारणों से अप्रार्थी संस्थान उद्योग की परिभाषा में ही आता है । अतः नियोजक की प्राथमिक आपत्तियां निराधार मानते हुए अपास्त की जाती हैं ।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है प्रार्थी संघ ने तो क्लेम में यह दर्ज कर दिया कि खेताराम की नियुक्ति 23-8-83 को चतुर्थ श्रेणी कर्म के पद पर की गई थी सही पर उसने 24-6-84 तक लगातार बिना किसी व्यवधान के कार्य किया था और वह एक स्थाई कर्मचारी था । उक्त तथ्यों को अप्रार्थी ने जरिये प्रत्युत्तर अस्वीकार किया है इसलिए इसे साबित करने का भार सबूत प्रार्थी संघ पर ही था । सर्वश्री खेता राम तथा राम प्यारेलाल ने अपने शपथ पत्रों में उक्त तथ्यों का जो उल्लेख किया है परन्तु इन दोनों को प्रति परीक्षा हेतु पेश नहीं किया गया इसलिए इनके शपथ पत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकता । नियोजक की तरफ से सर्वश्री मानकचंद सोनगरा तथा दिनेश चंद शर्मा के शपथ पत्र पेश हुए हैं परन्तु इनसे श्रमिक प्रतिनिधि ने जिरह नहीं की । ऐसी कोई प्रालेखिक साक्ष्य भी अभिलेख पर प्रार्थी संघ की तरफ से पेश नहीं की गई है जिससे खेताराम का स्थाई कर्मचारी होना साबित होता हो या उसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त होना साबित होता हो, अथवा 23-8-83 से 24-6-85 तक लगातार सेवा करना साबित होता हो। प्रार्थी संघ द्वारा प्रस्तुत डब्ल्यू–1 लगायत डब्ल्यू–II फोटो प्रतियों को नियोजक ने एडमिट भी नहीं किया है इसलिए भी साबित किए बिना इनका प्रयोग साक्ष्य में नहीं किया जा सकता । तर्क के लिए यह मान भी लिया जाय कि डब्ल्यू–3 प्रमाण-पत्र नियोजक के स्टेशन इंजीनियर श्री पी.सी. पावा द्वारा जारी किये गये थे तो भी इसमें इतना ही दर्ज है कि 23-8-83 से 23-6-84 तक की अवधि तक जब जब आवश्यकता हुई इस श्रमिक से आकस्मिक तौर से पीओन का कार्य लिया गया है । अतः उपरोक्त समस्त कारणों से अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित नहीं है कि श्रमिक खेता राम ने 23-8-83 से 24-8-84 तक की अवधि में 240 दिवस की सेवा पूरी की हो।

9. क्लेम में प्रार्थी संघ ने यह दर्ज किया है कि खेताराम की सेवा मुक्ति करते समय इससे अनेक कनिष्ठ व्यक्तियों कार्य कर रहे थे । उक्त तथ्यों को नियोजक ने जरिये प्रत्युत्तर अस्वीकार किया है इसलिए इस तथ्य को साबित करने का भार सबूत भी प्रार्थी संघ पर ही था। प्रार्थी संघ ने न तो क्लेम में उन व्यक्तियों के नाम दर्ज किये जो सेवा मुक्ति के समय नियोजन में थे और श्रमिक से कनिष्ट थे और न ही शपथ पत्रों में ऐसे व्यक्तियों के नामों का उल्लेख है । सर्वश्री खेताराम व राम प्यारे लाल के शपथ पत्रों का उपयोग भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें प्रति परीक्षा हेतु पेश नहीं किया गया इसलिए साक्ष्य के अभाव में यह तर्क भी साबित नहीं होने से स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

10. प्रार्थी संघ ने क्लेम में यह भी दर्ज किया है कि सेवा मुक्ति के उपरान्त सर्वश्री साहिबराम, भगवानाराम व दीपचंद को नियुक्ति दी और इस श्रमिक को सूचना नहीं दी गई । इस तथ्य को भी नियोजक ने अस्वीकार किया है । नियोजक के अनुसार ये व्यक्ति भी खेताराम के साथ ही समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर बतौर आकस्मिक श्रमिक दैनिक वेतन पर नियोजित रखे गये थे। इसलिए साक्ष्य के अभाव में यह भी साबित नहीं है कि सेवामुक्ति के उपरांत इन व्यक्तियों को नियोजित किया गया हो ।

11. तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :

"श्रमिक खेता राम को 24-6-84 से सेवा मुक्ति करना उचित एवं वैध है और यह श्रमिक किसी राहत का अधिकारी नहीं है।"

12. अवार्ड की प्रति केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17(1) अधिनियम के पठाई जावे ।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 27 मई, 1992

का. आ. 1650—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पी. एंड टी डिपार्टमेंट कोटा के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल – 23/8/86–कान. I/डी- 2 (बी) (पी टी)].

बी एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th May, 1992

S.O. 1650.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of P&T Department Kota and their workmen, which was received by the Central Government on 25-5-92.

[No. 23/8/86-Con.I/D.II(B)(Pt.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर ।

केस नं. सी आई. टी. 73/87

केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या :
एल : 23 (8)/86 – कान. 1/डी. II (बी) दि. 2-9-87

मांगीलाल पुत्र श्री रामलाल, मार्फत हिन्द मजदूर सभा बंगाली कालोनी, छबनी, कोटा ।

बनाम

दी डिवीजनल इंजीनियर, टेलीफोन्स, पी एण्ड टी डिपार्टमेंट, कोटा

उपस्थिति

माननीय न्यायाधीश श्री जगत सिंह, आर. एच. जे. एस.
श्रमिक पक्ष की ओर से : श्री एफ. खान
नियोजक पक्ष की ओर से : श्री यू. डी. शर्मा
दिनांक अवार्ड : 24-10-91

अवार्ड

केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय अपनी अधिसूचना संख्या : एल 23 (8)/86 – कान. 1/डी II (बी) दिनांक 2-9-87 के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 (1) (डी) के अन्तर्गत प्रेषित किया है –

"Whether the action of the management of Divisional Engineer, Telephones, Kota in terminating Shri Mangilal from service with effect from 1-1-1985 is legal and justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2– प्रार्थी मांगीलाल, जिसे तत्पश्चात् श्रमिक सम्बोधित किया गया है, ने क्लेम प्रकट किया कि उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 1-6-83 से केजुअल मजदूर के पद पर एस. डी. ओ. फोन्स, सब–डिवीजन–II, कोटा, के यहां की तीन माह पश्चात् उसे एस. डी. ओ. फोन्स सब–डिवीजन –I कोटा में स्थानान्तरित कर दिया जहां पर उसकी 1-1-85 से छंटनी कर दी गई। श्रमिक कहता है वह एक ईमानदार, मेहनती, कर्तव्य-निष्ठ एवं आज्ञाकारी रहा है तथा उसने 1-6-83 से 31-12-84 तक निरन्तर कार्य किया है उसे छंटनी से पूर्व 10 दिवस की अवधि का ही नोटिस दिया गया था तथा छंटनी भत्ता नहीं दिया गया इसलिए नियोजक के धारा 25 (एफ) के प्रावधानों की अवहेलना की है। श्रमिक यह भी कहता है कि छंटनी से पूर्व वरिष्ठता सूची का प्रकाशन नहीं किया गया और छंटनी के पूर्व उससे कनिष्ठ कई कर्मचारी नियोजन में मौजूद थी इसलिए उसे लास्ट कम फर्स्ट गो सिद्धान्त की अवहेलना करके निकाला गया है और धारा 25 (जी) की अवहेलना की है। श्रमिक की प्रार्थना है कि सेवा मुक्ति आदेश अपास्त किया जाये और उसे नौकरी में बहाल करते हुए सेवा मुक्ति का वेतन व सभी लाभ दिलाए जायें।

3– अप्रार्थी नियोजक ने जरिए प्रति उत्तर कहा है कि श्रमिक की प्रथम नियुक्ति एस. डी ओ. फोन्स –II, कोटा में बतौर केजुअल वर्कर 1-7-83 से की गई थी जहां पर उसने 30-9-83 तक नौकरी की है तत्पश्चात श्रमिक स्वयं सब–डिवीजन फोन्स कोटा के यहां सेवा करने चला गया, उसका स्थानान्तरण नहीं किया गया। दिनांक 1-11-83 से 30-6-84 तक श्रमिक ने एस. डी. ओ. फोन्स –I, कोटा के यहां सेवा की है। नियोजक का कहना है सब-डिवीजन फर्स्ट और सब–डिवीजन सैकिण्ड अलग तथा स्वतंत्र सब डिवीजन हैं जिनको अलग-अलग केजुअल लेबर नियोजित करने का अधिकार है। नियोजक के अनुसार नोटिस की अवधि 1-12-84 से प्रारम्भ हो गई थी और 31-12-84 तक थी जो पूरे माह का होने के नाते धारा 25 (एफ) के अनुरूप था । नियोजक के अनुसार हालांकि स्थापित विधि के अनुसार नोटिस देना आवश्यक नहीं था क्योंकि श्रमिक ने 240 दिवस की सेवायें एक कलेण्डर वर्ष में पूरी नहीं की थी। फिर भी सद्भावना तथा औद्योगिक शांति एवं भाईचारा के अनुरूप अने. आर –I नोटिस दिया गया था जो एक माह की अवधि का था। नियोजक यह भी कहते हैं कि उक्त नोटिस द्वारा श्रमिक का आह्वान किया गया था कि वह दिनांक 1-1-85 को सब–डिवीजन फर्स्ट कोटा में उपस्थित होकर अपनी बकाया राशि प्राप्त कर ले परन्तु श्रमिक उपस्थित नहीं हुआ इसलिए नियोजक को राशि की अदायगी करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। नियोजक यह भी कहता है कि उन्होंने अपने पत्र अने – आर – 2 दिनांक 29-8-85 द्वारा रेलवे इलेक्ट्रीफिकेशन (टेलीकाम) में अन्य पद के लिए श्रमिक का आह्वान किया था जो श्रमिक ने अस्वीकार कर दिया इसलिए भी श्रमिक अब किसी भी लाभ का अधिकारी नहीं है। नियोजक के अनुसार आकस्मिक श्रमिकों की वरिष्ठता सूची नियमानुसार तैयार की गई थी तथा लास्ट कम फर्स्ट गो के सिद्धान्त की पालना की गई है। श्रमिक यह नहीं बता पाया कि उससे किस कनिष्ठ व्यक्ति को नियोजन में रखा गया है।

4– अपने कथनों को साबित करने के लिए श्रमिक मांगीलाल ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर सत्यापित कराया जिससे नियोजक प्रतिनिधि ने जिरह की और प्रलेखिक साक्ष्य में प्रदर्श डब्ल्यू – I लगायत डब्ल्यू -II फोटो प्रति पेश की, इसके विपरीत नियोजक की तरफ से श्री हरिप्रसाद गुप्ता उप मण्डल अधिकारी का शपथ पत्र पेश किया गया है जिससे श्रमिक प्रतिनिधि ने जिरह की है, तत्पश्चात् मैंने पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना।

5– मुख्य विवादक बिन्दु यह है कि क्या श्रमिक ने एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिवस सेवा पूरी की है। श्रमिक का कहना है कि उसने दिनांक 1-6-83 से 31-12-84 तक निरन्तर कार्य किया है जबकि नियोजक का कहना है कि श्रमिक ने सब-डिवीजन सैकिण्ड कोटा में दिनांक 1-7-83 से 30-9-83 तक कार्य किया है और तत्पश्चात् सब-डिवीजन फर्स्ट कोटा में 1-11-83 से 30-6-84 तक कार्य किया है। नियोजक के इस कथन को स्वीकार कर भी लिया जाए कि सब-डिवीजन फर्स्ट और सब-डिवीजन सैकिण्ड पृथक-पृथक अपने में स्वतंत्र इकाई हैं तो भी इससे विशेष अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि सब डिवीजन सैकिण्ड में श्रमिक ने जो सेवा की है उसी का साक्ष्य का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जा रहा है।

नियोजक के अनुसार सब-डिवीजन फर्स्ट में श्रमिक ने 1-11-83 से 30-6-84 तक सेवा की है। ऐसा ही कथन हरिप्रसाद गुप्ता नियोजक साक्षी ने अपने शपथ पत्र की चरण सं. 4 और 6 में किया है जबकि श्रमिक ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि उसने सब डिवीजन फर्स्ट में 1-10-83 से 31-12-84 तक कार्य किया है। पक्षकारों का मौखिक साक्ष्य की विश्वसनीयता आंकने हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत प्रलेखिक साक्ष्य का विश्लेषण करना आवश्यक है। प्रदर्श डब्ल्यू-1 अक्तूबर 83 की मस्ट्रोल की फोटो प्रति है जो नियोजक ने ही न्यायालय के आदेश से प्रस्तुत की है। इसके अनुसार भी मांगीलाल ने अक्तूबर 83 में 27+4 दिवस कार्य किया है अर्थात् 31 दिवस की उसकी हाजरी लगी हुई है। अभिप्राय यह है कि 27 दिवस तो उसने कार्य किया है और इसके अलावा चार रविवारीय अवकाश का उसे लाभ दिया गया है। नियोजक ने क्लेम के प्रति उत्तर में तो 1-11-83 से ही सब-डिवीजन फर्स्ट में कार्य करना बताया है जबकि नियोजक की ही मस्ट्रोल प्रदर्श डब्ल्यू-1 के अनुसार अक्तूबर-83 में भी इस श्रमिक ने 31 दिवस कार्य किया है। इस विषय में प्रतिपरीक्षा करने पर नियोजक साक्षी हरि प्रसाद गुप्ता कहते हैं प्रदर्श डब्ल्यू-1 के हिसाब से भी मांगीलाल ने 27+ 4 कुल 31 दिवस और कार्य किया है। इस प्रकार श्रमिक के

कथनों में सत्यता का आभास होता है कि उसने सब डिवीजन कर्म कोटा में दिनांक 1-10-83 से कार्य किया था। नवम्बर 83 की मस्ट्रोल डब्ल्यू-5 है, जिसके अनुसार मांगीलाल ने 26+4 दिवस कार्य किया है। दिसम्बर 83 की मस्ट्रोल की फोटो प्रति डब्ल्यू – 6 है जिसके अनुसार मांगीलाल ने 27+7 दिवस कार्य किया है। प्रदर्श डब्ल्यू –7 जनवरी 84 की मस्ट्रोल है जिसके अनुसार भी मांगीलाल ने 27+4 दिवस कार्य किया है। प्रदर्श डब्ल्यू – 8 फरवरी 84 की मस्ट्रोल है जिसके अनुसार मांगीलाल ने 25+4 दिवस कार्य किया है, मार्च 84 की मस्ट्रोल डब्ल्यू–2 है जिसके अनुसार मांगीलाल ने 24+4 दिवस कार्य किया है, प्रदर्श डब्ल्यू-9 मस्ट्रोल अप्रैल 84 की है जिसके अनुसार मांगीलाल ने 26+4 दिवस कार्य किया है, प्रदर्श डब्ल्यू – 10 मस्ट्रोल मई 84 की है, जिसके अनुसार मांगीलाल ने 18+3 दिवस कार्य किया है। प्रदर्श डब्ल्यू 11 मस्ट्रोल जून 84 की है जिसके अनुसार मांगीलाल ने 22+3 दिवस कार्य किया है। जून 84 की मस्ट्रोल न्यायालय के आदेश के बावजूद भी नियोजक ने पेश नहीं की और न ही कोई उचित कारण बताया। इस विषय में 26-11-88 की आदेशिका महत्वपूर्ण है। जिसके अनुसार अक्तूबर 83 से दिसम्बर 85 तक की मस्ट्रोल पेश करने का आदेश दिया गया था। नियोजक से अपेक्षा थी कि वह जून 84 के बाद की भी मस्ट्रोल की फोटो प्रति पेश करता चाहे उक्त मस्ट्रोल में श्रमिक का नाम हो नहीं होता। तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि श्रमिक ने जून 84 के बाद नियोजक के यहां सेवा नहीं की तो भी इससे नियोजक को कोई लाभ नहीं मिलता क्योंकि अक्तूबर 83 से जून – 84 तक की अवधि में जिनकी फोटो प्रतिलिपि पत्रावली पर प्रस्तुत है, से भी श्रमिक ने 256 दिवस सेवा कर ली थी इसलिए भी श्रमिक धारा 25 (एफ) के लाभ का अधिकारी था।

6– नियोजक प्रतिनिधि ने बहस के दौरान एक तर्क प्रस्तुत किया कि प्रदर्श एम – 1 नोटिस द्वारा श्रमिक की सेवा मुक्ति दिनांक 31-12-84 से की गई है इसलिए न्यायालय को दिनांक 1 जनवरी, 84 से 31-12-84 तक की अवधि में श्रमिक द्वारा कार्य करना भी देखना होगा। मैं नियोजक के उक्त तर्क से सहमत नहीं हूं। मेरी राय में सेवा मुक्ति से पूर्व कभी भी अगर किसी श्रमिक ने किसी भी 12 महीने में 240 दिवस की सेवा पूरी कर ली है तो उसे धारा 25 (एफ) के अन्तर्गत छंटनी भत्ता देना अनिवार्य है। यह उल्लेखनीय है कि जब नियोजक के कथनानुसार जून 84 के बाद श्रमिक ने सेवा नहीं की तो उसकी सेवा मुक्ति 31-12-84 से करने का कोई कारण नहीं था। अगर नियोजक प्रतिनिधि का तर्क मान लिया जाये तो प्रत्येक चतुर नियोजक श्रमिक की अनुपस्थिति लगाकर और उसके एक वर्ष उपरान्त सेवा मुक्ति आदेश पारित कर देगा तथा उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों से वंचित कर देगा। अतः उपरोक्त समस्त कारण से मेरी राय में इस श्रमिक ने जून 84 को समाप्त हुए एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक सेवा पूरी कर ली थी और वह धारा 25 (एफ) के अनुसार छटनी भत्ते का अधिकारी था। 30 दिवस का नोटिस अथवा नोटिस एवज में एक माह के वेतन का भी अधिकारी था। तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि नियोजक ने प्रदर्श एम – 1 नोटिस एक माह का दिया था तो भी छंटनी भत्ता नहीं दिया गया इसलिए भी धारा 25 (एफ) के विपरीत छंटनी की गई है जो स्वतः अनुचित एवं अवैध है।

7– यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श एम – 1 पत्र जारी करने की तारीख दिनांक 22-11-84 है परन्तु श्रमिक को यह कब प्राप्त हुआ इस बाबत नियोजक की तरफ से न तो कोई ए. डी. रसीद पेश की गई है और न ही ऐसा कोई मौखिक साक्ष्य जिससे यह साबित हो कि यह दिनांक 31-12-84 से एक माह पूर्व श्रमिक को प्राप्त हो गया था जब श्रमिक ने अपने क्लेम में ही यह दर्ज कर दिया था कि उसे नोटिस 10 दिवस की अवधि का ही मिला है तो नियोजक पर यह भारी सबूत था कि वह अपनी साक्ष्य से साबित करता कि श्रमिक को एक माह का नोटिस दे दिया गया था। अतः पूरे एक माह का नोटिस श्रमिक को देना ही साबित नहीं है।

8– जहां तक वरिष्ठता सूची बनाने का प्रश्न है हालांकि क्लेम के प्रति उत्तर में तो नियोजक ने कहा है कि नियमानुसार वरिष्ठता सूची बनाई गई थी जिस तथ्य को श्रमिक ने अस्वीकार किया है। तथाकथित वरिष्ठता की सूची न तो न्यायालय में पेश की गई और न ही वरिष्ठता सूची बाबत श्रमिक मांगीलाल से प्रतिपरीक्षा में सुझावात्मक प्रश्न किये गये। नियोजक साक्षी हरिप्रसाद गुप्ता प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करता है कि रिट्रेन्च के समय वरिष्ठता सूची नहीं बनाई थी। अगर वास्तव में कोई वरिष्ठता सूची छंटनी के पहले बनाई गई थी तो उसकी प्रतिलिपि न्यायालय में पेश की जानी चाहिए थी अतः धारा 25 (जी) एवं नियम 77, 78 की अवहेलना की गई है।

9– तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से दिनांक 1-1-85 के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता, इसे अनुचित एवं अवैध घोषित करते हुए अपास्त किया जाता है और इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :

श्रमिक मांगीलाल की सेवा मुक्ति का आदेश दिनांक 1-1-85 विधिवत एवं उचित नहीं है और इस श्रमिक को सेवा में नियोजित घोषित करते हुए इसे उक्त पद का वेतन व अन्य सभी लाभ दिलाये जाते हैं। सेवा की निरन्तरता भी कायम रखी जाती है, अगर नियोजक अन्दर तीन माह इस श्रमिक को उक्त अवधि का वेतन व अन्य सभी लाभ अदा नहीं करेगा तो मिलने वाली राशि पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी अदा करेगा। 100 रु. खर्चा मुकदमा भी दिलाया जाता है। उक्त आशय का अवार्ड पारित किया जाता है, जिसे प्रकाशनार्थ केन्द्र सरकार को अन्तर्गत धारा 17 (1) अधिनियम भेजा जाये।

जगत सिंह, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 27 मई, 1992

का.आ 1651:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार वैस्टर्न रेलवे अजमेर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41012/36/84–डी 2(बी) (पीटी)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th May, 1992

S.O. 1651.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Railway, Ajmer and their workmen, which was received by the Central Government on 25-5-92

[No L-41012/36/84-D.II(B)(Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 1/86

केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचन संख्या: एल. 41012(36)/84-डी. 2(बी)

दिनांक 26-12-85

श्री नरेश कुमार ए/10/4, सर्वी, रेलवे कोलोनी, न्यू कांडला, कच्छ

बनाम

दी डिवीजनल रेलवे मैनेजर, वेस्टर्न रेलवे,
अजमेर (राज.)
उपस्थिति

माननीय न्यायाधीश श्री जगत सिंह, आर.एच.जे.एस.
श्रमिक पक्ष की ओर से: श्री एम. एफ. बेग
नियोजक पक्ष की ओर से: श्री बी. एस. माथुर
दिनांक अवार्ड: 17-7-91

अवार्ड

केन्द्र सरकार ने निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को अन्तर्गत धारा 10(1)(डी) औ. वि. अधिनियम 1947 अधिनिर्णय हेतु अपनी अधिसूचना सं. एल 41012(36) 84-डी. II(बी) दिनांक 26-12-1985 के द्वारा प्रैषित किया है--

"Whether the action of the management of Divisional Railway Manager, Western Railway, Ajmer in dismissing Shri Naresh Kumar, Cabinman from service w.e.f 18-7-1983 is justified ? If not, to what relief is Shri Naresh Kumar Cabinman entitled ?"

2. प्रार्थी नरेश कुमार जिसे तत्पश्चात श्रमिक सम्बोधित किया गया है ने जरिये क्लेम प्रकट किया कि उसे नियोजक ने एक आरोप पत्र दिनांक 26-8-82 को जारी किया जिसमें 23-7-82 को कार्य से अनुपस्थिति का आरोप लगाया गया था और यह भी आरोप था कि उस रोज श्रमिक काण्डला पोर्ट और गांधीधाम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा आल इण्डिया शन्टिंग केबिन और यातायात स्टाफ एसोशियेशन के सदस्यों को अपनी विभिन्न मांगों के लिए प्रशासन पर दबाव डालने हेतु उन्हें उकसाने हेतु गया था। श्रमिक कहता है उसने उक्त आरोप पत्र का स्पष्ट रूप से उत्तर दिया था कि वह दिनांक 23-7-82 को काण्डलापोर्ट और गांधीधाम नहीं गया न ही किसी को उकसाया बल्कि उस रोज उसकी ड्यूटी 8 बजे से बीस बजे की शिफ्ट में थी और वह 17.15 बजे से 20 बजे तक अनुपस्थित नहीं था बल्कि अस्वस्थ हो जाने के कारण रेलवे डाक्टर के उपलब्ध न होने की स्थिति में प्राईवेट डाक्टर के पास उपचार हेतु गया था और एक दिन रेस्ट करने हेतु प्रमाण पत्र दिया था। तथा केबिन की चाबी और चार्ज तुफानी राम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को देकर गया था। श्रमिक कहता है उक्त स्पष्टीकरण के उपरांत भी नियोजक ने नियमों के विपरीत जांच कार्यवाही कर उसे सेवा मुक्त किया है तथाकथित जांच कार्यावाही भी प्रोपर एवं फेयर नहीं है और सेवा मुक्ति उपरांत से वह बेरोजगार बैठा है। इसलिए सेवा मुक्ति आदेश अपास्त किया जाये।

3. अप्रार्थी नियोजक ने जरिये प्रतिउत्तर श्रमिक के कथनों को अस्वीकार किया है और कहा है कि दिनांक 23-7-82 को श्री नरेश कुमार केबिनमैन ने जानबूझकर तथा नियोजक से अनुमति लिये बिना ड्यूटी से गैर हाजिर हो गया उस रोज उसकी ड्यूटी 8 बजे से 20 बजे तक थी तथा करीब 17 बजे उसने तीन घण्टे की छुट्टी के लिए निवेदन किया था परन्तु उसे अनुमति नहीं दी गई इस पर भी वह कार्य से अनुपस्थित हो गया। वास्तव में वह बीमार नहीं था बल्कि उक्त अवधि में काण्डला पोर्ट और गांधी धाम के क्लास फोर्थ तथा शन्टिंग केबिन और यातायात स्टाफ एसोशियेशन के सदस्यों को उकसाने गया था जिस बाबत काण्डला पोर्ट के सुपरिटेंडेन्ट की रिपोर्ट अने. 4 पेश है इसलिए श्रमिक के विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर नियमानुसार जांच कराकर दण्ड दिया गया है।

4. दिनांक 5-4-89 के आदेश के अनुसार श्रमिक प्रतिनिधि ने घरेलू जांच प्रोपर एवं फेयर होना स्वीकार किया था। उक्त विषय का उल्लेख आदेशिका में पाया जाता है इसलिए तत्कालीन अधिकारी ने कराई गई घरेलू जांच को प्रोपर एवं फेयर माना।

5. मैंने जांच पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तार पूर्वक सुना। मुझे यह देखना है कि नियोजक द्वारा कराई गई घरेलू जांच में ली गई साक्ष्य से श्रमिक पर लगाये गये आरोप साबित हैं अथवा नहीं? और नियोजक द्वारा दिया गया दण्ड अनुचित एवं अत्यधिक तो नहीं है।

6. जांच पत्रावली के अनुसार श्रमिक पर दो आरोप थे। एक तो 17.15 बजे से 20 बजे तक अनुपस्थिति का और दूसरा काण्डला पोर्ट एवं गांधी धाम पर क्लास फोर्थ स्टाफ तथा शण्टिंग केबिन एवं ट्रेफिक एसोसियेशन के स्टाफ को उकसाने का था। जांच अधिकारी ने ही आरोप सं. 2 साबित नहीं पाया इस लिए आरोप सं. 1 बाबत ही जांच में ली गई साक्ष्य का विश्लेषण करना आवश्यक होगा।

7. आरोप सं. 1 साबित करने के लिए नियोजक की तरफ से सर्व श्री आशाराम चौधरी, एन.एम. गुप्ता, प्रताप, माधुराम, मोहन पंजवानी के बयान कराये है। इसके विपरीत श्रमिक नरेश कुमार ने स्वंय का अपना बयान कराया है। श्रमिक का कथन यह है कि उस रोज वह 17.15 बजे से 20 बजे तक बीमारी की वजह से अनुपस्थित हुआ था और उसकी छुट्टी की अर्जी भी स्वीकृत नहीं हुई तथा रेलवे डाक्टर के उपलब्ध न होने से उसने प्राईवेट डाक्टर से उपचार करवाया जबकि नियोजक के कथन यह है कि वास्तव में श्रमिक बीमार नहीं हुआ बल्कि हड़तालो कर्मचारियों को उकसाने के लिए काण्डला पोर्ट व गांधी धाम गया। मुझे यह देखना है कि किस पक्षकार के कथन में सत्यता का आभास होता है।

8. नियोजक साक्षी आशाराम चौधरी अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करता है कि वह 10 बजे से 18 बजे तक स्टेशन पर ड्यूटी पर था, 17.15 बजे के करीब नरेश कुमार "ए" केबिन पर ड्यूटी कर रहा था उसने कहा तबीयत ठीक नहीं है अस्पताल जाना चाहता है मैंने उसको कहा मिक मेनो ले लो या एस.एम. साहब से पूछ लो। प्रतिपरीक्षा में साक्षी कहता तत्पश्चात है वह एस. एम. साहब के पास गया था वहां पर बाबू पी.के. हंस बोला नरेश कुमार छुट्टी चाहता

है क्योंकि उसकी तबियत खराब है परन्तु ए.एस.एम. साहब यहां नहीं हैं और मना करके गये हैं कि सिकमिमो किसी को नहीं देना। नियोजक साक्षी एन.एम. गुप्ता इस आरोप से संबंधित साक्षी नहीं है। नियोजक साक्षी प्रताप भी किसी प्रकार के कथन साबित नहीं करता। नियोजक माधूराम भी इस आरोप से संबंधित साक्षी नहीं है। जबकि नियोजक साक्षी मोहन पंजवानी का कहना है कि दिनांक 23-7-82 को नरेश कुमार ने 17 बजे से 20 बजे तक तीन घण्टे की परमीशन मांगी थी। श्री हंस क्लर्क ने इससे कहा कि एस.एस. साहब या ए. एस. एम आन ड्यूटी की परमीशन के बिना नहीं जाये। नियोजक की उपरोक्त साक्ष्य से भी यही निकला कि नरेश कुमार ने 17 बजे से 20 बजे तक तीन घण्टे की परमीशन मांगी थी जो उसे नहीं दी गई। श्रमिक ने पेट में दर्द होना और अस्वस्थ होना बताया था। मेरी राय में नियोजक से अपेक्षा थी कि वे श्रमिक को तीन घण्टे की अनुमति देते क्योंकि तर्क के लिए मान भी लिया जाये कि श्रमिक अस्वस्थ नहीं था और संघ के कार्य हेतु जाना चाहता था तो भी मोडल एम्पलोयर की हैसियत से श्रमिक को अनुमति देनी अपेक्षित थी, अतः मेरी राय में ली गई घरेलू साक्ष्य से भी आरोप सं. 1 साबित नहीं है और उक्त आरोप पर श्रमिक को दिया गया दण्ड भी आरास्त किया जाता है। सेवा मुक्ति अवधि में श्रमिक कहीं नियोजित नहीं रहा है इस लिए पूरे वेतन का अधिकारी है और इस निर्देश का अविलंब निम्न प्रकार से किया जाता है;

श्रमिक नरेश कुमार केबिन मैन को दिनांक 18-7-83 से सेवा मुक्ति करना उचित एवं वैध नहीं है और सेवा मुक्ति आदेश आरास्त किया जाता है तथा इसे केबिन मैने के पद पर नियोजित घोषित किया जाता है और उक्त पद के वेतन व अन्य सभी लाभ दिलाये जाते हैं। इसकी सेवायें निरन्तर मानी जायगी। 100 रु. खर्चा मुकदमा दिलाया जाता है। अगर नियोजक उक्त राशि अन्दर तीन माह में अदा नहीं करेगा तो उसे मिलने वाली राशि पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी अदा करेगा। उक्त आशय का पंचाट पारित किया जाता है जिसे वास्ते प्रकाशनार्थ केन्द्र सरकार को अन्तर्गत धारा 17 (1) अधिनियम भेजा जाय।

जगत सिंह, न्यायाधीश

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई, 1992

का.आ. 1652:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, दरीबा कापर प्रोजेक्ट अलवर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-43012/30/87-डी-III (बी)]
बी.एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th May, 1992

S.O. 1652.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dariba Copper Project, Alwar and their workmen, which was received by the Central Government on 26-5-1992.

[No L-43012/30/87-D.III(B)]
B. M DAVID, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

के. नं. सी.आई.टी: 21/1988

रैफरैंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-43012/30/87-डी-III (बी) दिनांक 9-3-88

कापर प्रोजेक्ट मजदूर यूनियन, अलवर।

--प्रार्थी

बनाम

दरीबा कापर प्रोजेक्ट, अलवर

-अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय श्री जगतसिंह जी, आर०एच०जे०एस०

प्रार्थी के ओर से : श्री एम.एफ. बेग
अप्रार्थी की ओर से : श्री मनोज कुमार शर्मा
दिनांक अवार्ड : 4 मार्च, 1992

अवार्ड

श्री काशीनाथ प्रार्थी स्वयं मय प्रतिनिधि श्री एम.एफ. बेग यूनियन की ओर से उपस्थित हैं श्री मनोज कुमार शर्मा विपक्षी की ओर से उपस्थित है। पक्षकारान के प्रतिनिधियों ने एक बाहरी समझौता पेश किया जिसे तस्दीक किया गया। पक्षकारों की प्रार्थनानुसार इस प्रकरण में समझौते के आधार पर अवार्ड पारित किया जाता है। समझौता अवार्ड का अंग रहेगा। अवार्ड की प्रति केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार पठाई जावे।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई, 1992

का.आ. 1653:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एस.डी.ओ (टी) सूरतगढ़ के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/64/89-डी-2 (बी) (Pt.)]
बी.एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th May, 1992

S.O. 1653.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of SDO(T) Suratgarh and their workmen, which was received by the Central Government on 25-5-1992.

[No L-40012/64/89-D II(B)(Pt.)]
B. M DAVID, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक प्राधिकरण, जयपुर,

केस नं० सी०आई०टी० 9/90

केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एल-40012/64/89-आई आर. (डी-यू) दि. 15-1-90 जनरल सैक्रेटरी, भारतीय मजदूर संघ, जे. सी.टी. मिल्स के मामले, श्री गंगानगर।

बनाम

सब डिवीजनल ऑफिसर (टेलीफोन) सूरतगढ़।

उपस्थिति

माननीय न्यायाधीश श्री जगत सिंह, आर.एच.जे.एस.

यूनियन की ओर से : श्री जयबीर सिंह

नियोजक की ओर से : श्री ए०डी० शर्मा

दिनांक अवार्ड : 13-2-92

अवार्ड

केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय हेतु अपनी अधिसूचना सं. एल-40012/64/89 आई.आर. (डीयू) दिनांक 15-1-90 के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 (1) (घ) के अंतर्गत प्रेषित किया है—

"Whether the action of the management of SDO(T) Suratgarh is justified in terminating the services of Sh. Arjun Singh Casual Labour from 1-7-88 ? If not to what relief is the workman entitled ?"

2. प्रार्थी अर्जुन सिंह जिसे तत्पश्चात् श्रमिक सम्बोधित किया गया है, ने जरिये क्लेम प्रकट किया कि उसकी नियुक्ति 4-8-81 को दैनिक वेतनभोगी श्रमिक के स्थाई व स्वीकृत पद पर की गई थी और उसने बिना किसी व्यवधान के 30-6-88 तक कार्य किया था। 30-6-88 को प्रतिवादी पक्ष द्वारा सेवा से पृथक किया गया। श्रमिक कहता है कि उसने हमेशा ईमानदारी, निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों को निभाया था और नियोजक को कभी भी अनुशासनिक कार्यवाही नहीं करनी पड़ी। श्रमिक का कहना है कि संस्थान में जब वह कार्यरत था तभी वह अस्वस्थ हो गया उसे डाक्टर के पास ले जाया गया जिसने पूर्ण इलाज कराने व आराम करने की सलाह दी और वह 1-5-84 से 17-11-84 तक उपचारार्थ रहा उक्त अवधि का चिकित्सा प्रमाणपत्र बीमारी का उसने नियोजक को भेज दिया था तत्पश्चात् भी उसका इलाज जारी रहा और 18-11-84 से 18-11-85 तक की अवधि का भी उसने बीमारी का प्रमाणपत्र नियोजक को भेजा था परन्तु फिर भी वह ठीक नहीं हुआ और दिनांक 19-5-85 से 1-5-86 उसके बाद 1-5-85 से 2-12-86 और अंतिम बार 2-12-86 से 28-12-86 तक भी वह उपचार में रहा था और उक्त अवधि में मेडिकल प्रमाणपत्र भी उसने स्वयं हाजिर होकर नियोजक को पेश कर दिया है श्रमिक कहता है कि नियोजक ने उक्त प्रमाणपत्रों स्वीकार कर लिया और 1-7-88 का ड्यूटी ज्वाईन करवा दी तथा पूर्व की भांति वह अपनी ड्यूटी अंजाम देने लग गया परन्तु फिर भी उसे अचानक दिनांक 1-8-88 को सेवा पृथक कर दिया। श्रमिक कहता है कि उसने प्रतिवर्ष 240 दिवस से अधिक ड्यूटी की थी परन्तु फिर उसे धारा 25 (एफ) के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया अर्थात् न तो नोटिस दिया न नोटिस की एवज में एक माह का वेतन दिया गया न ही छटनी भत्ता दिया गया। श्रमिक यह भी कहता है कि छंटनी के पूर्व में कोई वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की गई और न ही पीछे आओ पहले जाओ के सिद्धान्त की पालना की गई इसलिए नियोजक द्वारा धारा 25-एफ, जी., एच एवं नियम 77 की अवहेलना की गई है और सेवा मुक्ति अवैध एवं अनुचित होने से वह सवेतन नियोजित होने का अधिकारी है।

3. अप्रार्थी नियोजक ने जरिये प्रति उत्तर यह प्रकट किया कि श्रमिक 1-10-81 से दैनिक वेतन आधार पर अस्थाई केजुअल के स्थान पर लगाया गया था और उसने 30-4-84 तक कार्य किया है। उसने 1-5-84 से स्वेच्छा से आना बंद कर दिया। दिनांक 1-1-88 से उसकी प्रार्थना पर उसे फिर दैनिक वेतन अस्थाई केजुअल पद पर रखा गया और उसने कार्य की समाप्ति पर 1-7-88 से कार्य कराना बंद कर दिया। नियोजक के अनुसार इससे स्पष्ट है कि श्रमिक ने 1-10-81 से 30-6-87 तक नियमित कार्य नहीं किया है। नियोजक यह भी कहता है कि श्रमिक को एक निश्चित परियोजना एवं एक निश्चित कार्य के लिए लगाया गया था जिसकी समाप्ति के बाद उसे सेवा से हटाया गया था। नियोजक के अनुसार दिनांक 1-7-88 से पूर्व श्रमिक ने मात्र 152 दिवस कार्य किया है न कि 240 दिवस इसलिए वह धारा 25 (एफ) के अंतर्गत नोटिस अथवा नोटिस वेतन या छंटनी भत्ते का अधिकारी नहीं है। 1-5-84 से श्रमिक अनुपस्थित था और 1-3-89 को उसने एक साथ ही बीमारी के प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये थे। श्रमिक के इन बीमारी के प्रमाणपत्रों के आधार पर पुराने काम पर नहीं रखा गया था बल्कि नये काम की शुरूआत होने पर नये सिरे से परियोजना एवं निश्चित कार्य पर लगाया गया था इसलिए 1-1-88 से पूर्व की सेवा का श्रमिक से कोई संबंध नहीं है।

4. अपने कथनों के समर्थन में श्रमिक अर्जुन सिंह ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर सत्यापित कराया जिससे नियोजक प्रतिनिधि ने जिरह की और प्रलेखिक साक्ष्य में डब्ल्यू-I लगायत डब्ल्यू-II फोटो प्रति पेश की गई। इसके विपरीत नियोजक की ओर से श्री नरेंद्र कुमार सहायक अभियंता ने शपथ पत्र पेश किया जिससे श्रमिक प्रतिनिधि ने जिरह की तत्पश्चात् मैंने पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना।

5. क्लेम के प्रति उत्तर में नियोजक ने यह स्वीकार किया है कि 1-10-81 से 30-4-84 तक इस श्रमिक ने काम किया था और तत्पश्चात 1-5-85 से गैर हाजिर हो गया था। दिनांक 1-1-88 को वह काम पर आया तब उसने बीमारी का प्रमाणपत्र पेश किया था परन्तु उसे नये सिरे से अस्थाई केजुअल पर रखा गया था। नियोजक साक्षी नरेन्द्र कुमार ने भी अपने शपथ पत्र में उक्त तथ्यों को दोहराया है इन परिस्थितियों में यह तो साबित है कि 1-10-81 से 30-4-84 तक इस श्रमिक ने लगातार सेवा की थी और प्रत्येक वर्ष में 240 दिवस से अधिक सेवा पूरी कर ली थी। यह मान भी लें कि 1-5-84 से 30-9-84 तक यह श्रमिक गैर हाजिर हो गया था तो भी उक्त अनुपस्थिति नियोजक के स्थाई आदेशों एवं एल. रोबर्ट डिसूजा के न्याय दृष्टान्त 1982 (1) एल.एल.एन. 257 के अनुसार यह एक दुराचरण था जिसके लिए नियोजक से यह अपेक्षा की कि वह नियमानुसार आरोप अधिरोपित कर जांच कराकर श्रमिक को उचित दण्ड देता जो कार्यवाही निर्विवाद रूप से नियोजक द्वारा नहीं की गई।

6. दिनांक 1-1-88 को जब श्रमिक उपस्थित हुआ तो उसने 1-5-84 से 31-12-87 तक की अवधि के मेडिकल प्रमाण पत्र भी पेश किये थे जिसे तथ्य को क्लेम के प्रति उत्तर में तथा नियोजक साक्षी ने अपने शपथ पत्र द्वारा भी स्वीकार किया है। उक्त प्रमाणपत्रों की फोटो प्रतिलिपि डब्ल्यू-I लगायत डब्ल्यू-IX अभिलेख पर भी पेश की गई है। नियोजक ने न ही तो क्लेम के प्रति उत्तर में ही यह कहा कि श्रमिक द्वारा उपरोक्त स्वास्थ्य प्रमाणपत्र फर्जी थे और न ही नियोजक साक्षी नरेन्द्र कुमार ने इस बारे में कुछ कहा है। जिससे ही यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तव में श्रमिक के उपरोक्त स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों को उस समय तो मान लिया था अन्यथा मेडिकल के उन प्रमाणपत्रों को अस्वीकृत करने का कोई आदेश पारित किया जाता।

7 क्लेम के प्रति उत्तर में नियोजक ने कहा है कि 1-1-88 को श्रमिक को नये सिरे से किसी एक निश्चित परियोजना व लक्षित कार्य हेतु लगाया गया था। उक्त निश्चित परियोजना व उसका लक्षित कार्य क्या था। यह क्लेम के प्रति उत्तर में स्पष्ट नहीं किया गया है। इसमें यह

भी दर्ज नहीं है कि 1-1-88 को ही श्रमिक को ऐसी कोई सूचना दी गई हो कि उसे किसी निश्चित परियोजना व स्वीकृत कार्य के लिए लगाया गया हो। उक्त कार्य कितने दिन चलने वाला था यह क्लेम के प्रति उत्तर में दर्ज नहीं किया गया है और न ही श्रमिक से इस बारे में कोई प्रति परीक्षा की गई है। सर्वप्रथम नियोजक साक्षी नरेन्द्र कुमार ही शपथपत्र की चरण सं.-3 में 28-9-91 को ही प्रकट करता है कि श्रमिक को साफ बताते हुए कि श्रमिक की कार्य अवधि छः माह की है उसे 1-1-88 को काम पर लिया गया था। मेरी राय में नियोजक साक्षी के उक्त अपुष्ठ कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि छः माह की अवधि पर लेने का उल्लेख तथा ऐसा श्रमिक को भी स्पष्ट करने वाला तथ्य न तो क्लेम के प्रति उत्तर में दर्ज है और न ही इस विषय में श्रमिक से सुझावात्मक प्रति परीक्षा की गई है। अगर वास्तव में ऐसा था तो नियुक्ति के समय ही ऐसा कोई आदेश पारित क्यों नहीं किया गया।

8. क्लेम में श्रमिक ने यह भी दर्ज किया था कि सेवा मुक्ति से पूर्व वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई तथा "पीछे आओ पहले जाओ" सिद्धान्त की पालना नहीं की गई। उक्त कथन का कोई प्रति उत्तर नियोजक द्वारा क्लेम के प्रति उत्तर में नहीं किया गया है। नियोजक साक्षी नरेन्द्र कुमार ने भी अपने शपथ पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया है यहां तक कि श्रमिक से भी प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है। जब श्रमिक ने क्लेम के अनुसार ही अपने शपथ-पत्र में ही यह दर्ज कर दिया था कि सेवा मुक्ति से पूर्व वरिष्ठता सूची बनी नहीं और न ही श्रमिक से वरिष्ठ किसी व्यक्ति को हटाया गया तो नियोजक का यह उत्तरदायित्व था कि इस विषय में भी अपनी प्रलेखिक अथवा मौखिक साक्ष्य पेश करते। इसलिए अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से एवं उपरोक्त समस्त कारणों से नियोजक द्वारा धारा 25 (एफ) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है तथा धारा 25 (जी) और नियम-77 की भी अवहेलना की गई है। इसलिए इस निर्देश का अधिनियम निम्न प्रकार से किया जाना है—

श्रमिक अर्जुन सिंह केजुअल लेबर की 1-7-88 से सेवा मुक्ति उचित एवं वैध नहीं है और इसे सेवा में नियोजित मानते हुए उक्त पद का वेतन व अन्य सभी लाभ भी दिलाये जाते हैं। 100 रु. खर्चा मुकदमा दिलाया जाता है। अगर नियोजक ने अन्दर तीन माह में उक्त राशि अदा नहीं की तो 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उक्त राशि पर श्रमिक को ब्याज भी देगा। उक्त आशय का अवार्ड पारित किया जाता है जिसे केन्द्र सरकार को अंतर्गत धारा 17(1) अधिनियम प्रकाशनार्थ भेजा जावे।

जगत सिंह, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 27 मई, 1992

का. आ. 1654—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार वेस्टर्न रेलवे जयपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 25-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल—41012/24/88—डी-2 (बी) (पी टी)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th May, 1992

S.O. 1654.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of DRM, Western Railway, Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on 25-5-92.

[No. L-41012/24/88-D.II(B)(Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं., सी. आई. टी. 71/1989

रैफरैन्स : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-41012/24/88 डी-2(बी) दिनांक 19-7-89

श्री हैरल्ड आस्टीन मैसी पुत्र श्री ए. सी. मैसी, मिशन कम्पाउंड प्लाट नं. 33 अजमेर रोड, जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

डिवीजनल रेलवे मैनेजर पश्चिमी रेलवे, जयपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय श्री जगतसिंहजी, आर. एच. जे. एस. न्यायाधीश

प्रार्थी की ओर से .... श्री बी. एम. बागड़ा

अप्रार्थी की ओर से .... श्री संदीप सक्सेना

दिनांक अवार्ड 4-3-1992

अवार्ड

आज यह पत्रावली दोनों पक्षों की प्रार्थना पर लोक अदालत में ली गई। श्रमिक हैरल्ड मैसी तथा उसके प्रतिनिधि श्री बी. एम. बागड़ा उपस्थित हैं, नियोजक की तरफ से श्री संदीप सक्सैना उपस्थित हैं।

2. समझाने-बुझाने के पक्षकारान् निम्न तरीके से आदेश हेतु राजी हुए हैं। 3-10-91 को भी पक्षकारान ने एक बाहमी समझौता पेश किया था इसलिए इस निर्देश का निपटारा निम्न प्रकार से किया जाता है।

3. श्रमिक को नियोजक ड्यूटी पर लेगा और उसकी पुरानी सीनियोरिटी देगा परन्तु सेवा मुक्ति की तारीख से सेवा में लेने की तारीख तक का वेतन "नो वर्क नो पे" के सिद्धान्त पर नहीं दिया जाएगा। सेवा की निरन्तरता कायम रखी जाएगी तथा नोशनल फिक्सेशन करते हुए सेवा में लेने की दिनांक से वेतन व अन्य सभी लाभ दिए जायेंगे। श्रमिक से कनिष्ठ अगर किसी व्यक्ति को रेगलर कर दिया है तो नियोजक अति शीघ्र स्क्रीनिंग कमिटी का आयोजन करेगा और उसमें इस श्रमिक का मामला भी कन्सीडर करेगा। इस आदेश की प्रति सहित श्रमिक नियोजक को सेवा में लेने बाबत प्रार्थना पत्र देगा जिसकी प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर नियोजक श्रमिक को सेवा में ले लेगा। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना बर्दाश्त करेंगे।

4. उपरोक्त आशय का अवार्ड पारित किया जाता है जो भारत सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भेजा जाए।

जगत सिंह पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 28 मई, 1992

का. आ. 1655—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एयर-इण्डिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2 बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 27-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल—11012/29/87—डी-II (बी)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th May, 1992

S.O. 1655.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay, as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Air India and their workmen, which was received by the Central Government on the 27-5-92.

[No. L-11012/29/87-D. II (B)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT :

Shri P. D. Apshankar, Presiding Officer.

REFERENCE NO. CGIT-2/17 OF 1988

PARTIES :

Employers in Relation to the Management of AIR INDIA.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employer : Shri M. M. Verma, Shri R. Dayal, Shri N. S. Lall Advocates.

For the Workmen : Shri M. B. Anchan Advocate.

INDUSTRY : Aviation.

STATE : Maharashtra.

Bombay, dated, the 4th May, 1992.

AWARD

The Central Government by their order No. L-11012/29/87-D. II (B), dated 20-6-1988 have referred the following Industrial Dispute to this Hon'ble Court for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

"Whether the action of the management of Air India in terminating the services of Shri P. K. Shetty, Cleaner w.e.f. 4-8-1986 is legal and justified ? If not, what relief the workman is entitled to ?"

2. The case of the workman Shri P. K. Shetty as disclosed from the Statement of Claim (Ex. 2) filed by him in person in short is thus :

He joined the service in the Air India Corporation as a Cleaner in March, 1977 in the Flight Services Department, and was confirmed in that post in September, 1977. The charge sheet dated 17-3-1986 was issued to him on the ground of his alleged misconduct of absence without permission for 85 days from March, 1985 to December, 1985. As he was not conversant with the enquiry procedure, he did not submit his explanation to that charge sheet. As he was not keeping good health he could not attend the enquiry proceedings. As such the enquiry officer proceeded ex-parte and submitted his report to the disciplinary authority. On the basis of that report the services of the workman were terminated with effect from 4-8-1986 by the order dated 31-7-1986. During the enquiry proceedings, the workman was not given an apportunity to defend himself. That enquiry held against him was held against the principles of natural justice.

During the said period of 85 days he could not attend to his duties due to the sickness of his wife and children. He was to take them to the hospitals for treatment. Whenever he remained absent, he had informed his supervisor on telephone about his non-attendance. He had remained absent with the permission of his supervisor. After returning his duties he could not regularise his leave as the leave card was not available in the section. The work of the regularisation of the leave is of the management, and it was not his work. The punishment of removal from service is disproportionate to the charge levelled question as unjust and illegal, and should from service he is unemployed and his family is starving. The workman, therefore, lastly prayed that this Tribunal should hold the action of the management in question as unjust and illegal, and should direct the management to reinstate him in service with full back wages and the continuity of service.

3. The Deputy Industrial Relations Manager of the Air India Corporation by his Written Statement (Ex. 3) opposed the said claim of the workman, and in substance contended thus :

The said workman had joined the service in the Corporation as a cleaner in March, 1977 and he was confirmed in that post in September, 1977. Since the year 1978 onwards the workman was consistently irregular, as stated below. On 4-12-1978 he was issued a letter by the management for his ratings for the year 1978, as his job Performance Punctuality was 'below average'. On 2-3-1979, he was issued a show-cause notice as to why his increment due on 1-3-1979 should not be deferred in view of his unsatisfactory attendance. As he failed to submit any satisfactory explanation, his increment due on 1-3-1979 was deferred by 6 months. In spite of that he continued his irregular attendance, and hence his annual increment due on 1-3-79 was again withheld for the period of one year. He was again issued a show-cause notice as to why his increment due on 1-3-1980 should not be withheld. Because of his consistant unsatisfactory attendance a charge sheet was issued to him on 11-3-1981 for his unsatisfactory attendance from April, 1980 to January, 1981, i.e. for a period of about 10 months. He admitted the guilt of having remained absent without

permission, and hence the competent authority on 16-4-1981 awarded the punishment of suspension on loss of pay and allowances for a period of 4 days by taking a lenient view. However he continued remaining absent unauthorisedly and again a charge-sheet dated 17-3-1982 was issued to him for his unauthorised absence for the period from March, 1981 to January, 1982. He again continued remaining absent without intimation from 4-4-1982. Thereafter the punishment of reduction of his basic pay for a period of 2 years was inflicted upon him with effect from 1-7-1982. As the workman remained absent without intimation from 4-4-1982 his services were treated as voluntarily abandoned by him. However he again requested for reinstatement, and as a special case he was allowed to resume his duty with effect from 23-3-1983 by treating his absence of the period of about one year as absence without permission.

4. As regard the charge-sheet issued against him in question, the management contended thus :

The charge-sheet dated 17-3-1986 was issued to him for his unsatisfactory attendance from March, 1985 to December, 1985. It is not true that the Workman was not conversant with the enquiry procedure. It is not true that the workman was not keeping good health, as alleged by him. He did not inform the management about his illness He was given full opportunity to defend himself during the enquiry proceedings, and the rules of natural justice were properly followed by the enquiry officer. The enquiry held against him was just and proper. He had not applied for the regularization of his leave during the period he had remained absent without permission. He had not applied to the Corporation for leave in advance, nor did he submit any application thereafter for sanctioning his leave. As such the management was left with no other option but to remove him from the service of the corporation, as he continued to commit the same misconduct again and again. He did not even appear before the enquiry officer even though the reminders were sent to him in that respect by the management. The punishment awarded to the workman is not disproportionate to the misconduct committed by him. His past service record was highly unsatisfactory. Therefore the management lastly prayed for the rejection of the claim of the workman, and prayed that this Tribunal should hold the action of the management in question as just and proper.

5. The Issues framed at Ex. 4 are :

(1) Whether the workman proves that the Enquiry held against him, was held in violation of the principles of natural justice, and that he was not given proper opportunity to defend himself ?

(2) Whether the action of the management of Air India in terminating the services of Shri P. K. Shetty, Cleaner with effect from 4-8-1986, is legal and justified ?

(3) If not, to what relief the workman is entitled ?

(4) What Award ?

6. My findings on the said Issues are :

(1) No.
(2) Yes.
(3) Issue does not survive.
(4) Award as per below.

REASONS

ISSUE NO. 1

7. The workman Shri P. K. Shetty filed his affidavit in support of his case at (Ex. 5), and he was cross-examined on behalf of the management. No oral evidence was led on behalf of the management. In substance the workman stated in his affidavit thus :

As he was mentally disturbed and was sick, he could not attend the enquiry proceedings on 11-7-1986. There was a quarrel between him and his father, and as such, he left his father's house and had gone to stay at the house of his friend. His father had accordingly informed the management about it. He could not regularise his leave, as the leave card was not available in the section. He should be reinstated in service.

However, in his cross-examination the workman stated and admitted thus :

The chargesheet was issued to him by the management in March, 1986. He was asked to put his say to it within 7 days from the date of the receipt of that charge-sheet. He had approached his union, but no 'say' was filed by them to the charge-sheet. He had received the letter from the management that Shri J. S. Rueben was appointed as the enquiry officer. He had received a letter from the enquiry officer that the enquiry proceedings would be held on 11-7-1986. However, he did not appear before the enquiry officer on that day, as he was then sick. His father had sent a letter dated 7-7-1986 to the management that he was not available at his address at the Air India Quarters since 16-5-86. (However the contents of that letter, according to the workman, are not true and correct.) He had not sent any medical certificate to the enquiry officer or to the management about his illness. He was aware of the fact that he was supposed to send the necessary Medical Certificate about his illness. During his period of service of 11 years with the Corporation, he was given a warning, and his increments were stopped.

It is thus quite clear from the admissions made by the workman in his cross-examination that he was given full opportunity to defend himself, but that he himself did not avail of it, and he remained absent. Therefore, the enquiry held against him was held properly, and as per the rules of natural justice.

8. The original file regarding the enquiry proceedings held against the workman has been produced by the management at Ex. 10. It can be seen therefrom thus:

He was charge-sheeted for "Absence without permission" during the period of March to December, 1985, for

85 days. He was thereafter asked to submit his 'say' to that charge-sheet within 7 days from the day of the receipt of that letter dated 17-3-1986. By the letter dated 2-4-1986 the Commercial Manager "Inflight Services" of the Corporation informed the workman that he had not submitted any explanation to the said charge-sheet, and that in case he would not attend the enquiry proceedings, the enquiry would be conducted ex-parte against him, (Thus, he was well informed by the management that in case he would not attend before the enquiry officer, the matter would proceed ex-parte against him). By the letter dated 27-6-1986, the enquiry officer Shri J. S. Reuben had informed the workman that the enquiry would be held in the office of the enquiry officer on 11-7-1986, and that in case he would not attend the enquiry proceedings, the enquiry proceedings would be conducted ex-parte against him. By the letter dated 7-7-1986 the workman's father Shri K.B. Shetty informed the management that since 16-5-86 his son, i.e., workman in question, is out of his house at Santacruz, and he is trying to find out his whereabouts. As such, the workman could not attend the enquiry proceedings on 11-7-1986. However as he did not attend the enquiry proceedings on that day, the enquiry officer adjourned the proceedings to 28-7-1986, and sent the necessary letter dated 11-7-1986 about it to the workman through his office. Even on that day the workman remained absent. On that day Shri A. M. Kulkarni, the witness for the management, was examined and he deposed about the unauthorise absence of 85 days of the workman.

The workman has alleged that the enquiry proceedings were conducted ex-parte against him. However, as noted above, the management and the enquiry officer had taken the proper steps to inform him about the dates of the enquiry proceedings, but he himself had remained absent. Ex. 9 is a letter dated 15-3-1990 sent by the workman to the management. This letter was sent during the pendency of the present Reference before this Tribunal. However, in that letter the workman stated that, "the notices of the enquiry held on 11-7-86 and on 28-7-86 were not served upon him. He was not at his father's place when the notices were sent on that address". As such the workman clearly admitted in the said letter that the management had sent the necessary notices regarding the enquiry proceedings at the last place of his residence. It was for the workman to inform well in advance to the management about the change of his address, if any. However, he had not informed the management about it at any time. As such the necessary steps were properly taken by the enquiry officer and the management to inform him about the dates of the enquiry proceedings, but the workman himself had remained absent on those two days, viz. 11-7-1986 and 28-7-1986, and hence the enquiry proceedings were conducted ex-parte against him. Therefore, it is quite clear from the admissions made by the workman in his cross-examination as well as from the said documentary evidence on record that the enquiry proceedings were held properly and as per the rules of natural justice, and every oportunity was given to the workman to defend himself but that the workman himself did not avail of that opportunity. The enquiry officer therefore found the charge levelled against the workman duly proved. The Disciplinary Authority, i.e., the Commercial Manager 'Inflight Services' by the order dated 4-8-1986 accepted the findings of the enquiry officer that the workman had unauthorisedly remained absent during the said period of March to December, 1985 for 85 days and passed the punishment of removal from service upon the workman under Regulation 43(g) of the Air India Employees Service Regulations.

Issue No. 1 is therefore found in the negative.

9. According to the workman, the punishment of removal from service inflicted upon him by the Disciplinary authority is disproportionate to the nature of the charge levelled against him. However, this contention of the workman is not at all tenable in view of the most unsatisfactory service record of the workman of the previous 7 years. The original file regarding his past record of service from the year 1978 to 1985, i.e. till the date of issuing the charge-sheet in question against him, has been produced by the management at Ex. 11. It will be seen therefrom, and as already stated by the management in their Written Statement, that during the period of 1978, to 1985 the workman used to remain absent without permission often and again and for several days. For that unauthorised absence he was being given warnings by the management from time to time. His increments were also deferred on certain occasions. A disciplinary action was also taken against him. His annual confidential reports were bad, The remarks passed therein were that his work performance was below average and his punctuality was also below average.

His basic pay was also reduced on certain occasions, After he used to remain absent, he was being directed to resume his duty on a particular date, but he was not resuming his duties, and used to continue remaining absent. As such, his past service record was highly bad and most unsatisfactory. He had not improved his behaviour in spite of several warnings and memos issued to him. Even during the enquiry proceedings in question, he had remained absent from service. As such, the punishment of removal from services inflicted upon him by the management is quite, just, legal and proper, and the workman is entitled to no relief.

Issues Nos. 2 and 3 are therefore found accordingly.
In the result, the following Award is passed :

AWARD

The action of the management of Air India in terminating the services of Shri P. K. Shetty, Clearner w.e.f. 4-8-1986 is quite just and legal.

The parties to bear their own costs of this Reference.

P. D. APSHANKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 मई, 1992

का. आ. 1656 .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सीनियर सुपरिन्टैंडेण्ट आफ पोस्ट आफिस, पाली, राजस्थान के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को..... को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल—40012/22/85—डी-2 (बी) (पी टी)]
बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th May, 1992

S.O. 1656.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sr, Supdt. of Post Office, Pali, Rajasthan and their workmen, which was received by the Central Government on.....

[No. L-40012/22/85-D.II(B)(Pt.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 50/1984

रैफरैंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-40012/1/85-डी.III (बी) दिनांक 12-6-84

श्री उमर खान पुत्र श्री शकरू खान द्वारा बाल विद्या भवन (प्राईमरी स्कूल) शिवगंज, जिला सिरोही ।

—प्रार्थी

बनाम

सीनियर सुपरिन्टैंडैंट ऑफ पोस्ट ऑफीसज, पाली जिला पाली मारवाड़ (राजस्थान)

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री जगतसिंहजी, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से :	श्री अशोक परिहार
अप्रार्थी की ओर से :	श्री आर. सी. पापड़ीवाल
दिनांक अवार्ड :	4-2-1992

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10(1)(घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है :

"Whether removal from services of Shri Umar Khan Extra Departmental Branch Post Master Patehpura by the Senior Superintendent of Post Offices is justified? If not, to what relief Shri Umar Khan is entitled?"

2. श्री उमर खान प्रार्थी, जिसे तत्पश्चात श्रमिक संबोधित किया है ने जरिए क्लेम प्रकट किया कि वह 4-2-72 से एक्सट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच पोस्ट मास्टर (ई. डी. बी. पी. एम.) फतहपुरा में कार्यरत था और उसने ईमानदारी, मेहनत व लगन से अपना कार्य किया था, काम के संबंध में कभी कोई शिकायत नहीं हुई थी, उक्त कार्य के अलावा उसने ई. डी. एम. सी. ओ. ई. डी. डी. ए. का भी कार्य किया है जो भी अपने आप में स्वतंत्र पद थे जिन सब के लिए उसे वेतन भत्ता आदि भी मिलता रहा है। उक्त कार्य के अलावा श्रमिक ने नियमानुसार सभी रजिस्टर व रिकार्ड भी तैयार किए हैं परन्तु कुछ स्थानीय व्यक्तियों से अदावत के कारण उसे अनेकों बार कार्य करने में बाधा पैदा हुई है। श्रमिक कहता है वह 6-12-78 से 5-2-79 तक स्वीकृत अवकाश पर था और 6-2-79 को अवकाश उपभोग के उपरांत वह जब ब्रांच पोस्ट आफिस फतहपुरा में कार्य ग्रहण करने आया तो उसे ड्यूटी जोइन करने की अनुमति नहीं दी। मेल ओवरसीयर श्री तुलसीराम से श्रमिक की निजी दुश्मनी थी जिसने ही 5-2-79 के पत्र द्वारा श्रमिक को ड्यूटी जोइन नहीं करने के लिए कहा परन्तु उक्त पत्र में भी कोई कारण दर्ज नहीं था और मेल ओवरसीयर को ऐसा पत्र जारी करने का अधिकार भी नहीं था। इस पर प्रार्थी श्रमिक ने मेल ओवरसीयर के उक्त आदेश बाबत आपत्ति की परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ और 14-2-79 से विपक्ष ने उसे ड्यूटी से आफ कर दिया और 6 माह उपरान्त दिनांक 26-7-79 को एक आरोप जारी कर दिया तत्पश्चात से ही श्रमिक को हैरान व परेशान करना प्रारंभ कर दिया। फरवरी 1979 से श्रमिक को उसके पद का वेतन भी नहीं दिया न ही कोई निर्वाह भत्ता दिया और करीब ढाई वर्ष तक जांच जारी रखी गई जो भी एक फर्जी जांच थी तथा अनुचित तरीके से की गई थी। श्रमिक को अपनी रक्षा करने के लिए उचित अवसर नहीं दिया गया। श्रमिक द्वारा निवेदन करने पर भी जांच अधिकारी के समक्ष संबंधित रिकार्ड पेश नहीं किया गया। गवाहों के बयान तथा उनकी जिरह भी जांच अधिकारी द्वारा सही तरीके से नहीं लिखे गए तथा श्रमिक को भी सफाई पेश करने हेतु पूरा अवसर नहीं दिया। इस सब के होते हुए भी जांच में ली गई साक्ष्य से आरोप साबित नहीं होने थे फिर भी 27-3-82 के आदेश से उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। श्रमिक के अनुसार प्रार्थी नियोजक द्वारा दिया गया उपरोक्त आदेश अनुचित, अवैध तथा श्रम विरोधी नीति का द्योतक था इसलिए उक्त आदेश को अपास्त करते हुए उसे सवेतन पुनः सेवा में बहाल किया जाए।

3. अप्रार्थी की तरफ से प्रारंभिक आपत्तियां की गई है कि भारत सरकार का विभाग होने के नाते रेलवे नेचर की प्रकृति होने से अप्रार्थी संस्थान धारा 2(जे) के अनुसार उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है तथा उमर खान प्रार्थी भी अपने कार्यालय का पूर्णरूपेण इन्चार्ज था और प्रशासनिक प्रकृति के अधिकारों से अधिकृत था इसलिए धारा 2(एस) के अन्तर्गत वह कर्मकार की परिभाषा में नहीं आता है और इसलिए इस न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है।

4. गुणावगुण पर अप्रार्थी का कहना है कि 4-2-72 से उमरखान को फतहपुरा में ई. डी. बी. पी. एम. लगाया गया था जिसे ई. डी. डी. ए. की भी ड्यूटी सौंपी गई थी। नियोजक के अनुसार प्रार्थी उमरखान प्रारंभ से ही अनियमित तथा गैर जिम्मेवाराना कार्य कर रहा था। उसके विरुद्ध अनेकों शिकायतें प्राप्त हुई थी और इसलिए उसका कार्य संतोषप्रद नहीं था। 6-12-78 से 5-2-79 तक प्रार्थी का अवकाश मंजूर नहीं हुआ था फिर भी वह अनाधिकृत रूप से अवकाश पर चला गया और इस प्रकार दुराचरण किया। 5-2-79 को प्रार्थी को सेवा से हटाने बाबत कोई आदेश जारी नहीं किया गया। 14-2-79 से उससे सेवा नहीं ली गई, प्रार्थी को आरोप पत्र जारी किया गया जिनका स्पष्टीकरण देने हेतु उसे उचित अवसर दिए गए और घरेलू जांच प्रारंभ की गई। प्रार्थी एक्सट्रा डिपार्टमेंटल एम्पलोयी था और नियमित कर्मचारी नहीं था इसलिए उसे निर्वाह भत्ता देने के कोई नियम नहीं थे। प्रार्थी को अपने साक्षी पेश करने के लिए व सुरक्षा करने का पूरा अवसर जांच अधिकारी द्वारा दिया गया था। विपक्षी ने भी जिरह करने का उसे पूरा अवसर दिया गया था और जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच प्रोपर एवं फेयर थी। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार सभी आरोप साबित पाए गए थे और इसलिए 27-3-82 से प्रार्थी को सेवा मुक्त किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रार्थी ने निदेशक पोस्टल सर्विसेज जोधपुर को अपील भी की थी जो भी खारिज हुई। अप्रार्थी के अनुसार प्रार्थी द्वारा किए गए दुराचरण गंभीर प्रकृति के थे जिस पर सेवा मुक्ति का आदेश अनुचित एवं अत्याधिक नहीं था। प्रार्थी के विरुद्ध न तो कोई श्रम विरोधी नीति अपनाई गई और न ही शोषण की कार्यवाही की गई इसलिए प्रार्थी किसी अनुतोष का अधिकारी नहीं है।

5. अप्रार्थी द्वारा घरेलू जांच का रिकार्ड प्रस्तुत किया गया था जिसका निरीक्षण करके और पक्षकारों को सुनने के उपरांत दिनांक 24-3-87 के आदेश द्वारा तत्कालीन योग्य अधिकारी ने अप्रार्थी द्वारा कराई गई घरेलू जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं पाई और अप्रार्थी को इसी न्यायालय में आरोप साबित करने का अवसर दिया। फलस्वरूप अप्रार्थी की तरफ से सर्वश्री पूनमदास, तुलसीराम, रूपदास, पी. एल. मीणा, आर. पी. सोनी, रतीराम, सी. बी. सांखला, बोला राम, व मगसिंह के शपथपत्र पेश किए गए हैं जिनसे श्रमिक प्रतिनिधि ने जिरह की है। प्रोलेक्षिक साक्ष्य में एम-1 लगायत एम-9 फोटो प्रतियां पेश हुई हैं। इसके विपरीत प्रार्थी उमर खां ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया जिससे नियोजक प्रतिनिधि ने जिरह की। तत्पश्चात् मैंने पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना।

6. अप्रार्थी नियोजक की प्रारंभिक आपत्तियां यह हैं कि उनका संस्थान भारत सरकार का होने से "रीयल फन्क्शन" करना है इसलिए उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है तथा प्रार्थी उमर खान को अपने कार्यालय का स्वतंत्र व एक मात्र अधिकारी था और प्रशासनिक कार्यों करने के लिए अधिकृत था इसलिए वह कर्मकार की परिभाषा में नहीं आता है। हालांकि उक्त प्रारंभिक आपत्तियां क्लेम के प्रत्युत्तर में तो दर्ज की हैं किंतु इनके बाबत अप्रार्थी की तरफ से किसी भी प्रकार की मौखिक अथवा प्रालेखिक साक्ष्य पेश नहीं हुई है। अप्रार्थी नियोजक के किसी भी साथी ने इन प्रारंभिक आपत्तियों बाबत कथन नहीं किया है और न ही प्रार्थी उमर खान से इस विषय में कोई प्रति परीक्षा की गई है इसलिए साक्ष्य के अभाव में प्रारंभिक आपत्तियां साबित नहीं हैं। यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी उमर खान ई. डी. बी. पी. एम. था जिसका कार्य डाक लाना व ले जाना तथा बांटना था और जिसका वेतन भी 138/- रुपये प्रति माह था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी जैसे स्तर का कर्मचारी धारा 2 (एस) के अन्तर्गत कर्मकार नहीं हो प्रबंधकीय कार्यों से अधिकृत होने बाबत नियोजक

की तरफ से कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई है और न ही प्रार्थी से प्रति-परीक्षा की है इसलिए दोनों प्रारंभिक आपत्तियां आधारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7. जहां तक आरोप साबित होने का प्रश्न है, 26-7-79 को श्रमिक पर निम्न लिखित आरोप लगाये गये थे:—

कि श्रमिक उमर खान शिवगंज के एक निजि पाठशाला में कार्य करने के कारण अपने कार्यालय का शाखा डाकघर बैग जो कानपुरा शाखा कार्यालय में प्रातः 9.15 पर लाना था तथा लेखा कार्यालय को जाने वाला अपना शाखा डाकघर थैला फतहपुरा से 6.30 प्रातः लेकर कानपुरा पहुंचाना था वह न तो निर्धारित समयानुसार थैला लाता है और न ही ले जाता है। इसके अलावा शाखा डाकघर फतहपुरा के कार्यकाल प्रातः 9 से 11 बजे व सायंकाल 4 से 5 बजे के अनुसार डाक घर नहीं चलाता है।

श्रमिक पर दूसरा आरोप यह था कि उमर खान को सालोदरिया गांव में 12 बजे से 12.30 बजे तक चल डाकघर सुविधा उपलब्ध करानी है लेकिन वह सालोदरिया गांव नहीं जाता है।

8. उक्त दोनों आरोपों का प्रत्युत्तर भी श्रमिक ने नियोजक को लिखित में पेश किया था और कहा था कि फतहपुरा गांव का वह स्थाई निवासी है और उपरोक्त समय के अनुसार फतहपुरा से कानपुरा की डाक लाने ले जाने का कार्य 9 वर्ष से करता आ रहा है और फतहपुरा कार्यालय दोनों ही समय सही रूप से खोलकर कार्य करता है। श्रमिक अपने प्रत्युत्तर में यह भी कहता है कि उपरोक्त कार्य करने के पश्चात् वह शिवगंज में प्राईवेट पाठशाला में ट्यूशन का अध्यापन कार्य शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक करता है। दूसरा आरोप भी श्रमिक ने अपने प्रत्युत्तर द्वारा अस्वीकार किया है। और कहा है कि वह रोजाना सालोदरिया मीआईल डाकघर में 12 बजे से 12.30 तक जाकर कार्य करता है। फतहपुरा का कार्य व कर्तव्यों का पालन पूर्ण रूप से निर्धारित समय पर और ईमानदारी से कर रहा है। उक्त आरोपों को सिद्ध करने के लिए नियोजक की तरफ से श्री पूनमदास ने शपथ पत्र दिया है जो तत्कालीन समय पर पालड़ी जोधा शाखा में डाकपाल का कार्य करता था। साक्षी का कहना है 4-12-78 को ई. डी. एम. सी. सुन्दरदास ने आकर उसे इत्तला दी कि सांच पोस्ट मास्टर फतहपुरा के नहीं मिलने से डाक नहीं लेकर आया। फतहपुरा का डाकघर बंद था। साक्षी कहता है इस पर वह भी सुंदरदास के साथ फतहपुरा गया और सुमेरपुर पोस्ट ऑफीस को फोन किया तो उन्होंने बताया कि लिखकर दी जिम पर वह सुमेरपुर में श्री तुलसा राम जमादार के घर गया और उसे इत्तला दी तथा ऐरर बुक में नोट किया और सूचना एम. ओ., एम. पी. एम. सुमेरपुर, आई. पी. ओ. पाली, पी. एम. पाली को भी दी। रिपोर्ट सं. 223 दिनांक 4-12-78 मेरे द्वारा की गई है। साक्षी कहता है 4-12-78 को डाक नहीं आई, 6-12-78 को डाक प्रातः 11.30 बजे प्राप्त की। 7-12-78 को डाक 2.30 बजे शाम प्राप्त की। 5-2-79 को भी फतहपुरा डाकघर बंद था। ई. डी. एम. सी. कानपुरा में गया जहां सालों डाक ई. डी. एम. सी. को नहीं दी और न ली। इसलिए वह सीधा सुमेरपुर आया और सुमेरपुर से डाक 5 बजे लेकर आया। साक्षी कहता है प्रलेख एम—12 शिकायत उसकी कलमी है, ऐरर बुक में इसका उल्लेख एम—11 भी उसका कलमी है। साक्षी के अनुसार ऐरर बुक की पेज सं. 4 पर 4-12-78 को जो इन्द्राज है और 6-12-78 को ऐरर बुक में पेज सं. 7 में जो इन्द्राज है उसकी कापी सांच पी. एम. फतहपुरा को नहीं दी। इसी प्रकार 7-12-78, 19-12-78 व 5-2-79 की ऐरर बुक की प्रतियां भी सांच पोस्ट मास्टर फतहपुरा को नहीं दी। प्रति परीक्षा में भी साक्षी कहता है डाक देर से आती थी, 4-12-78 को भी देर से आई 11.30 बजे और 12 बजे दिन आई, जबकि 9 बजे प्रातः डाक आनी थी। ऐरर बुक नोट किया गया है। उक्त बुक रिकार्ड में जमा करा दी। लिखित में भी शिकायत थी जो 7 या 8-12-78 को की थी। पोस्ट मास्टर सुमेरपुर को तथा सुप्रिंटेंडेंट टपाली को की थी। इस साक्षी से विस्तारपूर्वक प्रति परीक्षा नहीं की गई है और न ही ऐसे सुझावात्मक प्रश्न किये हैं जिससे उसके प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध मिथ्या कथन करने का कोई कारण हो।

9. नियोजक का दूसरा साक्षी तुलसाराम है जो तत्कालीन समय में मेल ओवरसीयर सुमेरपुर था और 1983 से सेवा निवृत्त हो चुका है। इसने भी कहा है कि फतहपुरा ई० डी० बी० उसके हल्के में था और उसने 26-8-77 को पत्र में 12 निरीक्षक डाक घर आबू रोड को लिखा था जो एम-1 है। साक्षी कहता है वह 23-8-77 को करीब 8.00 बजे सुबह फतहपुरा गया, उस दिन उमर खान कार्य स्थान पर उपस्थित नहीं था। गांव वालों ने बताया कि उमर खान कभी-कभी कार्य पर आता है, समय पर कभी नहीं आता था, उसका कोई निश्चित समय नहीं था। साक्षी कहता है वह 23-8-77 को करीब 12-1 बजे तक फतहपुरा रहा, उसके बाद सालोदरिया गांव चला गया वहां पर भी सरपंच व चम्पानाई ने बताया कि उमर खान नहीं आया। यह भी बताया कि उमर खान का गांव में आने-जाने का समय निश्चित नहीं है। साक्षी कहता है उसके बाद वह कानपुरा सांच आफीस में गया जहां पर फतहपुरा की डाक पड़ी दिखी जिस बाबत डाकपाल कानपुरा से पूछा तो बताया कि उमर खान लेने नहीं आया। तुलसा राम यह भी कहता है कि कानपुरा में उमर खान शाम को 6.30 बजे आया। इस प्रकार कानपुरा की ऐरर बुक में नोट कराकर और वहां के लोगों की गवाही लेकर फतहपुरा की डाक उमर खान को दी। साक्षी कहता है उसने उमर खान के लेट आने का कारण पूछा तो बताया कि वह बच्चों को पढ़ाने जाता है और उसके बाद डाक लेकर चला गया। साक्षी यह भी कहता है कि उसने एम-2 पत्र 7-12-78 को श्री सी० बी. गांगुला निरीक्षक डाकघर पाली को लिखा था। साक्षी ने अनुसार उसके बाद 4-12-78 को शाखा डाकपाल पालड़ी जोधा आया और कहा कि उसे डाक नहीं मिली इस पर वह पूनमदास शाखा डाकपाल के साथ कानपुरा शाखा गया वहां फतहपुरा की टी०बी० पड़ी मिली। रूप भारती शाखा डाकपाल के बयान लिये और रिपोर्ट के साथ पाली निरीक्षक को भेजे। साक्षी कहता है वह उसी दिन शाम को सुमेरपुर आया और शाखा डाकपाल को कहा कि डाक टी० बी० वहीं रखना। साक्षी के अनुसार दूसरे दिन सुबह 5.00 बजे शाखा डाकपाल कानपुरा डाक लेकर आया। यह भी कहता है कि उसने एम—3 पत्र 25-11-78 को प्रवर अधीक्षक डाक पाली को लिखा था क्योंकि वह जब 21 व 22 नवम्बर, 1978 को फतहपुरा गया तो उसे दोनों दिन उमर खान डाकपाल नहीं मिला। 22-11-78 को शाम 5 बजे तक उमर खान का इन्तजार किया और उसके बाद कानपुरा गांव चला गया। वहीं पर 22-11-78 को डाक थैला पड़ा मिला और शाखा डाकपाल कानपुरा श्री रूप भारती ने बताया कि 21-11-78 को डाक थैला यहां खोलकर यहीं बंद करके दिया। साक्षी कहता है 22-11-78 को उमर खान उसके पास नहीं आया। तुलसा राम यह भी कहता है कि रूप भारती शाखा डाकपाल ने कुछ चिट्ठियां दी थी जो सालोदरिया व फतहपुरा की थी जो उसे धोला राम ने दी थी जिसे स्कूल के बच्चों ने दी थी। साक्षी कहता है उसने उन चिट्ठियों के बारे में भी ऐरर बुक में नोट करके धोला राम माली से लिखवाया और दूसरे दिन चिट्ठियां सुमेरपुर वापस की। साक्षी कहता है एम-1 रिपोर्ट निरीक्षक डाकघर सिरोही को श्री धोलाराम ई० एम० डी० बी० कानपुरा व श्री रूप भारती बी० पी० एम० कानपुरा के बयानों के साथ थी। यह साक्षी भी प्रति परीक्षा में कहता है उसकी ड्यूटी पोस्ट आफिस तक करना था, डाक के आने जाने का बंदोबस्त करना था। वह फतहपुरा माह में एक बार जाता था। गांव वालों से पूछताछ पर पता चला कि उमर खान समय पर नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। साक्षी कहता है उसने गांव वालों के लिखित बयान लिये और फतहपुरा में ही रिपोर्ट बनाई थी। जो सुप्रिंटेंडेंट पोस्ट आफिस पाली को डाक से भेज दी थी। साक्षी कहता है उसने उमर खान से भी पूछताछ की थी और उसने लिखित में दे दिया था लेकिन उसने बयान देने से इंकार कर दिया। यह साक्षी 1983 में सेवा निवृत्त हो चुका है, इसका नियोजक से प्रभावित होकर कथन करने का कोई कारण व संभावना नहीं है। प्रति परीक्षा में भी श्रमिक ने ऐसे सुझावात्मक प्रश्न नहीं किये जिससे उसका श्रमिक के विरुद्ध मिथ्या कथन करने का कोई कारण नजर आता हो।

10 रूपदास नियोजक साक्षी ने उमर खान से फतहपुरा डाकघर का 6-12-78 को चार्ज लिया था। इसका कहना है उसे उमर खान ने पूरा चार्ज नहीं दिया और चार्ज संभलवाये बिना ही चला गया। साक्षी कहता है उसे रास्ते में उमर खान रोकता था, मारने पीटने की धमकियां देता था, डाक का थैला भी फाड़ डाला, एक दो बार उसे पीटा भी था जिसकी रिपोर्ट उसने सुलसा राम जमादार को की थी। साक्षी कहता है उससे उमर खान बार बार पूछता था कि किस किस की चिट्ठी आई और किस किस का मनीआर्डर आया है। यह साक्षी भी प्रति परीक्षा में कहता है उसने मारपीट करने की लिखित में दो बार शिकायत की थी पुलिस में भी रिपोर्ट की थी। थैला फाड़ने की शिकायत ब्रांच आफीस में की थी, पुलिस ने उमर खान को बुलाया था व पूछताछ की थी। पुलिस में उमर खान के विरुद्ध मुकदमा चल रहा है उसे एक बार पुलिस ने बुलाया था, उसके बयान लिये थे। साक्षी कहता है कि वह आफीसर के कहने से झूठा बयान नहीं दे रहा है। यह साक्षी भी प्रति परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरा है और इसका भी श्रमिक के विरुद्ध मिथ्या कथन करने का कोई कारण नजर नहीं आता।

11. नियोजक साक्षी पी. एन. मीणा तत्कालीन समय में निरीक्षक सिरोही था और सुमेरपुर हल्का उसके अधीन था, साक्षी कहता है उसने एक पत्र 10-10-78 को सीनियर सुप्रडेंट पाली को भेजा था जो एम ओ सुमेरपुर के पत्र के आधार पर था साक्षी कहता है उसे जानकारी मिली थी कि उमर खान ही.पी. एम, फतहपुरा शिवगंज में एक प्राईवेट स्कूल चला रहा था जिसका समय प्रातः 8 बजे से 1.00 बजे तक था। यह साक्षी भी प्रति परीक्षा में कहता है उसने उमर खान को स्कूल चलाते देखा है और स्वयं उमर खान ने भी कहा था कि वह हेड मास्टर है। उसी संबंध में उसने सुप्रीडेंट को रिपोर्ट भेजी थी। साक्षी कहता है उसने 8 बजे सुबह के बाद और 12 बजे दोपहर के पहले उमर खान को स्कूल चलाते देखा है। इस साक्षी से भी विस्तार पूर्वक प्रति परीक्षा नहीं की है और इसका भी श्रमिक के विरुद्ध मिथ्या कथन करने का कोई कारण नजर नहीं आता।

12. आर. पी. सोनी नियोजक का एक अन्य साक्षी है जो सहायक अधीक्षक पाली है जिसके अधीन सुमेरपुर उप डाक घर आता था। साक्षी कहता है फतहपुरा डाक घर मोबाईल था और सालोदरिया गांव के कार्य का समय 12 बजे से 12.30 बजे दोपहर तक का था जहां पर शाखा डाकघर का कार्य करना होता है। नियोजक को यह साक्षी किसी दुराचरण को साबित करने के लिए नहीं है बल्कि सालोदरिया डाकघर का कार्य समय सिद्ध करने के लिए है। इस साक्षी से भी विस्तारपूर्वक प्रति परीक्षा नहीं की गई है और न ही श्रमिक ने यह अस्वीकार किया है कि सालोदरिया गांव का समय 12 से 12.30 दिन का न हो।

13. नियोजक साक्षी रतिराम तत्कालीन समय में प्राइमरी विद्यालय फतहपुरा का प्रधान अध्यापक था जिसने भी कहा है कि वह उमर खान को जानता है। उमर खान गांव में डाक पहुंचाने स्वयं नहीं आता था। बच्चों के द्वारा एक दो दिन बाद डाक बंटवाता था। जब कभी यह साक्षी डाक की पूछताछ करने जाता तो अधिकतर उमर खान उसे नहीं मिलता था। जयसिंह निवासी फतहपुरा के पेंशन के कागज भी उमर खान ने गायब कर दिये थे। साक्षी कहता है उसने निरीक्षक डाकघर पाली को अपने पत्र संख्या 372 दिनांक 22-2-72 द्वारा रिपोर्ट की थी। साक्षी भी प्रति परीक्षा में कहता है। जयसिंह और जिनकी डाक गायब हुई उन्होंने मेरे सामने शिकायत की थी जो एम-5/1 है उस पर ए टू बी उसके स्वयं के हस्ताक्षर हैं और सी टू डी जयसिंह के हस्ताक्षर है। जय सिंह अंधा था उसको असहाय होने की 40/रु. पेंशन मिलती थी, उमर खान 5/ रुपये लेकर पेंशन के पैसे देता था। यह शिकायत 22-2-72 की है। साक्षी कहता है उसने डाक गुम होने की शिकायत विकास अधिकारी के मार्फत पुलिस को भी की थी। पुलिस वाले पूछताछ करने उसके पास आयें थे परंतु पता नहीं कि उमर खान कि खिलाफ उन्होंने क्या कार्यवाही की। साक्षी यह भी कहता है कि उमर खान बच्चों के द्वारा डाक बंटवाता था। साक्षी के अनुसार उससे पोस्ट आफीस के अंवरसीयर व निरीक्षक ने भी पूछताछ की थी और लिखकर भी ले गये थे। इस साक्षी से भी प्रति परीक्षा में ऐसा सुझावात्मक प्रश्न नहीं किये हैं जिससे उसका कोई मनमुटाव श्रमिक के प्रति उजागर हो और उसका मिथ्या कथन करने का कोई हित या हेतु प्रदर्शित होता हो।

14. नियोजक साक्षी सी. बी. साम्बला तत्कालीन समय में निरीक्षक डाकघर पाली था, सुमेरपुर कस्बा भी उसी के कार्यक्षेत्र में आता था। साक्षी कहता है उसने 7-2-79 को एम-8 रिपोर्ट डाकघर पाली को उमर खान शाखा डाकपाल फतहपुरा के असंतोषप्रद कार्य के बाबत की थी। 14-3-79 को भी अधीक्षक डाकघर पाली को एम-9 रिपोर्ट उमर खान के असंतोषप्रद कार्य के बारे में की थी। इस साक्षी से नाम मात्र की ही प्रति परीक्षा की गई है और यह साक्षी भी निष्पक्ष कोटि का विश्वसनीय साक्षी है।

15. नियोजक साक्षी धौला राम कानपुरा का निवासी है जो रूप भारती डाकपाल व उमर खान को जानता है। साक्षी कहता है उसने रूप भारती को 4–5 पोस्ट कार्ड दिये थे। जो उसे रास्ते में पड़े मिले थे। प्रति परीक्षा में कहता है यह बात करीब दस साल पहले की है, उसे सालोदरिया गांव के रास्ते में पोस्ट कार्ड पड़े मिले थे। नियोजक साक्षी मग सिंह भी सालोदरिया पंचायत का सरपंच है और कहता है कि उमर खान कभी भी समय पर डाक नहीं बांटता था। वह कभी समय पर नहीं आता था। यह कभी सुबह को कभी शाम को डाक बांटता था और कभी-कभी आता भी नहीं था साक्षी कहता है। 23-8-77 को सुलसा राम मेल अंवरसीयर सुमेरपुर हमारे गांव सालोदरिया सुबह आया और उमर खान डाकपाल के बारे में पूछताछ की। उस रोज भी उमर खान डाक बांटने नहीं आया। साक्षी के अनुसार गांव में डाक बांटने का 11 बजे का समय निश्चित था। इस साक्षी से भी नाम मात्र की ही प्रति परीक्षा की गई है।

16. नियोजक के उपरोक्त समस्त साक्षियों के कथनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि ये सभी साक्षी निष्पक्ष कोटि के साक्षी हैं और इनका श्रमिक के विरुद्ध कोई मनमुटाव या रंजिश भी नहीं है और न ही इनमें से किसी का श्रमिक के विरुद्ध मिथ्या कथन करने का को हित या हेतु नजर आता है इस प्रकार उपरोक्त सभी नियोजक साक्षी विश्वसनीय एवं सत्यवादी हैं। श्रमिक उमर खान के इनमें से किसी भी साक्षी के प्रति परीक्षा में न तो ऐसे सुझावात्मक प्रश्न किये हैं जिनसे इनका श्रमिक के विरुद्ध मिथ्या कथन करने को कोई हित या हेतु प्रदर्शित होता हो और न ही श्रमिक ने अपने शपथ पत्र में उक्त विषय के कोई कथन किये है इसलिए उपरोक्त सभी नियोजक साक्षी निष्पक्ष कोटि के सत्यवादी साक्षी पाये जाते हैं जिनका मौखिक कथनों की पुष्टि उन्हीं के द्वारा लिखे गये पत्रों व प्रलेखों से भी होती है।

17. नियोजक की उपरोक्त साक्ष्य के विपरीत श्रमिक उमर खान ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है और कहा है कि उसके द्वारा तीनों पदों का कार्य करने के कारण उसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता मांगे जाने के कारण ही विभाग के कुछ अधिकारी उससे नाराज थे, साथ ही गांव के कुछ स्वार्थी तत्वों के भी विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से उसके विरुद्ध झूठी बेबुनियाद शिकायतें कर दी थी मेरी राय में श्रमिक द्वारा शपथ पत्र में कथन अंकित करने मात्र से ही वह स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि श्रमिक से अपेक्षा

थी कि वह उन विभागीय अधिकारियों के अथवा गांव के स्वार्थी व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करता जो उससे रंजिश रखते थे। न तो अपने क्लेम में और न ही अपने शपथ पत्र में श्रमिक ने ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है यहां तक कि नियोजक द्वारा प्रस्तुत साक्षियों में से ही किसी भी व्यक्ति के नाम बाबत सुझावात्मक प्रश्न नहीं किए हैं जो उससे रंजिश रखते थे। श्रमिक उमर खान प्रति परीक्षा में स्वीकार करता है कि प्रदर्श एम-6 उसे मिला था जिस पोस्ट आफिस वह काम करता था उसके किसी भी व्यक्ति से उसकी नाराजगी नहीं थी। श्रमिक यह भी स्वीकार करता है कि उसकी ड्यूटी फतेहपुरा से कानपुरा डाक ले जाने की थी। वह 6.30 बजे डाक कानपुरा पहुंचा दिया करता था। उसकी यह भी ड्यूटी थी कि वह 9.30 बजे कानपुरा से फतेहपुरा डाक का थैला ले जाता था। फतेहपुरा में उसकी ड्यूटी 9 बजे से 11 बजे तक थी फिर 4 से 5 बजे तक डाकघर खोलने की ड्यूटी थी। इस बीच 12 से 12.30 बजे तक मोबाईल पोस्ट आफिस सालोदरिया ड्यूटी थी जिसका उसे मोबाईल अलाउंस 15 रु. अलग से मिलता था। प्रति परीक्षा में श्रमिक कहता है वह शिवगंज में स्कूल नहीं चलाता था, 11 मैम्बर स्कूल चलाते थे उनमें से एक मैम्बर वह भी था, श्रमिक के अनुसार वह शिवगंज में स्कूल में रात में पार्ट टाईम काम करता था। रात को ट्यूशन पढ़ाता था। यह उल्लेखनीय है कि नियोजक प्रतिनिधि द्वारा सुझावात्मक प्रश्न करने पर साक्षी कहता है उसे पता नहीं कि स्कूल का समय क्या था। उसे पता नही कि स्कूल का समय कितने बजे से कितने बजे तक का था। साक्षी द्वारा दिये गये उपरोक्त उत्तर से यह निष्कर्ष निकलता है कि साक्षी स्कूल का समय बताना नहीं चाहता। यह संभव नहीं है कि स्कूल चलाने वाली कमेटी में होते हुए भी और स्कूल में पार्ट टाईम ट्यूशन पढाते हुए भी श्रमिक को स्कूल का टाईम पता नहीं हो। साक्षी से आरोपों बाबत विस्तारपूर्वक प्रति परीक्षा की गई है जिनको उसने अस्वीकार किया है साक्षी ने यह जो कहा है कि उसे 4-12-78 को छुट्टी स्वीकृत कर दी गई थी परंतु साथ में यह भी कहता है कि शायद उस रोज वह छुट्टी पर था। श्रमिक द्वारा प्रति परीक्षा में दुराचरण बाबत पूछे गये प्रश्नों को अस्वीकार करने मात्र से इस विषय में नियोजक द्वारा प्रस्तुत मौखिक व प्रालेखिक साक्ष्य को निरस्त नहीं किया जा सकता विशेषकर उस परिस्थिति में जबकि नियोजक द्वारा प्रस्तुत समस्त साथी निष्पक्ष कोटि के पाये गये हों और जिनके मौखिक कथनों की पुष्टि उनके द्वारा लिखित पत्रों प्रलेखों से होती हो वह अतएव उपरोक्त समस्त कारणों से मेरी राय में भी श्रमिक पर लगाये गए समस्त आरोप साबित पाये जाते हैं।

18. उक्त आरोपों पर श्रमिक को दिये गये सेवा मुक्ति के दंड पर भी मैंने पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को सुना। मेरी राय में श्रमिक पर गंभीर दुराचरण साबित हैं और चूंकि श्रमिक स्थाई पद पर नियुक्त नहीं था और एक्सट्रा डिपार्टमैंटल ब्रांच पोस्ट मास्टर ही नियुक्त था इसलिए उसे सेवा मुक्ति का दण्ड देना मेरी राय में अनुचित एवं अत्याधिक नही है।

19. श्री परिहार, श्रमिक प्रतिनिधि का एक तर्क यह था कि श्रमिक को फरवरी 1979 से निर्वाह भत्ता भी नहीं दिया गया है हालांकि नियोजक ने यह कहा है कि उनके नियमों के अनुसार नियमित वह स्थाई कर्मचारियों को ही निर्वाह भत्ता देने का प्रावधान है परन्तु मेरी राय में श्रमिक जैसे अस्थाई कर्मचारी को भी जांच के दौरान निर्वाह भत्ता देना आवश्यक था इसलिए फरवरी 1979 से सेवा मुक्ति दिनांक 27-3-82 तक यह श्रमिक स्थाई श्रमिकों की तरह ही निर्वाह भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी है, जो अप्रार्थी नियोजक उसे इस आदेश के तीन माह के अन्दर अदा करेगा अन्यथा 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।

20. श्री परिहार श्रमिक प्रतिनिधि का एक तर्क यह था कि नियोजक द्वारा कराई गई घरेलू जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं पाई गई है इसलिए "रिलेशन बैक" थ्योरी लागू नहीं की जा सकती और न्यायालय के आदेश तक का श्रमिक को वेतन दिलाया जाये। मेरी राय में नियोजक द्वारा जो घरेलू जांच कराई गई है वह जांच का एक बहाना मात्र ही नहीं बल्कि प्राकृतिक न्यायालय के सिद्धान्तों के अनुरूप विस्तृत जांच की गई थी तथाकथित जांच इसलिए प्रोपर एवं फेयर नहीं पाई गई क्योंकि श्रमिक ने किसी भी नियोजक साक्षी से जिरह नहीं की थी फिर भी कुछ साक्षियों की जिरह में यह लिख दिया गया था कि श्रमिक को जिरह का अवसर दिया गया और कुछ की जिरह में उक्त उल्लेख नही किया गया था तथा श्रमिक की जांच के दौरान निर्वाह भत्ता भी नहीं दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ए. आई. आर. 1959 (एस. सी.) 923 सासा मूसा के न्याय दृष्टांत में निम्नलिखित व्यक्त किया गया है :—

> "Where management discharges a workman by an order which is void for want of any enquiry or for blatent violation of rules of natural justice, the relation back doctrine could not be invoked. Jurisprudential difference between a void order which by subsequent judicial resuscilation comes into being denova and an order which may suffer from some defects but is not still born or void and all that is needed in the eye of law to make it good is a subsequent approval by a tribunal which is granted, cannot be objuscated."

राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी संगम एक्सपोर्टस बनाम जज, लेबर कोर्ट एस. बी. सिविल रिट 1020/80 निर्णय दिनांक 10-11-86 में निम्न मत व्यक्त किया है :—

> "Where management does not hold domestic enquiry and justify the charges in court and misconduct justified punishment of dismissal, then the dismissal will operate from the date of award and not from the date of passing of order by management."

इससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि जहां पर नियोजक द्वारा या तो घरेलू जांच करवाई ही नहीं गई हो अथवा तथाकथित जांच का बहाना मात्र हो वहीं पर रिलेशन बैक थ्योरी लागू नही होती। विवेचनाधीन विवाद में तो जैसा कि मैंने ऊपर मत व्यक्त किया है, नियोजक द्वारा विस्तारपूर्वक जांच की गई थी। जांच के दौरान श्रमिक भी उपस्थित था अनेकों साक्षियों का विपक्षी की तरफ से परीक्षण हुए थे और अनेकों प्रलेख भी पेश हुए थे परंतु श्रमिक ने किसी भी नियोजक साक्षी से प्रति परीक्षा जानबूझ कर नहीं की। अभिप्राय यह है कि विवेचनाधीन विवाद में नियोजक द्वारा कराई गई घरेलू जांच हालांकि तकनीकी रूप में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं पाई गई थी परन्तु फिर भी उक्त जांच नियोजक द्वारा कराई गई घरेलू जांच का बहाना मात्र नहीं कहा जा सकता। अतः इन परिस्थितियों में रिलेशन बैक थ्योरी ही लागू की जा सकती है। यह सही है कि अगर प्रबंधकों द्वारा पारित किया गया सेवा मुक्ति आदेश शून्य हो तो ए आई आर 1976 एस.सी. 1760 एवं ए आई आर 1980 एस सी 1896 के न्याय दृष्टान्तों के अनुसार रिलेशन बैक सेवा मुक्ति को दिनांक को नहीं हो सकता परन्तु ए आई आर

1963 ए. सी. 1756 पी एवं कल्याणी बनाम एयर प्रोम तथा डी. सी० राय बनाम प्रिसाइडिंग आफीसर इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल 1976 लैब आई सी 1142 पर उपलब्ध उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टान्तों के अनुसार

> "Where the tribunal comes to the conclusion on its own appraisal of the evidence educed to before it, that the dismissal is justified, the dismissal will relate back to the date when the order of dismissal was made by the employer."

विवेचनाधीन विवाद में मेरी राय में प्रबन्धकों द्वारा कराई गई घरेलू जांच का एक बहाना ही नहीं थी बल्कि वास्तव में जांच अधिकारी नियुक्त करके नियमानुसार जांच करवाई गई थी। प्रबंधकों के साक्षियों के ब्यान भी श्रमिक की उपस्थिति में हुए थे, श्रमिक के प्रति परीक्षा करना नहीं चाहा इन परिस्थितियों में नियोजक द्वारा पारित किया गया सेवा मुक्ति आदेश शून्य नहीं था उपरोक्त समस्त कारणों से इस विवाद में रिलेशन बैंक थ्योरी ही लागू होती है।

21. मद्रास उच्च न्यायालय में भी अशोका लर्लेंड बनाम लेबर कोर्ट 1988 (1) एल एल एन 302 के न्याय दृष्टान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कल्याणी वाले न्याय दृष्टान्त तथा गुजरात स्टील ट्यूबस के न्याय दृष्टांत में 1980 (1) एल एल एन 230 पर विचार करने के उपरांत रिलेशन बैंक थ्योरी को ही अपनाया था क्योंकि नियोजक द्वारा कराई गई जांच बहाना मात्र नहीं थी।

22. अतः उपरोक्त समस्त कारणों से इस केस में भी रिलेशन बैंक थ्योरी ही लागू की जाती है और यह श्रमिक सेवा मुक्ति की दिनांक से इस अधिनिर्णय की दिनांक तक का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथ्यों और विधि उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :—

> "प्रार्थी उमर खान ई.डी.बी. पी. एम. फतहपुरा की सेवा मुक्त उचित और वैध है और यह श्रमिक किसी सहायता का अधिकारी नहीं है। नियोजक के स्थाई आदेशों के अनुसार नियमित श्रमिकों की तरह ही इस श्रमिक को भी दिनांक 5-2-79 से 27-3-82 तक निर्वाह भत्ता देना होगा।

23. उपरोक्त आशय का अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17 (1) अधिनियम भेजा जाये।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 28 मई, 1992

का. आ. 1657.—समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 25 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का. आ. 269 के अधिक्रमण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सलाहकार समिति का पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल है :—.

सलाहकार समिति:—

1. केन्द्रीय श्रम मंत्री/उप श्रम मंत्री —अध्यक्ष
2. सचिव, श्रम मंत्रालय —पदेन सदस्य
3. संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय, (बाल एवं महिला श्रमिक संबंधी मामलों के प्रभारी) पदेन सदस्य
4. संयुक्त सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग नई दिल्ली -वही-
5. सलाहकार, श्रम एव नियोजन प्रभाग योजना आयोग, नई दिल्ली -वही-
6. सचिव, श्रम विभाग, आन्ध्र प्रदेश शासन, हैदराबाद -वही-
7. सचिव, श्रम विभाग, भारत सरकार दिसपुर -वही-
8. सचिव, श्रम विभाग, संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली -वही-
9. श्री विजय जी. कालन्तरी -वही- अध्यक्ष, अखिल भारतीय विनिर्माता गैर सरकारी सदस्य संघ, . आवमैरो इन्डस्ट्रीज, 73. बम्बई समाचार मार्ग, बम्बई-400023
10. डा. (सुश्री) एन हमसा, -वही- उप सचिव अखिल भारतीय नियोजक संगठन फैडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली—110007
11. सुश्री मंजुला रे -वही- अध्यक्ष, पं. बंगाल इन्टक वीमेन वर्किंग कमेटी फ्लैट, 4, 12 स्वीनहो स्ट्रीट कलकत्ता
12. श्रीमती कमला सिन्हा, -वही- उपाध्यक्ष हिन्द मजदूर सभा, नगीनदास चैम्बर्स 167. पी. डी. मैलो रोड, बम्बई
13. श्री सी. एम. कृष्णा, -वही- निदेशक कार्मिक, हिन्दुस्तान एरोनाटिकस लि., 15/1, कुबोन रोड, बम्बई
14. श्रीमती सुनीला बी. पंडोले -वही- भारतीय मजदूर संघ, विदर्भ प्रदेश, 542, डा. मुंजे मार्ग, कांग्रेस नगर, नागपुर
15. डा. लतिका सरकार, -वही- महिला विकास अध्ययन केन्द्र, बी—43, पंचशील इन्कलेव, नई दिल्ली
16. सुश्री जया अरुणाचलम, अध्यक्ष वर्किंग वोमेन्स फोरम (भारत),

55. भीमसेन गार्डन रोड, माइलापोर, मद्रास	सरकारी सदस्य
17. सुश्री मीना पटेल, सैल्फ इम्पलाइड वीमेन्स एसोसिएशन सेवा स्वागत केन्द्र, लोकमान्य तिलक मार्ग के सामने भद्रा, अहमदाबाद	—वही—
18. सुश्री भारतिन्दी जेना इन्स्टीच्युट आफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट, 5, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली,	—वही—

2. समान पारिश्रमिक नियमवाली, 1991 संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति के नियम 4 के अनुसार गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल नामित करने की तारीख से दो वर्ष होगा । इसमें यह भी व्यवस्था है कि ऐसे सदस्य अपने उत्तराधिकारी के नामित होने तक अपने पद पर बने रहेंगे ।

[सं. एस-42025/49/84सी एण्ड डब्ल्यू एल-II]

शशि जैन, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 28th May, 1992

S.O. 1657—In exercise of the powers confered by sub- section (1) of Section 6 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976) and in supersession of notification published in the Gazette of India vide S.O. 269 dated the 25th January, 1986, the Central Government hereby reconstitute the Advisory Committee consisting of the following members :—

Advisory Committee	
1. Union Minister for Labour/ Deputy Labour Minister	Chairman
2. Secretary, Ministry of Labour.	Ex-Officio Member.
3. Joint Secretary, Ministry of Labour. (Incharge of Child and Women Labour)	,,
4. Joint Secretary, Department of Women and Child Development, New Delhi.	,,
5. Adviser, Labour & Employment Division. Planning Commission, New Delhi.	,,
6. Secretary, Labour Department, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.	,,
7. Secretary, Labour Department, Government of Assam, Dispur.	,,
8. Secretary, Labour Department, Union Territory of Delhi, Delhi.	,,
9. Shri Vijay G. Kalantri, President, All India Manufacturers' Organisation, M/s. Abro Industries, 73, Bombay Samachar Marg, Bombay.	Non-Official Member
10. Dr. (Ms.) N. Hamsa, Deputy Secretary, All India Organisation of Employers. Federation House, Tansen Marg, New Delhi-110001.	,,
11. Ms. Manjula Ray, President, INTUC Women Working Committee of West Bengal Flat, 4, 12 Swinhoe Street, Calcutta.	,,
12. Mrs. Kamla Sinha, Vice.President, Hind Mazdoor Sabha. Nagindas Chambers, 167, P.D. Mello Road, Bombay.	,,
13. Mr. C.M. Krishna, Director (Personnel) Hindustan Aeronautics Ltd., 15/1, Cubbo Road, Bombay.	,,
14. Smt. Sunita V. Padoley, Bharatiya Mazdoor Sangh, Vidarbh Pradesh, 542, Dr. Munje Marg, Congress Nagar, Nagpur.	,,
15. Dr. Lotika Sarkar, Centre for Women's Development Studies, B-43, Panchsheel Enclave, New Delhi.	,,
16. Ms. Jaya Arunachalam, President, Working Women's Forum (India) 55, Bhimsena Garden Road, Mylapore, Madras.	,,
17. Ms. Meena Patel, Self Employed Women's Association, SEWA Reception Centre, Opposite Lokmanya Tilak Baug Bhadra, Ahmedabad.	,,
18. Ms. Bratindi Jena, Institute of Social Studies Trust 5, Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi.	,,

2. The terms of office of non-official member(s) of the Committee shall be two years from the date of their nomination in accordance with Rule 4 of the Central Advisory Committee on Equal Remuneration Rules, 1991. It is further provided that such member shall, continue to hold office until his/her successor is nominated.

[No. S-42025/49/84-C&WL-II Section]

SHASHI, JAIN, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 28 मई, 1992

का. आ. 1658.—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट होने के पश्चात् कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को, इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए यह निर्णय करने के लिए कि भारत से बाहर जाने वाला अमुक व्यक्ति उत्प्रवासी नहीं है, उत्प्रवास संरक्षी का कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

1. पासपोर्ट अधिकारी, नागपुर

2. पासपोर्ट अधिकारी, गोवा

[सं जैड-11025/68/89—उत्प्रवास]

जी के भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 28th May, 1992

S.O. 1658.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government after satisfying that it is necessary so to do, hereby authorises the following officers to perform the functions of Protector of Emigrants for deciding that a person intending to depart from India, is not an emigrant, for the purposes of the Act, namely :—

1. Passport Officer, Nagpur.

2. Passport Officer, Goa.

[No. Z-11025/68/89-Emig.]

G. K. BHATTACHARYA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 2 जून, 1992

का. आ. 1659.—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और इस मंत्रालय की समसंख्यांक अधिसूचना दिनांक 18-5-1992 के अनुक्रम में, केन्द्रीय सरकार श्री ए. के. निगम, अनुभाग अधिकारी तथा उत्प्रवास संरक्षी II, बम्बई को और पन्द्रह दिन के लिए 30-5-92 पूर्वाह्न के 13-6-92 अपराह्न तक उत्प्रवास संरक्षी गोवा के रूप में नियुक्त करती है ।

[संख्या जैड-11025/68/89 उत्प्रवास]

सरिता मित्तल, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd June, 1992

SO. 1659.—In exercise of the powers conferred by Section 3, sub-section (1) of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), in the continuation of this Ministrys Notification of even number dated 18-5-1992 the Central Government hereby appoints Shri A. K. Nigam, Section Officer, and Protector of Emigrants II, Bombay as Protector of Emigrants Goa for further fifteen days with effect from 30-5-92 (FN) to 13-6-92 (AN).

[No Z-11025/68/89-Emig.]

SARITA MITTAL, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992